केवल कार्यालय उपयोगार्थ

राजस्थान सरकार

मंत्रि-मण्डल सचिवालय

व्यवस्था एवं पद्धति (संकलन) अनुभाग

अक्टूबर, 1968 में
शासन सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गए महत्वपूर्ण परिपत्रादि का मासिक संकलन

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

1969

विभागों की सूची

(उन विभागों की सूची जिनके महत्वपूर्ण परिपत्रों आदि को अक्टूबर, 68 के संकलन में मुद्रित किया गया है ।

अक्टूबर, 1968

AGRICULTURE DEPARTMENT

INDEX

(i)

राज्य शासन की आज्ञा संख्या एफ. 1(1) नियवित (स्पेशल), दिनांक 8 अक्टूबर, 1954 का आंशिक अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल महोदय, ने भरतपुर स्थित उप निदेशक, कृषि विभाग का मुख्यालय (हैड क्वार्टर) जयपुर स्थानान्तरण किये जाने की आज्ञा प्रदान की है ।

[कृषि (प्रकोष्ठ-1) विभाग आज्ञा क्रमांक प.10(2)/कृषि-1168 दिनांक 18-10-68 ।]

APPOINTMENTS DEPARTMENT

INDEX

(26)

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendments in the Rajasthan Civil Services (Grant of Merit Pay) Rules, 1961, namely:—

AMENDMENTS

In rule 6 of the said rules,—

1. for the existing rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The Merit Pay shall be treated as personal pay and shall be free from the operation of provisions of clause (27) of Rule 7 and sub-rule (4) of rule 27 of Rajasthan Service Rules and shall be in addition to and shall not be merged in any further increase in the pay of a Government servant in the time-scale or otherwise."

2. after the existing sub-rule (2), the following new sub-rule shall be added, namely:—

"(3) If a Government servant retires from Government service on attaining the age of superannuation before the expiry of the period for which the merit pay has been sanctioned to him, he shall continue to receive merit pay for the full period for which it has been sanctioned to him, irrespective of the fact that he no longer continues in Government service. The merit pay shall also be admissible to a Government servant during the period of his re-employment should he happen to be re-employed to the extent the period of re-employment falls within the period for which the merit pay has been sanctioned."

NOTE:—These amendments shall be deemed to have come into force with effect from 30th June, 1967.

[Appointment (A-II) Deptt. notification No. F. 1 (6) Apptt. (A-II)/61, dated 19-10-68]

(27)

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with rule 11 of the Rajasthan Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1958, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendment in Schedule I appended to these rules, namely:—

AMENDMENT

In Schedule I to the said Rules under the heading "Tourism Facilities Department" after the existing item I, the following new item shall be added, namely:—

"2 Manager, Tourist Bungalow, Extension Block, Mt. Abu".

[Appointment (III) Deptt. notification No. F.3(10)/Apptt. A-III/68, dated 31-10-68.]

(मंत्रि-मण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पध्दति अनुभाग सहित)
CABINET SECRETARIAT (INCLUDING O & M)

सूची
INDEX

(78)

कृपया इस सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति) की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 18-4-68 के द्वारा निर्मित परियोजना समिति, नागौर के क्रम संख्या 1 पर "श्री गुलाममुस्तफा हुसेन मकराना वाले" पढ़ें।

[मंत्रि-मण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) शुद्धि-पत्र संख्या प. 5(25) व्य. एवं प. 63, दिनांक 7-10-68]

---

(79)

The Governor has been pleased to appoint the Deputy Secretary, Industries as Member-Secretary on the Committee constituted vide Secretariat (O & M) order of even number, dated the 28th August, 1968 for the promotion of the Rajasthan Industries and Minerals Development Corporation.

Shri Suresh H. Mathur, Deputy Legal Draftsman will be associated with the deliberations of the Committee so that legal shape could be given to the Memorandum and Articles of Association of the proposed Corporation.

(Cabinet Sectt. (O & M) order No. F.5(36) O & M/68, dated 10-10-68)

---

(80)

विषयः—सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के गठन एवं उनके कार्य में सुधार हेतु सुझाव देने के लिये समिति का गठन।

राज्यपाल एतद्द्वारा इस सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति) की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 27-5-1968 के क्रम में उपरोक्त समिति का कार्यकाल दिनांक 30-9-68 ई. तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

[मंत्रि-मण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) आज्ञा संख्या प. 5 (1) व्य. एवं प. 68, दिनांक 10-10-68।]

---

(81)

The Governor is pleased to appoint the Deputy Minister for Agriculture as member of the Advisory Board for Jaipur Milk Supply Scheme constituted vide Secretariat (O & M) order of even number dated 16th January, 1968.

(Cabinet Sectt. (O&M) order No. F.5 (34)O &M/67, dt. 10-10-68

(82)

राज्यपाल एतद्द्वारा इस सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति) की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 13-3-1968 के द्वारा निर्मित समिति का कार्यकाल तीन माह अर्थात् दिनांक 12 दिसम्बर, 1968 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है।

[मंत्रि-मंडल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा संख्या. प. 5 (6) व्य. एवं प./68, दिनांक 14-10-68]

---

(83)

राज्यपाल एतद्द्वारा जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों (विशेष कर नाहरी का नाका, बडौदिया, गंगा टाकीज की बस्तियां) में रहने वाले लोगों को भू-खण्ड आंवटित करने हेतु निम्नांकित सदस्यों की एक समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. श्री रामकिशोर व्यास, राजस्व मंत्री—अध्यक्ष।
2. श्री भैरों सिंह शेखावत, सदस्य विधान सभा सदस्य
3. श्री सरदार मल सिंघवी, अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जयपुर—सदस्य
4. जिलाधीश, जयपुर—सदस्य-सचिव।

[मंत्रि-मण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) आज्ञा संख्या प. 5 (44) व्य एवं. प./68, दिनांक 14-10-68]

---

(84)

राज्यपाल एतद्द्वारा नगर यातायात सेवा अर्थात् सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज (सी.टी.एस.) के कार्य-क्रम का पुनरावलोकन करने हेतु निम्नांकित सदस्यों की एक स्थाई समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. जिला दण्डनायक, जयपुर .. .. अध्यक्ष
2. संचालक, यातायात विभाग, राजस्थान, जयपुर .. .. सदस्य
3. अधीक्षक, आरक्षी विभाग, जयपुर .. .. .. ,,
4. प्रशासक, नगर पालिका मंडल, जयपुर .. .. ,,
5. बस चालकों का एक प्रतिनिधि .. .. .. ,,
6. क्षेत्रीय यातायात अधिकारी, जयपुर .. .. .. सदस्य-सचिव.

उपरोक्त स्थाई समिति सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के कार्यक्रम आदि का पुनरावलोकन कर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की कार्य-पद्धति में सुधार लाने हेतु सरकार को समय समय पर अपने सुझाव देगी। उपरोक्त समिति की बैठक प्रति माह बुलाई जा सकेगी तथा सम्बन्धित अधिकारी अपने स्तर पर बसों के चलाने में सुधार की दिशा में जो भी कार्यवाही अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगी, वे कर सकेंगे। जिन मामलों में सरकारी आदेशों की आवश्यकता होगी उनके लिये समिति अपने सुझाव संचालक, यातायात विभाग के मार्फत सरकार को प्रस्तुत करेगी।

[मंत्रि-मण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) आज्ञा संख्या प. 5 (45) व्य. एवं प।68, दिनांक 14-10-68]

---

(85)

राज्यपाल, एतद्द्वारा राजस्थान में औषधि पौधे तथा आयुर्वेदिक औषधियों के परीक्षण हेतु बगीचा लगाने व इस प्रयोजनार्थ राजस्थान में एक डिपो स्थापित करने के लिये निम्न सदस्यों की एक वैज्ञानिक परामर्श दात्री समिति" के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. सचिव, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, जयपुर .. .. अध्यक्ष
2. मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर .. .. .. सदस्य
3. परामर्शदाता भारत देशीय चिकित्सा पद्धति, नई दिल्ली .. ,,
4. मैनेजर, आयुर्वेदिक रसायन शालाएं, अजमेर .. .. ,,
5. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर .. .. सदस्य–सचिव

उपरोक्त समिति दो वर्ष के लिये होगी जिसकी एक बैठक हर तीन महिने बाद होगी जो प्रगति का सिंहावलोकन करेगी ।

[मंत्रि-मंडल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) आज्ञा सं. प. 5(46) व्य. एवं प.68, दिनांक 15-10-68]

=———

(86)

राज्यपाल एतद्द्वारा राज्य में सूखे की स्थिति की भीषणता का समय समय पर सिंहावलोकन कर उसका मुकाबला करने के लिये आवश्यक सुझाव देने हेतु राज्य के प्रमुख राजनैतिक एवं सामाजिक दलों के निम्नांकित प्रतिनिधियों की एक परामर्शदात्री समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. मुख्य मंत्री, राजस्थान .. .. अध्यक्ष
2. वित्त मंत्री, राजस्थान .. .. सदस्य
3. जन स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान .. .. ,,
4. सिंचाई मंत्री, राजस्थान .. .. ,,
5. अकाल सहायता मंत्री, राजस्थान .. .. .. ,,
6. सार्वजनिक निर्माण मंत्री, राज स्थान .. .. .. ,,
7. पशु पालन मंत्री, राजस्थान .. .. ,,
8. श्री माणिकलाल वर्मा .. .. ,,
9. महारावल श्री लक्ष्मण सिंह .. .. ,,
10. श्री भैरोंसिंह शेखावत .. .. ,,
11. श्री मास्टर आदित्येन्द्र .. .. ,,
12 श्री बद्री प्रसाद .. .. ,,
13. प्रतिनिधि, मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी, कलकत्ता .. .. ,,
14. मुख्य सचिव .. .. ,,
15. वित्त आयुक्त (व्यय) .. .. ,,
16. सहायता आयुक्त .. .. सदस्य सचिव

[मंत्रि-मडल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) आज्ञा संख्या प. 5(48) व्य. एवं प.168, दिनांक 16-10-68]

(87)

The Governor is pleased to appoint a Committee consisting of the following:—

1. Shri Dwarka Das Purohit — Chairman.
2. The Secretary, Local Self-Govt. Deptt. — Secretary.

The above Committee will work out a scheme of the Housing Board in the Rajasthan State to give impetus to the constructions of houses in the State and to work for mobilising resources from all financial organisations after a thorough study of the various Housing Boards in the country.

Shri Dwarka Das Purohit, the Chairman of the Committee will draw an allowance of Rs. 1,000/- and Rs. 250/- as House Rent.

The Committee shall submit its report to the Government within a period of three months.

[Cabinet Sectt. Order No. F. 5 (49) O & M/68, dt. 24-10-68.]

---

(88)

राज्यपाल, एतद्द्वारा राजस्थान में आयुर्वेद पद्धति में अनुसंधान एवं अन्वेषण योजना संचालित करने हेतु निम्नांकित सदस्यों की एक वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. सचिव, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर .. .. अध्यक्ष
2. श्री पी. एन. वी. कुरुप, एडवाईजर आई. एस. एम. स्वास्थ्य मन्त्रालय, एफ. पी. एण्ड यू. डी., नई दिल्ली .. .. .. सदस्य
3. डा. वी. एन. शर्मा, अध्यक्ष, फार्मेसोलोजी विभाग, सवाई मान सिंह मैडीकल कालेज, जयपुर .. .. "
4. श्री जयराम दास, रिटायर्ड प्रिंसिपल, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, जयपुर "
5. वैद्य एम. एल. द्विवेदी, लखनऊ सैन्ट्रल कौंसिल आफ आयुर्वेदिक रिसर्च, लखनऊ .. .. "
6. प्रिंसिपल, गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कालेज, जयपुर .. .. "
7. डाइरेक्टर, आयुर्वेदिक विभाग, अजमेर .. .. सदस्य-सचिव ।

प्रिंसिपल, गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कालेज, जयपुर इस योजना के लिये प्रोजेक्ट अधिकारी की हैसियत से भी कार्य करेंगे ।

उपरोक्त समिति दो वर्ष के लिये होगी ।

[मंत्रिमण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) आज्ञा सं. प. 5 (47) व्य. एवं प. 168, दिनांक 25-10-68]

(89)

राज्यपाल एतद्द्वारा राज्य के विभिन्न जल-प्रदाय कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने हेतु इस सचिवालय (व्य. एवं प.) की सम संख्यक आज्ञा दिनांक 13-3-1968 के द्वारा निर्मित समिति में सदस्य श्री आर. के. भार्गव, तकनीकी सहायक, मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य का स्थानान्तरण उदयपुर हो जाने के परिणाम स्वरूप रिक्त स्थान पर श्री बी. के. सुराणा, तकनीकी सहायक, मुख्य अभियन्ता को समिति का सदस्य मनोनीत किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

[मंत्रि-मण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) आज्ञा सं. प. 5 (6) व्य. एवं प. 68, दिनांक 25-10-68.]

---

(90)

राज्यपाल, एतद्द्वारा इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 26-3-68 द्वारा पुनर्गठित राष्ट्रीय बचत राजस्थान परामर्शदात्री मण्डल में श्री भागचन्द भण्डारी, एडवोकेट जालौर को सदस्य मनोनीत किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

[मंत्रि-मण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) आज्ञा सं. प. 5(8) व्य. एवं प./68, दिनांक 28-10-68.]

---

(91)

विषय :—सचिवालय में लेखन सामग्री का हिसाब।

सचिवालय के विभागों / अनुभागों / खण्डों आदि द्वारा लेखन सामग्री के हिसाब को विधिवत् रखने के संम्बन्ध में सचिवालय कार्यविधि के अनुच्छेद 333 से 337 तक स्पष्ट प्रावधान किया गया है तथा इस संबंध में व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग के परिपत्र संख्या एफ. 1 (7) व्य. एवं. प./60, दिनांक 17-6-60 तथा एफ. 1 (7) व्य. एवं प./60, दिनांक 22-9-60 के द्वारा भी आवश्यक निदेश जारी किए गए है। नियुक्ति (ख-2) विभाग के परिपत्र संख्या एफ. 13 (4) नि. ख./2/68, दिनांक 28-5-68 द्वारा भी लेखन सामग्री के हिसाब आदि के लिखने एवं निर्धारित रूप में अभियाचन भेजने के लिये अनुरोध किया जा चुका है।

उपरोक्त निदेशों के बावजूद भी बहुधा यह देखने में आया है कि संबंधित विभाग उनका पालन नहीं करते है। प्रायः विभागों द्वारा समय पर अभियाचन फार्म तो भेजे ही नहीं जाते साथ ही उन्हें निर्धारित प्रपत्र में भी नहीं भेजा जाता। उक्त निदेशों के पालन न होने से जहां अव्यवस्था होती है वहां स्टेशनरी का उचित उपयोग भी नहीं हो पाता।

अतः सभी संबंधित अधिकारियों से यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त निदेशों का कड़ाई से पालन करते हुए स्टेशनरी का विधिवत् लेखा रक्खें और भविष्य में समय पर निर्धारित रूप में अभियाचन भेजें।

[मंत्रि-मण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) परिपत्र सं.प. 11(30) व्य. एवं प./68, दिनांक 7-10-68.]

(92)

For the words "Heads of Departments" appearing in the first line of the last paragraph of this office order of even number dated 28th/29th May. 1968, kindly read "Appointing authorities".

[Cabinet Sec. (O.&M.) Corrigendum No. F.11 (2) O.&M.)/65 dated 28-10-68.]

---

(93)

विषय:—जिलाधीशों द्वारा किये गये निरीक्षण और दौरों के अर्धवार्षिक प्रतिवेदन

सन्दर्भ:—व्य. एवं प. अनुभाग क परिपत्र संख्या 15(24) व्य.एव पं.165, दिनांक 4 जनवरी, 1966 तथा 30-7-1968

सन्दर्भान्तर्गत परिपत्र दिनांक 4-1-1966 के परिच्छेद 21(1) में दिये गये निर्देशों के अनुसार जिलाधीशों द्वारा किये गय निरीक्षणों एवं दौरों के अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन, उक्त परिपत्र के परिशिष्ट 4 के रूप में व्यवस्था एव पद्धति अनभाग को निर्धारित समय पर नियमित रूप से भिजवाये जाने चाहिये किन्तु बहुत से जिलाधीशों द्वारा—

(1) ये प्रतिवेदन या तो भेजे ही नहीं जाते हैं और यदि भेजे जाते भी हैं तो बहुत विलम्ब से भेजे जाते हैं।

(2) इन अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदनों के स्थान पर त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजे जाते हैं।

(3) ये अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 4-1-66 के उक्त परिपत्र के परिशिष्ट 4 के रूप में नहीं भेजे जाते।

दिनांक 30-7-68 के परिपत्र संख्या 15(24) व्य.एवं प.165 द्वारा उपर्युक्त सभी बातों की ओर सभी सम्बन्धितों का ध्यान दिलाते हुए तथा भविष्य में अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन समय पर भिजवाने के लिये सचेष्ट रहने हेतु पुनः निर्देश देते हुए यह भी निवेदन किया गया था कि मार्च, 1968 तक समाप्त होने वाली जिन अर्द्धवार्षिक अवधियों के प्रतिवेदन अभी तक व्यवस्था एव पद्धति अनुभाग को नहीं भिजवाये गये हैं उन्हें अब एक माह की अवधि में भिजवाने की व्यवस्था की जावे। किन्तु खेद है कि बहुत से जिलाधीशों द्वारा इस ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया।

अतः समस्त जिलाधीश महोदयों से पुनः अनुरोध है कि—

(1) वे 31-3-68 तक समाप्त होने वाली समस्त अर्द्धवार्षिक अवधियों के अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 4-1-66 के परिपत्र से संलग्न परिशिष्ट 4 के प्रपत्र में ही भिजवावें और कृपया ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि ये समस्त अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन एक पखवाडे की अवधि में ही व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग में पहुंच जावें।

(2) भविष्य में त्रैमासिक प्रतिवेदन न भेजे जावें।

(3) भविष्य में अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित समय पर व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग में भिजवाने की निश्चित व्यवस्था करदें।

[मंत्रिमण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग परिपत्र प. 15(17) व्य.एवं प.166, दिनांक 28-10-68.]

EDUCATION DEPARTMENT

INDEX

(5)

The Governor has been pleased to order that following amendment be made to item 5 of Appendix VI of the Grant-in-aid Rules issued *vide* Notification No. F. 2 (24) Edu/Cell/VI/62 dated 19th January, 1963:—

"(4) Under Col. 5 against "Water and Light Charges" substitute Rs. 1000/- instead of Rs. 500/-."

(Education cell (vi) No. F 1 (26)Edu/cell vi/68 dt. 26-10-68)

FINANCE DEPARTMENT (Expenditure)

INDEX

FINANCE DEPARTMENT (Expenditure)

(165)

SUBJECT:—House Rent Allowance Rules.

The Governor has been pleased to order that the following amendment in the Rules for grant of House Rent Allowance (appearing in Appendix XVII of the Rajasthan Service Rules, Volume II), namely:—

The following shall be added as "Government of Rajasthan's Decision below Rule 9 of the said rules;—

"Government of Rajasthan Decision;—It has been decided that a Government servant who was occupying rented accommodation at his old station and who on transfer at his new headquarters does not get either rented accommodation or is not allotted Government accommodation immediately on or after taking over charge will be entitled to draw house rent allowance for a period of one month from the date he handed over charge at his old headquarters or till he gets a rented accommodation or is allotted Government accommodation at the new headquarters whichever period is less. The period of one month will run concurrently with the joining time. While claiming house rent allowance, the Government servant concerned shall record a certificate as under; —

"Certified that I .... designation .... posted in the ....Department at ....(name of the place) continued to occupy the rented accommodation from .... to ....after handing over charge of the post.............in the ....Department ....at .... (name of old headquarter city)."

This order takes effect from 1-4-66.

[F. D. (Rules) order No. F 1 (50) F D (Rules) 68 dated 5-10-68]

(166)

SUBJECT:—Minimum pension for Government employees.

In accordance with Finance Department Memorandum No. F. 1 (12) FD (Exp-Rules)/64 dated 15-4-1965 minimum pension is admissible at the rate of Rs. 30/- per month. A doubt has been raised whether provisions of the aforesaid order are also applicable to Extraordinary family pension granted under Rule 275 & 276 of the Extraordinary Pension Rules contained in Chapter XXIV of the Rajasthan Service Rules.

It is clarified that the provisions of the aforesaid order are not applicable to Extraordinary family pension granted under Rule 275-276 referred to above. It is applicable to injury pension granted to Government servant himself under Rule 274 of the aforesaid rules.

[F. D. (Rules) mems No. F 1 (12) F D Exp. (Rules) 64 dated 8-10-68]

(167)

SUBJECT;—Creation of supernumerary posts.

In accordance with the Finance Department Order No. F. 1 (101) FD (Exp-Rules)/66 dated 17-7-1967 retrospective promotion by creation of supernumerary posts or upgrading of posts may be given in cases covered by para 1 of the aforesaid order with the approval of Finance Department

A question ha been raised as to whether cases which occurred prior to the date of issue of the aforesaid order in which retrospective promotion was not allowed and/or only benefit of re-fixation of pay was allowed or rejected can be re-opened and decided in accordance with aforesaid order. The matter has been examined and it has been decided that since the decision to allow retrospective promotion was taken by the Government on 8-7-1966 (although order was issued on 17-7-1967) cases of all Government servants who retired/retire on or after 8-7-1967 may be re-opened and decided in accordance with aforesaid order if such request is specifically made by the Government servant concerned in writing.

[Finance (Rules), Deptt. memo No. F 1 (101) F D (Exp.) Rules 166 dated 10-10-68]

(168)

Sub:—Rajasthan Services (Medical Attendance) Rules, 1958.

The Governor has been pleased to order that the following amendments shall be made in the Rajasthan Services (Medical Attendance) Rules, 1958, namely :—

In the said rules. Para No. 7 of Annexure below Rule 8A shall be substituted by the following ;—

"The concessions laid down in above paragraphs shall also be admissible to the families of Government servant under the conditions under which they are admissible to Government servants themselves. Family for the purpose of this para includes wife or husband as the case may be and to parents, children & step children wholly dependent upon the Government servants.

Explanations—(*i*) The term "parents" does not include "Step-parents". and the term "wholly dependant" in case of a parent means that there is no other adult son and no other source of income of the parent. If parent is a pensioner, with pension of less than Rs. 50/- p. m. he shall be treated as wholly dependant.

(*ii*) The term "children" will include children adopted legally.

(*iii*) The term "wife" includes more than one wife."

[Finance Deptt. (Rules) order No. F 1 (67)FD Rules 67 dated 30-10-68]

(169)

Sub;—Withholding and withdrawl of pension under Rule 170 of Rajasthan Service Rules.

According to proviso (a) of Rule 170 of the Rajasthan Service Rules, departmental proceedings, if instituted while the officer was in service, whether before his retirement or during his re-employment, shall, after the final retirement of the officer, be deemed to be proceedings under the said rule and shall be continued and concluded by the authority by which it was commenced in the same manner as if the officer had continued in service. A question has been raised whether in respect of an officer, whose case falls within the purview of the aforesaid provsio and proceedings against whom were instituted by an authority subordinate to the Governor, order for withdrawal/withholding of pension can be passed by the subordinate authority on the conclusion of the proceedings. or the authority should refer the case to the Governor for final orders. The matter has been considered and the undersigned is directed to clarify that the function of the Disciplinary Authority in respect of departmental proceedings referred to in Rule 170 is only to reach a finding on the charges and to submit a report recording its findings to the Government. It is then for the Government to consider the findings and take a final decision under Rule 170 of Rajasthan Service Rules. In case Government decide to take action under Rule 170 of Rajasthan Service Rules in the light of the findings of the Disciplinary Authority, the Government will serve the person concerned with a show-cause notice specifying the action proposed to be taken under Rule 170 of Rajasthan Service Rules and the person concerned will be required to submit his reply to the show-cause notice within such time as may be specified by the Government. The Government will consider the reply and consult the Rajasthan Public Service Commission. If as a result of such consideration in consultation with the Commission. it is decided to pass an order under Rule 170 of Rajasthan Service Rules, necessary orders will be issued in the name of the Governor.

[F. D. Rules memo No. F 1 (54) F D (ER) 67. dated 30-10-68]

(170)

Sub;—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules 1961-Budget Officer.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India. the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules. 1961;—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1-4-1966.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules 1961. Schedule I-Section B-Secretariat (page 36)-the words "R. Ac

S." shall be deleted from the entries inserted for the post of "Budget Officer" vide para 3(B) (1) of Finance Department Notification No. F2 (b) (34) FD (E-R) /66 dated 23-11-1966. The following new entries shall be inserted:—

"(*ii*) When held by an officer of R. Ac. S. (Sr. Scale) who has completed 12 years of permanent service in the Rajasthan Accounts Service pay and special pay (if any) prescribed from time to time to a Deputy Secretary to Government appointed from Rajasthan Accounts Service, shall be admissible.

[*F.D.* Rules notification No. F.2 (b) (34) FD (ER) 66 dated 5-10-68]

(171)

Sub.—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961 Schedule II-Part 4-Senior R. A. S.—Director of Transport.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules 1961 namely—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

2. They shall be deemed to have come into force with effect from 3-2-1965 and upto 25-11-1965.

3. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules 1961—Schedule II-Part 4-R. A. S.-Posts in Sale No. 28 (now 29 with effect from 1-4-1966)-the following new entries shall be inserted.

Director of Transpost (temporarily encadred in Senior Scale).	Rs. 150/-	The Special Pay of Rs. 150/- shall be admissible upto 25-11-1965.

[Finance Deptt. (Rules) notification No. *F* 2 (b) (55) Rules 168 dated 8-10-68]

(172)

Sub.—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961 Schedule I-Section B,

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services Revised Pay) Rules, 1961-namely.—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules 1968.

2. They shall be deemed to have come into force with effect from 1-9-1961.

3. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule I-Section B-other State Service Officers in various Departments-Education Department (page 26) the following shall be inserted above the entries for "Counsellor Vocational Guidance Bureau".

		From 1-9-61 to 31-3-1966.	1-4-66	Remarks.
Medical Officer of Education Department at Jaipur	200-10-280-EB-15-400.	225-20-285-25-435-EB-25-560-30-800 (25)	(26)	The E. B. at the stage of 435 shall not be crossed unless the incumbent Passes the M. B B. S. Examination.

[F.D. (Rules) notification No. F.2 (b) (54) F.D. (Rules)/68, dt. 8-10-68]

---

(173)

Sub.—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Legislative Assembly-Research & Reference Officer.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely.—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.
2. They shall be deemed to have come into force with effect from 20-7-1968, or from the date the post is filled whichever is later.
3. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule I-Section B-other State Service Officers in various Department-Rajasthan Legislative Assembly-the following new entries shall be inserted:—

Research & Reference Officer.	New	360-25-560-30-590-EB-30-860-900.	(27)	In accordance with the provision of Rule 9 of the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment & Condition of Service) Rules. 1952 the qualification shall be similar to those sanctioned for post of Assistant Secretary to Government or Assistant Secretary in Rajasthan Legislative Assembly.

[F.D. (Rules) notification No. F. 2 (b) (59) F.D. (Rules)/68, dt. 17-10-68]

(174)

Subject.—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule II—Part 4—Police Department—Special Pay to Prosecuting Inspector when doing the work of Public Prosecutor Jhalawar.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely :—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 2-1-1967.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule II—Part 4—Police Department—the following new entries shall be made :—

Prosecuting Inspector appointed to work as Ex-Officio Public Prosecutor.	Rs. 50/-	The Special Pay shall be granted upto 3-3-1968 and drawn in addition to pay and special pay admissible to Prosecuting Inspector.

[F.D. (Rules) notification No. F. 2 (b) (61) F.D.(Rules)/68, dt. 17-10-68]

(175)

Subject.—Pre-checking of pay fixation Statement of Patwaries.

It has been brought to the notice of Government that the pending cases of fixation of pay of Patwaries of Land Records and other subordinate staff of Revenue Department in Unification of Pay Scale 1950, Rationalised Pay Scales, 1956, Revised Pay Scales, 1961 and Amended Revised Pay Scales, 1966 have not been finalised so far. Some of the Patwaries and other staff members have retired and many of them are on verge of retirement. The pension cases have not been finalised for want of fixation of pay in pay scales revised from time to time. In order to avoid hardship, Governor has been pleased to order to declare all Treasury Officers as "pre-checking authority" of the statements of fixation of pay of Patwaries of Land Records and other subordinate staff.

[F.D. (Rules) circular No. F. 2(b) (53) F.D.(Rules)/68, dt. 26-10-68]

(176)

It has been brought to the notice of Government that payment of salary of Government servants appointed on or after 1-9-1968 has not been made in terms of warning circular No. F. 2 (b) (45) F.D. (Rules)/68, dated 22-8-1968. Non-payment of salary for want of indication of pay scales has caused hardship to the Government servant. The matter has been examined and it has been decided that persons appointed on or after 1-9-68 may be allowed pay in the existing Revised Pay Scales introduced from 1-9-1961, Amended Revised Pay Scales introduced from 1-4-1966 as the case may be on provisional basis subject to revision with effect from 1-9-1968 on publication of the New Pay Scales. The special pay attached to the Revised Pay Scales/Amended Revised Pay Scales, will, however, not be allowed to the persons appointed on or after 1-9-1968.

[F.D (Rules) warning Circular No. F. 2 (b)(45) F.D.(Rules)/68, dt. 31-10-68]

(177)

SUBJECT:—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Scales, 1961— Schedule I—Section D—Education Department—Physical Instructor.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely:—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1-9-1961.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule I—Section D—Education Department—the figure "150-15-300" in column 2 against the post of "Physical Instructor (B.S.T.C.) and the following shall be inserted below the existing remarks for Physical Instructor appearing in Column 5 (page 58):—

"The pay scale of "150-15-300" will be applicable to only those Physical Instructors for whom Administrative Department shall certify that they were appointed as Physical Instructor in the scale of 150-15-300 on the recommendation of the Rajasthan Public Service Commission."

[F.D, (Rules) notification No. F. 2 (a) (1) F D. (ER)/65, dt. 30-10-68.]

---

(178)

SUBJECT:—Rajasthan Travelling Allowance Rules.

The Governor has been pleased to order that rule 23 of the Rajasthan Travelling Allowance Rules be substituted by the following:—

23—A Government servant authorised to travel by air on tour is entitled to mileage allowance equal to one standard air fare for the journey plus an allowance for incidental expenses equal to one fifth of standard air fare limited to the amount of one daily allowance admissible under rule 27 for the place from where the journey commences or for the place where the journey ends, whichever is higher, provided that if more than one air journeys (including the return journey) are performed within 24 hours, the total entitlement to incidental allowance for all the journeys shall be restricted to one daily allowance for the place from where the journey commences or for the place where the journey ends:

Provided that in the case of journey to Bombay or Calcutta or Kanpur, the amount of incidental charges shall be one fifth of the standard air fare.

Provided further that if at either end of the journey by air a Government servant has to perform a connected journey by rail or road or steamer, he may draw the mileage allowance admissible for such Journey but no mileage allowance may be drawn in respect of the surface transport which forms part of the air journey and included in the fare paid for the air journey.

NOTE:—Standard air fare means actual single journey air fare payable for the service by which the journey is performed.

[F.D.(Rules) order No F. 3 (9) F. D. (Rules)/68, dt. 18-10-68]

(179)

SUBJECT:—Rajasthan Travelling Allowance Rules.

The Governor has been pleased to direct that the following amendments shall be made in the Rajasthan Travelling Allowance Rules, namely—

In Part III of the said Rules, for the words and figures "Rs. 800/-" appearing in Government of Rajasthan's Decisions No. 5 and No. 6 below Rule 22 (inserted vide Finance Department Orders No. F. 3 (3) FD Rules)/68 dated 18th June. 1968 and dated 12-9-1968) the following words and figures shall be substituted for Rs. 800/-.

"Rs. 500/-".

[F. D. (Rules) order No. F. 3 (3) F.D. (Rules)/68, dt. 31-10-68].

(180)

In pursuance of Rule 21 of Rajasthan Service Rules, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendment in the General Provident Fund (Rajasthan Services) Rules, 1954, namely:—

AMENDMENT.

Add the following note after Government decision under Rule 6 of the said rules, viz,—

"NOTE:—The submission of application for admission and acceptance of the application will not be necessary for the subscribers governed under rule 4 (2)."

[F. D. (Rules) notification No. F. 4 (5) F.D. (Rules)/68, dt. 30-10-68]

(181)

As per decision of the Rajasthan Canal Board on item No. 17 of the Agenda for the 53rd meeting. the Governor has been pleased to order that S. No. 13 of Part III-Other Powers—of the Schedule of Powers delegated to the Chief Engineer, Superintending Engineers and the

Executive Engineers engaged in the execution of the Rajasthan Canal Project under this Department Order No. 1095/60/F. 6 (4) F.D./A/59, dated 4-3-1960 be substituted by the following:—

S. No.	Particulars	Chief Engineers	Supdtg. Engineers	Executive Engineers	Remarks
1	2	3	4	5	6
13A	To grant leave to officers & staff.	*Full powers for officers of and below the rank of Assistant Engineers.	*Full power in respect of staff which he is competent to appoint.	*Full power in respect of Clerks, Tracers & Draftsman.	*This power will not extend to study leave and special disability leave or refused leave to be enjoyed after retirement.
	(B) To grant leave (excluding study and disability leave) to Gazetted Officers upto two months and where no substitute is required.	All Gazetted Officers posted at the Head Quarters of the Chief Engineer (excluding Supdtg. Engineers)	All Gazetted Officers Subordinate to him.	All Gazetted Officers subordinate to him.	In case a substitute is needed, the leave shall be granted by the appointing authority or such other lower authority to whom power of transferring such officers has been delegated.

[F.D. (Exp. III) Deptt. order No. F. 1(1) F.D.(Exp.-III)/66, dt. 4-10-68]

(182)

SUBJECT:—Appointment of Controlling Authority.

In supersession of existing orders on the subject, the Relief Commissioner-cum-Secretary to Government, Rajasthan. Jaipur is hereby declared as Controlling Authority in respect of the following head:—

'71-Miscellaneous
h-Grants-in-aid, Contributions etc.
(6) Grants-in-aid to Panchayat Samitis.
(i) Grants for other purposes
(1) Flood, Fire etc. Sufferers.

[F.D. (Budget) order No. F. 4 (271) F. (B)/67, dt. 29-10-68]

(183)

SUBJECT;—Appointment of Controlling Authority.

The Director of Small Savings and State Lotteries is hereby declared as Controlling Authority in respect of the following heads:—

XXI—Miscellaneous Departments—
(e) Miscellaneous—
10-Receipts of State Lotteries.

26—Miscellaneous Departments—
(c) Directorate of Small Savings and State Lotteries—

1. Small Savings.

2. State Lotteries.

[F.D. (Budget) order No. F. 4(18)F(B)/68. dt 10-10-68]

FINANCE (REVENUE) DEPARTMENT
वित्त (राजस्व) विभाग

INDEX
सूची

(51)

SUBJECT:—Amendment in the General Financial & Account Rules, Vol. I.

The Governor has been pleased to order that the following be added as a Government of Rajasthan Decision below Rule 307 of the General Financial & Account Rules, Vol. I, viz.—

GOVERNMENT OF RAJASTHAN DECISION

The mode of submission of utilisation certificate has been under consideration of the Government for some time past. After due consideration, the Governor has been pleased to order that.—

(1) (*a*) No utilisation certificate in respect of recurring grants-in-aid released to the Panchayat Samitis till the end of March, 1969 shall be furnished. For the recurring grants released on or after 1st April, 1969, the Vikas Adhikari shall furnish, yearly utilisation certificate, latest by the 30th of June of the following year, to the sanctioning authority, in the form and manner prescribed by such authority, in order to satisfy him that the grant released in the previous year has been fully utilised for the purpose for which it was sanctioned. The Vikas Adhikaris who are required to maintain scheme-cum-purpose wise ledgers of the funds received and expenditure incurred, shall submit quarterly statements of accounts on the basis of these ledgers to the Development Department, which will also be test-checked by the Examiner, Local Fund & Audit Department, at the time of audit. Grants shall be released on receipt of the required utilisation certificate and the statement of accounts from the Vikas Adhikaris.

(b) For all types of non-recurring and specific grants-in-aid or loans, utilisation certificates shall be submitted by the Vikas Adhikaris to the Development Department. The utilisation certificates for such grants shall be countersigned by the Development Commissioner/Additional Development Commissioner and furnished to the Examiner, Local Fund & Audit Department, who shall send them to the Accountant General with his remarks, if any. The utilisation certificates may be furnished and accepted to the extent of the amount actually utilised, for the purpose for which it was sanctioned even in cases of incomplete works. A consolidated utilisation certificates for each head of account or scheme can be furnished for grants or loans released in the previous years.

(2) In respect of grants (recurring or non-recurring) given to the Rajasthan Sangeet Natak Academy, Rajasthan Lalit Kala Academy, Rajasthan Sahitya Academy, Rajasthan Sports Council, Rajasthan Flying Club and the like, whose accounts are audited and certified to be correct by a Chartered Accountant or a recognised body of auditors, the utilisation certificates furnished by such institutions shall be admitted for purposes of audit without countersignatures of the sanctioning authority.

(3) In respect of the grants released in accordance with grant-in-aid rules approved by the Government, where the method of release of grant-in-aid provides for inspection of previous years' audited accounts, the utilisation certificates, furnished by such institutions may be accepted for audit purposes, without countersignatures of the sanctioning authority;

(4) In respect of recurring grants released to the Universities and Malviya Regional Engineering College, the utilisation certificate furnished by these institutions need not be countersigned by the sanctioning authority, whereas in case of non-recurring grants and loans released for the specific purpose, the sanctioning authority should satisfy itself that the amount has been utilised for the purpose for which it was sanctioned, and therefore, the utilisation certificate furnished by these institutions for such grants, should be countersigned by the sanctioning authority.

[F.D. (A &I) order No. F24(40) FD/A &I/G FAR/62 dt. 8-10-68]

(52)

SUBJECT.—Amendment in the Treasury Rules of Rajasthan Government-Insertion of Rules 23-A—regarding bill for payment of Government's Investment in Companies, etc.

In exercise of the powers conferred by clause 2 of Article 283 of the Constitution, the Governor, hereby makes the following amendment in the Treasury Rules of Rajasthan Government viz.—

Add the following as a new rule 23-A below in existing Rule 23 of the said Rules;—

23-A.—Unless the Government specially direct otherwise in any case, a Treasury Officer, shall not make payment on account

of Government's investment in a Company, Corporation or similar autonomous organisation except on the authority of Accountant General.

[F.D. (A&I) order No. F. 7(10)FD/A & I/G FAR/67 dt. 16-10-68]

---

(53)

Subject:—Amendment in the General Financial and Account Rules-Insertion of Rule 99-A regarding bill for payment of Government's Investment in Companies, etc.

The Governor has been pleased to order that the following be added as a new rule No. 99-A below the existing rule 99 of the General Financial and Account Rules, viz;—

Rule 99-A.—"Unless the Government specially direct otherwise in any case, money may not be withdrawn from the Consolidated Fund of the State on account of the Government's Investment in a Company, Corporation or similar autonomous organisation except on the authority of the Accountant General".

[F.D. (A &I) order No. F7(10)FD/A &I/G FAR/67, dt. 16-10-68.]

सामान्य प्रशासन विभाग

सूची

(सामान्य प्रशासन विभाग)

(42)

यह सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित विभागों के नाम इस अधिसूचना के प्रचलित होने की तिथि से उनके समक्ष लिखे गये नामों से संबंधित किये जाएंगे:—

(1) अकाल सहायता विभाग	सहायता विभाग
(2) सहायता एवम् पुनर्वास विभाग	पुनर्वास विभाग

[सामान्य प्रशासन (क) विभाग अधिसूचना संख्या 1(1) सा.प्र.क।68, दि. 3-10-68]

HOME DEPARTMENT

गृह विभाग

(सूची)

(24)

राज्यपाल के आदेश से श्री हसन मुस्तफा (मालपुरा जिला टोंक) व श्री मंजूर आलम एडवोकेट (टोंक) स्टेट हज कमेटी के सदस्य मनोनीत किये जाते हैं।

[गृह क विभाग आज्ञा सं. एफ. 22(4)गृह (क–2)/64, दिनांक 3–10–68]

---

(25)

विषय :—स्टेट गैरेज की गाड़ियों की दुर्घटनायें।

राज्य सरकार ने सन् 1949 में इस आशय का आदेश प्रसारित किया था कि सरकारी मोटर गाड़ी केवल उन ड्राइवरों द्वारा चलाई जावेगी जो कि इस काम के लिए राज्य द्वारा नियुक्त हैं। इन आदेशों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार द्वारा नियुक्त ड्राइवर के अतिरिक्त दूसरे लोगों द्वारा इस प्रकार की मोटर गाड़ी चलाना अनियमित है। सन् 1954 में इन आदेशों में कुछ अपवाद भी जारी किए गये थे।

2. देखने में आया है कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा सरकारी मोटर गाड़ियों को चलाने का अमल जारी है बल्कि बढ़ रहा है जिससे दुर्घटनायें होती हैं और राज्य की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है।

3. अतः इस विषय में जारी किए हुए समस्त पूर्व आदेशों को अन्तरभूत करते हुए यह आदेश प्रसारित किये जाते हैं कि भविष्य में सरकारी मोटर गाड़ी केवल सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत ड्राइवरों द्वारा ही चलाई जावेगी और किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उनका चलाया जाना अनियमित होगा। इन आदेशों की अवहेलना को अनुचित व्यवहार (मिस कन्डक्ट) समझा जाकर अपराधी के विरुद्ध सम्बन्धित नियमों के अनुसार अनुशासी कार्यवाही की जावेगी। विभाग और कार्यालय के अध्यक्षों की यह जिम्मेदारी होगी कि सरकारी मोटरों को अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा न चलाया जावे और ऐसा होने पर राज्यादेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

[गृह (ख–1) विभाग आज्ञा सं. प. 3 (19) गृह (ख–1)।68, दिनांक 11–10–68].

(V)

विधि विभाग

क.सं.	विषय	क्रमांक दिनांक	पृष्ठ सं
5.	निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपियां अपील। रिवीजन हेतु पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एवं पुलिस प्रोसीक्यूटर्स को नियमानुसार प्राप्त करने हेतु।	एफ.14(271)विधि क।68 दि. 28-9-68	5

(5)

विषय :—निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपियों, अपील/रिवीजन हेतु, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एवं पुलिस प्रोसीक्यूटर्स को नियमानुसार प्राप्त करने हेतु।

बहुधा यह देखने में आता है कि जिलाधीश महोदय, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एवं पुलिस प्रोसीक्यूशन के अधिकारीगण द्वारा प्राप्त की गई निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपियों के स्थान पर धारा 373 जाब्ता फौजदारी एवं क्रिमिनल रूल्स में उनको जो निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त होती है वह ही इस विभाग में भेज देते हैं। ऐसी निर्णय की प्रतिलिपियों द्वारा अपील या रिवीजन पेश नहीं की जा सकती है। अतः यह निर्देश दिया जाता है कि समस्त जिलाधीश अपने अधीन समस्त सम्बन्धित विभागों को कृपया निर्देश देवें कि वो नियमानुसार प्राप्त की गई प्रमाणित प्रतिलिपि ही भिजवायें ताकि पत्र व्यवहार में समय व शक्ति का दुरुपयोग न होवे।

[विधि विभाग सं.प.14(271) वैधिक/68, दिनांक 28-9-68]

MEDICAL & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

Index

(1)

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend the Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Special Selection Rules, 1968, namely:—

1. *Short title.*—These rules may be called the Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Special Selection (Amendment) Rules, 1968.

2. In the Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Special Selection Rules, 1968, at the end of Rule 6, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the Board may consider the applications received even after the aforesaid period of one month in the case of candidates who may have gone abroad for training or further studies.'

[Medical & Pub. Health Deptt. notification No. F. 17(37)MPH/67, Gr. I, dt. 30-10-68.]

—————

LIST OF DEPARTMENTS

List of Departments in respect of which important circulars, orders, etc. have been included in the monthly compilation for the month of September, 1968.

विभागों की सूची

(विभागों की सूची जिनके महत्वपूर्ण परिपत्रादि माह सितम्बर, 1968 के संकलन में मुद्रित किये गये हैं)

APPOINTMENTS DEPARTMENT
(नियुक्ति विभाग)

INDEX
सूची

APPOINTMENTS DEPARTMENT

(23)

SUBJECT:—Prosecution and departmental enquiries.

In cases of complaint against Government servants in which both criminal action and departmental action are possible the Government had *vide* this Department Circular No. F. 23 (36) AA/57. Gr. III, dated the 6th February, 1968 left on the discretion of the authority who is competent to dismiss the Government servant, to have recourse to either of the two actions. This matter has been reconsidered by the Government and following revised instructions are issued.

The Law does not admit of any curb on the powers of the Police to initiate investigation on receipt of an information of the commission of a cognizable offence. If the Police investigation has been set in motion in a particular case, it should be allowed to have its own course and should not be delayed for the completion of some departmental action. At the same time departmental enquiry, if warranted by the merits of the case in addition to the Police action, should go on simultaneously.

It is clarified that there should be no hurdle in adopting this course. The original documents are necessary to be kept in the custody of the Police or to be produced in a Court of Law. Therefore, these may remain with the Police. For the purpose of a departmental enquiry it should be sufficient to retain certified copies of such documents on the departmental enquiry file. It should, however, be ensured that in cases of departmental enquiry on charges substantially similar to the criminal charge the final decision should be deferred till the decision of a Criminal Court.

[नियुक्ति (क-3) विभाग परिपत्र सं. प. 5 (17) नियुक्ति (क-3)/68, दिनांक 21-9-68]

(24)

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India read with rule 11 of the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958, the Governor of Rajasthan makes the following amendments to Schedule (B) appended to these rules, viz.,—

AMENDMENT

In schedule (B) to the said rules, the figures 14 (3) appearing in note 2 below item No. 38 shall be substituted by figures 12 (3).

[नियुक्ति (क-3) विभाग अधिसूचना सं. प. 3 (11) नि. (क-3)/68, दिनांक 21-9-68]

(25)

In the Schedule appended to this Department Notification of even number dated the 11th April, 1967 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary, dated the 20th April, 1967, in column No. 3 against S. No. 14. "The Rajasthan Educational Service (C. B.) Rules, 1959", for the figure "10" read figure "12".

[नियुक्ति (क-2) विभाग शुद्धि-पत्र सं. प. 1 (10) नि. (क-2) 66, दिनांक 25-9-68]

CABINET SECRETARIAT (including O. & M.)
मंत्रिमण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग)

सूची (Index)

CABINET SECRETARIAT (including O. & M.)

CABINET SECRETARIAT (including O. & M.)

(63)

राज्यपाल, सचिवालय के वित्त (व्यय) विभाग में अस्थाई रूप से एक नया प्रकोष्ठ "वित्त (व्यय) वेतनमान संशोधन के नाम से निम्नांकित कर्मचारियों द्वारा कार्य निष्पादन हेतु सृजन करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. सहायक लेखाधिकारी .. .. एक
2. कनिष्ठ लिपिक .. .. एक
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी .. .. एक

यह प्रकोष्ठ उप सचिव वित्त (व्यय-नियम) के आधीन कार्य करेगा। पदों का सृजन नियुक्त विभाग से वित्त (व्यय) की सहमति से होगा।

[मंत्रीमण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा प. सं. 2(10) व्य. एवं प. /68, दिनांक 3-9-68]

---

(64)

राज्यपाल एतद्द्वारा मरु भूमि विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित गौचर भूमि विकास एवं पेय जल वितरण योजनाओं के अन्तर्गत चराई शुल्क तथा जल-कर निर्धारण हेतु निम्नांकित सदस्यों की दो समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

चराई शुल्क समिति

1. श्री पूनम चन्द विश्नोई .. .. .. अध्यक्ष
2. राज्य भू-संरक्षण अधिकारी .. .. .. सदस्य
3. जिलाधीश, जैसलमेर .. .. ,,
4. जिलाधीश, बाड़मेर .. .. ,,
5. खण्डीय वन अधिकारी, जोधपुर .. .. .. ,,
6. प्रमुख, जिला परिषद्, जैसलमेर .. .. .. ,,
7. उप प्रमुख, जिला परिषद्, जोधपुर .. .. .. ,,
8. जिला पशुपालन अधिकारी, जैसलमेर .. .. ,,
9. जिला पशुपालन अधिकारी, जोधपुर .. .. सदस्य-सचिव।

पेय जल-कर समिति

1. श्री पूनम चन्द विश्नोई .. .. अध्यक्ष
2. प्रमुख, जिला परिषद्, बाड़मेर .. .. .. सदस्य
3. श्री रणजीत सिंह, एम. एल. ए., ओसियां .. .. ,,
4. राज्य भू-संरक्षण अधिकारी .. .. .. ,,
5. जिलाधीश, जोधपुर .. .. ,,
6. अधिशासी अभियन्ता (श्री ए. के. भार्गव), जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकि विभाग, जोधपुर .. .. .. सदस्य-सचिव
7. अधिशासी अभियन्ता (ग्राउन्ड), राजस्थान भूमिगत जल मण्डल, जोधपुर .. .. सदस्य

उपरोक्त दोनों समितियां अपने प्रतिवेदन सरकार के समक्ष तीन माह की अवधि में में प्रस्तुत करेंगी।

[मंत्री मण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा प. सं. 5(38) व्य. एवं. प. 168, दिनांक 5-9-68]

---

(65)

राज्यपाल, एतद्द्वारा राजस्थान नहर क्षेत्र में प्रस्तावित एवं स्वीकृत सड़कों के निर्माण आदि के सम्बन्ध में प्राथमिकता सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित सदस्यों की एक समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. श्री अमीनुद्दीन, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण .. अध्यक्ष
2. श्री भीखा भाई, मंत्री, ग्रामीण जल प्रदाय योजना .. सदस्य
3. श्री राम प्रसाद लढ्ढा, उपनिवेशन मंत्री .. .. सदस्य
4. श्री मुख्य सचिव .. .. सदस्य-सचिव

उपरोक्त समिति की कार्यावधि तीन वर्ष होगी।

[मंत्री-मण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा प. सं. 5 (37) व्य. सं. प. 168, दिनांक 5-9-68]

---

(66)

राज्यपाल इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 29 जुलाई, 68 के द्वारा राजस्थान कृषि उद्योग नियम (एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन) की स्थापना के सम्बन्ध में निर्मित समिति

के अध्यक्ष श्री चन्दन मल वैद को राज्य मंत्रीमण्डल के मंत्रियों को नियमानुसार उपलब्ध सुविधाएं प्रदान किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

[मंत्रीमण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा प. स. 5 (29)व्य. एवं. प.। 68, दिनांक 5-9-68]

---

(67)

In partial modification of this department order of even number dated 16th December, 1967 regarding reconstitution of the State Planning Advisory Council, the Governor has been pleased to appoint Shri Alok Prakash Jain, Senior Vice President, Rajasthan Chamber of Commerce instead of Shri Ganga Sahai Purohit, Managing Director, Rajasthan Financial Corporation, Jaipur.

[मंत्रीमण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति आज्ञा सं. प. 5 (91) व्य. एवं प./ 67, दिनांक 19-9-68]

---

(68)

विषय:——काश्तकारों से राजस्व एवं सिंचाई विभागों से संबंधित वसूली एक ही परवा द्वारा किये जाने के प्रश्न पर विचार हेतु समिति ।

कृपया इस सचिवालय (व्य. एवं प.) की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 31-8-68 द्वारा निर्मित उपरोक्त समिति के क्रम सं. 3 पर वित्त आयुक्त (नियम) के स्थान पर कृपया वित्त आयुक्त (राजस्व) पढ़ें ।

[मंत्रीमण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग शुद्धि-पत्र संख्या 5(34) व्य. एवं प. 68, दिनांक 12-9-68]

---

(69)

राज्यपाल, एतद्द्वारा राजस्थान में मकानों पर स्थाई संख्या अंकित करने के संबंध में विस्तृत योजना तैयार करने हेतु निम्नांकित सदस्यों की राज्य स्तरीय समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं :——

1. श्री सी. एस. गुप्ता, खाद्य आयुक्त, राजस्थान .. अध्यक्ष
2. अतिरिक्त विकास आयुक्त .. .. .. सदस्य
3. सचिव, राजस्व विभाग .. .. .. „
4. मख्य निर्वाचन अधिकारी .. .. .. „
5. भू प्रवन्धक आयुक्त .. .. „
6. निदेशक, स्थानीय निकाय .. .. .. „
7. उप सचिव, सामान्य प्रशासन .. .. .. „

8. सुपरिन्टेन्डेन्ट, नेशनल सैम्पिल सर्वे, भारत सरकार .. सदस्य
9. श्री यू. पी. माथुर, डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जनगणना .. सदस्य-सचिव।

उपरोक्त समिति अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को 6 माह की अवधि में प्रस्तुत करेगी तथा समिति अपने प्रतिवेदन में इस कार्य के लिये प्रशासकीय व आर्थिक प्रबन्ध किये जाने के बावत विस्तृत रूप से अपने सुझाव भी प्रस्तुत करेगी।

[मंत्रीमण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा सं. प. 5(42) व्य. एवं प.168, दिनांक 19-9-68।]

---

(70)

राज्यपाल, एतद्द्वारा निम्नांकित सदस्यों की राज्य स्तरीय अल्प बचत प्रचार सलाहकार समिति के पुनर्गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. राज्य वित्त मंत्री .. .. अध्यक्ष
2. श्री रामकृष्ण कल्ला, एडवोकेट, नागौर .. .. .. सदस्य
3. प्रतिनिधि, राजस्थान व्यापार उद्योग मण्डल .. .. "
4. जिला प्रमुख, बूंदी .. .. "
5. जिला प्रमुख, गंगानगर .. .. "
6. स्टेशन डाइरेक्टर, आकाशवाणी, जयपुर .. .. .. "
7. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, जयपुर .. .. .. "
8. रीजनल डाइरेक्टर, फील्ड पब्लिसिटी, भारत सरकार, जयपुर .. "
9. निदेशक, अल्प बचत एवं स्टेट लौटरीज एवं उप सचिव, वित्त .. "
10. प्रादेशिक निदेशक, राष्ट्रीय बचत (भारत सरकार), जयपुर .. "
11. सहायक निदेशक (प्रचार), अल्प बचत एवं स्टेट लौटरीज .. सदस्य-सचिव।

नवगठित प्रचार सलाहकार समिति का कार्यक्षेत्र मुख्यतः इस प्रकार होगा :—

(1) अल्प बचत योजना में प्रचार हेतु कार्यक्रम व रूपरेखा निर्धारित करना।

(2) प्रचार कार्य को संगठित करने एवं उसमें समन्वय हेतु प्रचार दलों को सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

(3) प्रचार संबंधी मामलों में राज्य सरकार को परामर्श व सुझाव देना और ग्रामीण क्षेत्रों में जन सम्पर्क द्वारा प्रचार कार्य में सक्रिय योग देना।

उपरोक्त समिति का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

[मंत्रीमण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा सं. प. 5 (41) व्य. एवं प.168, दिनांक 19-9-68।]

(71)

The Governor is pleased to appoint an Expert Committee consisting of the following members:—

1. Shri K. N. Bhargava, Retired Chief Engineer, Public Health, Vivekanand Marg, Jaipur. — Chairman.
2. The Chief Engineer, Irrigation, Rajasthan, Jaipur — Member.
3. The Director of Medical & Health, Rajasthan, Jaipur. — ,,
4. The Dy. Director, Fisheries. — ,,
5. The Chief Engineer, Public Health, Rajasthan, Jaipur. — ,,
6. The Dy. Chief Engineer, Public Health, Rajasthan, Jaipur. — Member-Secretary.

The above expert Committee will examine the matter of the alleged pollution of the water supply in Jaipur, and suggest ways and means to improve the performance of the Water Works and removal of Pollution in such supply.

The above expert committee shall submit its report to the Government within 15 days.

[मंत्रीमण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा सं. प. 5 (43) व्य. एवं प./68, दिनांक 20-9-68।]

(72)

विषयः—सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के गठन एवं उनके कार्य में सुधार हेतु सुझाव देने के लिये समिति।

राज्यपाल, इस सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति) के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-1-68 के द्वारा निर्मित उक्त समिति में आंशिक परिवर्तन करते हुए श्री जसराज, उप मंत्री, सिंचाई को उपरोक्त समिति के अध्यक्ष पद पर यथावत् कार्य करते रहने की स्वीकृति प्रदान करते है।

[मंत्रीमण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा सं. प. 5 (1) व्य. एवं प./68, दिनांक 19-9-68।]

(73)

राज्यपाल, निम्नांकित सदस्यों की एक समिति के गठन की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है :—

1. श्री रामकिशोर व्यास .. .. अध्यक्ष
2. श्री नारायण सिंह मसूदा .. .. सदस्य
3. श्री पुनम चन्द विश्नोई .. .. ,,

4. श्री मनफूल सिंह .. .. सदस्य
5. श्री शंकर लाल, एम. एल ए. .. .. .. ,,
6. सचिव, कृषि उत्पादन .. .. ,,
7. मुख्य संरक्षक, वन विभाग .. .. ,,
8. सचिव, राजस्व विभाग .. .. सदस्य-सचिव।

उपरोक्त समिति राजस्थान में पशुपालकों की समस्याओं के निराकरण हेतु उपयुक्त सुझाव एक माह की अवधि में प्रस्तुत करेगी।

[मंत्रीमण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) आज्ञा सं. प. 5 (39) व्य. एवं प.168, दिनांक 19-9-68]

(74)

राज्यपाल, एतद्द्वारा निम्नांकित सदस्यों की एक समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर .. .. अध्यक्ष
2. वित्त आयुक्त (व्यय), राजस्थान, जयपुर .. .. सदस्य
3. सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर .. .. ,,
4. मुख्य अभियन्ता, पी. डब्ल्यू. डी., बी. एण्ड आर., राजस्थान, जयपुर ,,
5. श्रम आयुक्त एवं पदेन उपसचिव .. .. .. सदस्य-सचिव।

उपरोक्त समिति राज्य कर्मचारियों के लिये ज्वाइन्ट कन्सलटेटिव मशीनरी एण्ड कम्पलसरी आर्बीट्रेशन योजना लागू करने के प्रश्न पर विचार कर अपने सुझाव राज्य सरकार के समक्ष तीन माह में प्रस्तुत करेगी।

[मंत्रीमण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) आज्ञा सं. प. 5 (40) व्य. एवं प.168, दिनांक 19-9-68]

(75)

राज्यपाल, इस सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति) की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 3 जून, 1968 के द्वारा निर्मित औद्योगिक परामर्शदात्री परिषद् में निम्नांकित व्यक्तियों को परिषद् का सदस्य मनोनीत किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. श्री आलोक प्रकाश जैन, सीनियर वाइस प्रेसीडेन्ट, राजस्थान चैम्बर आफ कामर्स, जयपुर।
2. श्री के. एल. जैन, ओनरेरी जोइन्ट सेक्रेटरी, राजस्थान चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज, जयपुर।
3. श्री जगमोहन लाल तांवी, जनरल सैक्रेट्री, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज फेडरेशन, जयपुर।

[मंत्रीमण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) आज्ञा सं. प. 5 (23) व्य. एवं प.168, दिनांक 19-9-68]

(76)

इस अनुभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 3-9-1968 में "वित्त (व्यय-वेतन) मान संशोधन" के वजाय "वित्त (व्यय-वेतन मान संशोधन)" पढ़ा जावे।

[मंत्रीमण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) शुद्धि-पत्र सं. प. 2(10) व्य. एवं प.168, दिनांक 25-9-68]

---

(77)

राज्य सरकार द्वारा, मंडी क्षेत्रों के विकास के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि मण्डी क्षेत्रों को मण्डी कमेटी चालू रखने के वजाय नगर विकास न्यास के अधीन दे दिये जावें। जहां नगर विकास न्यास स्थापित नहीं हैं वहां नये स्थापित कर दिये जावें। इन क्षेत्रों में जमीन की कीमत ऊंची हो गई है क्योंकि सरकार द्वारा वहां अनेक विकास योजनाओं में धनराशि व्यय की गई है। अतः इन क्षेत्रों के विकास हेतु नगर विकास न्यास भू-खण्डों आदि की बिक्री की आय से निम्नांकित चार प्रकार के विकास कार्य तो विना राज्य सरकार की अनुमति के साधारण नियमों के अन्तर्गत ही कर सकेगा :—

(क) ड्रेनेज।
(ख) पानी का वितरण।
(ग) बिजली का वितरण।
(घ) सड़कों का निर्माण।

किन्तु उक्त आय को किसी अन्य मद में विना सरकार की पूर्व अनुमति के खर्च नहीं कर सकेंगे। उपरोक्त विकास कार्यों हेतु खर्च करने के उपरान्त अतिरिक्त (सरप्लस) धनराशि को किस प्रकार खर्च किया जावे। इस पर विचार करना है।

अस्तु राज्यपाल एतद्द्वारा तत्विषयक मामलों पर विचार विमर्श करके अपने प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करने हेतु निम्नांकित सदस्यों की एक समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(1) श्री रामप्रसाद लड्ढा, सिंचाई मंत्री .. .. .. अध्यक्ष
(2) मुख्य सचिव .. .. सदस्य
(3) वित्त आयुक्त (व्यय) .. .. ,,
(4) शासन सचिव, उपनिवेशन विभाग .. .. .. सदस्य-सचिव।

उपरोक्त समिति अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार के समक्ष दो माह की अवधि में प्रस्तुत करेगी।

[मंत्री मण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा सं. प. 5 (32) व्य एवं प.168, दिनांक 26-9-68]

FINANCE DEPARTMENT (Expenditure)

INDEX

FINANCE DEPARTMENT (Expenditure)

1	2	3	4
155	R. C. S. (Revised Pay) Rules, 1961—Amendment thereto Education Department—Scale No. 13.	F. 2 (b) (12) FD/ER/ 65-II, dt. 6-9-68.	145-146
156	Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Education Department—Headmasters of Blind School—Prescription of Pay Scales—Scale No. 22, 23 and 24.	F. 2 (b) (12) FD/ER/ 65-V, dt. 6-9-68.	146
157	Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—R. H. J. S.—Amendment thereto.	F. 2 (b) (12) Finance Rules/68, dt. 7-9-68.	147
158	Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule III—Scale No. 21—	F. 2 (b) (12) FD/ER/ 65-IV, dt. 6-9-68.	147-149
159	Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961-Schedule III—Scale No. 8-E. B. for Sanskrit Teachers.	F. 2 (b) (12) FD (ER/ 65, dt. 9-9-68.	150
160	Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961-Schedule II— Part IV— Ground Water Board—Special Pay to' Water Drivers working as Compressor Operator.	F.2(b)(50)FD(Rules)/ /68, dt. 21-9-68.	150-151
161	Rajasthan Travelling Allowance Rules, (Clarification of Rule 57).	F. 3 (11) FD (Rules)/68, dt. 5-9-68.	151
162	Amendment in Rule 22 of Rajasthan Travelling Allowance Rules.	F. 3(3)FD (Exp-R) 68, dt. 12-9-68.	151
163	Submission of Applications for admission to Provident Funds.	F. 4 (7) FD (Exp-R) 65-I, dt. 21-9-68.	152
164	Measure to reduce missing credits in General Provident Fund Accounts.	F. 4(7) FD(Exp-R)/ 65-II, dt. 21-9-68.	152

(145)

विषय·—पेन्शन के मामलों का शीघ्रता से निपटारा।

राज्य सरकार ने पेन्शन के मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु समय समय पर आदेश/परिपत्र प्रसारित कर विभागाध्यक्षों व प्रशासनिक विभागीय अधिकारियों से यह अपेक्षा की है कि वे इस ओर विशेष ध्यान देंगे तथा मामलों को निपटाने में विलम्ब न होने देंगे, परन्तु यह अत्यन्त खेद का विषय है कि इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में यह फिर से लाया गया है कि अभी तक भी कई विभागों द्वारा पेन्शन के पत्र अपूर्ण भिजवाये जा रहे हैं अथवा पेन्शन संबंधी पूरक सूचना जो महालेखाकार ने मांगी है उसे भेजने में बहुत विलम्ब किया जाता है। इस प्रकार की देरी के कारण सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेन्शन का भुगतान उचित समय पर आरम्भ नहीं हो पाता है।

पेन्शन के मामलों को शीघ्रता से निपटाने में प्रशासनिक/विभागीय अधिकारियों की उपेक्षा को सरकार गंभीर मामला मानती है तथा इनके निपटाने में गति लाने हेतु निर्देश देती है कि जो मामले अभी तक महालेखाकार को नहीं भिजवाये गये हैं तथा जो अपूर्ण रूप से भिजवाये गये थे उन सब को पूर्ण रूप से तैयार कर महालेखाकार, राजस्थान को 31-10-68 तक अवश्य प्रेषित कर दिये जावें। उक्त तारीख के पश्चात् प्रेषित किये जाने वाले पेन्शन संबंधी मामलों पर विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक विभाग ध्यान रखेंगे तथा संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे।

[वित्त विभाग (नियम) परिपत्र सं. प. 1 (42) वित्त (व्यय-नियम) 67-III, दिनांक 8-9-68]

---

(146)

SUBJECT:—Procedure regarding appointment—Delegation of Powers to the Secretaries of Administrative Departments to make Provisional Payment of Salary.

The undersigned is directed to refer to this Department Memo. No. F. 1 (39) FD (Exp-Rules)/65, dated 29th February, 1968 and to say that the Government have decided further to authorise Secretaries to Government in the Administrative Departments to sanction Provisional Payment of Salary upto 28-2-1969 in respect of Gazetted and Non-Gazetted Officers in whose cases concurrence of the Rajasthan Public Service Commission to their appointment has not been obtained or promotions have not been finalised by the Departmental Promotion Committees constituted under respective Service Rules.

[वित्त विभाग (नियम) मेमो सं. प. 1 (39) वित्त (व्यय नियम) 165, दिनांक 11-9-68.]

(147)

SUBJECT.—House Rent Allowance.

The Governor has been pleased to make the following amendment in the Rules for grant of House Rent Allowance (appearing in Appendix XVII of the Rajasthan Service Rules, Volume II), namely.—

In the said Rules, add the following as "Government of Rajasthan Decision No. 3" below Rule 4.—

"According to Rule 4 of these rules, house rent allowance is admissible to a Government servant only from the date of his application for providing Government accommodation but which is not provided to him by the Government. Some doubts have been raised whether it is necessary to obtain non-availability certificate before house rent allowance is claimed in case of a Government servant—

(*a*) whose pay is increased bringing him into the category of Government servants who are required to obtain a non-availability certificate before claiming house rent allowance under this rule;

(*b*) who was already in the category of Government servants who are required to obtain non-availability certificate and whose pay is increased but not to such an extent as to entitle him to accommodation of higher category;

(c) who was drawing house rent allowance after non-availability certificate was granted to him, and whose pay is increased resulting in entitlement to higher category of accommodation."

The matter has been considered and it has been decided that admissibility of house rent allowance in these cases will be as under:—

(1) In a case coming under category (*a*) above, the authority competent to issue the non-availability certificate may issue the same effective from the date of increase in pay, provided it is certified that no Government accommodation of the appropriate category was available on such date.

(2) In a case coming under category (b) above, fresh non-availability certificate will not be necessary.

(3) In case coming under category (c) above, fresh non-availability certificate will have to be obtained by the Government servant concerned. Such non-availability certificate may, however, be issued retrospectively from the date of increase in pay if the non-availability certificate issuing authority certifies that on that date no Government accommodation of appropriate category, was available. Application for fresh non-availability certificate must be made within 15 days of the receipt of pay-slip from the Accountant General.

[वित्त विभाग (नियम) आज्ञा सं. एफ. 1 (45) वित्त (नियम) 168, दि. 11-9-68.]

(148)

विषय:—वित्तीय नियमों आदि से संबंधित मामलों का निपटारा।

प्राय: ऐसा देखने में आया है कि बहुत से ऐसे मामले प्रशासनिक विभागों। विभागाध्यक्षों द्वारा वित्त विभाग (व्यय-नियम) अनुभाग को भिजवा दिये जाते है जोकि वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये स्टैंडिंग आर्डर के अनुसार इस अनुभाग मे नहीं आने चाहिये। साधारणतया इस प्रकार की पत्रावलियां भजी जाती ह जिन पर निर्णय स्वयं प्रशासनिक विभाग द्वारा लिया जाना चाहिये परन्तु फिर भी सावधानी या निर्णय लेने में सुविधा के विचार से पत्रावलियां भेज दी जाती है। जिससे कार्य भार क्रमश: बढ़ता जा रहा है। उक्त विभाग मे मुख्य रूप से नियमों में संशोधन, भाव समझने (interpretation) छूट इत्यादि के मामले भेजे जाने चाहिये। प्रशासनिक विभागों में नियुक्त स्टाफ को राजस्थान सेवा नियमों, वेतन नियमों तथा अन्य नियमों की पूरी जानकारी होगी, यह इस विभाग की मान्यता है। अत: अधिकांश मामले वहां पर ही तय हो जाने चाहिये।

अत: समस्त प्रशासनिक विभागों से अनुरोध है कि भविष्य में केवल स्टैंडिंग आर्डर म उल्लेखित विषयों से संबंधित मामले ही इस अनुभाग में भिजवायें। अन्य मामलों में प्रशासनिक विभाग नियमानुसार या तो स्वयं निर्णय लेवें और यदि राय की आवश्यकता हो तो संबंधित वित्त व्यय अनुभागों को भिजवायें।

समस्त विभागाध्यक्षों से भी अनुरोध है कि भविष्य मे वे व्यक्तिगत या अन्य प्रकार मामले संबंधित प्रशासनिक विभागों को ही भजा करें।

[वित्त विभाग (नियम) परिपत्र क्र.सं. 1(46) वित्त (नियम) 68, दिनांक 11-9-68]

---

(149)

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendment to Rajasthan Service Rules.—

In the Rajasthan Service Rules:—

The following shall be inserted as 'Note 4' below Rule 7 (24).—

"Note 4.—A Medical Officer who is sanctioned non-practising allowance from time to time shall not undertake private practice in any form what-so-ever. He shall record a certificate in the following manner in the pay bill in which the non-practising allowance is claimed"

"It is certified that no private practice was undertaken during the period for which the non-practising allowance has been claimed in the bill".

[वित्त विभाग नियम अधिसूचना स. 1 (47) वित्त (नियम)/68, दि. 16-9-68]

(150)

विषयः—सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि के संबंध में।

राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि राज्य कर्मचारी राज्य सेवा में रहते हुये मैट्रिक या अन्य समकक्ष परीक्षा पास करते हैं जिसके प्रमाण-पत्र में जन्म तिथि अंकित होती है और वे परीक्षा पास करने के पश्चात् उस प्रमाण–पत्र के आधार पर सेवा पुस्तिका में पूर्व अंकित जन्म तिथि, जो प्रथम नियुक्ति के समय अंकित की गई थी बदलवाने का प्रयत्न करते हैं।

इस समस्या का समाधान करने हेतु निदश दिये जाते है कि ऐसे कर्मचारी जो राज्य सेवा में रहते हुये मैट्रिक या अन्य समकक्ष परीक्षा पास करें जिसके प्रमाण पत्र में जन्म तिथि अंकित होती है, उसको सेवा पुस्तिका में पूर्व अंकित जन्म तिथि उक्त प्रमाण-पत्र के आधार पर नहीं बदली जावे।

[वित्त विभाग (नियम) परिपत्र सं. प. 1 (16) वित्त (नियम) 68, दिनांक 21-9-68]

---

(151)

Sub.—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961-Medical & Health Department-Regional Senior Trachoma Officer.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely:—

(*i*) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

(*ii*) They shall be deemed to have come into force with effect from 1-4-1966.

(*iii*) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules 1961-Schedule I-Section B-Medical & Health Service 'General Branch, the post of "Regional Senior Trachoma Officer" shall be inserted after the post of "Principal, Auxilary Health Workers School" appearing at para 6 x (e) of Finance Department Notification No. F. 2 (b) (34) FD/E-R/66-I, dated 16th June, 1966.

(*iv*) In Schedule V of the aforesaid rules the following entries shall be inserted as Item No. IA in 3D (b) of Finance Department Notification No. F. 2(b) (18) FD/Expenditure-Rules/65-I, dated 28th July, 1966.

(A)	Regional Senior Trachoma Officer.	150/-	(27)	(29)	The Non-practising allowance shall be admissible from 1-4-66 to 30-9-66.

[वित्त विभाग (नियम) अधिसूचना सं.प. 2(बी) (51) एफ.डे.(नियम)/68, दि. 21-9-68]

(152)

Sub.—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Industries Department—Inspector—Industries Establishment.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—namely:—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

(2) They shall be deemed to have come into froce with effect from 1-9-1961.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961-Schedule II-Section D-Industries Department-the following new entries shall be inserted:—

Inspector (Industries Establishment) 80-5-120-EB-5-160 105-5-200 (11)

[F.D Notification F. 2 (b)(56) FD Rules/68, dt. 25-9-1968]

---

(153)

Sub.—Rajasthan C vil Services (Revised Pay) Rules—Amendment thereto—Schedule III - Scale No. 16, Scale No. 17.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan here by makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 196, 1namely:—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil S ervices (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

2. They shall come into force with effect from 1-7-65.

3. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule III

(A) Scale No. 16:—in rule 38 of F.D. Notification No. F. 2(b) (12) FD (E-R)/65-IV, dated 7-10-67:—

(*i*) the Notes shall be numbered as 1 & 2.

(*ii*) in Note 1-the words "higher initial pay or" shall be inserted between the words" who have been allowed "and" two advance increments "appearing" in line 2 and shall be deemed to have been inserted with effect from 1-7-65.

(*iii*) In Note 2 the words "Master's Degree in Physical Education" shall be inserted between the words "Post-Graduate Degree in Education" and "acquired after" appearing in line 2 and shall be deemed to have been inserted with effect from 1-7-65.

(B) *Scale No.* 17.—In rule 3 of F. D. Notification No. F. 2 (b) (12) FD (E-R)/65-V, dated 7-10-67.

(*i*) The Notes below (b) shall be numbered as "1 & 2"

(*ii*) In Note No. 1-the words "higher initial pay or" shall be inserted between the words "who have been allowed" and "two advance increments" and shall be deemed to have been inserted with effect from 1-7-65.

(*iii*) In Note 2-the words "Master's Degree in physical Education" shall be inserted between the words "Post Graduate Degree in Education" and "acquired after" appearing in line 2 and shall be deemed to have been inserted with effect from 1-7-65.

[वित्त विभाग (नियम) अधिसूचना सं. प. 2 (बी) (12) एफ.डी./एफ.आर/65-111,] दिनांक 6-9-68

(154)

Sub—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961-Schedule III—Scale No. 8.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961-namely:—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

2. They shall be deemed to have come into force—

(*i*) with effect from 1-9-1061 3 (a) (i), (b), (c) (1);
(*ii*) with effect from 1-7-1965 3 (a) (ii). (c) (2), (d) and (e) (f).

3. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961-Schedule III-Scale No. 8 as amended vide Finance Department Notification No. F.2 (b) (12) FD (E-R)/67-II, dated 7-12-1967.

(a) Para 2 of the aforesaid Notification shall be substituted by the following:—

"(*i*) with effect from 1-9-1961 3-A (1), (2); (3); (5); (6); 7 (a) and (c); 8 (A) and (C); (11) and (12) (a) & (b).
12 Exception.

(ii) with effect from 1-7-1965 3-A (4); 7 (b), (d) & (e); 8 (B); 9 (A) & (B); and 10 (A), (B) and 12 (C).

(b) (1) In instruction No. 7 (a) (iii) the word "appointed" shall be inserted after the word "experience" and before the word and figures "upto 30-6-1970".

(2) The "Note" appearing below sub-instruction 7 (e) shall be substituted by the following:—

"A Science teacher (defined in sub-instruction 4 above) who possesses the certificate of training in Crafts or in Physical Education or a certificate of specialised course in Music or Art recognised by the department, shall be allowed higher initial pay as admissible under 7 (c). A Science teacher with any of the above qualification if also B. S. T. C. trained shall be allowed the higher initial pay as admissible under 7 (e) above."

(c) The existing instruction No. 8 (C) shall be numbered as 8 (C) (i) and the following instruction will be inserted as 8 (C)(ii)—

"(ii) Existing personnel who were trained as defined in instruction No. 3 (i) but were drawing pay in the Rationalised Pay Scale for untrained matriculate before 1-9-1961 shall be allowed higher initial pay or two advance increments which ever is advantageous to them. The date of increment shall remain unchanged."

(d) *Instruction No.* 8—of the aforesaid Notification.

(1) In sub-instruction (A) and (C), the words and figure "7 (a), (c) and (d)" shall be substituted by "7 (a) and (c)".

(2) The following shall be added at the end of sub-instruction No. 8 (A)—

"The date of increment shall remain unchanged".

(3) The sub-instruction (B) shall be substituted by the following:—

"B. The benefit of higher initial pay provided in sub-instruction 7 (b) and 7 (e) shall be admissible to science teachers recruited upto 30-6-1970. After 30-6-1970 Science teachers if possess, qualifications prescribed in 7 (a), 7 (c) and 7 (d) shall be allowed higher initial pay prescribed for such qualifications, and persons not similarly qualified shall be allowed the minimum of the pay scale as is ordinarily admissible."

(e) Instruction No. 9 (B) of the aforesaid Notification shall be substituted by the following.—

"(B) A Science teacher other than drawing pay in trained Matriculate or higher grade before 1-9-1961 who immediately on or before 1-7-1965 possessing or acquiring subsequently or freshly recruited Science teacher acquiring the qualifications mentioned in 7 (e) above, shall be allowed the higher initial pay mentioned therein or two advance increments whichever is advantageous to him. In case of teachers in service on or before 1-7-1965 whose pay is already fixed under instruction 8 above, the benefit of two advance increments shall not be allowed. The date of annual increment shall remain unchanged."

(*f*) In instruction No. 11 of the aforesaid Notification the word 'Science" shall be inserted between the words "and freshly recruited teachers of" and "Arts, Crafts" in Line 3.

(*g*) In instruction No. 12 of the aforesaid Notification the following shall be inserted as sub-instruction No (c)

(*c*) "A freshly recruited Science teacher unless he acquires R. S. T. C. qualification."

[F.D. Noti. No. F. 2 (b) (12) FD(ER)65-I, dt. 9-9-68]

---

(155)

SUBJECT.—R. C. S. (Revised Pay) Rules, 1961—Amendment thereto—Education Department—Scale No. 13.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules 1961, namely:—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Service (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

(2) They shall come into force with effect from 1-9-61—item 3 (i), (ii), ,(iii) (iv).

(3) In the Rajasthan Civil Service (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule III—Scale No. 13—paragraph 3 of Finance Department Notification No. F. 2 (b) (12)FD (E-R)/65-III, dated 7-10-1967.

(*i*) In note 1 below sub-Instruction (3) (1) (b)—the word "Classes" appearing in line 11 between words "or teaching Sanskrit" and "in Secondary Classes" shall be deleted.

(*ii*) In sub-instruction 3 (iii) of Instruction 2 (B) for higher initial start of Rs. 140/- the word "appointed" shall be inserted before "up to 30-6-1970".

(*iii*) In sub-instruction 3 (ii) of Instruction 3 for higher initial start of Rs. 125/-, the word "appointed" shall be inserted before "upto 31-3-64".

(*iv*) In sub-instruction No. 5 (ii) the figure "4 (a) (i)" shall be substituted by "4 (a) (ii)".

[F. D. Noti, No. F. 2 (b) (12) FD(E-R)/65-II, dt. 6-9-1968]

(156)

SUBJECT:—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Education Department—Headmasters of Blind School—Prescription of Pay Scales—Scale No. 22, 23 and 24.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—namely—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

(2) They shall be deemed to have come into force as under;

(*i*) with effect from 1-9-1961 regarding item 3.

(*ii*) with effect from 1-7-1965—regarding item 4, 5, 6 and 7.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule I—Section B—State Service Officer—Rajasthan Education Service General Branch)—Post in ordinary Time Scale No. V, viz. (Page 15), the words with comma, "Blinds" shall be inserted between the words "Basic S. T. C." and "and childrens' Schools."

(4) In Rule 2 of this Department Notification No. F. 2 (b) (12) FD (E-R)/65/VII, dated 7-10-1967 for Scale No. 22 the figure "2-7-65" shall be read as "1-7-65".

(5) The words "or in scale No. 22" shall be added in sub-Rule 3 (b) of F. D. Notification No. F. 2 (b) (12) FD (ER) 65-VIII, dated 7-10-67 Scale No. 23—Schedule III after deleting full stop (.)

(6) The following shall be added in sub-Rule 3 (F) (i) of F. D. Notification No. F. 2 (b) (12) FD (E-R)/65-IX, dated 7-10-67 Scale No. 24 Schedule III after deleting full stop (.)—"provided that the benefit of two advance increments has not already been availed of as a teacher in any lower post or in scale No. 22 or 23."

(7) The words "or in scale No. 22 or 23 or 24" shall be added in sub-rule 3 (b) of F. D. Notification No. F. 2(b) (12) FD/(E-R)/65-X, dated 7-10-67—Scale No. 26 Schedule III after deleting full stop (.).

[F. D. Noti. No. F. 2(b) (12) FD/FR/675-V, dt. 6-9-1968]

(157)

SUBJECT;—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—R. H. J. S.—Amendment thereto.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely;—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 15-6-68.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961 the Schedule I-B-State Services—Rajasthan Higher Judicial Service—(i) the remarks appearing before the posts "Law Secretary-cum-Legal Remembrancer, Joint Legal Remembrancer, District and Sessions Judges/Registrar, Rajasthan High Court, Judge, Labour Court, Dy. Legal Draftsman, Dy. Legal Remembrancer, Additional District and Sessions Judges" vide F. D. Notification No. F. 12 (b)(12) FD;ER/68, dated 3-6-68 shall be substituted by the following:—

"Remarks.—The pay of an officer belonging to the defunct cadre of Civil and Additional Sessions Judge who, consequent upon the abolition of the cadre of Civil and Additional Sessions Judges, was appointed as Additional District and Sessions Judge on 15-6-68, shall be fixed at the stage equal to the Officer's actual pay drawn as Civil and Additional Sessions Judge in substantive or officiating capacity on 14-6-68 plus Rs. 200/- and in case, there is no equal stage, at the stage next above the officer's actual pay drawn as Civil and Additional Sessions Judge in substantive or officiating capacity plus Rs. 200/-.

(i) The date of increment shall remain unchanged in both the cases.

(ii) The date '1-4-68' appearing in para 2 and in column 4 of 3A (ii) of the notification cited in (i) above shall be read as '15-6-68'.

[F.D. Noti. No. F. 2 (b) (12) F. D. (Rules)/68, dt. 7-9-67]

---

(158)

SUBJECT:—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule III—Scale No. 21.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the

following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely:—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

2. They shall be deemed to have come into force—

(*i*) with effect from 1-9-61—3A (2) (i), (ii), (iii) (a), (iv)

(*ii*) with effect from 1-7-65—3 A2 (iii) (b), B (i) & (ii) (C), (D) & (E).

3. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule III—Scale No. 21—F. D. Notification No. F. 2 (b) (12) FD (E-R)/65-VI, dated 7-10-67.

(A) The existing instruction No. 2 as amended vide item D of F. D. Notification No. F. 2 (b) (12) FD/E-R/65, dated 30-9-1965 and 3 (a)(b) of No. F. 2 (b) (12) F.D./E. R./65-VI, dated 7-10-65 shall be substituted by the following;—

"(2) E. B. at Rs. 275/- shall not be crossed by the existing personnel as well as fresh recruits other than Senior Teachers of Science, for the following posts until they acquire the qualifications mentioned therein:—

(*i*) Librarians & Physical Instructors—qualifications mentioned at instruction 1 above.

(*ii*) Senior Teachers in charge of subjects in Higher Secondary Schools—qualification—B. Ed.

(*iii*) In the following cases E. B. shall operate at the stage of Rs. 315/-

(*a*) all existing persons whose pay in the new scale is fixed at Rs. 265/- or above.

(*b*) freshly recruited or existing senior teachers of Science whose pay is fixed at Rs. 285/- or less.

(*iv*) In the case of Sr. Teachers of Drawing, Painting, Music, Dance, Home Science and Urdu, E. B. at Rs. 275/- shall not be crossed unless they acquire Post Graduate Degree/Diploma in the subject or have 7 years, experience of teaching Secondary Classes as Senior Teacher in the relevant subject.

(*v*) There will be no E. B. for persons whose pay is fixed *at Rs. 315/- or above.*

(B) (*i*) In instruction No. 5 of the aforesaid Notification the word "whichever is advantageous" shall be inserted between the

words "as the case may be" and "shall be admissible" in line 3.

The proviso—"provided this benefit.......... and who" shall be substituted by the following:—

"provided that the benefit of two advance increments will not be admissible where the same has been availed of as Grade III or Gr. II teachers who"—

(ii) The words "from the date of declaration of result" shall be inserted after the words "on or after 1-7-65" appearing in 5 (b) after deleting full stop (.).

(C) The existing instruction 7 of the aforesaid Notification shall be substituted by the following—

"(7) Two advance increments with cumulative effect shall be admissible to a senior teacher in service, who is also a Graduate in Education provided that this benefit has not been availed of in lower scales 13, 16 & 17:—

(a) if he possessed Master's Degree in Education before 1-7-65 with effect from 1-7-65.

(b) if he acquires Masters Degree in Education on or after 1-7-65 from the date of declaration of result".

(D) Instruction 8 of F. D. Notification No. F. 2 (b) (12) FD/ER/65-VI, dated 7-10-67 shall be deleted.

(E) Notes appearing at the end of the instruction No. 8 (now deleted) shall be substituted by the following:—

NOTE:—For the purpose of these instructions "Master's Degree in Education" means "Master's Degree in Education or Physical Education awarded after a regular 9 months full time course or equivalent Diploma recognised as such by the Department and awarded aftera regular 9 months full time course."

NOTE 2—"A Senior teacher in Science" means "a senior teacher of Physics, Chemistry, Biology or Mathematics who possesses 'Master's Degree in Science and fulfills the qualifications prescribed for the post."

NOTE 3—A person who is B. Sc. and has successfully completed special Training Course of 9 months duration recognised by the Rajasthan Board of Secondary Education for Senior Teachers may be appointed as Senior Teacher with intiial pay of Rs. 225/- up to 31-3-71.

NOTE 4—The date of normal increment of a teacher who has been allowed higher initial pay or two advance increments under instructions No. 4, 5, 6, and 7 above shall remain unch anged.

[F. D. Moti, No. F. 2 (b) (12) F.D. (E-R)/65-IV, dated6-9-68.]

(159)

Sub:—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule III—Scale No. 8-E.B. for Sanskrit Teachers.

In exercse of powers conferred by the proviso to Artic'e 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely:—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1-9-1961.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule III-Scale No. 8—

(A) (*i*) Sub-instruction (*iii*) & (*iv*) of Instruction No. 11 inserted vide Finance Department Notification No. F. 2(b) (12)FD (E-R)/65-II, dated 7-10-1967 the words "and is above 35 years of age" appearing in lines 6 and 7 of sub-instruction (*iii*) and in lines 5 and 6 of sub-instruction (*iv*) shall be deleted.

(*ii*) the word "unless he" shall be inserted between the words "Praveshika Qualifications" and "gain 10 years' teaching experience" in sub-instruction No. (*iii*) and between the words "Upadhyaya" and "gains 7 years" in sub-instruction (*iv*) respectively.

(B) Sub-instruction (*vi*) and (*vii*) of Instruction No.12 inserted vide Finance Department Notification No. F.2(b)(12) FD (E-R)/65-II, dated 7-10-1967, the words "and is above 35 years of age" appearing in lines 6 & 7 of the aforesaid sub-instruction shall be deleted.

[वित्त विभाग नियम अधिसूचना सं. प. 2 (बी) (12)एफ. डी. (ई-आर)165, दिनांक 9-9-68]

---

(160)

Sub :—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule II- Part 4— Ground Water Board Special Pay to Truck Drivers working as Compressor Operator.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely:—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1-8-1968.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules,1961—Schedule II-Part 4—Agriculture Department the following entries along with sub-heading shall be inserted :—

Ground Water Board.	Truck Driver working as Driver Cum-Compressor Operator.	Rs. 15/-p.m.	(6)

[वित्त विभाग (नियम) अधिसूचना सं.प. 2 (बी) (50) वित्त (नियम)।68, दिनांक 21-9-68]

(161)

Sub :—Rajasthan Travelling Allowance Rules.

In pursuance of Rule 57 of the Rajasthan Travelling Allowance Rules, the Governor has been pleased to order that the Lower Division Clerks appearing in an examination conducted under Finance Department Order No. F. 2 (b) (21) FD (Exp. -Rules)67, dated 28th March, 1968 may be treated as on duty and be allowed travelling allowance only once at tour rates for journeys to and from the place of examination and daily allowance for the day on which the examination is held If, however, such a Government servant fails in the examination, he may not be allowed any Travelling Allowance for his subsequent journeys performed for appearing in the examination.

[वित्त विभाग (नियम) आज्ञा सं. प. 3 (11) वित्त (नियम)।68, दि. 5-9-68.]

(162)

Sub :—Rajasthan Travelling Allowance Rules.

The Governor has been pleased to order that the following amendments be made in the Rajasthan Travelling Allow ance Rules, namely:—

In Part III of the said rules, the following be inserted as Government of Rajasthan Decision No.6 below Rule 22:—

No. 6:—Under proviso to Rule 22, it has been decided to accord general permission to Government servants drawing pay of Rs. 800/- p.m. and above to undertake journeys by air in "Jam AIR COMPANY' from and to Jaipur/Kotah

[वित्त विभाग (नियम) आज्ञा सं. प. 3(3) वित्त (व्यय-नियम)।68, दि. 12-9-68.]

(163)

Sub :—Submission of applications for admission to Provident Funds.

It has been reported by the Accountant General, Rajasthan, Jaipur that one of the reasons for the accumulation of unposted Provident Fund credits is that the applications for admission to Provident Funds are, in a number of cases, not received in his office in time with the result that subscription to Provident Fund is commenced without allotment of the requisite Account numbers.

In order to obviate such delays it has been decided that in case of non-Gazetted Government servants the Head of Departments should obtain the applications in the prescirbed form duly filled in and forward it to the Accounts Officer, after check for allotment of Account Number well in advance of the date from which the Government servant is required to subscribe.

[वित्त विभाग (नियम) ज्ञापन सं. प. 4 (7) वित्त (व्यय-नियम) 165-I, दि. 21-9-68]

---

(164)

Sub :—Measure to reduce missing credits in General Provident Fund Accounts.

According to Rule 7 (*i*) of General Provident Fund (Rajasthan Services) Rules, 1954, a Government servant who exercises the option to subscribe to General Provident Fund, may discontinue subscribing to the Fund at any time, but right of renewing subscription shall lapse if he discontinues subscribing except when on leave, more than three times. It has, however, been experienced that this option to discontiune subscrition to General Provident Fund without any prior notice to the Accountant General, Rajasthan, Jaipur has resulted in increase in the number of missing credits unnecessarily.

To overcome this difficulty the following procedure is prescribed in cases of discontinuance of Provident Fund subscription :—

(*i*) Discontinuance and renewal of Provident Fund subscriptions should be allowed only with effect from the beginning of Financial year i.e. salary for March paid in April.

(*ii*) The Government servant desiring to discontinue Provident Fund subscriptions should send an intimation to the Accountant General, Rajasthan, Jaipur well in advance of 1st April, and should not discontinue subscribing to Provident Fund unless he receives an acknowledgment of the intimation from the Accountant General.

[वित्त विभाग (नियम) ज्ञापन सं. प. 4 (7) वित्त (व्यय-नियम) 165-II, दि. 21-9-68.]

(INDEX)

(44)

Sub:—Amendment in the General Financial and Account Rules—Vol. I (Rule 137 ibid)

The Governor has been pleased to order that the following be added as a new Rule 137(*A*) below the existing Rule 137 of the General Financial & Account Rules—Vol I.—

Rule 137(*A*):—When any sum is payable in respect of pay, pension, gratuity, or other similar allowance to any person by the State Government and the person to whom the sum is payable is certified by a Magistrate to be a lunatic, the Government Officer under whose authority such sum would be payable if the payee were not a lunatic may pay so much of the said sum as he thinks fit to the per on having charge of the lunatic, and may pay the surplus, if any, or such part thereof as he thinks fit for the maintenance of such members of the lunatic's family as are dependent on him for maintenance. The Government shall be discharged of all liability in respect of any amount paid to any person mentioned above in accordance with Section 95(1) of the Indian Lunacy Act, 1912 (Act No. 4 of 1912).

[वित्त लेखा एवं विनियोजन विभाग आज्ञा सं. 6 (15) वित्त (ले. एवं विनियो.) जी. एफ. ए. आर./67, दिनांक 11-9-68]

(45)

Sub.—Amendment in General Financial and Account Rules—Vol-I (Rule 174-A).

The Governor has been pleased to order that following amendm… be made in the General Financial & Accounts Rules, Vol. I viz.:—

(*i*) The following heading be inserted below Rule 174 of the said Rules:—

"*Payment of Pay and allowances, Pension & Gratuity to Lunatics*'

(*ii*) The following be added as a new Rule 174 (A) under the above heading below the exi.ting Rule 174 of the said Rules:—

"Rule-174-A"-Pay and allowances of a person who is certified by a Magistrate to be a lunatic should be paid in accordance with th

detailed procedure given below :—

(1) On receipt of information that a Govt. servant has been certified to be a lunatic the Head of Office, in which the Government servant before his being certified to be a lunatic was last employed should on the basis of the orders issued by the Appointing Authority, indicating the person (s) to whom and the proportion in which the pay and allowances admissible to the Government servant may be disbursed in accordance with the provisions of Section 95(1) of the Indian Lunacy Act, 1912, draw the pay and allowances of the Government Servant in the appropriate bill form, gazetted or non-gazetted as the case may be from the treasury or other office of disbursement. The claim should be supported by all the relevant certificates which the Head of the Office is required to furnish in the normal circumstances. However, in respect of the certificates which solely depend on the personal knowledge of the Govt. servant and which cannot be furnished in such cases, the Head of the Office should record, if he is satisfied about the reasonableness of the claim, a certificate to the effect that the claim is not susceptible of verification but is considered reasonable. If the Government servant is invalided from service, the claim would be the last one in respect of him and the requisite payment in case he was a gazetted Government servant shall be made only after the Head of the Office has satisfied himself by reference to the Accountant General, the Departmental authorities, if any and his own records that no Govt. dues are out standing against him. In other cases payment be made on the responsibility of the Head of the Office concerned.

(2) The amount withdrawn in the manner stated above may be paid to the person (s) referred to in sub-paragraph (1) above in the proportion determined by the appointing authority and receipts obtained, stamped where necessary, in accordace with Rule 137-A of these rules.

(3) Where a Government servant has been invalided from service and it is found that some Government dues are outstanding against him even after the adjustment of his claims for pay and allowances, the same may be adjusted against the amount of the death-cum-retirement gratuity, if any.

(*iii*) The following be inserted below the above Rule :—

"(Extract from the Indian Lunacy Act, 1912-Act No. 4 of 1912)"

Section 95 (1). When any sum is payble in respect of pay, pension. uity, or other similar allowance to any person (by the Central Go- nent or a State Government) and the person to whom the sum able is certified by a Magistrate to be a lunatic, the Government under whose authority such sum would be payable if the payee ot a lunatic may pay so much of the said sum as he thinks he person having charge of the lunatic, and pay the surplus.

if any, or such part thereof, as he thinks fit for the maintenance of such members of the lunatic's family as a dependent on him for maintenance.

(2) The Government concerned shall be discharged of all liability in respect of any amount paid in accordance with this section."

[F.D. (A&I) Deptt. No. F. 6 (15) F.D. (A&I)/GFAR/67, dated 9-9-68]

---

(46)

In pursuance of rule 21 of the Rajasthan Service Rules, 1951 the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendment in the Rajasthan Government Servants' Insurance Rules, 1953, namely :—

AMENDMENT

For the existing Sub-rule (3) of rule 45 of the said Rules, the following Sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3)" If no communication in writing intimating selection of one of the above alternatives reaches the Director within six months from the date with effect from which the insured ceases to be in service the policy will automatically be converted into a paid-up one, as from the date from which the insured ceased to be in service. In case death occurs during the said period of six months without intimation of the selection of one of above alternatives having already reached the Director, the policy will be treated as having been in force for full sum assured and claim will be paid in accordance with the rules, applicable to policies in force for full sum assured, after deduction of unpaid premiums till the last day of the month in which death occurs together with interest at 6% per annum."

[वित्त लेखा एवं विनियोजन (विभाग) अधिसूचना सं. प. 7 (22) वित्त (ले. एवं विनियोजन) 67, दिनांक 16-9-68]

---

(47)

In pursuance rule 21 of the Rajasthan Service Rules, 1951, the Government of Rajasthan hereby makes the following amendment in this Department Order No. F. 9 (10) F/Com/61, dated the 10th January, 1964, namely :—

AMENDMENT

In the said Order, between the expressions "pleased to order that" and "the following shall", the following expression shall be inserted, namely :—

"With effect from the 1st April, 1961".,

[वित्त लेखा एवं विनियोजन विभाग अधिसूचना सं. प. 9 (10) एफ काम/61 दिनांक 17-9-1968]

(48)

Sub:—Chairman, Regional Transport Authority as Head of the Department Class I.

The Governor has been pleased to declare the Chairman, Regional Transport Authority, as Head of Department Class I, under General Financial & Account Rules.

[वित्त लेखा एवं नियोजन विभाग आज्ञा सं. एफ. 13 (19) एफ.डी. (ले एवं नियोजन) जी. एफ.ए. आर./68, दिनांक 9-9-68]

---

(49)

Sub ;—Amendment in General Financial and Account Rules—Vol.II

The Governor has been pleased to order that the figure of "Rs 100/-" be substituted for the existing figure of "Rs 25/-" appearing in certificate No. I of the form No.G.A.108,of General Financial and Account Rules Vol. II

[वित्त लेखा एवं विनियोजन विभाग आज्ञा सं. प. 6 (18) एफ. डी. (ले वि) दिनांक 26-9-68)

---

(50)

Sub :—Amendment in the General Financial and Account Rules, Vol. I-Viz. deletion of Note below Rule 239 & addition of a note in column No.3 against item No. 29 of Appendix VIII.

The Governor has been pleased to order that the following amendments be made in the General Financial & Account Rules, Vol. I viz. :—

I Rule 239 *Page* 133 Delete the Note appearing thereunder.

II Appendix VIII—Add the following as a note in Col. No. 3 against item No. 29 Page 362

Note:—At places where the telephone Service is under the control of the Post and Telegraphs Department, bill for the telephone charges will be forwarded. in duplicate to the officer served, who on approving the bill, will draw the amount from tne treasury by presenting a fully Vouched Contingent bill and pay the amount in cash to the Post and Telegraph authority within a period of 15 days from the date of receipt of the telephone bill and obtain a receipt thereof. On such bills which are more than Rs 50/(fifty) the treasury officer will order that the payment shall be made through bank draft and not in cash. This will have effect from 1-4-1968.

[वित्त लेखा एवं विनियोजन विभाग आज्ञा सं. प. 13 (28) एफ. वित्त (ले. वि.)/68, दिनांक 26-9-68]

सामान्य प्रशासन विभाग

(सूची)

(39)

विषयः—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से उनकी इच्छा के प्रतिकूल घरू कार्य लेने के संबंध में।

समस्त शासन सचिव, विभागाध्यक्षों। कार्यालय अध्यक्षों का ध्यान सामान्य प्रशासन (क) विभाग के आदेश संख्या एफ. 4 (26) सा।प्र।क।157, दिनांक 21-9-57 तथा आदेश संख्या एफ. 4(2)सा।प्र।क।59, दिनांक 31-1-59 की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि उपरोक्त आदेशों का पालन कुछ अधिकारियों द्वारा भली भांति नहीं किया जा रहा है फलस्वरूप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घरू काम काज उनकी इच्छा के विरुद्ध लिया जाता है जो संबंधित प्रचलित आदेशों के प्रतिकूल है।

समस्त शासन सचिवों/विभागाध्यक्षों/कार्यालय अध्यक्षों से निवेदन है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक हिदायतें दे देवें ताकि संबंधित आदेशों का बड़ी कड़ाई से पालन किया जावे।

[सामान्य प्रशासन (क) विभाग परिपत्र सं. प. 2 (24) सा. प्र. क। 68, दिनांक 21-9-68]

---

(40)

विषयः—कार्य विधि नियम में संशोधन।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 177 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय एतद् द्वारा आदेश प्रदान करते हैं कि कार्य विधि नियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन कर दिये जायें :—

संशोधन

1. भाग 6—राजस्व विभाग के क्रम संख्या 34 व 35 में वर्णित विषयों को हटा दिया जावे तथा क्रम 36 के स्थान पर 34 कर दिया जावे और इसी क्रम में क्रम संख्या को ठीक कर दिया जावे।

2. भाग 6—राजस्व विभाग के बाद नया अनुभाग निम्नलिखित विषयों सहित जोड दिया जावेः—

"6-क—राजस्व विभाग (सैनिक कल्याण)"

(1) सैनिकों के कल्याण सम्बन्धी सभी कार्य (जिसमें सैनिक—नाविक एवं वैमानिक मण्डलों का प्रशासन भी सम्मिलित है)।

(2) सैनिक कार्यवाहियों से युद्ध काल में हुई नागरिक क्षति की क्षति पूर्ति व्यवस्था।

(3) सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिये निम्नलिखित रियायतें :—

(1) वित्तीय सहायता के रूप में नकद अनुदान।

(2) भूमि अनुदान।

(3) लापता कर्मचारियों के परिवार को सहायता ।
(4) भूतपूर्व सैनिकों को पैनशन भुगतान की व्यवस्था ।
(5) वच्चों को छात्रवृत्ति वितरण ।
(6) विभिन्न शिक्षण एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षित पदों (Seats) पर शिक्षणहेतु नियोजन ।

(4) सैनिक शौर्य पदक प्राप्तकर्त्ताओं को नकद पारितोषिक अनुदान एवं भूमि अनुदान ।

(5) सैनिकों को कानूनी । सलाह । सहायता-अनुदान सम्बन्धित कार्य ।

(6) R.A.C./C.R.P. एवं B.S.F. के कार्मिकों को नकद अनुदान एवं भूमि अनुदान ।

(7) युद्ध अथवा संघर्ष काल में सेवारत होते हुए हताहत अथवा वीर गति प्राप्त हुए राज्य-कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं अन्य सुविधाएं ।

(8) सैनिकों । भूतपूर्व सैनिकों को रहवास हेतु भू-खण्ड आवंटन कार्य ।

(9) सेवा मुक्त सैनिकों एवं सेवा रत्त विकलांग सैनिकों का पुनर्वास एवं आर्थिक अनुदान व भूमि आवंटन ।

(10) उन मामलों को छोडकर जो नियुक्ति, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को सौंप दिये गये हैं, विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों और कर्मचारी वर्ग के स्थापना संबंधी समस्त मामले ।

[सामान्य प्रशासन (क) विभाग आदेश सं. प. 1 (1) सा.।प्र. क।68, दिनांक 18-9-68]

---

(41)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि राज्य सरकार के विभागों । कार्यालयों को जब कभी अधिकारियों । प्रशिक्षार्थियों आदि के लाने लेजाने व अन्य राजकीय कार्यों के लिये वसों की आवश्यकता होती है तो बहुत से विभाग । कार्यालय प्राईवेट वसों को किराये पर ले लेते हैं ।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एक राजकीय प्रतिष्ठान है और उसमें काफी संख्या में वसें उपलब्ध हैं जो राजकीय विभागों । कार्यालयों से उनसे संबंधित सभी कार्यालयों के लिये निगम द्वारा निश्चित दरों पर सुगमता से उपलब्ध की जा सकती हैं । अतः सभी सचिवों । विभागाध्यक्षों व अन्य अधिकारियों से अनुरोध है कि वे आवश्यकता के समय केवल निगम की वसें ही किराये पर लिया करें ।

[सामान्य प्रशासन (क) विभाग परिपत्र सं. प.15 (20) सा.।प्र.।क।68 वृन्द 2, दिनांक 12-9-68]

(गृह विभाग)
HOME DEPARTMENT

INDEX
(सूची)

(22)

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3-8-68 द्वारा, पथ परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 17 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिये गठित की गई तीन उपयोग कर्त्ता सलाहकार समितियों में से जयपुर क्षेत्र व जोधपुर-बीकानेर क्षेत्र के लिये गठित समितियों में दो-दो विधान सभा सदस्यों का मनोनयन शेष था। अतः एतद् द्वारा राज्य सरकार निम्नांकित विधान सभा सदस्यों को उक्त समितियों के सदस्य मनोनीत करती है :—

जयपुर क्षेत्र के लिये उपयोग कर्त्ता सलाहकार समिति

1. श्री बलवन्तराम, सदस्य विधान सभा।
2. श्री हरिप्रसाद, सदस्य विधान सभा।

जोधपुर-बीकानेर क्षेत्र के लिये उपयोगकर्त्ता सलाहकार समिति

1. श्री बीरबल, सदस्य विधान सभा।
2. श्री कालूराम आर्य, सदस्य विधान सभा।

[गृह ख-1 विभाग आदेश सं. एफ. 2 (4) (85) गृह (ख-1)।67, दिनांक 18-9-68]

---

(23)

Sub :—Supply of State Government publications to the Department/offices of Central Government.

Rajasthan Government has agreed to supply the State Government Publications to the Department/Offices of the Government of India at a discount of 25% on reciprocal basis.

[गृह (घ) विभाग सं. प. 5 (1)/63 गृह, दिनांक 20-9-68]

INDEX

श्रम एवं नियोजन विभाग

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

(5)

In partial modification of order No. F. 9 (143) Lab/60, dated 21st December, 1962 the Governor has been pleased to order that the age limit for admission in the Industrial Training Institutes for the ex-servicemen shall be relaxable upto 45 years.

[No. F. 7 (8) L&E/ 68 (Trg.), dt. 13-9-68]

55/46

केवल कार्यालय उपयोगार्थ

राजस्थान सरकार

मंत्रि-मण्डल सचिवालय

व्यवस्था एवं पद्धति (संकलन) अनुभाग

मार्च, 1968 में
शासन सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गए महत्वपूर्ण परिपत्रादि का मासिक संकलन

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

1968

LIST OF DEPARTMENTS

(In respect of which important circulars etc. have been printed in this compilation).

S. No.	Name of Department	PAGE No.
1.	Appointments Department	2
2.	Cabinet Secretariat (including O. & M. Section) .. .	7
3.	Finance Department (Expenditure)	11
4.	Finance Department (Revenue)	39
5.	General Administration Department	44
6.	Home Department	50
7.	Law Department	53
8.	Revenue Department	55

विभागों की सूची

(उन विभागों की सूची जिनके महत्वपूर्ण परिपत्रों आदि को मार्च 68 के संकलन में मुद्रित किया गया है

क.सं.	विभागों के नाम	पृष्ठ संख्या
1.	नियुक्ति विभाग	2
2.	मंत्रिमण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति सहित)	7
3.	वित्त (व्यय) विभाग	11
4.	वित्त (राजस्व) विभाग	39
5.	सामान्य प्रशासन विभाग	44
6.	गृह विभाग	50
7.	विधि विभाग	53
8.	राजस्व विभाग	55

मार्च, 1968

APPOINTMENTS DEPARTMENT

INDEX.

APPOINTMENTS DEPARTMENT

(4)

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules farther to amend the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-Service Personnel) Rules, 1959, namely;—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-Service Personnel) (Amendment) Rules, 1967.

2. In rule 7 of the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-Service Personnel) Rules, 1959, for the word "December" the word "April" shall be substituted.

(Apptts. (A-II) Deptt. Noti. No. F. 3 (9) Apptts (C)/58 dated 31-3-68)

---

(5)

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 the Constitution of India. the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendments with effect from 26-8-1966 to the Service Rules mentioned below, namely.—

AMENDMENTS

1. The Rajasthan State Insurance Service Rules, 1959, after the existing rule 24-A, the following new rule shall be added:—

24-B. *Appointment to the post of Assistant Director.*—Appointment to the post of Assistant Director shall be made by Government on occurrence of substantive vacancies in the cadre of the Service in the manner prescribed by Rules, 22, 24 and 24-A.

2. For the existing rule 25, the following shall be substituted:—

25. *Appointment to senior and selection posts.*—Appointment to senior and selection posts shall be made by Government from amongst the members of the service in the next below category on the basis of merit and seniority-cum-merit in the ratio of 1:2 on the recommendations of a Committee which shall consist of the following: but in the case of selection to the post of Director, the Director shall not be a member of the Committee:—

1. Chairman, Rajasthan Public Service Commission or a Member nominated by him .. .. Chairman

2. Special Secretary to Government in the Appointments Department or his representative not below the rank of Deputy Secretary .. .. Member.

3. Secretary to Government in the Finance Department, which term includes the term of Special Secretary .. .. Member.

4. Director of Insurance .. .. .. Member.

The procedure and the principles for selection by merit shall, in so far as it may apply, be the same as provided in rule 24-A. For selection by Seniority-cum-Merit, the Committee shall consider the cases of all the persons eligible for promotion by examining their C. Rs , and personal files and interviewing such of them as may be deemed necessary, and shall select a number of candidates equal to the number of vacancies likely to be filled by promotion by Seniority-cum-Merit:

Provided that Government may fill a vacancy on the senior or selection posts temporarily by appointing thereto for a period not exceeding one year in an officiating capacity, any member of the service who is eligible for such appointment under the rules.

[Apptt. (A-II) Deptt. No. F. 1 (6) Apptts. (D) 59-Pt. III dated 26-3-68.]

(6)

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby, makes the following amendments to the Rajasthan Secretariat Service Rules, 1954, namely:—

AMENDMENTS

In the said Rules,

(1) in rule 6,

(a) in sub-rule (1), after clause (iii), the following new clause shall be added, namely;—

"(iv) Assistant Legal Draftsman;"

(b) after the proviso to sub-rule (2) the following further proviso shall be added, namely —

"(iii) that only one post of Assistant Legal Draftsman shall be included in the service."

(2) in rule 7, the following further proviso shall be added, namely:—

"Provided further that recruitment to the post of Assistant Legal Draftsman shall be made by promotion of substan-

ive Head Legal Assistant who has put in at least seven years' service as Head Legal Assistant inclusive of his service as Legal Assistant."

(3) after rule 11A, the following new rule shall be added, namely—

"11AA. Recruitment to the post of Assistant Legal Draftsman —

(1) Notwithstanding anything contained in rule 10 and 11, recruitment to the post of Assistant Legal Draftsman shall be made by Government by promotion of Head Legal Assistant on the basis of the recommendation of the Committee consisting of the following:—

(*i*) Chairman of the Rajasthan Public Service Commission or a Member nominated by the Chairman ... *Chairman.*

(*ii*) Secretary to the Govt. in the Law Department .. .. .. *Member.*

(*iii*) Special Secretary to the Government in the Appointments Department .. *Member-Secy.*"

(4) in rule 12, in sub-rule (2), after the words "A temporary vacancy in the service may be filled by the Government", the words "In case of the post of Assistant Secretary or Registrar" shall be inserted, and after the words "Officiating Capacity" the words "and in case of the post of Assistant Legal Draftsman, by appointing thereto a Head Legal Assistant in an officiating capacity" shall be inserted.

[Apptts (A-II) Deptt. Noti. No. F. 13 (2) Apptt. (A) 53/Pt. IV, dated 31-3-68].

---

(7)

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है कि प्रशासन का समस्त कार्य हिन्दी में ही किया जावे और इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए भाषा विभाग द्वारा हिन्दी मुद्रण व शीघ्र लिपि के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सम्बन्ध में पहले भी समस्त विभागों से अनुरोध कर दिया गया है कि उनके विभागों में कार्य कर रहे कनिष्ट लिपिकों को हिन्दी मुद्रण प्रशिक्षण दिलाया जावे। यद्यपि इस प्रणाली के अनुसार विभागों द्वारा पूर्णरूप से सहयोग देकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिलाया गया किन्तु वह अड़चन अब भी है कि अमुक कर्मचारी हिन्दी की पुरानी मशीन पर ही टाइप कर सकते हैं। इस अड़चन को हटाने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि हर विभाग के हर कनिष्ठ लिपिक को यदि वह हिन्दी की नये मॉडल की मशीन पर मुद्रण नहीं जानते तो उन्हें प्रशिक्षण दिया जावे।

अतः सचिवालय के समस्त विभागाध्यक्ष अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने विभाग के कनिष्ठ लिपिक के नाम, जो हिन्दी के नये मॉडल पर मुद्रण नहीं जानते हैं भाषा विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें तथा साथ ही इसकी सूचना इस विभाग को भी दे दें।

चूंकि यह प्रशिक्षण भाषा विभाग द्वारा समय समय पर दिया जाता है अतः सुविधानुसार ही कर्मचारियों के नाम भेजें।

[नियुक्ति (ख1) विभाग परिपत्र संख्या एफ. 2 (2) नि. । ख।68, दिनांक 6-3-68]

CABINET SECRETARIAT (INCLUDING O & M SECTION)
INDEX

CABINET SECRETARIAT
(including Organisation & Method Section)

(8)

विजय:—मन्त्रि मण्डलीय खाद्य समिति

सम संख्यक आज्ञा दिनांक 29 सितम्बर, 1967 के आंशिक संशोधन में राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा निम्नलिखित स्थायी खाद्य मन्त्रि मण्डलीय समिति के गठन की आज्ञा प्रदान करते हैं :—

1. वित्त मंत्री—अध्यक्ष,
2. राजस्व मन्त्री,
3. खाद्य मन्त्री,
4. कृषि मन्त्री।

पूर्व गठित खाद्य एवं अकाल सहायता मन्त्रि-मण्डलीय समिति अब केवल अकाल सहायता मन्त्रि-मण्डलीय समिति रहेगी ।

[मंत्रि-मण्डल सचिवालय आज्ञा संख्या एफ. 1(1)(20) केब.67, दिनांक 1-3-68]

---

(9)

विषय:—कर्मचारियों द्वारा पत्र प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दिये जाने वाले हस्ताक्षर ।

प्राय: ऐसा देखने में आया है कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले पत्रों की प्राप्ति स्वरूप कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले हस्ताक्षर स्पष्ट तथा पूरे रूप में नहीं किये जाते जिससे आवश्यकता पर पत्र लेने वाले कर्मचारी का पता लगाने में कठिनाई ही नहीं होती अपितु कभी कभी पता ही नहीं चलता ।

ऐसी संभाव्य परिस्थिति को भविष्य में रोकने की दृष्टि से यह निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति करने के प्रमाण स्वरूप किये जाने वाले हस्ताक्षर सदा सुपाठ्य तथा पूरे रूप में (लेजिबल एण्ड फुल सिग्नेचर्स) दिये जाने चाहियें । यदि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर सुपाठ्य न हों तो उसे अपने हस्ताक्षरों के नीचे अपना नाम सुपाठ्य अक्षरों में कोष्ठक में अनिवार्य रूप स लिखना होगा ।

इस आदेश की अवहेलना करने वाले सम्बन्धित व्यक्ति अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी होंगे ।

[व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग परिपत्र क्रमांक प. 1 (4) व्य.एवं.प./67, दिनांक 4-3-68]

FINANCE DEPARTMENT (Expenditure)
INDEX

FINANCE DEPARTMENT (Expenditure)

1	2	3	4
33.	राजस्थान सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) नियम, 1961 अनुसूची 11, भाग 4 राज. लेखा सेवा अधिकारी प्रशिक्षणालय।अधिसूचना	एफ. 2 (ब) 34 वित्त नियम। 66, दिनांक 20-3-68	32
34.	राजस्थान सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) नियम, 1961 न्याय सेवा-सहायक विधि प्रारूपकार आदि शुद्धि-पत्र	एफ. 2 (बी) (26) वित्त (व्यय-नियम) 67, दिनांक 25-3-68	33
35.	राजस्थान सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) नियम, 1961 अनुसूची 3-वेतन मान संख्या 9 –शुद्धि-पत्र	एफ. 2 (ब) (21) वित्त (व्यय-नियम) 67, दि. 20-3-68	33
36.	Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—as amended on 1-4-1966 Schedule II—Part 4—Rajasthan Accounts Service —Officers Training School—Amendments.	F. 2 (b) (34) FD(E-R)/66, dated 20-3-66.	33
37.	Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule III—Scale No. 10—Amendment.	F. 2 (b) (21) FD (E-R)/67-I, dated 5-3-68.	34
38.	Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—as amended on 1-4-66—Patwaries of Colonisation/Irrigation—Amendments.	F. 2 (b) (2) FD (R)/68, dated 1-3-68.	35
39.	Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Sheep & Wool Department—Amendments.	F. 2 (b) (5) Finance (Rules)/68, dated 5-3-68.	37
40.	Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Amendment thereto—Schedule II—Section D-Agriculture Department—Subordinate Agriculture Service.	F. 2 (b) (89) FD (E-R)/67, dated 5-3-68.	38
41.	Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Amendment thereto—Schedule I Sec. D—Archives Department—Senior Technical Assistant.	F. 2 (b) (3) FD (E-R)/68, dated 5-3-68.	41
42.	Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule B—Election Department.	F. 2 (b) (8) Finance (Rules)/68, dated 5-3-68.	42

FINANCE DEPARTMENT (Expenditure)

1	2	3	4
43.	Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Bifercation of Medical & Collegiate Service—Special Pay to them.	F. 2 (b) (77) FD (E-R)/67-IV, dated 20-3-68.	43
44.	वित्तीय वर्ष के आखरी दिनों में असाधारण खर्च न करने के बारे में	एफ. 3 (36) वित्त (व्यय)/68 दिनांक 21 मार्च, 1968।	44
45.	Opening of a full fledged Public Debt Office at Jaipur.	F. 1 (1) F. W. M./68, dated 4-3-68.	44

FINANCE DEPARTMENT (Expenditure)

(22)

SUBJECT;—Rajasthan Services (Concession on Border Road Construction Organisation) Rules, 1967.

Rule 5 of the Rajasthan Services (Concession on Border Road Construction Organisation) Rules, 1967 restricts the admissibility of the Border Road Construction Allowance for during the period of temporary transfer/leave not exceeding two months. A question has been raised as to who will certify that a Government servant has reported for duty to the post on the expiry of this period. The matter has been considered, and it has been decided that authority competent to sanction temporary transfer or leave shall give the following certificate to enable the Government servant to draw Border Road Construction allowance.

"CERTIFIED that Shri .... has remained on temporary transfer or on leave from .... to .... (period) and has reported to or has been reposted to the post on which the said allowance is admissible. He is entitled to Border Road Construction Allowance for a period of from ....to.......... (period)."

[Finance Deptt. (Rules) memo. No. F. 1 (97) FD (Exp-Rules)/66, dated 4-3-1968.]

विषय:—राजस्थान सर्विसेज (कन्सेशन ओन बोरडर रोड कन्स्ट्रक्शन ओरगेनाईजेशन) नियम, 1967

राजस्थान सर्विसेज (कन्सेशन ओन बोरडर रोड कन्सट्रक्शन ओरगेनाईजेशन) नियम, 1967 के नियम 5 में बोरडर रोड कन्सट्रक्शन भत्ता दो माह तक अस्थाई स्थानान्तर या उपार्जित अवकाशके समय मिलता है। इस संबंध में यह स्पष्टीकरण किये जाने का निर्देश है कि यदि अस्थायी स्थानान्तर या उपार्जित अवकाश की अवधि दो माह से अधिक हो तो उक्त भत्ता केवल दो मास के लिये ही स्वीकृत किया जावेगा।

अस्थाई स्थानान्तर या उपार्जित अवकाश की अवधि में उक्त भत्ता सक्षम अधिकारी द्वारा नम्न प्रमाण-पत्र दिये जाने पर ही मिल सकेगा।

"प्रमाणित किया जाता है कि .... पद .... दिनांक ..... से दिनांक .... तक अस्थाई स्थानान्तर या उपार्जित अवकाश पर रहे, और तदोपरान्त इनकी नियुक्ति .... के पद पर हुई जिस पद पर बोर्डर रोड कन्सट्रक्शन भत्ता दिया जाता है।

क्रमांक एफ. 1(97) वि. वि. (व्यय.नियम) 66, दिनांक 4-3-1968

(23)

वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 2 (बी) (2) वित्त (व्यय-नियम)/ 67, I व II, दिनांक 2-3-67 द्वारा वतन श्रृंखला 9 और 10 में कनिष्ठ लिपिकों को दक्षता अवरोध पार करने तथा उच्चतर प्रारम्भिक वेतन का लाभ प्राप्त करने हेतु जो परीक्षा वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. 1 (51) वित्त (व्यय-नियम)/ 4-49, दिनांक 28-10-63 के अनुसार जिला एम्पलायमेन्ट एक्सचज कार्यालय द्वारा ली जाती थी अब यह परीक्षा नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी द्वारा ली जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावित होगा व इस आदेश मे पूर्व जो कर्मचारी परीक्षा नहीं दे सके है उनकी परीक्षा नियुक्ति कर्ता अधिकारी द्वारा ली जायेगी। भविष्य में जिला एम्पलायमेन्ट एक्सचेज कार्यालय द्वारा टंकण की यह परीक्षा नहीं ली जायेगी।

परीक्षा लेने संबंधी प्रणाली के आदेश व्यवस्था एवं पद्धति विभाग द्वारा प्रसारित किये जायेगें।

[वित्त विभाग (नियम) आदेश क्रमांक एफ. 2 (बी) वित्त (व्यय-नियन) ।67-1, दिनांक 28-3-68]

---

(24)

In this Department Notification No. F. 2 (b) (9) FD (E-R)/63-II, dated 14-4-1964, the figures "200/-" and "150/-" appearing against item (a) and (b) shall be substituted by figures "400/-" and "350/-" respectively.

The amendment shall be deemed to have come into force with effect from 1-1-1964.

[F. D. Notification No. F. 2 (b) (77) FD. (E-R) 67-II, dated 20-3-68.]

---

(25)

विषयः—राजपत्रित अधिकारियों द्वारा डेथ-कम-रिटायरमेन्ट-ग्रेज्यूएटी के लिये नामांकन-पत्र

राजस्थान सेवा नियम के नियम 260 (2) और (8) के अनुसार समस्त स्थायी राजपत्रित अधिकारियों को जिनकी सेवा अवधि पांच साल हो चुकी है डेथ-काम-रिटायरमेन्ट-ग्रेज्यूएटी के लिये नामांकन-पत्र महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को भेजना चाहिये। परन्तु महालेखाकार राजस्थान इस विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि बहुत से राजपत्रित अधिकारियों ने नामांकन-पत्र नहीं भेजे हैं। अतः आपके विभाग में नियुक्त समस्त स्थाई राजपत्रित अधिकारियों को जिनका सेवा काल 5 वर्ष हो चुका है कृपया सूचित करदें कि वे 30-4-68 तक उपरोक्त नामांकन पत्र महालेखाकार कार्यालय में भेज दें।

जो कार्यवाही इस विषय में की जावे उसकी सूचना शीघ्र ही महालेखाकार, राजस्थान व इस विभाग को भेजने की कृपा करें।

[वित्त विभाग (नियम) ज्ञापन क्रमांक प. 1 (8) वित्त (नियम) 68, दिनांक 29-3-68]

(26)

SUB.—Recovery of Loans/Advances from the Government servants retiring after 1-7-1967.

According to para 3 (XVI) of the Finance Department Order No. F. 1 (42) FD (Exp-Rules)/67-II, dated 13-6-1967 Loans/Advances and the interest thereon outstanding against the Government Servants retired on 1-7-1967 is to be recovered in suitable monthly instalments from pension payable up to the month preceding the month in which the Government Servant could have retired on attaining the age of 58 years. The Governor has been pleased to order that in the case of Government Servants retiring after 1st July, 1967 the recovery of outstanding Loans/Advances and the interest thereon should be made as indicated below:—

(*a*) In the case of Government servants retiring up to 30-6-1968, the recovery of Loans/Advances and the interest thereon be made from their pension and the entire amount be recovered up to the month preceding the month in which they attain the age of 58 years.

(*b*) In the case of Government Servants retiring after 30-6-1968, the instalments should be re-calculated so as to effect recovery of the entire amount before the date of retirement.

(*c*) Cases already decided otherwise need not be re-opened.

[F. D. Memo No. F. 1 (42) F. D. (E-R) 67, dated 25-3-68.]

---

(27)

SUBJECT.—Grant of honorarium—Rajasthan Service Rules—Volume II.

Attention is invited to S. No. 10 in Appendix IX of Rajasthan Service Rules Volume II (as amended vide Finance Department Order No. F. 1 (37) FD (Exp-Rules)/67 dated 19-5-1967) under which powers to grant honorarium to non-gazetted Government servants have been delegated to Heads of Departments subject to conditions mentioned in the aforesaid order.

2. With a view to facilitating proper verification by audit while checking the entitlements as given in the sanctions of honorarium, it has been decided that a suitable record of permanent nature showing the following particulars should be maintained by all Drawing/Disbursing Officers.

3. It is therefore enjoined upon all Drawing/Disbursing Officers that they should maintain a register named "REGISTER OF SANCTION/PAYMENT OF HONORARIUM UNDER ITEM 10 APPENDIX OF RAJASTHAN SERVICE RULES VOLUME II", in the following *pro-*

forma in their respective offices with immediate effect, to be provided to Audit parties on demand:—

S.No.	Name of the incumbent	Particulars of work of occasional character/ special merit.	No. of hours of extra work.
1	2	3	4

Period during which extra work performed			Reference to No. & date of sanction of competent authority.	Amount payable.
Date	Time			
	From	To		
5	6	7	8	9

Signature of Head of Office	Reference to Bill No. & date with Vr. No. & date of payment.	Signature of Head of Office	Remarks
10	11	12	13

[F.D. (Rules) Deptt. Memo. No. F. 1 (37) F.D.(E-R)/67, dated 2-3-68.]

---

(28)

विषय—मंहगाई भत्ता

वित्त विभाग आदेश संख्या एफ. 1 (64) एफ.डी. (एक्सपें.-रूल्स)/ 67, दिनांक 26 अक्टूबर, 1967 के अनुच्छेद 3 में यह उल्लेख है कि फरवरी, 67 से सितम्बर, 67 तक की अवधि में महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई राशि का भुगतान नकद म न किया जाकर कर्मचारियों के संबंधित सामान्य प्रावधिक निधि लेखा में जमा किया जावे। इसी प्रकार जो कर्मचारी सामान्य प्रावधिक निधि के सदस्य नहीं हैं उनके लेखा खोले जाकर उपर्युक्त राशि सामान्य प्रावधिक निधि में जमा की जायेगी। इस मामले में पुनः विचार किया जाकर राज्यपाल महोदय उपरोक्त आदेश के अनुच्छेद 3 में वर्णित प्रावधानों मे आंशिक परिवर्तन करते हुए आदेश प्रदान

करते हैं कि महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई राशि सामान्य प्रावधिक निधि में जमा नहीं की जाकर निम्न-लिखित मद में जमा की जावे :—

घा-अनिधि वद् ऋण

अन्य लेखे—

क—राज्य सरकार की बीमा निधि

महंगाई भत्ते बकाया निक्षेप-आय

2. उपरोक्त आदेश को क्रियान्वित करने हेतु संबंधित आहरण व राशि वितरण अधिकारी (ड्राइंग व डिसबर्सिंग आफिसर) महंगाई भत्ते के बिल तैयार करके संबंधित कोषागारों को इसी वित्तीय वर्ष में भेजेंगे। यह रकम वास्तव में प्राप्त न की जाकर उपरोक्त अनुच्छेद 1 में वर्णित मद में जमा (By book adjustment)की जावेगी।

3. (अ) संबंधित आहरण व राशि वितरण अधिकारी महंगाई भत्ते के बिल को कोषागारों में भेजने के पूर्व संलग्न फार्म की पूर्ति करेंगे व इसकी प्रतियां तैयार करेंगे। एक प्रति बिल के साथ कोषागारों को भेजेंगे व दूसरी प्रति कार्यालय में रखेंगे।

(ब) उपरोक्त (अ) के आधार पर संबंधित आहरण एवं राशि वितरण अधिकारी संलग्न फार्म संख्या 2 की पंजिका तैयार करेंगे और उसमें प्रत्येक कर्मचारी का लेखा रखा जावेगा।

4. राजपत्रित अधिकारी जो स्वयं अपने वेतन इत्यादि के बिल तैयार कर रकम प्राप्त करते हैं उनके बारे में महालेखाकार संबंधित अधिकारियों को पे-स्लिप जारी करेंगे व इसके आधार पर संबंधित अधिकारी अपना बिल तैयार करेंगे और संलग्न फार्म नं. 1 की पूर्ति करेंगे व इसकी 3 प्रतियां तैयार करेंगे। कोषाधिकारी इन प्रतियों में से एक संबंधित अधिकारी को ट्रेजरी वाउचर अंकित कर वापस करेंगे व दूसरी महालेखाकार को भेज देंगे। तीसरी प्रति कोषागार में रहेगी। राजपत्रित अधिकारियों को नकद राशि न दी जाकर इसका जमा-खर्च कोषाधिकारी उपरोक्त बजट मद में स्वयं करेंगे व फार्म 2 की पंजिका में लेखा रखेंगे। महंगाई भत्ते की राशि का जमा-खर्च चालू वित्तीय वर्ष में किया जावेगा।

5. उपरोक्त महंगाई भत्ते की राशि को चुकारा किये जाने के बारे में अलग से आदेश प्रसारित किये जावेंगे।

[वित्त विभाग (नियम) आदेश क्रमांक एफ. 1 (64) वित्त (नियम) 67, दिनांक 13-3-68]

फार्म 1

माह फरवरी, 67 से सितम्बर, 67 तक के बकाया मंहगाई भत्ते की राशि के जमा / चुकारे का विवरण-वित्त विभाग आदेश संख्या एफ 1(64) एफ. डी. (एक्सपें-रूल्स)।67, दिनांक 26 अक्टूबर, 1967

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी	पद	जमा का विवरण		विशेष विवरण
			रकम	ट्रेजरी वाउचर नं.	
1	2	3	4	5	6

हस्ताक्षर आहरण एवं राशि वितरण अधिकारी
पद
दिनांक

फार्म 2

माह फरवरी, 67 से सितम्बर, 67 तक के बकाया मंहगाई भत्ते की राशि के जमा / चुकारे का विवरण-वित्त विभाग आदेश सं. एफ. 1(64) एफ.डी (एक्सपें.-रूल्स) 67, दिनांक 26 अक्टूबर, 1967

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी	पद	जमा का विवरण	
			रकम	ट्रेजरी वाउचर नम्बर
1	2	3	4	5

चुकारा किये जाने का विवरण

प्रथम किश्त यानी 1-10-69 को चुकाये जाने वाली राशि

मूलधन	ब्याज	योग	रकम प्राप्त करने का ट्रेजरी वाउचर नं.	तारीख चुकारा मय तसदीक अफसर
6	7	8	9	10

द्वितीय किश्त यानी 1-10-7 को दी जाने वाली राशि

मूलधन	ब्याज	योग	रकम प्राप्त करने का ट्रेजरी वाउचर नम्बर	तारीख चुकारा मय तसदीक अफसर	विशेष विवरण
11	12	13	14	15	16

(29)

SUBJECT:—Grant of dearness allowance to Government Servants entitled to concessions of free board & lodging.

Instead of the rates of dearness allowance sanctioned in Finance Department Order No. F. 1 (15) FD (E-R)/67 dated 29-4-67 and No. F. 1 (15) FD (Exp-Rules)/67 dated 24-11-67 the Governor has been pleased to order that Nursing Staff of Government Hospitals who entitled to free board (or messing allowance in lieu thereof) and free lodging as a condition of their appointment and who are drawing pay in the Revised Scales of Pay (as amended from time to time) may be allowed Dearness Allowance with effect from 1-11-1967 at the rates indicated below:—

Pay per month	Rate of dearness allowance per month w. e. f. 1-11-67.
	Rs.
Below Rs. 110/-	40/-
Rs. 110/- & above but below Rs. 150/-	66/-
Rs. 150/- & above but below Rs. 210/-	79/-
Rs. 210/- & above but below Rs. 400/-	102/-
Rs. 400/ & above but below Rs. 450/-	115/-
Rs. 450/- & above but upto Rs. 499/-	118/-
Above Rs. 499/- but below Rs. 532/-	Amount by which Pay falls short of Rs. 617/-
Rs. 532/ & above but upto Rs. 540/-	85/-

(F. D. Order No. F. 1 (15) F. D. (E-R)/67. dated 13-3-68)

विषय:—निःशुल्क भोजन एवं निवास की रियायत प्राप्त करने के हक प्राप्त राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के आदेश सं. एफ. 1 (15) वित्त विभाग (व्यय-नियम) 67, दिनांक 29-4-67 एवं सं. एफ 1 (15) वित्त विभाग (व्यय-नियम) 67, दिनांक 24-11-67 में स्वीकृत किए गए मंहगाई भत्ते की दरों के स्थान पर राज्यपाल ने आदेश दिया है कि राजकीय अस्पतालों के उपचर्या कर्मचारीगण (नर्सिंग स्टाफ को, जो कि निःशुल्क भोजन (या निःशुल्क भोजन के बदले भोजन भत्ता) एवं निःशुल्क निवास की सुविधा, अपनी नियुक्ति की शर्तों के रूप में, प्राप्त करने के हकदार है एवं जो (समय समय पर यथा संशोधित) परिशोधित वेतन मान में [illegible]

वेतन प्राप्त कर रहे हैं, दिनांक 1-11-67 से मंहगाई भत्ता निम्न निर्दिष्ट दरों पर स्वीकृत किया जाएगा:—

वेतन प्रति माह	दिनांक 1-11-67 से प्रति माह भत्ते की दर
	रु.
110 रु. से नीचे	40 -
110 रु. एवं इससे अधिक लेकिन 150 रु. से कम	66/-
150 रु. एवं इससे अधिक लेकिन 210 रु. से कम	79/-
210 रु. एवं इससे अधिक लेकिन 400 रु. से कम	102/-
400 रु. एवं इससे अधिक लेकिन 450 रु. से कम	115/-
450 रु. एवं इससे अधिक लेकिन 499 रु. तक	118/-
499 रु. के ऊपर लेकिन 532 रु. से कम	वह धनराशि जो 617 रु. के वेतन से कम पड़ती हो ।
532 रु. एवं इससे अधिक लेकिन 540 रु. तक	85/-

(30)

विषय:—बकाया मंहगाई भत्ते का लेखा ।

वित्त विभाग के आदेश सं. एफ. 1 (64) वित्त (नियम) 67, दिनांक 13-3-68 द्वारा यह आदेश प्रसारित किये गये हैं कि फरवरी 67 से सितम्बर 67 तक की अवधि में मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गई धन राशि के नगद में भुगतान न की जाकर "ब -अनिनि वद् ऋण-अन्य लेखे-राज्य सरकार की बीमा निधि-मंहगाई भत्ते की बकाया निक्षेप–आय" के मद में जमा (By book adjustment) की जायगी ।

2. कोषाधिकारी उपरोक्त मद के शिड्यूल की एक प्रति अधिक तैयार करेंगे जो निदेशक, राज्य बीमा विभाग को भेजी जायगी ।

3. बिलों के साथ संलग्न फार्म 1 (जिसमें कि कर्मचारी-वाइज मंहगाई भत्ते की धन राशि का विवरण अंकित होगा) अलग किये जाकर "ब अनिनि वद् ऋण-अन्य लेखे-क-राज्य सरकार की बीमा निधि-मंहगाई भत्ते की बकाया-आय" के शिड्यूल के साथ संलग्न किये जाकर महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किये जावेंगे ।

4. निदेशक, राज्य बीमा विभाग के कार्यालय में कोषाधिकारियों से प्राप्त शिड्यूलों की सहायता से, इस मद का मिलान (reconciliation) किया जायगा तथा मिलान करने पर यदि कोई त्रुटि पाई जावे तो राज्य बीमा विभाग सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचित करेगा

या सम्बन्वित विभाग त्रुटि का निवारण नियमानुसार कोषाधिकारी के द्वारा महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को लिखकर करेंगे ।

(वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ. 1 (64) वित्त (नियम)/ 67, दिनांक 30-3-1968)

(31)

SUB — Fixation of Pay of Officers on posts encadred in the Rajasthan Medical Services (Collegiate Branch).

In this Department Order No. F. 2 (b) (34) FD (E-R)/66-3, dated 23-1-1967 the method of pay fixation inserted vide Finance Department order of even number dated 9-1-1968 appearing against item No. (ix) shall be numbered as (a) and the following shall be inserted as number (b) and shall be deemed to have been inserted from the date of issue of the aforesaid order:—

"(b) In respect of Senior Specialists appointed to work as Clinical Professors or Additional Professors on or after 1-1-1964 but not appointed to the Collegiate Branch by direct recruitment, pay in the Scale No. 32 prescribed for the post of Professor under Finance Department order No. F. 2 (b) (9) FD (E-R)/63-II, dated 19-12-1963 and Scale No. 32-A prescribed with effect from 1-4-1966 vide Finance Department Notification No. F. 2 (b) (34) FD (E-R)/66-I, dated 16-6-1966 (item XI of para 6 pertaining to Medical & Health Services (Collegiate Branch), shall be fixed by application of Rule 26-A of Rajasthan Service Rules and where pay so fixed under Rule 26-A of Rajasthan Service Rules is less than the pay plus special pay granted for teaching work the difference shall be allowed as personal pay which shall not absorb in future increments."

(*F. D. Order No. F.* 2 (*b*) (77) *F. D* (*E-R*)/67-*III dated* 20-3-68)

(32)

SUB —Revision of pay scales of teaching staff of Medical Colleges.

In this Department order No. F. 2 (b) (9) FD (E-R)/63, dated 18-1-1965 the following addition, alteration and amendment shall be made:—

(*a*) the word "other than persons appointed as clinical Professor" shall be added after the words "clinical teachers" appearing in sub-para (ii) of para 1—Fixation of pay in the new pay scales.

(*b*) the following shall be added as sub-para (iii) below sub-para (ii) of para I Fixation of pay in the new pay scales,

(*iii*) in respect of persons appointed as clinical Professors, the pay in the scale of a Professor shall be fixed by application of Rule 26-A of Rajasthan Service Rules and where pay so

fixed is less than the pay plus special pay the difference shall be allowed as personal pay which shall not absorb in future increments.

The above addition/alteration/amendment shall be deemed to have come into force with effect from 1st January, 1964.

(*F. D. Order No. F.* 2 (*b*) (77) *F. D.* (*E-R*)/67-*I*, *dated* 20-3-68.)

---

(33)

विषयः—राजस्थान सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) नियम, 1961—दिनांक 1-4-66 को यथासंशोधित अनुसूची II-भाग 4-राजस्थान लेखा सेवा अधिकारी प्रशिक्षणालय।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) नियम, 1961 में अग्रिम संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. ये नियम राजस्थान सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) संशोधन नियम, 1967 कहलायेंगे ।

2. ये दिनांक 19-5-65 से प्रभाव में आए हुए समझे जाएंगे ।

3. राजस्थान सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) अनुसुची(*ii*)विभाग 4 में—

(1) 'राजस्थान लेखा सेवा' शीर्ष के अन्तर्गत शब्द के रूप में पदस्थापित साधारण समय मान में 'अधिकारी' के पूर्व परन्तु 'अधिकारी प्रशिक्षणालय' में, शब्द के बाद 'वरिष्ठ प्रशिक्षक' के स्थान पर "अध्यापक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा । देखिए वित विभाग की अधिसुचना सं. एफ. 2 (ख) (34) (एफ. डी.) (व्यय-नियम)/66-1, दिनांक 16-6-66 (राज-पत्र असाधारण दिनांक 30-6-66 के पृष्ठ सं. 198) का मद संख्या एफ (*ii*)

(2) 'अधिनस्थ लेखा सेवा' शीर्ष के अन्तर्गत 'अवर प्रशिक्षक' के स्थान पर 'अवर प्राध्यापक' शब्द प्रतिस्थापित किया जायगा । देखिये उपर्युक्त (1) में वर्णित वित्त विभाग की अधिसूचना (राज-पत्र असाधारण दिनांक 30-6-66 के पृष्ठ सं. 199) का परिच्छेद संख्या एफ. (*iii*) (ख) ।

[वित्त विभाग (नियम) अधिसूचना क्रमांक एफ. 2 (बी) (34) वित्त विभाग (नियम) 66, दिनांक 20-3-1968 ।]

---

(34)

विषय :—राजस्थान सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) नियम, 1961 दिनांक 1-4-66 को यथा संशोधित अनुसूच. 2 भाग 4 राजस्थान न्यायिक सेवा-सहायक विधि प्रारूपकार आदि ।

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 2 (बी) (26) वित्त (व्यय-नियम)/67 दिनांक 15 फरवरी, 1968 के अनुच्छेद 3 की आठवीं पंक्ति में पीरीयड 'period 22-5-67' के स्थान पर 'पीरीयड 'period 1-4-66' पढ़ा जावे ।

[वित्त विभाग (नियम) शुद्धि-पत्र-क्रमांक एफ. 2(बी) (26) एफ. डी. (व्यय-नियम)/ 67, दिनांक 25-3-1968]

---

(35)

विषय—राजस्थान सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) नियम 1961 अनुसूचि 3 वेतन मान संख्या 9 ।

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 2 (21) (एफ. डी. (ई-आर)/67-11, दिनांक 2-3-67 के अनुच्छेद 3(1) (1) की चौथी पंक्ति में "District Employment Exchange" के स्थान पर "Appointing authorities" तथा नोट 2 व 3 की दूसरी पंक्ति में "District Employment Exchange" तथा "Employment Exchanges" के स्थान पर "Appointing authorities" शब्द पढ़ा जावे ।

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 2 (बी) (21) एफ. डी. (ई-आर)/67-1 दिनांक 2-3-67 के अनुच्छेद 3(बी) के तीसरी पंक्ति में "District Employment, Exchange" के स्थान पर "Appointing authorities" पढ़ा जावें ।

यह शुद्धि दिनांक 28-3-68 से प्रभावित मानी जावेगी ।

(वित्त विभाग (नियम) शुद्धि-पत्र क्रमांक एफ. 2 (बी) (21) वित्त विभाग (व्यय-नियम)/67-11, दिनांक 20-3-67 ।)

---

(36)

SUB;—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—as amended on 1-4-1966—Schedule II—Part 4—Rajasthan Accounts Service—Officers Training School.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely:—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1967.

2. They shall be deemed to have come into force with effect from 19-5-1965.

3. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule II-Part 4—

   (*i*) Under heading "Rajasthan Accounts Service" the words "Lecturer" shall be substituted in place of words "Senior Instructor" appearing after the words "Officer in ordinary time scale posted as" but before "in Officers Training School" vide item F (ii) of Finance Department Notification No. F. 2 (b) (34) FD (E-R)/66-I, dated 16-6-1966 (page 198 of the Gazette—Extraordinary dated 30-6-1966).

   (*ii*) Under heading Rajasthan Subordinate Accounts Service the words "Junior Lecturer" shall be substituted in place of "Junior Instructor" vide para F (iii) (b) of Finance Department Notification cited in (i) above (page 199 of the Gazette—Extraordinary dated 30-6-1966).

[*F. D. Noti. No. F.* 2 (*b*) (34) *F. D.* (*E-R*)/66, *dated* 20-3-68].

---

(37)

SUBJECT.—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule III—Scale No. 10.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely:—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1st January, 1967.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule III—Scale No. 10 the instruction No. 3 para (iv) inserted vide Finance Department Notifcation No. F. 2 (b) (21) FD (E-R)/67-I. dated 2nd March, 1967 shall be substituted by the following:—

"(iv) In case of Lower Division Clerks who have reached the stage of Rs. 98/-, 102/-, 106/-,110/-, 115/-, 120 and 125/- before 1-1-67, the EB shall operate at the stage of 115/-, 120/-, 125/- 130/-, 135/-, 145/- and 150/- respectively and shall be crossed in the manner prescribed in (i) above."

[*F. D.* (*Rules*) *Deptt. Noti. No. F.* 2 (b) (21) *F. D.* (*E-R*)/67-I, *dated* 5-3 68]

(38)

SUBJECT.—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—as amended on 1-4-66—Patwaries of Colonisation/Irrigation.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further, the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely:—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1967.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1-4-66.

(3) In the Ra asthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule I—Section D—the entries for the "Patwari" under heading (i) Colonisation inserted vide Finance Department Notification No. F. 1 (51)/FD (A)/R/67-IV, dated 1-7-63 and (ii) sub-heading "Public Works (Irrigation) of the head Public Works (Irrigation) & (B & R)" page 97) shall be substituted and deemed to have been substituted by the following:—

		Revised pay scale from 1-9-61 to 31-3-67	Amended Rev. Pay scale from 1-4-66	Remarks
Patwari	40-1-50-2-60			
		65-1-70-2-90 (3)	75-3-105-111-3-120-5-130-SB-& 140-5-150.	Pay in this scale shall be admissible to a person appointed on or after 1-4-66 only if he is a Matriculate.

(4) In Schedule III—Scale No. 5—the following new instructions shall be inserted below the entries "for Amins" inserted vide Finance Department Notification No. F. 2 (b) (3)/FD (Exp)/67, dated 4-5-67.

"for Patwaries of Colonisation/Irrigation Department"

(VI) (1) The initial pay of Rs. 90/- shall be admissible to a Patwari of Colonisation/Irrigation department as under:—

(*i*) Existing Personnel who were in service immediately before 1-4-66 and who are matriculates and have either passed the Patwar Examination as prescribed in para 4 of the Rajasthan Land Revenue (Land Records Rules) or successfully completed Departmental training or have been exempted for such examination/training under the provisions of aforesaid rules or orders of Government.

(*ii*) Fresh recruits who are matriculate and have passed Patwar Examination/departmental training prescribed.

(2) Existing non-matriculate Patwaries who are trained or have been exempted from training under the relevant rules/orders of Govt./ or the provisions of Rajasthan Land Revenue (Land Records Rules) and have put in at least 5 years service as a Patwari and whose pay on fixation comes to less than Rs. 90/- may be given higher initial pay at the rate of 'one' increment in the Amendment Revised Pay Scale of the post for every 5 years completed years of service as a Patwari or equivalent post, subject to the condition that the number of such increments shall not be more than three and the initial pay shall not exceed Rs. 90/-.

(5) The fixation of pay shall be made in accordance with the provision of Rule 14 of the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, vide Finance Department Notification No. F. 2 (b) (34) /FD/ER/66, dated 5-4-67 and according to the columns of table number 5 indicating fixation of Amins of Settlement Department vide Notification of even number dated 12-1-68.

(6) In the Finance Department Notification No. 2 (b) (34) FD. ER/66 dated 12-1-68 the words within bracket '(a)' shall be added in line 1 of para 4 (i) (a), before the words "Amins of Settlement Department. The words and figures "and (b) Patwaries of the Colonisation and Irrigation Department" shall be added after the words and figures "dated 5-4-1967" after deleting full stop (.)".

(7) "The words Patwaries of the Colonisation and the Irrigation Department" sha inserted in Table 5 in between the words "dated 5-4-1967" and "effective from 1-4-1966".

(F. D. Noti. No. F. 2 (b) (2) F. D. (R) 68, dated 1-3-68.)

(39)

Subject.—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules 1961-Sheep & Wool Department.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan, hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely :—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968. –
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 1966 or from the date the posts are created which ever is later.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961 Schedule I-Section B-other State Service Officers in various departments-the following entries along with sub-heading "Sheep & Wool Department" shall be inserted .—

1	2	3	4	5
Sheep & Wool Department				
(1) Joint Director	New		900-50-1500-with minimum of Rs. 1050/- (32)	The post will continue as long as the post of Director of Sheep & Wool is not held by a whole time officer.
2) Deputy Director	500-30-800-50-900.	550-30-820-EB-30-850-50-950 (28)	550-30-820-EB-30-850-50-1100 with minimum pay of Rs. 640/- (29)	
(3) Assistant Director (if not held by R. A. S. Officer)	New	225-20-285-25-435-EB-25-560-30-800 (25)	360-25-560-30-590-EB-30-860-900 with minimum pay of Rs. 385/- (27)	This scale will be admissible to;— (a) Persons who are substantively holding any of these posts in Sheep & Wool Department and who continue
(4) District Sheep & Wool Officer	New			
(5) Wool Grading Officer	New			

(6)	Principal, Sheep & Wool Training Institute	New			to hold them substantively or officiate on higher post enumerated herein.
(7)	Lecturer in Sheering Sheep & Wool Training Institute	New			(b) Officers of the Rajasthan Animal Husbandry Service posted in Sheep & Wool Department.
(8)	Artificial Insemination Officer	New			
(9)	Laboratory Officer	250-25-600			
(10)	Sr. Superintendents of Sheep Breeding Farms, (Jobar Beer, Jaipur, Kodam Desar, Pokaran)	New			(c) The posts in this scale shall be 24 only.
(11)	Sheep & Wool Extension Officer, Jr. Superintendents Sheep Breeding Farms (Mandore, Chittorgarh) and other equivalent posts.	New	225-20-285-25-435-EB-25-560 30-800 (35)	225-20-285-25-435-EB-25-560-30-800 (25)	The officers of the Rajasthan Animal Husbandry Service posted in Sheep and Wool Department shall be eligible to draw pay in this scale.

(F. D. Noti. No. F. 2 (b) (5) F. D. (R)/68, dated 5-3-68.)

(40)

Sub:—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961-Amendment thereto-Schedule II-Section D-Agriculture Department-Subordinate Agriculture Service.

In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely:—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1-3-1967.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961-Schedule I-Section D-Agriculture Department (Page 41).

(*i*) The following posts appearing in column I under sub-heading "Posts in Subordinate Agriculture Service (this scale is admissible only to Graduate in Agriculture) viz.:—"(page 41) shall be deleted.

Farm Manager.
Agriculture Extension Officer.
Agriculture Assistant.
Plant Protection Assistant.
Horticulture Assistant.
Food Assistant.
Plant Protection Supervisor.
Rat Menace Control Officer.
Planning Assistant.
Soil Conservation Assistant.

(*ii*) under sub-heading "subordinate posts if not held by Graduate in Agriculture".

(*a*) the following posts appearing in column I having pay Scale No. 14 shall be deleted —
"Horticulture Assistant Marketing Inspector"

(*b*) the following posts inserted vide Finance Department Notification No. F. 2 (b) (2) FD (E-R)/65, dated 22-4-1965 alongwith entries in column 2, 3 and 4 shall be deleted.

	2	3	4
"Agriculture Extension Officer Farm Manager }	110-5-135-10-225.	130-5-155-10-235-250	(14)

(*c*) the following posts appearing in column No. 1 and are bracketted with pay scale No. 11 shall be deleted:—

Agriculture Assistant.
Food Assistant.
Plant Protection Supervisor.
Rat Menace Control Inspector.

(*iii*) The following new entries alongwith the sub-heading "Posts in Subordinate Agriculture Service" shall be inserted:—

		2	3	4	
1.	Agriculture Extension Officer	(150-10-250-12½-350) (110-5-135-10-225)	155-10-285-15-435-25-485	(20)	The higher initial pay of Rs. 175/- will be allowed to Graduate in Agriculture freshly recruited Future recruitment shall be restricted to Agricultural Graduates.
2.	Agriculture Assistant who is Agricultural Graduate	150-10-250-12½-350			
	Food Assistant who is Agricultural Graduate	150-10-250-12½-350			
	Plant Protection Assistant	150-10-250-12½-350			
	Plant Protection Supervisor who is Agricultural Graduate	150-10-250-12½-350			
	Rat Menace Control Officer	150-10-250-12½-350			
	Horticulture Assistant	150-10-250-12½-350 (110-5-135-10-225)			
	Soil Conservation Assistant	150-10-250-12½-350			
	Planning Assistant	150-10-250-12½-350			
	Farm Manager	(150-10-250-12½-350) (110-5-135-10-225)			
	Marketing Inspector	110-5-135-10-225			
	Agriculture Assistant who is not Agricultural Graduate	80-5-175	105-5-155-166-8-190 200-SB-220-10-240	(11)	
	Food Assistant who is not Agricultural Graduate				
	Plant Protection Supervisor who is not Agricultural Graduate				
	Rat Menace Control Inspector				

[F. D. (Rules) Noti. No. F. 2 (b) (89) F. D. (E-R) 67, dated 5-3-68.]

(41)

Sub.—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Amendment thereto—Schedule I—Sect. D—Archives Department—Senior Technical Assistant.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely.—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

(2) These shall be deemed to have come into force w. e. f. 1-3-1963.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, Schedule I—Section D-"Archives" (Page 64) the following entries may be inserted—

1 Post	Rationalised Pay scale	Revised Pay scale from 1-9-61 to 31-3-66	Amended revised pay scale from 1-4-66	Qualifications.
Senior Technical Assistant	-	170-10-310-12-1/2-385 (18)	170-10-270 290-10-310-12-1/2-347-1/2-SB-375-12-1/2-400 (18)	(*i*) B. A. with Kamil in Persian or Persian Degree equivalent to B.A. or B. A. with Sahitya Ratna or Acharya with knowledge of Rajasthani & 2 years experience in Research or Editing. *OR* (*ii*) M. A. in Persian or M. A. in Hindi with knowledge of Rajasthani language *OR* (*iii*) Matriculate with 10 years experience of deciphering and translation of old P r-sian and Rajasthani documents.

[F. D. (Rules) Noti. No. F. 2 (b) (3) F. D. (E-R) 68, dated 5-3-68.]

(42)

Subject.—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule B—Election Department.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely:—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

2. They shall be deemed to have come into force with effect from 29-11-67 or from the date it is filled in whichever is later.

3. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule I—Section B—under heading other State Services offices in various department—Election Department—(page 28) the following new entries shall be inserted·—

1	2	3	4	5
Assistant Chief Electoral Officer-cum-Asstt. Director.	New	225-15-270-20-390-25-640	(23)	The existing post of Chief Election Supervisor in Scale No. 19 appearing in Schedule-D-under heading Election Deptt. (page 67) shall be held in abeyance. *Qualifications* : Graduate with at least 10 years experience of Election work (relating to Assembly, Parliament, Panchayat and Municipal Election) on responsible Gazetted Post.

[F. D. (Rules) Noti. No. F. 2 (b) (8) F. D. (Rules) 68, dated 5-3-68.]

(43)

Sub.—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Bifercation of Medical & Collegiate Service—Special pay to them.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961.

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules. 1968.

2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1-4-1966.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule II-Part 4-remarks appearing against Serial No. 1, 2 & 3 inserted vide Finance Department Notification No. F. 2 (b) (18) FD (E-R)/65, dated 8th November, 1966 shall be deleted.

[F. D. Notification No. 2(b) (77) FD (E-R) 67/IV, dated 20-3-68.]

---

(44)

राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष यह निर्देश जारी किये जाते रहे हैं कि वित्तीय वर्ष के आखरी दिनों में असाधारण खर्च न किया जाय। इस संबंध में वित्त (लेखा एवं विनियोजन शाखा-1) विभाग से जारी किये गये आदेश संख्या 5(4) (ले. वि.)।66 दिनांक 8-3-68 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

इस बार 31-3-68 को इतवार होने के कारण वित्तीय वर्ष का आखरी कार्य दिवस (वर्किंग डे) शनिवार दिनांक 30-3-68 है। इसलिये महालेखापाल राजस्थान ने आग्रह किया है कि वे तमाम स्वीकृतियां जिनके आधार पर उनके कार्यालय से पेमेन्ट आथेरिटीज (Payment authorities) जारी करनी है उनके यहां 26-3-68 तक अवश्य पहुंच जानी चाहिये ताकि उन पर चालू वित्तीय वर्ष में कार्यवाही की जा सके।

अतः अनुरोध किया जाता है कि ऐसी समस्त स्वीकृतियाँ महालेखापाल के कार्यालय में उक्त तिथि तक अवश्य पहुंचा दी जाय। यदि विशेष परिस्थिति म कोई स्वीकृति 27 मार्च और 30 मार्च के दरमियान जारी की जाय तो उसे महालेखापाल के यहाँ कार्यालय समय मे हाथों हाथ पहुंचाने की व्यवस्था की जाय ताकि उसी दिन आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

[वित्त (व्यय-3) विभाग आदेश क्रमांक एफ. 3 (36)।वित्त।व्यय-3।68, दिनांक 21-3-1968.]

---

(45)

Subject:—Opening of a full fledged Public Debt Office at Jaipur.

I am directed to enclose a copy of letter No. C. O. Dt. Admn. 3-66/67-5161 dated the 27th February, 1968, alongwith copies of enclosures, received from the Reserve Bank of India, Central Office, Central Debt Section, Bombay-1, for information and necessary action. It is requested that necessary instructions may kindly be issued to all Treasury/Sub-Treasury Officers, and all concerned as contemplated by the Reserve Bank of India, in the aforesaid communication, under intimation to this department.

As regards the issue of a Press Communique on the lines of the draft proposed by the Reserve Bank of India, action is being taken separately by this Department.

[F. D. (Wage & Means Section) Letter No. F. 1 (1) F. W. M./68, dated 4-3-68.]

RESERVE BANK OF INDIA CENTRAL OFFICE,
CENTRAL DEBT SECTION, BOMBAY NO. 1.

Post Box 406
27*th February*, 1968
8 *Phalguna*, 1889 (*Saka*).

No. C. O Dt. Admn. 3-66/67—5161.

IMMEDIATE

The Secretary to the
Government of Rajasthan,
Finance Department, Jaipur.

Dear Sir,

Opening of a full-fledged Public Debt Office at Jaipur.

As you are aware, our Public Debt Office at Jaipur performs limited functions at present. viz. issue and management of various Jagir and Zamindari Abolition Compensation Bonds of the Government of Rajasthan. It appears from our Jaipur Manager's as well as the Bank's Inspector's recent reports that volume of work pertaining to the issue and management of compensation bonds is declining. the flow of indents against which Public Debt Office issues compensation bonds is uneven and irregular and, in any case, the present receipt of indents is insufficient to keep the staff of the Pulic Debt Office, Jaipur, fully engaged. This, consequently, increases the cost of compensation bonds work which, under the present arrangements, is entirely borne by the State Government. In view of this and as a part of our policy to establish full-fledged Public Debt Offices in different parts of the country to cope with the increasing work of issue and management of the Public Debt of the Central and State Governments, it has been decided to enlarge the functions of the Public Debt Office at Jaipur and convert it into a full-fledged Public Debt Office *with effect from the 1st April*, 1968. As from that date, your Government will be charged only for the staff engaged for the issue and management of compensation bonds and other expenditure on proportionate basis. Our detailed proposals in this regard will be sent to you separately.

2. As from the appointed date, i. e. 1st April, 1968, our Public Debt Office, Jaipur, will perform the following functions.—

(*i*) It will act as the parent Public Debt Office for all Rajasthan Government loans,

(*ii*) It will act as a Local Public Debt Office for all loans of the Government of India enfaced for payment of interest/instalments at treasuries/sub-treasuries in Rajasthan, and

(iii) Government Promissory notes of other State Government loans will also be enfaceable at the Public Debt Office, Jaipur, vide Rule 9 of the Public Debt Rules, 1946.

However, so far as the Annuity Deposit Schemes are concerned, the State of Rajasthan will, for the present, continue to be under the jurisdiction of the Public Debt Office, New Delhi.

3. In the absence of proper accommodation for opening full fledged Banking Department of the Bank at Jaipur, it is not possible at this stage, to set up a Public Accounts Department at that centre and the cash work of the Public Debt Office, Jaipur will, therefore, continue to be handled by the local branch of the State Bank of Bikaner and Jaipur. Consequently, the existing arrangements for receipt of new loan applications will continue i. e. the State Bank of Bikaner and Jaipur, Jaipur. will continue to receive applications for all future loans of the Government of Rajasthan and the Government of India (including applications for 4-1/2% Defence Deposit Certificates and 15-year Annuity Certificates). In addition to this. the State Bank of Bikaner and Jaipur, Jaipur will also be authorised, as a special case. to receive applications to the new loans to be floated, in future, by other State Governments. Under this arrangement, payment of interest on the securities of the Central and State Governments will be made by the Public Debt Office, Jaipur, by means of warrants drawn payable on the local branch of the State Bank of Bikaner and Jaipur, which will, as usual, make payment by initial debit to the account of your Government; the debit being eventually adjusted by the concerned Accountants General through Inter-State Suspense Account. Necessary instructions in this behalf may please be issued to the Accountant General, Rajasthan, under advice to us at an early date.

4. The transfer of loan balance from the books of the Public Debt Office, New Delhi, to that of the Public Debt Office. Jaipur. will take place gradually. At present all the securities of Rajasthan and Central Governments, interest on which is payable at Jaipur and other treasuries/sub-treasuries in Rajasthan are carried on the books of the Public Debt Office, New Delhi. These balances will continue to remain in the books of the Public Debt Office, New Delhi, for the present. The Public Debt Office, Jaipur, will take these securities on its books as and when these are presented for change of enfacement, renewal, etc. The exact procedure which will be followed in this behalf is detailed in the enclosed Memorandum of Procedure to be followed by the Public Debt Office, Jaipur and other Public Debt Offices.

5. After the opening of the full-fledged Public Debt Office at Jaipur, all paid interest/instalment warrants in respect of stock certificates, or securities held by the Public Debt Office in safe custody or securities enfaced at treasuries but presented to the Pubic Debt Office for drawal of interest will be sent to the Public Debt Office which issued the warrants. i.e. Public Debt Office, Jaipur or Public Debt Office, New Delhi, as the case may be. In case of other securities of Government of Rajasthan and Government of India (including Small Savings Securities, i.e. Defence Deposit Certificates. Treasury Savings Deposit Certificates and 15 Year Annuity Certificates) enfaced at treasuries/sub-treasuries in Rajasthan, the vouchers relating to payment of interest/instalments will have to be

sent as under.–

(a) In case of securities issued by the Public Debt Office, Jaipur (which will bear the prefix 'JP') to the Public Debt Office, Jaipur.

(b) In case of securities issued by the Public Debt Office, New Delhi (which bear the prefix 'DH') to the Public Debt Office, New Delhi.

However, as the Annuity Deposit work relating to Rajasthan area is not being transferred to Jaipur, all receipts in form 6 and form F and paid warrants relating to annuity payments will continue to be sent to the Public Debt Office, New Delhi.

Government may please issue suitable instructions to the Accountant General, Rajasthan, under advice to us, and our Jaipur and New Delhi Offices.

6. Under the existing arrangements, payment of interest on Jaipur-enfaced G. P. Notes of Government of Rajasthan and of the Government of India is made by the Treasury Officer, Jaipur. From the appointed day, i.e. 1st April, 1968, this work will be taken over by the Public Debt Office, Jaipur, from the Jaipur Treasury. The Treasury Officer, Jaipur is at present maintaining a register in form G.S.M. 9 and other registers and records prescribed in the Government Securities Manual in respect of the loans of Central Government and your Government. Some of these records/registers will, therefore, have to be transferred from Jaipur Treasury to the Public Debt Office. However, the register in form G.S.M. 9 cannot be transferred to the Public Debt Office straightaway as it also contains entries in respect of G.P. Notes enfaced for payment at the sub-treasuries under the jurisdiction of Jaipur Treasury. In terms of paragraph 42 of the Government Securities Manual (4th Edition), whenever a G.P. Note is enfaced by the Public Debt Office for payment of interest at a sub-treasury, the main enfacement advice is issued to the District Treasury and the District Treasury Officer issues an order in form G.S.M. 15 to the Sub-treasury Officer, after entering the particulars of the relative G.P. Note in his own register in form G.S.M. 9, although the actual payment on the security is made by the Sub-treasury and not by the District Treasury. Also, as and when payments on the G.P. Note are made by the Sub-treasury, the relative paid vouchers are sent by the Sub-treasury to the district treasury alongwith the daily statement and these payments are recorded by the District Treasury in its registers in forms G.S.M. 9 and 14. In view of this procedure, it will be necessary for the Treasury Officer, Jaipur, to prepare another register in form G.S.M. 9 which will contain the particulars of only those G.P. Notes/Treasury Savings Deposit/Defence Deposit Certificates/15-Year Annuity Certificates which stand enfaced at the *Sub-treasuries* subordinate to the Jaipur Treasury. This new register will be maintained as per Government Securities Manual and additions and deletions therein will be made in terms of advices issued by the Public Debt Office, Jaipur, from time to time. The existing register in form G.S.M. 9 should be handed over to the Public Debt Office, Jaipur, against receipt. We shall be glad if you will please request the Accountant General, Rajasthan, to issue necessary instructions

to the Treasury Officer, Jaipur to prepare a fresh register in form G.S.M. 9 for his own use and transfer the existing register in that form with other connected records to our Jaipur Office, which will give receipt for them.

7. For facilitating smooth transfer of these records, it will be necessary to declare a '*shut period of three days at the Jaipur Treasury from the 28th March to 30th March*, 1968.' Accordingly, we shall be glad if your Government will kindly issue a Press Communique on the lines of the enclosed draft which should appear in the leading English and Hindi newspapers in Rajasthan in the second week of March 1968.

8. Suitable instructions will also have to be issued by the Accountant General, Rajasthan, to all Treasuries and Sub-treasuries in the State of Rajasthan regarding the proposed change on the lines of the enclosed draft. You may please advise the Accountant General, Rajasthan, accordingly.

9. Consequent on the up-grading of the Jaipur Office to the status of a full-fledged Public Debt Office, necessary changes will be made by us in the scrip forms of your Government's securities.

10. We shall be glad if early action in the matter is taken by the Government.

Yours faithfully,

Encls. 3 Sd/-

Deputy Chief Accountant

No. C.O. Dt. Admn. 3/66-67/5162 *of date.*

Copy, with copies of the enclosures forwarded for information to—

(1) The Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi;

(2) The Finance Secretaries to all the State Governments (except Rajasthan);

(3) All Civil Accountants General in India;

(4) The Accountant General, Central Revenues, New Delhi;

(5) The Comptroller and Auditor General of India, New Delhi;

(6) The Managing Director, State Bank of India, Central Office, Bombay. He may please issue suitable instructions to the branches of the State Bank of India and State Bank of Bikaner and Jaipur, in the State of Rajasthan. *This may please be treated as very urgent.*

(7) The General Manager, State Bank of Bikaner and Jaipur, Head Office S.M.S. Highway, Jaipur;

(8) The Chief Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Administration and Personnel, Bombay.

(9) The Chief Officer, Reserve Bank of India, Department of Banking Operations and Development, Bombay.

(10) The Chief Officer, Reserve Bank of India, Agricultural Credit Department, Bombay;

(11) The Inspector/Deputy Inspector. Reserve Bank of India, Central Office, Bombay;

(12) The Manager, Reserve Bank of India, Bombay/Calcutta/Madras/Bangalore/Patna/Hyderabad/Nagpur/Kanpur/Byculla, Bombay-8.

Encls. 3

Sd/-
Deputy Chief Accountant.

Immediate

No. C.O. Dt. Admn. 3-66/67-5163 *of date.*

Copy, together with the copies of the enclosures forwarded to the Manager, Reserve Bank of India, Public Debt Office, Jaipur with reference to the correspondence resting with his letter MGR No. 1312/C. 19-67/68, dated the 21st November, 1967 for information and necessary action.

2. He may please contact the local Treasury Officer immediate and ascertain from him the number of G.P. Notes interest on which is payable at Jaipur, the Government of Rajasthan may also be simultaneously contacted and requested to take early action on the above lines and also arrange for the issue of necessary instructions by the Accountant General to the Treasury Officer, Jaipur, to copy out the entries relating to sub-treasury-enfaced notes from his register in from G.S.M. 9 as early as possible to facilitate smooth transfer of work and records during the "shut" period.

3. During the "shut" period relevant records and registers along with G.P. Notes, if any, tendered at the Treasury for renewal etc. and remaining undisposed of by the Treasury as on 28th March, 1968, will have to be taken over by the Public Debt Office, Jaipur, against proper receipt. The receipt should be prepared in quardruplicate, one copy thereof being given to the Treasury Officer and one copy each being sent to this office and the Accountant General, Rajasthan, The Fourth copy should be retained by the Public Debt Office.

4. Sanction for additional staff required by him in this connection has already been conveyed to him vide Chief Manager's Office letter Staff No. 7614/52 F (2)-67/68, dated the 22nd February, 1968. A copy of this letter has been endorsed to New Delhi Office.

Copy forwarded to the Manager, Reserve Bank of India Public Debt Office, New Delhi, for information and necessary action. In this connection reference is invited to Chief Manager's Office endorsement Staff No. 7615/52 F (2)-67/68, dated the 22nd February, 1968.

Encls. 3

Sd/-
Deputy Chief Accountant.

No. C.O. Dt. Admn. 3-66/67-5164. *of date.*

Copy, together with copies of enclosures forwarded for information to the Treasury Officer, Jaipur, Rajasthan.

Sd/-
Dy. Chief Accountant.

FINANCE DEPARTMENT (Revenue)

INDEX

(9)

विषय :—गैर-आयोजना मद से मार्च, 1968 में नई खरीद करने पर प्रतिबन्ध ।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर माह मार्च में जल्दी में भण्डार की वस्तुएं खरीदने में नियमों का पूर्णतया पालन न होने के कारण एवं सरकारी खर्च में कमी करने की दृष्टि से राज्यपाल महोदय ने आदेश दिये हैं कि सभी विभागाध्यक्ष तथा उनके अधीन कार्य करने वाले सभी अधिकारीगण सन् 1967-68 के आय-व्ययक के गैर-योजना मद के अन्तर्गत माह मार्च, 1968 में कोई नवीन खरीद नहीं करेंगे :—

2. ये आदेश निम्नांकित मामलों पर लागू नहीं होंगे :—

1. जिन मामलों में खरीद संबंधी अनुबन्ध/आदेश में शर्त के अनुसार ठेकेदारों द्वारा माल भेजने की बिल्टियों को बैंक के माध्यम से भेजने पर, पूरा या आंशिक भुगतान करना आवश्यक हो।

2. राज्य सरकार के माध्यम द्वारा प्राप्त किये गये आयात के लाइसेन्स के अन्तर्गत खरीद के मामलों पर ।

3. राज्य सरकार को आवंटित कोटा (Quota) के अन्तर्गत चीनी व अन्य नियन्त्रित वस्तुओं की खरीद के मामलों पर।

4. राज्य सरकार के खाते में खाद्य सामग्री की खरीद के मामलों पर ।

5. आबकारी विभाग द्वारा, रेक्टीफाइड स्प्रिट, मद्य तथा अन्य नशीली वस्तुओं के खरीद के मामलों पर ।

6. पैट्रोल, डीजल तथा मोटर के अन्य प्रकार के तेलों की खरीद के मामलों पर ।

7. आरक्षी विभाग द्वारा शस्त्र व गोला बारूद सम्बन्धी क्रय के मामलों पर ।

8. जिन मामलों में वित्त (व्यय) विभाग द्वारा विशेष रूप से स्वीकृति प्राप्त करली गई हो।

9. दुग्ध, सब्जियों तथा शीघ्र नष्ट होने वाली खाद्य सामग्री के मामलों पर ।

10. कोषालय द्वारा पास किये हुये बिलों को पुनर्वैद्य करने के कारण भुगतान के मामलों पर ।

11. दिनांक 31 मार्च, सन् 1968 तक चालू रहने वाले अनुबन्ध के अन्तर्गत, अस्पतालों में भर्ती बीमारों के लिये, 15 मार्च से पूर्व प्राप्त दवाइयों, खाद्य सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद के मामलों पर ।

3. दिनांक 15 मार्च, 1968 के पश्चात् कोषाधिकारी-गण यदि कोई कन्टिन्जेंट या पूर्व में लिये हुवे अग्रिम सम्बन्धी डी. सी. बिल उपरोक्त आदेशों के विपरीत हो, तो पास न करें ।

4. इस विषय पर इस विभाग द्वारा जारी किये गये सम संख्यक आदेश दिनांक 9 मार्च, 1966 में उल्लिखित अनुदेश इस वर्ष भी लागू रहेंगे । चूंकि इस वर्ष 31 मार्च, 1968 को राजपत्रित अवकाश है, अतः समस्त आदान एवं संवितरण अधिकारीगण अपने विभाग से सम्बन्धित बिल कोषालयों में दिनांक 25 मार्च, 1968 के पूर्व ही भिजवावें ।

5. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर से भी अनुरोध है कि यदि कोषाधिकारी इन आदेशों के विपरीत बिल पास करते हैं तो मामले की जांच कर सम्बन्धित कोषाधिकारी के विरुद्ध कोष-अनियमितता-पंजिका में अनियमितता अंकित करें ।

[वित्त विभाग लेखा एवं विनियोजन शाखा-1 आदेश क्रमांक प. 5(4) वित्त(ले.वि.) 66, दिनांक 8-3-68 ।]

---

(10)

विषय :—गैर-आयोजना मद से मार्च, 1968 में नई खरीद करने पर प्रतिबन्ध ।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ कोषाधिकारी गण उन बिलों को जिनमें माल खरीदने के आदेश माह मार्च के पूर्व ही दे दिये गये थे परन्तु जिनका माल माह मार्च में सप्लाई किया गया है, उनको कोषालय में स्वीकार नहीं करते हैं । इस के साथ 2 यह भी ध्यान में आया है कि प्रतिदिन के खर्च के इम्प्रेस्ट के बिल भी स्वीकार नहीं किये जाते ।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8-3-68 का यह आशय नहीं है कि इस प्रकार के बिल भी कोषालय में स्वीकार नहीं किये जावें । ऐसे बिल कोषालय में दिनांक 25-3-1968 तक उसी प्रकार स्वीकार किये जावें जैसे अन्य बिल स्वीकार किये जाते हैं । अति आवश्यक बिलों को जो इस विभाग के आदेश दिनांक 8-3-68 के विपरीत न हो उनको माह के अन्तिम दिन तक स्वीकार किये जावें ।

[वित्त विभाग लेखा एवं विनियोजन शाखा-1 आदेश क्रमांक एफ. 5(4) वित्त(ले.वि.) 66, दिनांक 23-3-68.]

---

(11)

विषय :—खाली चैक की पुस्तिकाओं की अभिरक्षा—उनके खो जाने पर कोषालय को सूचना देने के विषय में ।

रिजर्व-बैंक-आफ इन्डिया, द्वारा केन्द्रीय सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले लाये गये हैं जिनमें सरकारी चैकों पर जाली हस्ताक्षर कर सरकारी खाते से भुगतान प्राप्त कर लिये हैं ।

इसका यह कारण है कि आदान अधिकारीगण, जिन्हें बैंक द्वारा भुगतान करने हेतु प्राधिकृत किया हुवा है, खाली चैकों को व बैंक-पुस्तिकाओं की अभिरक्षा या उनके खो जाने पर संबंधित बैंक एवं कोषालय/उप-कोषालय को यथा समय सूचना देने संबंधी, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 118-118-ए, व 119 का यथोचित अनुसरण नहीं करते ।

अत: विभागाध्यक्षों से निवेदन है कि वे उक्त नियमों को (जिनको शीघ्र सन्दर्भ हेतु इस परिपत्र के पृष्ठ भाग पर उद्धरित कर दिया गया है) उनके अधीनस्थ समस्त आदान एवं संवितरण अधिकारियों, जिन्हें बैंक द्वारा भुगतान करने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है, के ध्यान में लाकर निदेश दें कि इनका पूर्णतया पालन किया जावे ताकि भविष्य में जाली भुगतान न हो ।

[वित्त विभाग लेखा एवं विनियोजन शाखा-1 परिपत्र क्रमांक प 7 (3) वित्त (ले.वि.) सा. वि. के.166, दिनांक 8-3-68]

Copy of Rule No. 118, 118-A and 119 of General Financial and Accounts Rules, Vol. I.

118. Each cheque book must be kept under lock and key in the personal custody of the drawing officer who, when relieved, shall take a receipt for the exact number of cheques made over to the relieving officer.

118-A. In case where withdrawal of fund by cheques is no longer necessary, all the cheque forms of cheque books, which remain partly or wholly unused, shall be cancelled by writing the word "cancelled" prominently across each cheque form and counterfoil, without signature of the drawing officer and thereafter returned to the Treasury Officer concerned who shall destroy them by incineration in the presence of the Collector, after keeping a note of the fact in the relevant records of the Treasury under proper attestation."

119. The loss of a cheque book or a bank cheque form shall be notified promptly to the Bank/Sub-treasury with whom the disbursing officer concerned has a drawing account.

(F. D/ Order No. F. 24 (36) F (A&I) 62, dated 12-1-65).

---

(12)

कोषालय संहिता के नियम 57 के अधीन राज्य सरकार, राज्य के समस्त कोषालय/उप-कोषालय के लिये कार्य के निम्न दिवस व समय निर्धारित करते हैं:—

	दिवस	समय
1.	समस्त राजकीय कार्य दिवस (प्रत्येक माह की 10 वीं और अन्तिम तारीख के सिवाय)	10-30 बजे पूर्वान्ह से 1-30 बजे अपरान्ह तक और 2-00 बजे अपरान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह तक ;
2.	प्रत्येक माह की 10 वीं और अन्तिम तारीख ।	10-30 बजे पूर्वान्ह से 1-30 बजे अपरान्ह तक ।

टिप्पणी 1. अगर किसी माह की 10 वीं अथवा अन्तिम तारीख को रविवार अथवा राजपत्रित अवकाश हो तो उसके पूर्व कार्य दिवस में केवल 10-30 पूर्वान्ह से 1.30 अपरान्ह तक ही कार्य होगा ।

टिप्पणी 2. रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन कोषालय/उप-कोषालय बन्द रहेंगे परन्तु जिन उप-कोषालयों में रकम का लेन देन बैंक के माध्यम से नहीं होता है वे वित्तीय वर्ष के अन्तिम 3 दिनों में रविवार अथवा राजपत्रित अवकाश होने पर भी रकम की लेन देन का कार्य करेंगे ।

[वित्त विभाग लेखा एवं विनियोजन शाखा-2 क्रमांक एफ. 5(16) वित्त (ले.वि) 68, दिनांक 22-3-1968.]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

INDEX

(9)

इस विभाग के तद्विषयक सम-संख्यक समस्त आदेशों के अधिलंघन में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों व न्यायालयों (राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों को छोड़ कर) के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का दैनिक कार्यकाल पूरे वर्ष दिनांक 18-3-68 से 10 बजे पूर्वान्ह से 5 बजे अपराह्न तक रहेगा तथा मध्यान्ह अल्पाहार का समय 1.30 बजे से 2.00 बजे तक रहेगा।

प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को ही केवल सार्वजनिक अवकाश रहेगा व शेष शनिवार कार्य दिवस रहेंगे।

अधिकारीगण जो इस विभाग के आदेश संख्या प. 2(2) सा.प्र.क.165 दिनांक 19-6-67 के अन्तर्गत पूर्वान्ह 9 बजे कार्यालय आते हैं व 1 बजे से 2-30 बजे तक मध्यान्ह अल्पाहार के लिये जाते हैं के लिये उक्त आदेश को निरस्त करते हुये दिनांक 18 मार्च, 1968 से उनका भी दैनिक कार्यकाल 10 बजे पूर्वान्ह से 5 बजे अपरान्ह तक रहेगा तथा मध्यान्ह अल्पाहार का समय 1-30 बजे से 2 बजे तक रहेगा।

[सामान्य प्रशासन (क) विभाग आज्ञा संख्या प. 1 (51) सा।प्र।क।64, दिनांक 14-3-1968]

---

(10)

विषय---राजस्थान राजनैतिक पीड़ित सहायता नियम, 1959 में संशोधन करने हेतु।

राज्यपाल महोदय सहर्ष राजस्थान राजनैतिक पीड़ित सहायता नियम में निम्नांकित संशोधन करते हैं।

संशोधन

नियम 7 (ग) के स्थान पर कृपया निम्नांकित संशोधन नियम पढ़ें।

नियम 7(ग) :—उक्त पेंशन या पेंशनों के अतिरिक्त राजनैतिक पीड़ित को किसी कंवारी लड़की या बहिन का विवाह करने या किसी राजनैतिक पीड़ित की डाक्टरी चिकित्सा के लिये।

(सामान्य प्रशासन (क) विभाग विज्ञप्ति संख्या प. 18 (2) सा.प्र.क 67,। दिनांक 20-3-1968)

(11)

विषय :—मध्यान्ह अल्पाहार के समय की पाबन्दी ।

महोदय,

इस विभाग के आदेश संख्या प. 1(51) सा.प्र.क.।64 दिनांक 14-3-1968 के क्रम में निवेदन है कि मध्यान्ह अल्पाहार का समय समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों का 1-30 बजे से 2 बजे तक का है अतः समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपरोक्त समय का ही अल्पाहार के लिये सदुपयोग करें। उपरोक्त समय के अलावा किसी समय का सामूहिक चाय आदि पीने में दुरुपयोग न करें। यदि चाय आदि पीने की इच्छा हो तो वे कार्यालय में ही चाय मंगा कर पी सकते हैं लेकिन इससे राज्य कार्य पर अनुचित प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

उपरोक्त आदेशों का भलीभांति अनुपालन कराने का दायित्व विभागाध्यक्षों/जिलाधीशों के अतिरिक्त संबंधित कार्यालय अधीक्षकों पर होगा।

कृपया पत्र की प्राप्ति भेजें।

[सामान्य प्रशासन (क) विभाग संख्या प. 2(2) सा.प्र.क.।68, दिनांक 18।23-3-68]

---

(12)

विषयः—सन् 1968 के सार्वजनिक अवकाश-ऐच्छिक अवकाश थदड़ी के संबंध में।

उपरोक्त विषय में इस विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ. 9 (3) जी. ए.।ए.। 67 दिनांक 25-11-67 के ऐच्छिक अवकाश क्रमांक 5 "थदड़ी" के सन्मुख अंकित "ज्येष्ठ 26, जून 16 रविवार" के स्थान पर "श्रावण 24 अगस्त 15 गुरुवार" पढ़ा जावे।

[सामान्य प्रशासन विभाग संशोधन संख्या प. 9(3)।सा.प्र.क.67, दिनांक 28-3-68]

---

(13)

विषयः—सन् 1968 के सार्वजनिक अवकाश।ऐच्छिक अवकाश के संबंध में।

उपरोक्त विज्ञप्ति में इस विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ 9(3)जी.।ए.।67 दिनांक 25-11-67 के नोट संख्या 7- प्रत्येक कर्मचारी द्वारा दो ऐच्छिक अवकाश का उपयोग करने के सम्बन्ध में कई विभागाध्यक्षों द्वारा कुछ स्पष्टीकरण चाहा है वह निम्न प्रकार है :—

1. उपरोक्त विज्ञप्ति में जिन ऐच्छिक अवकाशों की सूची दी है वह सरकार द्वारा स्वीकृत अवकाश है और प्रत्येक कर्मचारी इच्छानुसार कोई भी दो ऐच्छिक अवकाश का उपभोग कर सकता है।

2. जिस कर्मचारी ने दिनांक एक जनवरी के बाद भी दो ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करने की सूचना दी है उन्हें भी इस वर्ष अनुमति दी जावे किन्तु आगामी वर्ष से कर्मचारियों को चाहिए कि एक जनवरी तक अपेक्षित सूचना अपने अधिकारियों को देवें अन्यथा उक्त अवकाश का उपभोग करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

3. यदि कोई कर्मचारी चयन किये हुए ऐच्छिक अवकाश में परिवर्तन करना चाहे तो कारण बताते हुए परिवर्तन करा सकता है।

[सामान्य प्रशासन (क) विभाग विज्ञप्ति संख्या 9(3) सा.प्र.क.167, दिनांक 28-3-68]

(14)

The question of courtesies which should be shown to the Chief Justice and Judges of the Supreme Court. Chief Justice of the High Courts and the Comptroller and Auditor General of India whenever they visit any place in this State e her officially or on vacation has been under the consideration of the Government. The Government have examined the question and have decided considering the high position enjoyed by these high Dignatories in the Warrant of Precedence the following courtesies should be shown to them:—

(i) If the visit is to the headquarters of a district, the Collector and the Superintendent of Police, should call on the dignatory at the earliest opportunity during his stay in their jurisdiction. If they are on camp during the preiod, the senior most Revenue and Police Officials stationed at the headquarters of the district should call on the high dignatory and explain suitably why the Collector/Superintendent of Police has not called on him.

(ii) If the visit is to a place other than the headquarters of the district, the senior most Revenue and Police Officials stationed at that place shall call on the dignatory.

[G. A. D. (A) Deptt. F. 14 (a) (71) G.A./A/68 dated 28-3-68.]

(15)

विषय:—मितव्ययता के संबंध में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में की गई कटौती के संबंध में।

राज्य सरकार एतद् द्वारा आदेश प्रदान करती है कि सामान्य प्रशासन (क) विभाग के आदेश संख्या एफ. 1(15) सा.प्र.क.ग्रुप-II/61, दिनांक 8-4-61 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों में 20 प्रतिशत की गई कटौती (विवरण संलग्न है) को दिनांक 1-6-61 से समाप्त मानी जावे।

[सामान्य प्रशासन (क) विभाग संख्या प. 2 (7) सा. प्र.क 168, दिनांक 23-3-68]

Economy Cut in the Strength of Class IV Servants.

Head of Account	Total No. of posts of peons on 1-3-1961	No. of posts reduceable according to 20% cut	Posts actually reduced	Difference between Cols. 3 & 4
1	2	3	4	5
9. Land Revenue	1619	362	130	—232
10. State Excise Duties	Included under '12-A-Sales-Tax'			

1	2	3	4	5
11. Taxes on Vehicles	54	10	8	—2
12. Sales Tax	1110	220	28	—192
13. Other Taxes & duties	20	4	4	..
14. Stamps	6	1	..	—1
15. Registration	4	..	..	..
18. Parliament & State Legislature 19 General Administration	6851	1377	372	—1005
21. Administration of Justice	555	108	2	—106
22. Jails	29	6	6	..
23. Police	772	151	26	—125
26. Miscellaneous Departments	1628	310	58	—252
27. Scientific Department	113	20	19	—1
28. Education	6038	1209	761	—448
29. Medical	6066	1204	36	—1168
30. Public Health	587	113	15	—98
31. Agriculture	391	77	51	—26
32. Rural Development	..	..	..	..
33. Animal Husbandry	892	175	23	—152
34. Cooperation	513	101	101	..
35. Industries	270	54	49	—5
37. C. D. P. etc.	30	6	..	—6
38. Labour & Employment	389	77	37	—40
39. Miscellaneous Social & Development Organisation.	included under '26 Miscellaneous Deptt.'			
42. Multipurpose River Schemes	108	8	14	—[illegible]

1	2	3	4	5
43. Irrigation Electricity (Commercial)	29	6	14	- 8
44. Irrigation (Non-Commercial)	115	23	21	—2
Irrigation (Commercial Establishment)	236	47	2	—45
50. Public Works	650	130	120	—10
57. Road & Water Transport	79+65=114	16	..	—16
64. Famine Relief	8	2	3	+1
68. Stationery & Printing	7	1	1	..
70. Forest	152	30	30	..
71. Miscellaneous	79	16	15	—1
52. Capital Outlay on public Works	3 4	—	—	—
GRAND TOTAL .	29,683	5,864	1,946	—3,918

HOME DEPARTMENT
INDEX

HOME DEPARTMENT

(8)

राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, 1951 (राजस्थान अधिनियम 11 सन् 1951) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1(1) (11) होम (बी-ग्रुप-1) 165 दिनांक 31 दिसम्बर, 66 के अनुक्रम में राज्य सरकार गीता प्रेस, गोरखपुर की मोटर गाड़ी संख्या आर. एस. एल. 4060 को 1-1-1968 से 31-12-1968 तक उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से इस शर्त के अध्यधीन छूट देती है कि उक्त गाड़ी का उपयोग केवल उनके ही प्रकाशनों के वहन हेतु किया जायेगा।

[गृह ख-1 विभाग अधिसूचना संख्या एफ. 1 (1) (11) होम (बी-ग्रुप-1) 65, दिनांक 29 मार्च, , 1968]

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Rajasthan Act 11 of 1951), and in continuation of this Department Notification No. F. 1 (1) (11) Home (B.Gr.1)/65, dated the 31st December, 1966, the State Government hereby exempts, Motor Vehicle No. RSL-4060, belonging to Gita Press, Gorakhpur from the payment of the tax under the said Act, from 1-1-1968 to 31-12-1968, subject to the condition that the said vehicle is used only for the carriage of their publication.

[Home (B.Gr.I) Deptt. Notification No. F. 1 (1) (11) Home (B-Gr.I)/65, dated 29-3-1968.]

---

(9)

राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण नियम, 1951 के नियम 108 के अनुसरण में तथा राजस्थान राज-पत्र भाग 4(ग) दिनांक 6 जुलाई, 1967 में प्रकाशित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 5 जुलाई, 1967 का अधिलंघन करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अपील अधिकरण, परिवहन विभाग को पुनर्गठित करती है तथा श्री अनोपसिंह, आर. एच. जे. एस. को सदस्य, अपील अधिकरण, परिवहन विभाग के रूप में उस तारीख से नियुक्त करती है जिसको वे श्री जे. एस. रानावत, जज, औद्योगिक अधिकरण तथा सदस्य, अपील अधिकरण, परिवहन विभाग से कार्यभार ग्रहण करें। राज्य सरकार एतद्द्वारा और आदेश देती है कि श्री अनोपसिंह, आर. एच. जे. एस. से उनकी सेवा निवृत्ति के पश्चात् भी, अर्थात जब तक यह अधिसूचना प्रवृतमान रहे, यह पद धारण करते रहेंगे।

[गृह (ख-1) विभाग अधिसूचना संख्या एफ. 12 (1)।31।एच. (बी-ग्रुप-1) 62, दिनांक 29-3-68]

In pursuance of rule 108 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1951 and in supersession of this Department Notification of even number dated the 5th July, 1967; published in the Rajasthan Gazette dated the 6th July. 1967 Part IV (C), the State Government hereby reconstitute the Appellate Tribunal, Transport Department and to appoint Shri Anop Singh, R. H. J. S. as Member, Appellate Tribunal, Transport

Department with effect from the date he takes over charge from Shri J.S. Ranawat, Judge, Industrial Tribunal and Member, Appellate Tribunal, Transport Department. The State Government hereby further orders that Shri Anop Singh will continue to hold this appointment even after his retirement from R H J. S .i. e , till this notification remains in force.

[Home (B.Gr.1) Deptt., Notification No F. 12 (1) 31/H; (B Gr. I) 62, dated 29-3-68]

(10)

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Rajasthan Act 11 of 1951), the State Government hereby exempts Motor Vehicle No. RJY-3380 belonging to Bhartiya Lok Kala Mandal, Udaipur, from the payment of the tax payable under the said Act, subject to the condition that the said vehicle is used for Cultural and other allied activities of the said Institution.

[Home (B. Gr. I) Deptt. Noti. No. F. 1 (1) 18/Home (B. Gr. I)/67, dated 29-3-68.]

(11)

In pursuance of Rule 8 of R. S. R. the Governor has been pleased to prescribe the maximum age limit of 35 years for recruitment to the post of Police Automobile Officers, in respect of candidates who are already in Government Service in any State or Administration of the Indian Union.

[Home (E) Deptt. Order No. F.1 (11) H. E/I/55, dated 1-3-68].

LAW DEPARTMENT

INDEX

LAW DEPARTMENT

(2)

न्याय विभाग की आज्ञा संख्या सम दिनांक 28-4-67, 20-10-67 तथा 18-1-68 के क्रम में निम्नलिखित जिलाधीशों को उपरोक्त विषय में वित्तीय वर्ष सन् 1967-68 के लिये अतिरिक्त धनराशि के उपभोग करने का अधिकार दिया जाता है। यह धनराशि प्रोसीक्यूटिंग इन्सपैक्टर सब-इन्सपैक्टरों को फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, 1954 के तहत भत्ता तथा मानदेय के रूप में होगी। यह खर्चा मद "21-न्याय प्रशासन—डी—न्याय अधिकारी-भत्ता तथा मानदेय" के अन्तर्गत होगा।

क्रम नं.	नाम जिलाधीश	धन राशि जो अलॉट की गई सन् 1967-68
1.	कोटा	500.00
2.	गंगानगर	500.00
3.	झालावाड़	2,500.00
	योग ..	3,500.00

(रुपये तीन हजार पांच सौ मात्र)

यह आवन्टन शेष वित्तीय वर्ष के लिये है। खर्चा अलॉटमेन्ट से किसी भी सूरत में ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक प्रतिलिपि हर एक मंजूरी की ज्यूडिशियल डिपार्टमेन्ट को भेजी जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत प्रोसिक्यूटिंग इन्सपैक्टर व सब-इन्सपैक्टरों को पेमेन्ट दिया जावे।

[न्याय विभाग आज्ञा संख्या एफ. 23 (11) न्याय/67, दिनांक 20-3-68]

REVENUE DEPARTMENT

INDEX

(8)

संख्या एफ. 6(120) राज।ख।62, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम सं. 15 सन् 1956) की धारा 20 के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त तहसीलदार, कोटा को कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर व भरतपुर जिलों की समस्त तहसीलों के लिये अतिरिक्त तहसीलदार तथा श्री बृजमोहन लाल त्रिवेदी को जयपुर, सीकर, झुन्झुनू, अलवर व टोंक जिलों की समस्त तहसीलों के लिए अतिरिक्त तहसीलदार नियुक्त करती है, उनके मुख्यालय क्रमशः कोटा तथा जयपुर तहसीलों में रहेंगे ।

और, उक्त अधिनियम की धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि स्थिर भाटक (डेड रेण्ट), भूतल भाटक, अधिकार शुल्क (रायल्टी), भाटक और अधिकार शुल्क संग्रहण संविदा की रकम के सम्बन्ध में कोई देय भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने के लिये राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1959 के नियम 55 के साथ पठित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 256 द्वारा कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों का तथा इस सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अध्याय 10 में अन्तर्विष्ट आनुषंगिक शक्तियों का उक्त तहसीलदारों द्वारा क्रमशः उनसे सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग किया जायगा ।

यह अधिसूचना इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 6(120) रेवे।बी।62, दिनांक 25 जनवरी, 1968 का अधिलंघन करेगी तथा 25 जनवरी, 1968 से प्रवृत हुई समझी जावेगी।

[राजस्व (ख) विभाग अधिसूचना संख्या एफ. 6(120) राज।ख।62, दिनांक 21-3-68]

---

(9)

संख्या एफ. 6(120) राज.(ख) 62, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या 15 सन् 1956) की धारा 20 के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा श्री लक्ष्मीराज माथुर अतिरिक्त तहसीलदार जोधपुर को जोधपुर, पाली, नागौर, बाडमेर, जालौर, जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर, चूरू, गंगानगर जिलों की समस्त तहसीलों के लिये अतिक्ति तहसीलदार नियुक्त करती है। उनका मुख्यालय जोधपुर तहसील में रहेगा ।

और उक्त अधिनियम की धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि स्थिर भाटक (डेड रेण्ट), भूतल भाटक, अधिकार शुल्क (रायल्टी) भाटक और अधिकार शुल्क संग्रहण संविदा की रकम के सम्बन्ध में कोई देय भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स 1959 के नियम 55 के साथ पठित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 256 द्वारा कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों का तथा इस सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व

अधिनियम, 1956 के अध्याय 10 में अन्तर्विष्ट आनुषंगिक शक्तियों का उक्त अतिरिक्त तहसील-दार द्वारा क्रमशः उनसे सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग किया जायेगा।

[राजस्व (ख) विभाग अधिसूचना संख्या एफ. 6 (120) राज. (ख) 62, दि. 21-3-68]

55/16

राजस्थान सरकार

मंत्रि-मण्डल सचिवालय

व्यवस्था एवं पद्धति (संकलन) अनुभाग

अप्रेल, 1968 में शासन सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गए महत्वपूर्ण परिपत्रादि का मासिक संकलन

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

1968

LIST OF DEPARTMENTS

(In respect of which important Circulars etc have been printed in the compilation of the month of April, 1968).

विभागों की सूची

(उन विभागों की सूची जिनके महत्वपूर्ण परिपत्रों आदि को अप्रेल, 68 के संकलन में मुद्रित किया गया है।)

APPOINTMENTS DEPARTMENT

INDEX

(8)

विषयः——राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244(2) के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244(2) के अन्तर्गत अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की जाय और इसके लिये निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

1. प्रतिवर्ष की पहली मार्च को प्रत्येक नियुक्तिकर्ता अधिकारी अगले साल की 31 मार्च तक 25 वर्ष की अर्ह सेवा (क्वालीफाइंग सर्विस) पूरे करने वाले उनके अधीनस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची तैयार करेंगे।

2. नियुक्तिकर्ता अधिकारी इनकी अर्ह सेवा की जांच करने के पश्चात् अगले वर्ष की 31 मार्च को 25 वर्ष की अर्ह सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों की निम्न प्रकार से सूची तैयार करेंगे :—

1. क्रमांक
2. नाम
3. पद जिस पर नियुक्त है
4. जन्म दिनांक
5. राज्य सेवा में नियुक्ति का दिनांक
6. अर्ह सेवा (क्वालीफाईंग सर्विस) के प्रारम्भ होने का दिनांक
7. 25 वर्ष की अर्ह सेवा पूर्ण होने का दिनांक
8. सेवा निवृत्ति की आयु का दिनांक

3. नियुक्तिकर्ता अधिकारी उपर्युक्त कर्मचारियों की निजी पत्रावली, सेवा पुस्तिका, विभागीय जांच सम्बन्धी पत्रावली, यदि कोई हो, की संवीक्षा कर, जिन कर्मचारियों को उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत अकुशलता के कारण अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करना उचित समझा जाय उनके बारे में अपनी सिफारिश, कारण सहित, मय सारे रिकार्ड के विभागाध्यक्ष को भेजेंगे। इस तरह की सिफारिश पर अंतिम निर्णय विभागाध्यक्ष या जहां वह स्वयं नियुक्तिकर्ता अधिकारी हो, प्रशासनिक सचिव द्वारा लिया जावेगा।

4. जब तक कि कर्मचारी का विशेष तौर से रिकार्ड खराब न हो और यदि वह उसी साल के अन्त तक 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवा निवृत्त होने वाला हो तो ऐसे कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने की सिफारिश नहीं की जावे। इनके अतिरिक्त दूसरे मामलों में खराब रिकार्ड पर उचित ध्यान देना चाहिये। प्रत्येक विभाग के सम्बन्ध में ऐसी सूची यथा समय तैयार की जाकर शीघ्र निर्णय लिया जावे ताकि सेवा से निवृत्त किये जाने वाले व्यक्ति

को नियमानुसार नोटिस देने के लिये पर्याप्त समय बच रहे और वह बाकी छुट्टी का उपभोग भी कर सके। सेवा निवृत्ति का अन्तिम निर्णय लिये जाने के पश्चात् संलग्न प्रारूप के अनुसार नियुक्तिकर्ता अधिकारी सेवा निवृत्ति के आदेश प्रसारित करेंगे।

5. ऐसे कर्मचारियों को जो अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये जाने वाले हों, यदि उनकी छुट्टी बाकी हो तो, उनको छुट्टी का उपभोग करने का लाभ उठने दिया जावे जो किसी अवस्था में 120 दिन से अधिक नहीं हो सकती। यदि छुट्टी का उपभोग किया जावे तो नोटिस का समय व छुट्टी दोनों साथ साथ चलेंगी। ऐसे मामलों में छुट्टी के खतम होने की तारीख से सेवा निवृत्त प्रभावशील होगी। इस विषय में सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेवा-निवृत्ति किये जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वह कर्मचारी 25 साल की अर्ह सेवा पूरी कर चुका है व सेवा निवृत्ति की तारीख का निर्धारण इस ढंग से हो कि उपार्जित अवकाश, जो 120 दिन से ज्यादा नहीं, भोगने का अवसर तथा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (2) के अन्तर्गत प्रावधान किया हुआ कम से कम 3 महीने का नोटिस उसको मिल जाय। यदि वह कर्मचारी छुट्टी न जाकर नोटिस की अवधि में काम करना चाहे तो ऐसा करने दिया जावे।

6. नियुक्तिकर्ता अधिकारी व विभागाध्यक्ष इस प्रकार से सेवा-निवृत्त किये गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक रजिस्टर रखेंगे जिसमें निम्न प्रकार का विवरण होगा:—

(1) क्रम संख्या

(2) कर्मचारी का नाम मय पिता के नाम के

(3) पद

(4) विभाग या कार्यालय का नाम जहां कार्य करता हो

(5) जन्म दिनांक

(6) अर्ह सेवा प्रारम्भ होने की तारीख

(7) 25 वर्ष की अर्ह सेवा पूर्ण होने की तारीख

(8) सेवा-निवृत्ति की तारीख

(9) नियुक्तिकर्ता अधिकारी की सिफारिश व अन्तिम निर्णय

(10) नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा प्रसारित किये हुए सेवा निवृत्ति के आदेश की संख्या एवं दिनांक

(11) दिनांक जिससे सेवा निवृत्ति प्रभावशील होगी

(12) विवरण।

7. चूंकि यह प्रक्रिया कर्मचारियों के सेवा काल को कम करती है इसलिये ऐसे मामलों में सिफारिश बड़ी सतर्कता व सावधानी के साथ की जानी चाहिए।

(नियुक्ति (1) गो. प.। विभाग परिपत्र संख्या एफ. 4 (19) नियुक्ति-क (1) प्र. 1165, दिनांक 15-4-68।)

नोटिस का प्रपत्र

संख्या .... दिनांक ....

प्रेषिती :

....

....

....

श्री । श्रीमती .... पद नाम .... दिनांक ....
को 25 वर्ष की अर्ह सेवा (क्वालिफाईंग सर्विस) पूर्ण कर लेंगे / कर चुके हैं।

और चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त राज्य कर्मचारी को और सेवा की अभिमुक्ति प्रदान करना लोकहित में है।

अतः अब, वित्त विभाग के आदेश सं. एफ. 1 (34) एफ. डी. ए. रूल्स/62, दिनांक 13-11-63 के साथ पठित राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (2) के अनुसरण में निम्न हस्ताक्षरकर्ता उक्त श्री/श्रीमती .... को दिनांक ....
से या उस पर इस नोटिस की तामील होने से 3 कलेण्डर मास की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, सेवा मुक्त होने की अपेक्षा करते हुए, एतद्द्वारा नोटिस देता है तथा उक्त दिनांक से श्री/श्रीमती .... के अनिवार्य सेवा मुक्ति का और आदेश देता है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर।

टिप्पणी:—सरकार से भिन्न किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी राज्य कर्मचारी को जो 25 वर्ष की अर्ह सेवा (क्वालिफाईंग सर्विस) पूर्ण कर लेगा/कर चुका है, दिया जायगा।

यहां वह दिनांक विनिर्दिष्ट कीजिए जो उस दिनांक की ठीक अनुवर्ती हो जिसको कि उक्त राज्य कर्मचारी 25 वर्ष की अर्ह सेवा (क्वालिफाईंग सर्विस) पूर्ण कर लेता है।

CABINET SECRETARIAT INCLUDING O. & M. SECTION

INDEX

CABINET SECRETARIAT INCLUDING O &M SECTION

(10)

In partial modification of this Department orders No. F. 2 (6) O&M/64, dated 28-6-64 and No. F. 2 (16) O&M/67, dated 4-6-67, it is hereby ordered that with effect from 15th April, 1968, the work in the Finance Department shall be distributed as follows:—

FINANCIAL COMMISSIONER & SECRETARY TO THE GOVERNMENT

He shall function as Secretary to Government in all matters not dealt with by F. C. (Rev.). He shall also function as Cell Officer for Plan Finance, Pay Commission, Dearness Allowance and Economy Measures.

OFFICERS UNDER F. C.

(1) Deputy Secretary, Exp. (I).
(2) Deputy Secretary, Exp. (II) & Stores purchase Officer,
(3) Deputy Secretary, Exp. (III),
(4) Deputy Secretary, Exp. (Rules),
(5) Budget Officer,
(6) Deputy Secretary, Finance Commission,
(7) Director, Small Savings & Lotteries and ex-officio Deputy Secretary to the Government.

FINANCIAL COMMISSIONER (REV.) & SECRETARY TO THE GOVERNMENT

He shall function as Cell Officer for Taxation Policy, Town Planning Section and Treasury Rules and Manuals.

OFFICERS UNDER F. C. (REV.).

(1) Deputy Secretary, Com. Taxes
(2) Deputy Secretary, Excise, Recovery & R. Ac. S.
(3) Deputy Secretary (Accounts & Investments).

(Organisation & Methods Section Order No. F. 2 (16) O & M/67 dated 15-4-68.)

(11)

राज्यपाल, इस सचिवालय की सम संख्यक आज्ञा दिनांक 30-3-68 के द्वारा राज्य के समस्त विभागों से सम्बन्धित सेवा नियमों के हिन्दी अनुवादों के प्रकाशनार्थ निर्मित समिति में आंशिक परिवर्तन करते हुए, श्री विष्णुदत्त शर्मा, गृह आयुक्त को 'संयोजक' के बजाय समिति का 'अध्यक्ष' एवं श्री सुरेशचन्द्र माथुर, उप-सचिव, विधि विभाग को केवल सदस्य के स्थान पर अब समिति का 'सदस्य-सचिव' मनोनीत किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(मंत्रिमण्डल सचिवालय आज्ञा क्रमांक एफ 5 (11) व्य. एवं. प.168 दिनांक 29-4-68)

---

(12)

विभागीय विवरण राज्य विधान सभा में आय-व्ययक सम्बन्धी मांगों पर विचार से पर्याप्त समय पूर्व प्राप्त न होने के कारण, सदस्यों में यथा समय वितरित नहीं किये जा सकते परिणाम स्वरूप मांग सम्बन्धी विचार विमर्श के समय विपक्षी दलों द्वारा आपत्तियां की जाती हैं। गत विधान सभा सत्र में विपक्षी दल के नेता द्वारा स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग की मांग से सम्बन्धित विवरण समय पर राजस्थान विधान सभा में न पहुंचने के कारण और सदस्यों में देर से वितरित किये जाने पर इसी प्रकार की आपत्ति उठाई गई जिस पर विधान सभाध्यक्ष को यह व्यवस्था देनी पड़ी कि मांग पर विचार से पर्याप्त समय पूर्व विवरण के प्राप्त न होने की स्थिति में वे सदस्यों में वितरित नहीं किये जायेंगे। स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने भी सरकार की ओर से यह विश्वास दिलाया कि भविष्य में मांग पर विचार से पर्याप्त समय पूर्व विवरण सदस्यों में वितरित किये जाने की व्यवस्था कर दी जायेगी।

अतः समस्त शासन सचिवों से अनुरोध है कि भविष्य में इस प्रकार की अवांछनीय स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिए सम्बन्धित विभागीय विवरण तत्सम्बन्धी मांग पर विचार से पर्याप्त समय पूर्व राजस्थान विधान सभा सचिवालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।

(मंत्रिमण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग परिपत्र क्रम. सं. एफ. 10(14) व्य.एवं.प.167, दिनांक 18-4-1968)

---

(13)

विष.:—संसदीय सचिवों को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों का निर्वतन—

मंत्रिमण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) के परिपत्र क्रमांक प. सं. 1 (2) व्य. एवं. प.168, दिनांक 21-2-68 में दिये गये निर्देश, संसदीय सचिवों को सीधे प्रस्तुत होने वाले उन आवेदन-पत्रों / प्रार्थना-पत्रों आदि के सम्बन्ध में भी लागू समझे जायेंगे जिनके बारे में संसदीय सचिवों द्वारा कोई जानकारी चाही गई हो।

(मंत्रिमण्डल सचिवालय परिपत्र सं. प. 1 (2) व्य. एवं प.168, दिनांक 29-4-68)

---

(14)

जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, आश्वासन समिति आदि से सम्बन्धित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये आवश्यक प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में समय समय पर आदेश जारी किये जाते रहे हैं और सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने तथा अपने यहां के अधिकारियों को इन कामों के लिये विशेष रूप से जिम्मेवार बनाये जाने के आश्वासन भी प्राप्त होते रहे हैं। इन मामलों की प्रगत्यात्मक सूचना से सभी सम्बन्धितों को अवगत रखने के लिये त्रैमासिक विवरण-पत्र भिजवाये जाने की व्यवस्था भी

की गई है। किन्तु इन सबके बावजूद, यह देखने में आया है कि, जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, आश्वासन समिति आदि से सम्बन्धित मामलों तथा विधान सभा के प्रश्नों के बारे में आवश्यक सूचनायें समय पर नहीं दी जातीं।

उपर्युक्त सभी मामलों से सम्बन्धित स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से पहिले समय-समय पर दिये गये अनुदेशों, आदेशों आदि के दृढ़ता के साथ पालन की आवश्यकता पर बल देते हुए यह निश्चय किया गया है कि भविष्य में जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, आश्वासन समिति आदि से सम्बन्धित मामलों की प्रगति की समीक्षा की दृष्टि से—

(1) मुख्य सचिव महोदय सम्बन्धित सचिवों की एक त्रैमासिक बैठक बुलाया करेंगे जिसमें कि मुख्य सचिव महोदय को सचिव गण अपने अपने विभागों की प्रगति से अवगत करायेंगे।

(2) इसके अतिरिक्त समय समय पर होने वाली सचिवों की बैठकों की कार्य सूचियों में उपर्युक्त मामलों की प्रगति का विषय एक स्थायी अंग रहेगा।

(मंत्रिमण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग परिपत्र क्रमांक एफ. 10 (8) व्य. एवं. प./68, दिनांक 8-4-68)

EDUCATION DEPARTMENT

INDEX

EDUCATION DEPARTMENT

The words "one advance increment shall be allowed to heads of institutions frome the 1st July, 1961. This will not have effect on his normal date of increment. This will not have cumulative effect, provided 'at—" occuring in para 2 of this department order No. F. 10(e) (89)Edu./A/61 dated the 20th July, 1961 under the headings for Higher Secondary Schools and for High Schools be substituted as under:—

"One advance increment may be allowed to heads of Institutions on the date when next increment becomes due following the declaration of the result. This increased rate of pay on account of advance increment may be drawn till the next anniversary of the normal date of increment after which the Government servant shall be entitled to draw pay at the rate corresponding to his position in the time scale. This will be subject to the conditions that:—"

This issues with the concurrence of Finance Department vide this I.D. No. 999 dated the 28th Fabruary 1968.

[Education Department Cell VII Order No. F. 6 (h) 9282/Edu./2/62, dated 29-4-1968.]

FINANCE DEPARTMENT (Expenditure)

INDEX

(46)

विषय:—आय-व्ययक अनुमान 1968-69 ।

राजस्थान विधान सभा ने वर्ष 1968-69 में किये जाने वाले व्यय की पूर्ति के लिये उनके समक्ष रखी गई आय-व्ययक मांगों को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिया है तथा विनियोग विधेयक भी अनुमोदित कर दिया है। इन मांगों पर आधारित विस्तृत आय-व्ययक अनुमान (खण्ड 1 व 2), स्पष्टीकारक स्मृति-पत्र सहित, सम्बन्धित विभागों के पास पहिले ही पृथक से भेज दिये गये हैं। सब नियन्त्रण अधिकारी उनमें दिये गये विवरण के अनुसार अपनी वित्तीय शक्तियों तक सीमित रहते हुए सम्बन्धित अनुदानों का उपयोग कर सकते हैं।

2. मुद्रित आय-व्ययक अनुमानों में कई शीर्षकों में आयोजना या आयोजना भिन्न व्यय के अन्तर्गत एक मुश्त प्रावधान है। इनका उपयोग करने से पूर्व नियन्त्रक अधिकारियों को चाहिये कि वे इनके विस्तृत विवरण प्रशासनिक एवं वित्तीय विभागों द्वारा अनुमोदित करा लेवें। आयोजना व्यय से सम्बन्धित एक मुश्त प्रावधानों के उपयोग किये जाने से पूर्व आयोजना विभाग का अनुमोदन भी आवश्यक होगा। इसी प्रकार नये पदों पर नियुक्तियां भी पदों के सृजन के लिये स्वीकृतियां प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही की जानी चाहिये।

3. केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनायें जिनके लिये आय-व्ययक अनुमानों में भारत सरकार या अन्य स्रोतों से तदनुरूप सहायता की अपेक्षा की गई है तथा जो या तो पहले से ही अनुमोदित हैं अथवा चालू हैं उनके लिये रखे गये प्रावधानों का उपयोग सहायता की स्वीकृति की सीमा तक अथवा अनुच्छेद 2 में पूर्व वर्णित विभागों की स्वीकृति से किया जावेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के परिपत्र सं. एफ 14 (23) एफ. डी./डब्लू. एम./63-2 दिनांक 25 मार्च, 1966 में वर्णित अनुदेशों का भी पूर्ण तथा पालन किये जाने की ओर विशेष ध्यान रखा जाना है।

4. आय-व्ययक अनुमानों में आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय दोनों के लिये ही अलग अलग प्रावधान किये गये हैं। इनकी प्राथमिक इकाईयां तथा विस्तृत मद एक समान ही हैं किन्तु महा लेखाकार द्वारा तैयार किये जाने वाले विनियोग लेखों में आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय अलग अलग दिखाये जाने हेतु पृथक पृथक इकाइयां रखी गई हैं।

5. व्यय पर समुचित नियन्त्रण रखने हेतु विभागीय लेखाओं का महालेखाकार द्वारा रखे जाने वाले लेखों से समय समय पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मिलान करते रहना चाहिये। गत वर्ष के लेखों एवं अंकेक्षा प्रतिवेदनों को देखने से प्रतीत होता है कि कुछ विभाग तो वर्ष भर के लिये स्वीकृत अनुदान कुछ महीनों में ही खर्च कर डालते हैं और कुछ विभाग साल के अन्तिम दिनों में एक साथ खर्च करने की होड़ में रहते हैं। यह दोनों प्रकार की ही प्रवृत्तियां आक्षेप-जनक हैं। अतः समस्त नियन्त्रक अधिकारियों एवं प्रशासनिक सचिवों से अनुरोध है कि स्वीकृत अनुदानों के अन्तर्गत व्यय की गति पूरे वर्ष में सन्तुलित रखी जावे और वित्त विभाग तथा अन्य सक्षम विभागों की स्वीकृति के बिना अनुदानों से अधिक खर्च किये जाने पर वित्तीय नियमों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।

[वित्त (आय-व्ययक) विभाग परिपत्र सं. एफ. 4 (1) वि./ब./68, दिनांक 1-4-68]

(47)

Sub:—Grant of anticipatory pension.

In accordance with Finance Department Memo. No. F. 1(52) FD (Exp-Rule) 65 dated 14-9-1966 as modified vide Memo No. F. 1(52) FD (Exp-Rules)/65 dated 29-4-1967 the pension sanctioning authorities were authorised to (a) sanction anticipatory pension equal to the amount of minimum rate of pension, (b) draw the same on a pay bill from without authority from the Accountant General and (c) arrange payment to the retired Government servant concerned.

2. The matter has been re-examined in consultation with the Accountant General and in supersession of the aforesaid order, it has been decided that in respect of non-gazetted Govt. Servant the Head of office should draw anticipatory pension to the extent of 75% of the pension calculated by him from the Treasury at which the pay and allowances are drawn by him and arrange to disburse the same to the retired Government servant on the first day of the month following the month in which the latter retires from service, and on the first day of each succeeding month during which anticipatory pension has to be paid under this order. Such anticipatory pension should be drawn on the form appended to this Memo. If the pensioner desires the payment to be made to him through Money Order or Bank Draft at the place where he is residing, the pension should be remitted to him through Money Order/Bank Draft, the commission charges being borne by the department as a contingent charge. The payment of anticipatory pension in this amount shall continue upto a period of six months from the date of retirement unless a P.P.O. is issued by the Accountant General before the expiry of this period whereupon payment of anticipatory pension should cease. The pension disbursed in the above manner shall be provisional and subject to adjustment on the issue of final P.P.O. by the Accountant General. Where a pension case is not finalised within six months of the date of retirement the Head of office should request the Accountant General for issue of authority for continuing the payment of anticipatory pension for a further specified period.

3. With a view to ensure that payments of anticipatory pension made by the Heads of Office in accordance with paragraph 2 above do not escape the notice of Accountant General while authorising final payment the Heads of offices should strictly follow the procedure laid down hereunder viz.—

(i) A note about the sanctioning of anticipatory pension should be recorded in the Service Book and details of all payments made till such time as the Service Book along with other pension papers are sent to the Accountant General's office for authorising final payment of pension should be entered therein.

(ii) Copies of the sanction for the grant of anticipatory pension should invariably be sent to the Accountant General.

(iii) A certificate prescribed as under to the effect that anticipatory pension has been paid should be recorded in the pension papers below the order sanctioning pension and a reference to the order under which anticipatory pension was sanctioned should be given.

"Certified that provisional pension @ Rs.——————p.m. sanctioned in favour of Shri/Shrimati——————vide No.——— date————has been/will be drawn for the period from———— to——————.

It is further certified that no amount on the above account has been/will be drawn after the period specified above."

(iv) Proper acquittance of anticipatory pension disbursed should be obtained and kept on record.

The above procedure will not apply to Gazetted Officers who can draw anticipatory pension only on the basis of an authority issued by the Accountant General.

[Finance Deptt. (Rules) Memo. No. F. 1 (52) FD (Exp.-Rules) 65, dated 20-4-1968.]

FORM

(*See Rule* 296)

Bill Form for drawal of provisional pension Gratuity/D.C.R. Gratuity of non-gazetted officers whose pay and allowances are drawn on Establishment Bills by the Head of Office.

District	Head of Account	Voucher No......... for	List ....

	Rs.	P.
Received the amount of provisional pension due to Shri/Shrimati .... for the month of ....19 .... and Gratuity/D. C. R. Gratuity.		
Less Income Tax.		
Net.		

In Words ....

Certificate from the pensioner regarding non-employment is attached.

Station................ Signature..................

Date.................. Designation of the Drawing Officer

Examined and entered. Pay Rs. ......Rupees ......

Treasury Accountant In cash ....Rs. ....

Date.............. IV-Taxes on Income Rs...........

Treasury Officer.

For Use in A. G's. Office

Admitted........................ Rs.........................

Objected....................... Rs.........................

Auditor. *Superintendent.* *G. O.*

(48)

विषयः—सेवा निवृत्ति के बाद निधि में भविष्य निधि की धन राशि को रोके रखना ।

निदेशानुसार निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस विभाग के आदेश संख्या एफ. 4 (4) एफ. डी. (व्यय-नियम) 64, दिनांक 23-12-64 की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है कि जिसमें कि अभिदाता (सबस्क्राइबर) की सेवा निवृत्ति के बाद निधि में भविष्य निधि की राशि को रोके रखने की योजना तीन वर्षों के लिये लागू की गयी थी ।

राज्यपाल ने प्रसन्नतापूर्वक आदेश दिया है कि उपर्युक्त योजना की अवधि दिनांक 23-12-67 से तीन वर्ष के समय के लिए और बढ़ाई जाती है ।

[वित्त विभाग (नियम) आदेश क्रमांक एफ. 4 (4) एफ. डी. (व्यय-नियम) 64, दिनांक 17-4-1968]

(49)

विषयः—राजस्थान सेवा नियम का नियम 48 ।

इस विभाग की सम संख्यक आज्ञा दिनांक 18-11-67 में राज्य कर्मचारियों को यह अनुमति प्रदान की गई थी कि वे बिना नजर अधिकारी की स्वीकृति के आकस्मिक यात्राओं पर परिवार

नियोजन के कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में शंका की गई है कि क्या राज्य कर्मचारी इस प्रसारण का रेम्यूनरेशन (Remuneration) भी बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त कार्य के लिये रेम्यूनरेशन प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है।

[वित्त विभाग (नियम) परिपत्र क्रमांक एफ. 1 (74) वित्त (व्यय-नियम)।67, दिनांक 4-4-68]

---

(50)

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Service Rules, namely.

1. These rules may be called the Rajasthan Service (Amendment) Rules, 1968.

2. In the Rajasthan Service Rules—

(i) in rule 347—

(a) for the words and figure "Rs. 10" wherever they occur the words and figure "Rs. 50/-" shall be substituted;

(b) the existing "Note 2" shall be substituted by the following—

"2. In the case of Government servants who have retired or who retire hereafter before attaining the age of 55 and are re-employed, pension to the extent indicated below shall be ignored in fixing their pay on re-employment:—

(i) in the case of pension not exceeding Rs. 50/- per mensom, the actual pension;

(ii) in other cases, the first Rs. 50/- of the pension.

No amount of pension shall be ignored in fixing the pay of a re-employed pensioner who retires after attaining the age of 55."

(c) the existing notes 3 and 4 be renumbered as notes 4 and 5 respectively and the following be inserted as note 3:—

"3. The pay of persons who are on re-employment on 8-4-68 may be refixed on the basis of note 2 with effect from this date provided they exercise an option in writing for such refixation within a period of six months therefrom. In the event of such refixation their terms should be determined afresh as if they have been re-employed from the said date. The option, once exercised shall be final."

(ii) in rule 351—

(a) the existing 'Note 1' shall be substituted by the following:—

"1. In the case of persons who have retired or who retire from military service before attaining the age of 55 and are re-employed, pension to the extent indicated below shall be ignored in fixing their pay on re-employment:—

(i) in the case of pension not exceeding of Rs. 50/- per mensum, the actual pension;

(ii) in other cases, the first Rs. 50/- of the pension.

No amount of pension shall be ignored in fixing the pay of a re-employed pensioner who retires after attaining the age of 55."

(b) the existing notes 2, 3 and 4 be renumbered as notes 3, 4 and 5 respectively and the following be inserted as note 2—

"2. The pay of persons who are on re-employment on 8-4-1968 may be refixed on the basis of note 2 with effect from this date provided they exercise an option in writing for such refixation within a period of six months therefrom. In the event of such refixation their terms should be determined afresh as if they have been re-employed from the said date. The option, once exercised shall be final.

[Finance Deptt. (Rules) Notification No. F. 1 (80) FD (Exp.-Rules)/65, dated 8-4-68.]

---

(51)

Subject:—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Amendment thereto.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—namely:—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

2. They shall be deemed to have come into force with effect from the date of issue of this Notification.

3. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961 Schedule II part 4 under the heading R.A.S. "Post ordinarily in Scale №.28 (now 29 with effect from 1-4-1966) when held by Officer in Scale №.26" at (page 118) the following entries shall be deleted:—

Deputy Development Commissioner	100/-
Dy. Registrar, Cooperative Societies	100/-

[Finance Deptt. (Rules) Notification No. F. 2 (b) (13) Finance (Rules)/68, dated 15-4-1968.]

(52)

Subject:—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—as amended on 1-4-1966—Schedule II—Part IV—Secretariat.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely:—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) *Amendment* Rules, 1968.

2. They shall be deemed to have come into force with effect from the date of creation of the post or the date of joining whichever is latter.

3. In Schedule II-Part 4 of the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961 the following new entries may be inserted under heading "Secretariat" (Page 120).

P. A. attached to Parliamentary Secretaries. 25/- p.m.

[F. D. Notification No. F. 2 (b) (14) F. D. (Rules)/68, dated 30-4-1968.]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

INDEX

(16)

राज्यपाल महोदय सहर्ष समस्त जिलाधीशों को अपने अपने जिले में आगामी उप-चुनाव के सम्बन्ध में मतदान के दिन तथा उससे एक दिन पहले केवल मतदान क्षेत्र में ही सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिये प्राधिकृत करते हैं।

[सामान्य प्रशासन (क) विभाग आज्ञा संख्या प. 2 (13) सा।प्रा।क।66, दिनांक 10-4-68।]

---

(17)

विषय:—राजकीय कार्यालयों/निवास स्थानों में परिवर्तन/परिवर्धन।

निदेशानुसार निवेदन है कि राज्य सरकार ने धनराशि की कमी को ध्यान में रख कर लिये गये निर्णय के अनुसार समस्त जिलों में (मुख्यालय व अन्तरंग भाग) राजकीय भवनों में परिवर्तन/परिवर्धन के लिए इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध धनराशि के जिलेवार संलग्न सूची के अनुसार आवंटन किया है। अतः आप से अनुरोध है कि आप अपने जिले के राजकीय भवनों में परिवर्तन/परिवर्धन सम्बन्धी प्रस्ताव संलग्न तालिका में अंकित प्रस्तावित आर्थिक सीमा के अन्तर्गत प्राथमिकता के अनुसार इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र भेज दें ताकि प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रचलित की जा सके। प्राथमिकता का आधार मंत्रि मण्डल या अन्य उच्चस्तरीय बैठकों के लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित करना तथा जिन जिलों में सरकारी कार्यालय किराये के मकानों में हैं उनको राजकीय भवनों में अतिरिक्त कमरे इत्यादि बना कर उनको उनमें स्थापित करना है। आर्थिक सीमा से अधिक राशि के प्रस्ताव स्वीकृति किये जाना किसी प्रकार भी संभव न होगा। आपके प्रस्ताव दिनांक 31-5-68 तक अवश्य ही इस विभाग को पहुंच जाने चाहिए। यदि इस दिनांक तक प्रस्ताव न प्राप्त हुए तो जिलों को आवंटित धन राशि अन्य कार्यों के उपयोग में ली जावेगी। यह भी लेख किया जाना आवश्यक है कि फुटकर प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार नहीं किया जावेगा और जो भी फुटकर प्रस्ताव अब तक इस विभाग को भेजे गये हैं उन पर विचार नहीं किया जावेगा।

समस्त विभागाध्यक्ष अपने विभाग में परिवर्तन/ परिवर्धन सम्बन्धी प्रस्ताव अपने जिले के जिलाधीशों को तुरन्त भेजेंगे तथा जिलाधीश द्वारा उपरोक्त वर्णित आधार पर प्राथमिकता से उन प्रस्तावों की सूची बनाकर इस विभाग में प्रेषित की जावेगी।

समस्त जिलाधीश अपने जिले के समस्त भवन निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव अपने जिले के सम्बन्धित अभियन्ता, द्वारा तैयार करा कर उनके अनुमानित व्यय तैयार कराकर इस विभाग को प्रेषित करेंगे। इसी प्रकार समस्त विभागाध्यक्ष भी अपने विभाग सम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा तैयार कर जिलाधीश की सूची में प्रविष्ट करने हेतु भेजेंगे तथा सूचना इस विभाग को भी देवेंगे।

[सामान्य प्रशासन (क) विभाग संख्या प. 5 (29) सा.प्र.।क।68, दिनांक 16-4-68]

विषय:—जिलेवार राजकीय भवनों में परिवर्तन/परिवर्धन के लिए उपलब्ध धनराशि की वितरण तालिका सन् 1968-69।

क्रम संख्या	जिला	धन राशि
1.	राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	50,000)
2.	राजस्थान सचिवालय, जयपुर	3,000)
3.	गंगानगर	15,000)
4.	बीकानेर	15,000)
5.	चूरू	10,000)
6.	झुंझुनूं	10,000)
7.	अलवर	15,000)
8.	भरतपुर	15,000)
9.	सवाई माधोपुर	12,000)
10.	जयपुर	28,000)
11.	सीकर	12,000)
12.	अजमेर	17,000)
13.	टोंक	12,000)
14.	जैसलमेर	3,000)
15.	जोधपुर	17,000)
16.	नागौर	12,000)
17.	पाली	12,000)
18.	बाड़मेर	12,000)
19.	जालौर	12,000)
20.	सिरोही	12,000)
21.	भीलवाड़ा	15,000)
22.	उदयपुर	25,000)
23.	चित्तौड़गढ़	12,000)
24.	डूंगरपुर	12,000)
25.	बांसवाड़ा	10,000)
26.	बूंदी	7,000)
27.	कोटा	15,000)
28.	झालावाड़	10,000)
	योग : ..	4,00,000)

(18)

The Governor has been pleased to order that Shri B. K. Kaul, Chairman of the Committee Constituted to consider the amalgamation of the two Corporations viz., The Rajasthan State Hotels Corporation Ltd, Jaipur and the Rajasthan Small Scale Industries Corporation Ltd., Jaipur will be entitled to stay in the Circuit Houses on the same terms and conditions on which the Ministers are entitled.

This order will have the effect from the date of his appointment as Chairman of the Committee.

[G. A. (A) Deptt. order No. F. 27 (3) GA/A/66, dated 23-4-68].

---

(19)

Copy of letter No. 18/9/67-pub-II dated 5th August, 1967 from the under Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi to All State Governments.

Sub:—Use of abbreviation by recipients of awards after their names—

I am directed to enclose for the *information* and guidance of the State Government/Union Territory Administration, a copy of the Ministry of Defence Memorandum No. F. 3 (43)/61/D (Ceremonials) dated the 22nd July, 1967, on the subject mentioned above.

Copy.

No. F. 3 (43)/61/D (Ceremonials).

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, July 22, 1967.

MEMORANDUM

Sub:—Use of Abbreviation by Recipients of Awards after their names.

In the supersession of this Ministry's memorandum of even number dated 19th July, 1962 and in partial modification of this Ministry's U. O. note of even number dated 18th May, 1965, on the subject mentioned above, it has been decided that the following abbreviations may be used by the recipients after their names:—

Ashoka Chakra	—AC
Kriti Chakra	—KC
Shiurya Chakra	—SC
Param Vishisht Seva Medal	—PVSM
Ati Vishisht Seva Medal	—AVSM
Vishisht Seva Medal	—VSM

Sena Medal —SM
Nao Sena Medal —NM
Vayu Sena Medal —VM

[सामान्य प्रशासन (क) विभाग पत्रांकन सं एफ 12 (13) सा.प्र. (क)/68, दिनांक 5-4-1968]

(20)

The Governor has been pleased to order that Rule 6 for the maintenance and occupation of Government Cottages at Mount Abu appended with this department letter No. F. 17 (a) (63) GA/A/62-Gr.I, dated the 12th November, 1962, may be amended so as to include "Speaker and Dy. Speaker" under item No. 2 of the said, Rule.

This issues with the concurrence of the Finance Department vide their I.D No. 440/F.D./Exp.-II/63, dated the 27th March, 1968.

[G. A. (A) Order No. F. 17 (a) (7) G. A/A/64 Gr. I dated 17-4-68.]

(21)

Copy of latter No. 24/5/67—Adm. dated the 16th Feb., 1968 from Shri K.K. Leuva, Zonal Director, Backward Classes Welfare, Government of India, office of the Zonal Director to the Secretary to the Government of Rajasthan General Administration Department, Jaipur.

Sub:—Closure of the offices of the Deputy Director, Backward Classes Welfare, Governmen of India, at Poona and Jaipur.

Due to reorganisation of the office of the Director General, Backward Classes Welfare, Government of India, the offices of the Deputy Directors, Backward Classes, Welfare in the various states and Union Territories have now been closed. Accordingly the office of the Deputy Director, Backward Classes Welfare at Poona/Jaipur has been closed from 1st February, 1968. It is, therefore, requested that all correspondance intended for the Deputy Director, Backward Classes Welfare Poona/Jaipur, or Deputy Commissioner/Assistant Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Poona/Jaipur may now be addressed to the undersigned as follows:—

The Zonal Director
Backward Classes Welfare
(West Zone), Government of India,
Yashkamal Building, 6th Floor,
Lokmanya Tilak Road, *BARODA-5.*

The telephone number and the Telegraphic address as mentioned above may also please be noted.

[G. A (A) Deptt. endst. No. F. 2 (5) GA/A/66, dated 17-4-1968.]

HOME DEPARTMENT

INDEX

(12)

विषय:—प्रूफ लौटाने में विलम्ब के लिये पैनल्टी के रूप में अतिरिक्त प्रभार वसूल किये जाने के सम्बन्ध में ।

उक्त विषय में इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र सं. एफ. 3 (14) गृह (घ)/62 दिनांक 5 दिसम्बर, 1962 के अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को राजकीय विभागों/ कार्यालय द्वारा सम्बन्धित मुद्रणालय को प्रूफ पढ़ कर तथा आवश्यक संशोधन कर उन्हें लौटाने में आवश्यकता से अधिक विलम्ब करने की आशा में ऐसे विभागों/कार्यालयों के विरुद्ध पैनल्टी लगाये जाने हेतु अधिकृत किया गया था, किन्तु उक्त परिपत्र में पैनल्टी की कोई दर निश्चित नहीं की गई थी । अतः वर्तमान में भी उक्त विषयक शिकायतें विद्यमान होने के कारण राज्य सरकार ने मामले पर पुनः विचार कर विलम्ब से प्रूफ लौटाने के लिये पैनल्टी की दर निश्चित करते हुए वसूली के सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्धति अपनाई जाने का निर्णय लिया है :—

(1) साधारण एवं असाधारण कार्यों के प्रूफ्स को पढ़ कर मुद्रण आदेश के साथ उनकी प्राप्ति के क्रमशः 7 दिवस एवं 15 दिवस की अवधि में नहीं लौटाने की दशा में दोषी विभाग/कार्यालय के विरुद्ध कम्पोजिंग प्रभार के 5 प्रतिशत प्रति दिवस के हिसाब से पैनल्टी लगाई जावेगी जिसकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित विभाग/कार्यालय द्वारा दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों से वसूली की जावेगी ।

20 पृष्ठ फुल स्केप साइज एवं इसके अनुरूप प्रूफ मैटर को साधारण कार्य तथा 20 पृष्ठ से अधिक प्रूफ मैटर को असाधारण कार्य समझा जायेगा । जहां प्रूफ किस्तों में प्राप्त होंग, प्रत्येक किस्त को पृथक कार्य इकाई समझा जायेगा ।

(2) पांडुलिपि को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही मुद्रण हेतु मुद्रणालय को भेजा जाना चाहिये । यदि मुद्रणालय को भेजने के पश्चात् पाण्डुलिपि में कोई हेर फेर किया जायगा तो ऐसी दशा में कम्पोज किये मैटर के लिए दुबारा पूर्व में कम्पोज किए गए मैटर के साथ कम्पोजिंग प्रभार लगाया जाकर सम्बन्धित विभाग के नाम लिखा जावेगा ।

(3) पैनल्टी के प्रभार विलम्ब की अवधि का विस्तृत विवरण देते हुए बिल में पृथक से अंकित किये जावेंगे । जहां प्रूफ किस्तों में प्राप्त होते हैं वहां प्रत्येक किस्त के लिए विलम्ब की अवधि दिखाई जायेगी ।

(4) विलम्ब से प्राप्त होने वाले प्रूफ्स के लिए लगाई गई पैनल्टी के समस्त मामलों के इन्द्राज हेतु राजकीय मुद्रणालय द्वारा एक पंजिका उपयुक्त तालिका में रखी जावेगी ।

(5) प्रूफ्स लौटाने में लिए गए समय की गणना विभाग/कार्यालय को प्रूफ्स मिलने की तिथि से उसके वापिस मुद्रणालय को लौटाने की तिथि तक अग्रिम पड़ने वाले राजपत्रित अवकाशों को पृथक करते हुए, की जावेगी ।

(6) विलम्ब से प्रूफ लौटाने के समस्त मामलों की कार्यालय अध्यक्षों द्वारा बिल प्राप्ति के एक माह में जांच कर सम्बन्धित मुद्रणालय को यह सूचित करना चाहिए कि क्या दोषी व्यक्ति के विरुद्ध हानि की वसूली हेतु सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है या विलम्ब को उचित मानते हुए मामले में अन्तिम निर्णय लेने हेतु विभागाध्यक्ष को लिख दिया गया है। विभागाध्यक्ष विलम्ब का उचित प्रमाणीकरण देने के लिए अन्तिम सक्षम प्राधिकारी होंगे। और बिल प्राप्ति के तीन माह की अवधि में निर्णय लेकर सम्बन्धित राजकीय मुद्रणालय को सूचित कर देंगे।

(8) जिन कार्यालयाध्यक्षों अथवा विभागाध्यक्षों से अनुच्छेद 6 में वर्णित रिपोर्ट प्राप्त नहीं होगी, उनके बारे में निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, सम्बन्धित शासन सचिवों को प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक सूचना दे देंगे जो अग्रिम उचित कार्यवाही करेंगे।

(9) उक्त पद्धति अन्तिम प्रूफ पढ़ने के पश्चात् नये हेर फेर कर यथोचित परिवर्तन करने वाले मामलों पर भी लागू होगी।

[गृह (घ) विभाग परिपत्र संख्या प.4(9) गृह (घ)।67, दिनांक 17-4-63।]

---

(13)

विषय:—प्रूफ लौटाने में विलम्ब के लिये पैनाल्टी के रूप में अतिरिक्त प्रभार वसूल किये जाने के संबंध में।

इस विभाग से प्रचलित समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17-4-68 के बिन्दु संख्या "8" व "9" को कृपया '7' और '8' पढ़ा जावे।

[गृह (घ) विभाग शुद्धि पत्र संख्या प. 4(9) गृह (घ)।67, दिनांक 27-4-68]

---

(14)

Subject:—Proscription of Urdu book entitled 'Hadiya Tayyab (Ulmaroof Ba Mohare Sakoot' written by Syed Ali Ulnaovi) 'Asar' Amrohivi M. A. (Aligarh) Retd. Principal.

I am directed to forward for information and necessary action a copy of Notification No. 8694-RVM-BM-1249/66, dated 8-2-1968 from the Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Lucknow on the subject cited above.

[Home (A) Deptt. letter No. F. 17 (5) H.A.-II/68, dated 8-4-68.]

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 8694-R/VIII-B-129/65, dated February 8, 1968.

NOTIFICATION

No. 8694-R / VIII-B-II 1249 / 66. *Dated February 8, 1968.*

Whereas, it appears to the State Government that the book entitled 'Hadiya Tayyab (Ulmaroof Ba Mohare Sakoot)' written in

Urdu by Syed Laqa Ali Ulnaovi 'Asar', Amrohivi M.A. (Aligarh) Retired Principal. and Printed and Published by Syed Laq Ali Nasheman, Moh. Guzri, Amroha at Semo Letho Press, Delhi makes insulting and derogatory remarks against Amir Meaviva, Hazrat Abu-Baker Siddiq, Hazrat Omar and Hazrat Aoesha, which are liable to give offence to Sunni Muslims generally and thus contains matter which promotes and is intended to promote feelings of enmity and hatred between different classes of the citizens of India namely, Shia Muslims and Sunni Muslims and the publication of which is punishable under section 153-A of the Indian Penal Code (Act No. 45 of 1860);

Now, therefore, in exercise of the powers under section 99-A of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. 5 of 1898), and on the grounds mentioned above, the Governor is pleased to declare every copy of the aforesaid book written in Urdu and of any other documents containing copies, reprints and translation of, or extracts from the said book to be forfeited to Government.

By Order,
Sd/- HARIHAR CHAUBE,
Sahayak Sachiva.

LAW DEPARTMENT

INDEX

विषय :—नोटेरीज एक्ट, 1952 के अन्तर्गत नोटेरी की नियुक्ति ।

राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार श्री जय सिंह नरूला, एडवोकेट को जयपुर जिला (जयपुर शहर को सम्मिलित करते हुए) के स्थानीय क्षेत्र में नोटेरी के पद पर नियुक्ति किया जाता है ।

यह नियुक्ति उस तिथि से जिस दिन से उन्हें निर्धारित शुल्क 100) रुपये जमा कराने पर प्रमाण-पत्र जारी किया जाये, तीन वर्ष की अवधि के लिये होगी ।

[न्याय विभाग आज्ञा संख्या एफ. 39 (2) न्याय 167, दिनांक 17-4-68.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

INDEX

In exercise of the powers conferred by Section 7-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act 14 of 1947), the Government of Rajasthan hereby constitutes with immediate effect an Additional Industrial Tribunal for the adjudication of industrial disputes relating to the matters specified in the Second or the Third Schedule to the Act and as arising in the State of Rajasthan, and appoints Shri B.C. Ojha, Judge Labour Court as its Presiding Officer.

[Labour & Employment Deptt. Notification No. F. 1 (13) Lab./68/(L&E) dated 17/18-4-1968.]

केवल कार्यालय उपयोगार्थ

राजस्थान सरकार

मंत्रि-मण्डल सचिवालय

व्यवस्था एवं पद्धति (संकलन) अनुभाग

फरवरी, 1968 में
शासन सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गए महत्वपूर्ण परिपत्रादि का मासिक संकलन

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

1968

उन विभागों की सूची जिनके महत्वपूर्ण परिपत्रों आदि को फरवरी, 68 के संकलन में मुद्रित किया गया है :—

CABINET SECRETARIAT INCLUDING O. & M.

INDEX

CABINET SECRETARIAT
(including O. & M.)

(3)

विषय:—मंत्रियों । उप मंत्रियों को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों का निवर्तन ।

उपर्युक्त विषय में इस सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) के परिपत्र संख्या प. 1 (44) नियुक्ति (व्य. एवं प.) । 57 दिनांक 1-11-57 में यह अभिव्यक्त किया गया था कि मंत्रियों । उप मंत्रियों को सीधे प्रस्तुत होने वाले आवेदन-पत्रों । प्रार्थना-पत्रों इत्यादि पर सम्बन्धित विभागाध्यक्षों । सचिवालय के विभागों । अनुभागों । प्रकोष्ठों द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देकर मंत्रियों । उप मंत्रियो द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर दिये जावें और विभागाध्यक्षों द्वारा औपचारिक उत्तर संबधित शासन सचिव द्वारा प्रस्तुत करने के साथ साथ उनके प्रतिवेदनों की अग्रिम प्रतिलिपियां मंत्रियो । उप मंत्रियों के निजी सचिवों को मंत्री महोदय के सूचनार्थ सीधी पृष्ठांकित की जावे । परन्तु उपरोक्त आदेशों का पूर्णरूपेण पालन नहीं हो रहा है ।

अतः पुनः साग्रह अनुरोध है कि भविष्य में उपरोक्त आदेशों का कड़ाई के साथ पालन किया जावे तथा अपेक्षित प्रतिवेदन तुरन्त प्रस्तुत किये जावे ।

[मंत्री मन्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग परिपत्र क्रमांक पत्र संख्या 1(2),व्य. एव प. 68, दिनांक 21-2-68]

---

(4)

विषय:—जन लेखा समिति की सिफारिशों का शीघ्र क्रियान्वन-पंजिका का रख-रखाव तथा व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग को विवरण का भिजवाना ।

उपरोक्त विषय मे विभिन्न परिपत्रों द्वारा समय समय पर जन लेखा समिति द्वारा मांगी गई सूचना को तत्काल भिजवाने तथा सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता रहा है तथा शासन सचिवों से निवेदन किया जाता रहा है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों से सम्बन्धित जन लेखा समिति की सिफारिशो के विचाराधीन विषयों का त्रैमासिक विवरण नियमित रूप से भिजवाने का प्रबन्ध करें । किन्तु खेद है कि इस ओर अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है और सामान्य तौर पर जन लेखा समिति से सम्बन्धित मामलो पर उसी समय अधिक ध्यान दिया जाता है जबकि जन लेखा समिति की बैठक की सूचना प्राप्त होती है ।

2. पहले तो इस बात पर बल देना जरूरी है कि प्रत्येक विभाग का कार्य इस सुचारु रूप से किया जावे कि विभाग का कोई भी मामला जन लेखा समिति के सामने ही न आवे । यह तब सम्भव होगा जब कि लेखा तथा अन्य का सम्बन्धित नियमों का पूरी तरह पालन हो । फिर भी यदि कोई लेखा आक्षेप (आडिट आब्जेक्शन) आता है तो उसका तुरन्त जवाब दिया जावे । प्रायः ऐसा देखने में आया है कि आडिट के गम्भीर आक्षेपों का (जिसकी ओर महालेखाकार सम्बन्धित प्रशासनिक सचिव का विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं) समय पर जवाब नहीं दिया जाता और जब ड्राफ्ट पैरा आता है तो भी कभी उसका नियत समय में अन्तिम उत्तर नहीं भेजा जाता । इसके परिणामस्वरूप जन लेखा समिति के सामने बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा वांछित सूचना के अभाव में विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।

3. भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो इसके लिये समस्त सचिवों से अनुरोध है कि:—

(1) लेखा आक्षेप (आडिट आब्जेक्शन) के समय पर निपट के लिये तथा लेखा समाधान (रिकन्साइलेशन आफ अकाउन्ट्स) का कार्य पिछड़ा न रह जाये, इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जावे।

(2) ड्राफ्ट पैरा का अन्तिम उत्तर नियमित समय (8 सप्ताह) में भेजा जावे।

(3) वित्त (बजट) विभाग के अशासकीय टीप सं. एफ. 14 (16) एफ. (बी) । 55, दिनांक 4-8-55 (जिसकी प्रति संलग्न है) के अनुसार-

क. जन लेखा समिति द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित समय (4 माह) में भेजी जावे।

ख. जन लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(4) जन लेखा समिति सम्बन्धित पंजिकाओं के रख-रखाव के लिये व्यवस्था एवं पद्धति विभाग के परिपत्र संख्या एफ. 10 (30) अपाइन्टमेन्ट्स (ओ एन्ड एम) । 57, दिनांक 30 सितम्बर, 57 के पद तीन (जिसके उद्धरण की प्रतिलिपि संलग्न है) में दिये गये आदेशों की पूरी तरह पालना की जावे। इसके लिये सम्बन्धित अनुभागाधिकारी । सहायक सचिव । लेखाधिकारी सहायक लेखाधिकारी जो भी उस विभाग । अनुभाग । प्रकोष्ठ के अधिकारी हों वे इस कार्य के लिये जिम्मेवार होंगे।

4. समस्त शासन सचिव कृपया उनके अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों की एक बैठक बुलवाये और यह देखें कि लेखा आक्षेप (आडिट आब्जेक्शन) तथा जन लेखा समिति सम्बन्धी मामलों पर यदि उनके विभाग में उपरोक्त आदेशानुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है तो अब अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही आरम्भ करवाने की व्यवस्था करें, तथा भविष्य में व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग को उनके अधीनस्थ विभागों के उपरोक्त विषयों के त्रैमासिक विवरण उन्हीं के हस्ताक्षरों द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

5. चूंकि व्यवस्था एवं पद्धति विभाग को इस विषय के त्रैमासिक विवरण सम्बन्धित सचिवों के हस्ताक्षर से ही भेजे जावेंगे अत: आप उनसे अनुरोध है कि वे अपने अधीन किसी सहायक सचिव या उनके स्तर के किसी अन्य अधिकारी को उपरोक्त त्रैमासिक विवरण एकत्रित करने एवं व्यवस्था एवं पद्धति विभाग को समय पर भिजवाने के लिये नियोजित कर इस अनुभाग को सूचित करने की कृपा करें। यह अधिकारी अपने सचिव के आधीन सभी विभागों के लिये उपरोक्त कार्य के लिये उत्तरदायी होगा।

[एफ. 10 (8) व्य. एवं प. 68 दिनांक 14-2-68]

Copy of F. D. (Budget) U. O. Note No. F. 14 (16) *F. (B)*/55 dated 4th *August*, 1955.

A meeting of the Secretaries and Deputy Secretaries to Government was held on the 3rd July, 1955 in the Library Room under the presidentship of the Additional Chief Secretary to discuss the questions regarding supply of information by Government departments to the Public Accounts Committee and the implementation by the Government Departments of the recommendations of the Committee. attention of the Secretaries was also drawn to the Accountant General's complaint regarding the delay in the disposal of draft paras which are sent by the Accountant General's office to the different departments of the Secretariat for confirmation. It was decided in the meeting that the Accountant General's letters regarding draft paras should be promptly attended to and that the Secretaries may also see that the reconciliation of accounts was brought upto date as it was necessary for proper control of expenditure.

As regards implementation of the recommendations made by the Public Accounts Committee the following procedure was agreed to:—

1. The Finance Department should be the co-ordinating Department for the purpose of pursuing implementation of the recommendations made by the Committee and also for sending information required by the Committee as may be decided in the course of examinations of the officers.

2. There should be a register in each department. A proforma is being prepared by Finance Department and will follow. Such questions and informations which are to be dealt with in the Department should be taken down in the register and further progress should be recorded. Office Superintendents should be made responsible for the maintenance of this register.

3. A quarterly report should be sent to the Chief Secretary on the basis of the entries in the register with regard to the progress made in the matter of implementation of the committee's recommendations.

4. With a view to maintain consistency in the supply of information to the Public Accounts Committee the reply should be sent in consultation with the Finance Department. The draft replies should be sent to the Budget Officer by name in the Finance Department. The Budget Officer will dispose of these cases as expeditiously as possible.

The officers should take action for sending replies within a week to the Legislative Assembly in respect of the recommendations so far made.

These points were discussed by the Public Accounts Committee also on the 7th July, 1955 and they agreed to allow a maximum period of 3 months for sending replies to them. It was also agreed that the concerned administrative departments of the Secretariat should send periodical reports of the action taken and the results achieved on the recom-

mendations made by the Public Accounts Committee. The Committee had also no objection to replies being sent through the Finance Department. but for the time being it has been decided to adopt the procedure as agreed to in the meeting of the Secretaries to Government, and mentioned in item 4 above.

It is requested that the Secretaries will kindly ensure compliance of these instructions and may see that:—

(*i*) replies to the Public Accounts Committee are sent in time, i. e. 3 months from the date of reference,

(*ii*) prompt action is taken on the recommendations of the Committee in consultation with the Finance Deparmtent,

(*iii*) final replies to draft paras are given within the prescribed period of six weeks. and

(*iv*) that the reconciliation of accounts is not allowed to fall in arrears.

They may issue necessary instructions in this connection to all the Heads of Departments. other controlling authorities and Deputy and Assistant Secretaries under their control.

Sd/- (G. S. PUROHIT),
Secretary to the Government.

(*Extract taken from the Circular No. F.* 10 (30) *Apptts* (*O & M*)/57, *dated the* 30*th September*. 1957 *of Appointments* (*O & M*) *Deptt.*)

3. The following instructions should in future be observed in maintaining the Register;—

1. The Superintendent/Incharge of the Department/Section should first see that Report of the Public Accounts Committee and note down in the Register the paras of the report with which his Department/Section is concerned.

2. Atleast half page of the Register should be earmarked for each item.

3. References/enquiries on a particular para of the report, it received from the Public Accounts Committee should invariably be posted first in the Register in the space left under each item for a particular para of the Report. When a final reply is sent to the Public Accounts Committee, the entries must be got initialled by the Secretary of the Department concerned. The number and date of the Public Accounts Committee's communications should be noted in column 2 of the Register. Similarly oral enquiries made by the Public Accounts Committee at the time of examination about which a report has to be sent should also be entered in the Register.

4. So far according to para 3 of the Circular referred to above each department/Section was furnishing the Quarterly Return to this Department. Now it has been decided that in future the Quarterly Return will be sent by each Secretary in the proforma attached herewith the respect of all Departments/Section under his control.

5. It is requested that all the Secretaries will kindly see the return in the prescribed proforma on the 1st January, 1st April, 1st July and 1st October. The Organisation & Methods Section will then put up a consolidated statement to the Chief Secretary to the Government for information.

6. It is also suggested that replies to be sent to the Public Accounts Committee should be shown to the Minister-in-Charge also before transmission to the Finance Department for vetting except in the cases of minor recommendation of a routine nature.

Copy of letter dated the 28th February, 1968 received from the Secretary. Rajasthan Legislative Assembly. again complaining about the failure of various Departments to furnish copies of the replies to the questions in the Assembly in time is attached I had already addressed all Secretaries to Government and others concerned more than once emphasising the need to ensure the receipt of the copies of such replies by the Secretary of the Legislative Assembly sufficiently in time before the relevant questions are due for answer on the floor of the House It is extremely disappointing that the complaint still persists. Often this failure can lead to serious difficulties for Government themselves I would therefore once again impress upon the Secretaries to Government Heads of Departments and all other officers concerned. the necessity to ensure that the questions for reply in the Legislative Assembly receive immediate and top priority treatment at all stages. whether it be in the Secretariat or in the office of the Head of Department or in any other office. I had at one time suggested that an individual official should be made responsible in each office to deal exclusively with matters relating to the Assembly so that information will be readily available as to the time by which replies are to be sent and it will be easier to check up whether the replies have been sent I would like all concerned to ensure that this is done immediately and also to have a report as to the action taken in this direction on this and on my earlier communications

I would like to have the name of the officer made responsible for dealing with Assembly questions in each Department.

(Cabinet Sectt. O&M Section Circular No. F 10 (3) O&M/68. dated. 4-2-68).

Copy of D. O. Letter No. 3940 LA/68/QB. dated the 28th February, 1968, from Shri B. K D. Badgal. Secretary. Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur . addressed to Shri K. P. U. Menon. Chief Secretary to the Government of Rajasthan, Jaipur.

Kindly refer to my D. O. letter No. 455, dated the 11th January, 1968, regarding supply of copies of replies to questions.

In this connection I am desired to say that only a few replies to questions are received in this Secretariat by 12 00 noon on the day before the day on which they are scheduled for reply on the floor of the House and that in majority of cases such replies are received on the very day and sometimes even after their replies have been given in the House. It has also been noticed that in some cases lists. papers etc. referred to in the replies to questions, which are required to be laid on the table of the House, are not enclosed. The result is that their copies are not supplied to the Members concerned in advance, as required under the Rules and the Members complaint therefor in the House. Such a case happend on the 23rd February. 1968. and the Minister had to express regret for it. I may also state for your information that even today replies to 11 questions were not received from the Government Departments by 11.00 A. M. when the sitting of the House was to commence. Hon, ble the Speaker has also to look into the answers received but on account of the delay in sending copies he does not get an opportunity to look into them. He has expressed that this position is very unsatisfactory.

I shall, therefore, feel grateful if you would kindly ask all the Departments to send proposed replies to all the Starred and Unstarred Questions positively by 12.00 noon on the day before the day on which they are scheduled for reply on the floor of the House and also to ensure that the statements, lists etc referred to therein are enclosed.

Action taken in the matter may kindly be intimated to this Secretariat for the information of Hon'ble the Speaker.

---

(6)

विषय :—सचिवालय के अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों/अनुभागों/प्रकोष्ठों का सामयिक निरीक्षण।

सन्दर्भ :—व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग की आज्ञा सं. एफ. 5(66) व्य. एवं पं./63 दिनांक 29-8-63, तथा परि पत्र सख्या एफ. 11(20)ओ. एण्ड एम./63, दिनाक 6-2-64।

उपर्युक्त आज्ञा और परिपत्र के अनुसार सचिवालय के अधिकारियों को अपने अधीनस्थ विभागों।अनुभागों।प्रकोष्ठों का निरीक्षण करना और निरीक्षण प्रतिवेदन व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग को यथा समय भेजना आवश्यक होता है। प्रशासनिक कार्यो में होने वाले अनावश्यक विलम्ब तथा शिथिलता को दूर करने तथा कार्यकुशलता में वृद्धि क लिये निरीक्षणों का महत्वपूर्ण स्थान है। कार्य के सम्यक सम्पादन मे समय समय पर आने वाली कठिनाइयों।बाधाओं आदि के निराकरण मे भी सामयिक निरीक्षण बहुत लाभप्रद सिद्ध होते हैं।

किन्तु यह देखने में आया है कि कई अधिकारियों से उनके सामयिक निरीक्षण, प्रतिवेदन या तो प्राप्त ही नही होते और यदि प्राप्त होते है तो उनमें से बहुत से इतने विलम्ब से प्राप्त होते है कि निरीक्षण का उद्देश्य ही तिरोहित हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ निरीक्षण प्रतिवेदनों में निरीक्षण के उद्देश्यो की पूर्ति का अभाव प्रायः परिलक्षित होता है।

अतः सचिवालय के समस्त अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ विभाग। अनुभाग/प्रकोष्ठ का निरीक्षण कर निरीक्षण-प्रतिवेदन व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग को निर्धारित अवधि में भिजवाने की ओर विशेष ध्यान द।

जिस विभाग।अनुभाग।प्रकोष्ठ आदि में अनुभागाधिकारी नहीं है उसका त्रैमासिक निरीक्षण उस अनुभाग के सहायक लेखाधिकारी/सहायक/लेखाकार या जो भी उस अनुभाग/प्रकोष्ठ आदि का प्रभारी (इन्चार्ज) हो, करेगा। यदि किसी अनुभाग प्रकोष्ठ आदि मे इस स्तर का अधिकारी न हो तो उसका त्रैमासिक निरीक्षण उस अनुभाग।प्रकोष्ठ के प्रशासनिक सचिव द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा होगा। ऐसे निरीक्षण प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारी के अवलोकन के पश्चात् व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग की आज्ञा सं. एफ. 7(55)ओ. एण्ड एम./59 दि. 13-9-62 की अनुपालना में व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग को भेजे जावेंगे।

[व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग परि पत्र क्रमांक एफ. 7(28) व्य एवं पं- 67 दिनांक 10-1-68]

---

(7)

विषय :—सचिवालय मन्त्रालयिक कर्मचारी वर्ग के स्थानान्तरण सम्बन्धी नियम।

सन्दर्भ :—शासनादेश संख्या एफ़. 2(1)एपोइ।ओ.एण्ड एम।58 दिनांक 5-2-1958

उपर्युक्त शासनादेश के अनुच्छेद 2(2) में यह स्पष्ट किया गया था कि सभी लिपिक कम से कम तीन वर्षों में एक वार उनके तात्कालिक निर्दिष्ट कार्यों से हटाये जाकर उसी प्रशासनिक विभाग के उसी अनुभाग।प्रकोष्ट या दूसरे अनुभागों में दूसरे कार्यों पर वदल दिये जाने चाहिये। उनके साथ या उनके पीछे काम करने वाले अन्य लिपिक को भी कार्य निष्पादन का सम्यकज्ञान प्राप्त हो सके और किसी भी कारणवश उन तथाकथितविशेषज्ञों की अनुपस्थिति में उनके अन्य साथियों की उनके कार्यों से अनभिज्ञता के कारण आवश्यकता पर उन कार्यों के सम्यक सम्पादन में कठिनाई उत्पन्न न हो।

इसी दृष्टि से शासनादेश संख्या एफ़. 2(41) एपोइ।ओ. एण्ड एम.।59 दिनांक 10-9-1959 में यह सुझाव दिया गया था कि वे विभाग/अनुभागाधिकारी जिनके आधीन एक से अधिक अनुभाग प्रकोष्ट हैं अनुभवी तथा अनुभवहीन लिपिकों को अनुभागों। प्रकोष्टों में समानुपात में वांटलें। जिस विभाग अनुभागाधिकारी के आधीन केवल एक ही अनुभाग हो वह अपनी कठिनाई सम्बन्धित सचिव के सामने रखे ताकि सम्बन्धित सचिव महोदय अपने अधीनस्थ अनुभागों में कार्यानुभवी तथा अनुभवहीन लिपिकों का समानुपात रखने के लिये लिपिकों का तदनुरूप स्थानान्तरण करने की आवश्यक व्यवस्था करे:

किन्तु यह देखा गया है कि उपर्युक्त आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। यह अनुभव किया गया है कि लिपिकों में कार्य परिवर्तन के अभाव में उन्हें अन्य करणीय कार्यों का अनुभव नहीं हो पाता जहां तक कनिष्ठ लिपिकों का सम्बन्ध है उनमें से टंककों पर वड़ा श्रम पड़ता है जब कि दूसरे कनिष्ठ लिपिक टंकण में अपनी पूर्व प्राप्त गति भी खो बैठते हैं। अतः पुनः अनुरोध है कि ऊपर बताये आदेशों के अनुसार कर्मचारी वर्ग कनिष्ठ लिपिकों, वरिष्ठलिपिकों, तथा सहायकों का भी स्थानान्तरण कम से कम तीन वर्षों में एक वार उसी विभाग/अनुभाग में या सम्बन्धित प्रशासनिक सचिव के दूसरे विभाग या अनुभाग में कर दिया जाना चाहिये।

[व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा क्रमांक एफ 1(34) व्य. एवं प. 67 दिनांक 25-1-68]

———

FINANCE DEPARTMENT (Expenditure)

INDEX

(15)

Subject:—Procedure regarding appointment—Delegation of powers to the Secretaries of the Administrative Departments to make provisional payment of salary.

The undersigned is directed to refer to this department Memo. No. F.1 (39) FD (Exp-Rules)/65, dated the 21st October, 1967 and to say that the Government have decided further to authorise Secretaries to Government in the Administrative Departments to sanction provisional payment of salary upto 31st August, 1968 in respect of Gazetted and non-gazetted Officers in whose cases concurrence of the Rajasthan Public Service Commission to their appointment has not been obtained or 'promotions have not been finalised by the Departmental Promotion Committees constituted under respective service rules.

Finance Deptt. (Rules) Memo. No. F.1(39) FD (Exp-Rules)/65, dated 29-2-68.

---

(16)

इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 2 (वी) (90) एफ. डी. (ई.आर.) 67, दिनांक 10 जनवरी, 1968 में परिच्छेद 1 के क्रमांक 2 में "3-1-68 or from the date the Post is fil'ed" के स्थान पर 14-12-67 पढा जावे।

[वित्त विभाग (नियम) शुद्धि-पत्र एफ. 2 (वी) (90) एफ. डी. (ई. आर) 67, दिनांक 14 फरवरी, 1968]

(17)

विषय:—राजस्थान सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) नियम, 1961–प्राह्लपकार उच्च दर पर प्रारम्भिक वेतन ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) नियम, 1961 में अग्रिम संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

(1) ये नियम राजस्थान सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) संशोधन नियम, 1967 कहलायेगें ।

(2) ये दिनांक 1-4-66 से प्रभाव में आए हुए समझे जायेंगे ।

(3) राजस्थान सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) नियम, 1961 अनुसूची III-वेतन मान 16, में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 2(ख) (34) वित्त विभाग (व्यय नियम) 66, दिनांक 16-6-66 के अनुच्छेद 4 (क) 1 की प्रथम पंक्ति मे प्रदर्शित (पोलिटेकनिक डिप्लोमा) शब्दों के बाद 'या सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसके समक्ष रूप मे मान्यता में दी गई अर्हता' शब्द निविष्ट किए जायेगे ।

[क्रमांक एफ 2 (बी) (34) वित्त विभाग (व्यय-नियम) 66-12, दिनांक 29-2-1968.]

SUBJECT;—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules—1961—Draftsman—Higher initial start.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely:—

(1) These rules may be called the Rajasrhan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1-4-66.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules 1961—Schedule III—Scale 16, the words "or qualifications recognised by the Government in General Administration Department as

equivalent thereto." shall be inserted after the words "Polytechnic Diploma" appearing in first line of instruction 4 (a) (1) vide Finance Department Notification No. F. 2 (b) (34)/FD (E-R)/66, dated 16-6-66.

[No. F. 2 (b) (34) FD (E-R)/66-12, Dated Jaipur, the 29th February, 1968.]

(18)

Subject:—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—State Vigilance Commission.

In exercise of powers conferred by the proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan, hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely :—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the date of issue of this notification.

(3) In Schedule II. Part 4 of the Rajasthan Cvil Services (Revised Pay) Rules, 1961, the following entries alongwith the heading Vigilance Commission namely :—

State Vigilance Commission.	Assistant Secretary	Rs. 75/-	The special pay of Rs. 75/- shall be admissible if the post is held by an officer of :— (1) Rajasthan Administrative Service in scale No. 26. (2) Rajasthan High Court-pay as admissible to Secretary to the Chief Justice.

[Finance Deptt. (Rules) Notification No. F. 2(b) (9) Finance (Rules)/68, dated 29-2-68.]

(19)

Subject:—Rajasthan C. S. (Revised Pay) Rules. 1961-Sch. I-Section D-Scale No. 20 Higher initial pay of Rs. 205/- to Post Graduate in Agriculture Extension.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the

following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely :—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1961.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the date of issue of these orders.

(3) In Sch. I-Section D of Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, under heading "Agriculture Department-Page 41) the following shall be inserted as remarks in column 5, against Scale No. 20-Posts in Subordinate Agriculture Service" (this scale is admissible only to Graduate in Agriculture) viz.—

(i) Higher initial pay of Rs. 205/- shall be admissible to freshly recruited persons possessing the post graduate qaualification of M. Sc. (Agriculture Extension), from a University of India on appointment as Agriculture Extension Officer.

(ii) Existing personnel who possess the aforesaid qualifications and who were recruited at the minimum of Rs. 175/- or Rs. 195/- in Scale No. 20 shall also be allowed Rs. 205/- if their pay was less than Rs. 205/- on appointment in the Subordinate Agriculture Service (Extension Wing).

(iii) Existing personnel who do not possess the aforesaid qualification and who were recruited at the minimum of the scale No 20 with minimum of Rs 175/- shall on their attaining the aforesaid qualifications—M. Sc. (Agriculture Extension) shall have their pay refixed at 205/- if it is less, on the date of declaration of the result by the University.

(iv) The date of increment in case of (ii) and (iii) Shall remain unchanged.

[Finance Deptt. (Rules) Notification No. F.2(b) (86) FD (E-R)/67, dated 12-2-68.]

(20)

Subject:—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules 1961 as amended on 1-4-1966. Schedule II. Part IV. Rajasthan Judicial Service—Assistant Legal Draftsman etc.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the follow-

ing rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules 1961 , namely:—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) amendment Rules, 1968.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1-4-1966.

(3) In Schedule II-Part 4 of the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules. 1961 the following new note shall be inserted below the remarks appearing against the post of the "Civil Judge posted as Assistant Legal Draftsman etc.," under heading "Rajasthan Judicial Service" inserted vide Finance Department Notification of even number, dated 22-5-67.

"Munsif posted as Assistant Legal Draftsman during the period 22-5-67 to 20-7-67 shall also be eligible for special pay of Rs.100"

[Finance Deptt. (Rules Notification No. F2 (b) (26)/FD(ER)/67, dated 15-2-68.]

No. Q 754 (S) BE II./64.

GOVERNMENT OF INDIA

(Ministry of External Affairs)

New Delhi, the 8th January, 1968.

Subject:—Purchase of Fiat Cars by Indian Missions/Posts abroad from Messrs. Fiat-Payment regarding.

Dear Mission/Post,

It has been the practice of our Missions abroad to place their orders for Fiat Cars with the Fiat Works in Turin direct advising them that the cost of Car, including C I. F. with marine insurance will be settled in USS by the Embassy of India, Rome. Since our Embassy in Rome do not have any USS account with the Local Bank and payment in Liras is not accepted by M/s Fiat for obvious reasons, they have to arrange payment in Pound Sterling which entails avoidable banking charges. Besides, this procedure also leads to unnecessary correspondence and accounting adjustments between the concerned Missions.

2. With a view to simplifying the existing practice, the matter has been examined and procedure for strict compliance in this regard is prescribed below. This may be inserted as Note IV below para 2 (iv) of the 'Note' circulated with this Ministry's letter No. F. 15 (7) B&AII/58 (EAI. No. 59/40), dated the 29th January, 1959.

"After compilation of the formalities indicated in the foregoing paragraphs, the purchaser should obtain an invoice from the firm and forward the same to the Chief Accounting Officer, High Commission of India. London with the usual seal authority from the A. G C. R /Controller of Defence Accounts to enable him to make payment in US Dollars to M/s. Fiat in accordance with the Government authority".

3. This issues with the concurrence of the Ministry of Finance (Department of E. A.) vide their U O. No. 15085-E A -67 dated 21-12-67.

Yours ever,
Sd/-
Ministry.

राजस्थान सरकार

वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक एफ. 16 (3) वित्त/मार्गोपाय/65 दिनांक 5 फरवरी 1968

प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि इस विभाग के परिपत्र संख्या एफ. 16 (5) मार्गोपाय/65 दिनांक 11 मई 1966 के संदर्भ में जिसके द्वारा एक पुस्तिका भेजी गई थी, उस पुस्तिका के पृष्ठ 19 में उपर्युक्त संशोधन कर लिया जावे।

[F. D. (W&M) Endt. No. F. 16 (3) F. W. M./65 dated 5-2-68.]

FINANCE DEPARTMENT (Revenue)

INDEX

(3)

Subject:—Amendment in General Financial & Account Rules Payees Receipt in Acknowledgement of the Payments Received (Rule 137).

The Governor has been pleased to order that the note existing below Rule 137 of the *General Financial & Account Rules*, Vol.I be numbered as No.1 and the following be added as note No.2 thereunder:—viz;

Note 2:—"A single receipt, stamped where necessary, given by a payee in acknowledgement of several payments or lump sum payment. either in cash or by cheque. made to him on one occasion. shall constitute a valid Equittance and the disbursing officer, in such cases, should give cross references on all vouchers to which the receipt relates."

[Finance Deptt. Accounts & Investment Section Order No. F.13(6) FD/A&I/GFAR/68 dated 22-2-68.]

---

(4)

Subject:—Signatures on the Challans by the Non-Gazetted Officers.

The Governor has been pleased to order that the following note be inserted below Sub-rule (6) of Rule 92 of the General Financial and Account Rules. Vol. I, namely:—

Note:—Notwithstanding anything contained in the above rule the following categories of Non-gazetted officers may also sign the challans before presentation to the Treasury or bank:—

S.No.	Name of the Non-gazetted officer.	Purpose.
1.	Excise Inspector Balotra	For depositing excise revenue.

[Finance Deptt. Account and Investment Section Order No. F.13 (16) FD/A&I/GF&AR/68, dated 22-2-68.]

---

(5)

राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम, 1954 (अधिनियम संख्या 28 सन् 1954) की धारा 4 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लेखे उक्त अधिनियम के अधीन परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर अंकेक्षण के अध्यधीन होंगे।

[Finance Deptt. Accounts & Investment Section-I Notification No. F. II (63) FD/A&I/63, Dated 27-2-68]

(6)

Subject:—Signature on the Challans by the Non-Gazetted Officers.

The Governor has been pleased to order that the following note be added below Sub-rule (6) of Rule 86 of Rajasthan Treasury Manual; namely:—

Note:—Notwithstanding anything contained in the above rule the following categories of Non-gazetted officers may also sign the challans before presentation to the Treasury or Bank:—

S.No.	Name of Non-gazetted Officer.	Purpose.
1.	Excise Inspector, Balotra.	For depositing Excise Revenue.

[Finance Department Accounts & Investment Section Order No. F.13 (16) FD/A&I/68, dated 22-2-68.]

---

(7)

In pursuance of rule 21 of the Rajasthan Service Rules, 1951, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendment in the Rajasthan Government Servants Insurance Rules, 1953 namely :—

Amendment

In the said Rules, for the existing sub-rule (5) of rule 47, including the proviso thereof, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(5) Subject to the conditions aforesaid. no further loan shall be granted before the expiry of at least a period of one year from the date of drawal of the previous loan or the repayment in full with interest, of the previous loan. if any, whichever is earlier."

[Finance Deptt. Accounts & Investments Section Notification No. .7 (16) FD A&S/67, dated 5-2-68.]

---

(8)

Subject:—Amendment in General Financial and Account Rules, Vol. I.

The Governor has been pleased to order that following be added as item No. 15 under note below Rule 81 of the General Financial and Account Rules. Vol. I; viz:—

"15-Managers of Devasthan Department."

[Finance Deptt. Accounts and Investment Section Order No. F13(18) F/A&G/GFAR/68 dated 28-2-68.]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

INDEX

(4)

इस विभाग के सम-संख्यक आदेश दिनांक 19-6-67 के क्रम में समस्त विभागाध्यक्षों। जिलाधीशों को निवेदन किया जाता है कि जो अधिकारी कार्यालय में 9.00 बजे उपस्थित होते हैं उनका अल्पाहार समय 1.00 बजे अपरान्ह से 2.30 अपरान्ह तक का है। वे कृपया उपरोक्त समय को ही अल्पाहार के लिये प्रयोग में लावें अन्य समय को अल्पाहार आदि के लिये काम में न लें।

विभागाध्यक्ष। जिलाधीश कार्यालयों के अतिरिक्त अधिकारियों का अल्पाहार समय 1.30 बजे से 2.00 बजे तक का है अतः उसी समय का ही वे अल्पाहार के लिये सद्उपयोग करें।

उपरोक्त आदेशों के भलीभांति अनुपालन कराने का दायित्व विभागाध्यक्षों। जिलाधीशों पर होगा।

[सामान्य प्रशासन (क) विभाग पत्र संख्या एफ. 2 (2) जी. ए.।अ।68, दिनांक 19-2-68]

---

(5)

State Government had under consideration for sometime the question of restricting the use of Bikaner House, New Delhi by wedding parties. In supersession of all previous orders in this connection, the following decisions are taken :—

1. The accommodation available in Bikaner House will in no case be allotted to any non-official or official of any other Government for accommodating wedding parties or for holding marriage ceremonies or other related functions.

2. The accommodation may be allotted to the official of this State Government for the above purposes in case the officer is himself/herself getting married or his/her real son or daughter is getting married.

3. Charges at the rate of Rs. 10/- per head per day would be realised whenever such an allotment is made. The charges will be payable in advance.

4. In no case no such accommodation would be reserved in advance earlier than three days. Even this reservation will be subject to the condition that it will be cancelled forthwith if the accommodation is required for the use of the State Government officers going on Tour.

This order will come into force w. e. from 1-3-1968.

[G. A. (A) Deptt. Order No. F. 27 (2) GA/A/66, dated 23-2-68]

(6)

विषय:—राजस्थान राजनैतिक पीड़ित सहाय्य नियम, 1959 में संशोधन करने हेतु ।

राज्यपाल महोदय इस विभाग द्वारा प्रेषित सम संख्यक विज्ञप्ति दिनांक 7-12-67 के सन्दर्भ में सहर्ष राजस्थान राजनैतिक पीड़ित सहाय्य नियम में निम्नांकित संशोधन करते हैं ।

संशोधन

उपरोक्त विज्ञप्ति के क्रम संख्या 4 पर "श्री हरिभाऊ उपाध्याय" के स्थान पर कृपया 'श्री बालकृष्ण कौल" पढ़ें ।

[सामान्य प्रशासन (क) विभाग आज्ञा संख्या एफ. 18 (137) सा।प्र।क।68, दिनांक 24-2-68]

(7)

इस विभाग के सविषयक परिपत्र संख्या एफ 1(51) सा।प्र।क।68, दिनाक 17-1-67 के क्रम में राज्य सरकार ने आदेश प्रदान किया है कि अग्रिम आदेश तक दिनांक 16-2-1968 से राज्य सरकार के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों व न्यायालयों (राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों को छोड़ कर) का दैनिक कार्यकाल 10 बजे पूर्वान्ह से लेकर 5 बजे अपरान्ह तक रहेगा तथा मध्यान्तर अल्पाहार का समय यथापूर्व रहेगा ।

अधिकारियों के लिये भी जो पूर्वान्ह 9 बजे कार्यालय आते हैं व 1 बजे अपरान्ह से 2.30 बजे अपरान्ह तक मध्यान्तर अल्पाहार के लिये जाते हैं, सायंकाल 5 बजे तक ही दैनिक कार्यकाल रहेगा ।

[सामान्य प्रशासन (क) विभाग आज्ञा संख्या प. 1 (51) सा।प्र।क।64, दिनांक 15-2-1968]

(8)

प्रेषिती

आयुक्त,
सतर्कता आयोग, राजस्थान, जयपुर ।

विषय:—कार्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वीकृति—

निर्देशानुसार गृह मन्त्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रसारित "फ्लेग कोड-इण्डिया" के नियम 10 (क) के अन्तर्गत आपको अपने कार्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । "फ्लेग कोड -इण्डिया" की एक प्रति इस सम्बन्ध में नियमों की पूर्ण जानकारी हेतु संलग्न की जाती है ।

कृपया इस पत्र के प्राप्ति की सूचना भिजवाय ।

[सामान्य प्रशासन (क) विभाग पत्र संख्या प. 2 (4) सा।प्र।क।68, दिनांक 7-2-68]

HOME DEPARTMENT
INDEX

(3)

I am directed to forward for information and necessary action a copy of Notification No. F. 7/67-(10)-C, dated the 22nd December, 1967, from the Delhi Administration Delhi on the subject cited above.

(Home (A) Deptt. Letter No. F. 17 (2) Home (A-Gr/-II) 68, dated 1-2-68.

DELHI ADMINISTRATION, DELHI

NOTIFICATION

Dated the 22nd December, 67.

No. F. 7/67-(10)-*C.*—WHEREAS the Lt Governor. Union Territory of Delhi. is satisfied that the Hindi Monthly "Shashwat Vani" for October, 1967, edited by Ashok Kaushik. printed at Rashtra Bharti Press, Delhi, contains matter which promotes feelings of enmity and hatred between the Hindus and the Muslims in India, publication of which is punishable under section 153-A of the I. P. C 1860 (Act XLV of 1860).

Now, therefore. in exercise of the powers conferred by section 99-A of the Code of Criminal Procedure. 1898 (Act V of 1898). the Lt. Governor, Union Territory of Delhi. hereby declares to be forefeited to Government every copy of the said Hindi Monthly and all other documents containing copies. re-prints and translations of or extracts from the said Hindi Monthly.

By Order,
Sd/-
(VINOD KUMAR SETH)
Under Secretary (Home).
Delhi Administratoion, Delhi.

---

(4)

I am directed to forward herewith for information and necessary action a copy of Notification No. 14216-IPB-67/35394, dated 26-9-1967 from the Home Department. Press Branch. Punjab Government. Chandigarh.

Home (A) Deptt. Letters No. F.17 (15) Home (A-Gr. II) 67, dated 1-2-68.

(to be published in Punjab Government Gazette)

HOME DEPARTMENT

Press Branch

NOTIFICATION

Dated Chandigarh, the 26th September, 1967.

No. 14216-*IPB*-67/35394.—Whereas it appears to the Governor of Punjab that the book entitled "The Village" written in English by

Shri Mulk Raj Anand, printed by U. Narasimha Mallya, proprietor B. B. D. Powers, Press Banglore-2 and published by Mughni Amrohvi for Kutub Publishers Ltd. Ganesh Bhawan, Kiln Lane, Lamington Road, Bombay-7, in the passages referred to in the Schedule below; contains matter, which is deliberately and maliciously intended to outrage the religious feelings of the Sikh Community;

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 99-A of the Code of Criminal Procedure. 1898, the Governor of Punjab is pleased to declare every copy of the aforementioned book and its Hindi version entitled the "Gaon" and other documents containing such matter to be forefeited to the Government of Punjab.

Schedule

Page of the book.	Passages
29—30	Beginning with the words "He wiped the prespiration" and ending with the words "But if only he could get it cut."
69—70	Beginning with the words "Lalu raised his hand to the turban" and ending with the words on account of these infernal coils.
96	Beginning with the words "I paid a visit to the kind George Vth Hair Cutting Saloon" and ending with the words "exchange of words with his brother."
98	Beginning with the words "do'nt upset yourself" and ending with the words "Aspersions on long hair."
100	Beginning with the words "But before they had time to advance a ste" and ending with the words "disruptables of the village".
109—110	Beginning with the words "He had lain in pitch darkness of the night" and ending with the words "scattered about on the hills."

Sd/- JASPAL SINGH.
Deputy Secretary to Government, Punjab,
Home Department.

(5)

In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 44 of the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act 4 of 1939), the State Government hereby makes the following amendment to this Department Notification No. F. 1 (9) (6) H5-I/62, dated the 6th December, 1963, published in the Rajasthan Gazette part I-B dated the 13th February, 1964. namely :—

Amendment

In the said notification in item 3 under the heading "Non-Official Members" for the expression "1. Shri mati Sumitra Devi, M. L. A.", the

expression "1. Shri Ghasi Ram Yadav, Ex-Deputy Minister" shall be substituted.

[Home (B-Gr.I) Deptt. Notification No F.1 (9) (6) Home (B-Gr. I)/62, dated 27-2-68.]

(6)

The exercise of the powers conferred by Section 50 of the Prisons Act, 1894 (Central Act 9 of 1894), as adapted to the State of Rajasthan the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Prisons Rules, 1951, namely:—

1. These rules may be called the Rajasthan Prisons (Amendment) Rules, 1967.

2. In Section V of part IX of the Rajasthan Prisons Rules, 1951, after the existing clause (b) of rule 99, the following new clause shall be added, namely:—

"(bb). Every male sikh convict shall be given one kachha on the specification as prescribed in Jails in Punjab for sikh Prisoners in lieu of Jangia of the same cloth as is used for preparing Jangia for the other convicts in jails in Rajasthan.

[Home (B-Gr. II) Deptt. Order No. F.1 (17) (32) H-B-II/65, dated 7-2-68.]

(7)

विषय:—रद्दी कागज व कागजों की कतरन की नीलामी के सम्बन्ध में—

कृपया इस विभाग के सम संख्यक परिपत्र दिनांक 10-1-68 के संलग्न शर्तों की शर्त 3 को निम्न रूप से पढ़ा जाये :

"सफल बोली दाता को उसके नाम पर बोली छूटते ही 200) रु0 दो सौ रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसकी अर्नेस्ट मनी की रकम जप्त करली जावेगी। सिक्योरिटी जमा करवाने पर अर्नेस्ट मनी उसी रोज लौटा दी जावेगी।"

[गृह (घ) विभाग शुद्धिकरण परिपत्र, सख्या प. 2 (65) गृह (घ)166, दिनांक 23-2-68।]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

INDEX

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

In exercise of powers conferred by section 14 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (Central Act XX of 1946), the State Government hereby exempts the Rajasthan State Electricity Board from the operation of the provisions of the said Act.

Labour & Employment Notification No. F. 1 (11) (25) L&E/66, dated 27-2-68.

REVENUE DEPARTMENT

INDEX

REVENUE DEPARTMENT

(6)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (अधिनियम संख्या 27 सन् 1954) की धारा 2 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध ओराई मीडियम प्रोजेक्ट द्वारा सिंचित क्षेत्रों पर, नीचे अनुसूची में दिये अनुसार लागू होंगे।

उपनिवेशन के रूप में घोषित किये जाने हेतु प्रस्तावित सिंचित भूमि सिंचाई विभाग द्वारा तयार किये गये नक्शे में दिखाई गई है जिसे कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा के कार्यालयों में देखा जा सकता है:—

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	तहसील का का नाम	जिले का नाम	ग्राम का नाम	समस्त सिंचित नहरी क्षेत्र एकड़
1	2	3	4	5	6
1.	ओराई परियोजना,	बेंगू	चित्तौड़गढ़	1. सियालिया	587
				2. गोपालपुरा	274
				3. टोरनिया	473
				4. कुंडालिया	40
				5. हरिपुरा	276
				6. जोधपुरिया	376
				7. डिकरीखेरा	35
				8. रायपुरिया	52
				9. चैनपुरिया	60
				10. इटावा	577
				11. राजगढ़	676
				12. रतनपुरा	126
				13. सोकिया	685
				14. सहेड़ा	412
				15. लोहारिया	610
				16. रूपपुरा	85
				17. अकोदिया	151
				18. मूरलिया	128
				19. चोमूं	64
				20. डूगर	1130
				21. रघुनाथपुरा	105
				22. कंवरपुरा	498
				23. दौलतपुरा	130
				24. सगजी की भागल	90
				25. कितियास	380

1	2	3	4	5	6
				26. मारन	72
				27. गुराइली	52
				28. तक्तपुरा	8
				29. माखनपुरा	35
				30. हिमिपुरिया	34
				31. हाडा की खेड़ी	4
				32. संग्रामपुरा	4
				33. वरनियास	13
				34. चोसला	13
				35. मालीखेड़ा	8
				36. वीलोद	67
				37. वड़ा खेड़ा	7
				कुल योग कमान्डॅड क्षेत्र:	1092
2	ओराई प्रोजेक्ट	मांडलगढ़	भीलवाड़ा	1. चोथा का खेड़ा	16
				2. वरूनोई	332
				3. देवलिया	24
				4. जोगवा	280
				5. हिंगवानिया	440
				6. धाकड़खेड़ा	962
				7. वागीड	84
				8. सिंगोली	60
				9. मानगंज	12
				10. विट्ठलपुरा	56
				11. नरायनसागर	10
				12. मन्डीनावाला	18
				13. लोटीयाना	251
				14. सन्द	22
				15. सारना	99
				16. मोटरा की खेरिया	16
				कुल सिंचित क्षेत्र. ..	1199

Revenue Colonisation Department Notification No F. 7 (226) Irrigation 62, dated 17-2-68.

(7)

In supersession of the Revenue Department Notification No. D. 3445/F. 22 (5) Rev./A/55, dated 20th April, 1955, published in Rajasthan Rajpatra, Part I(b), dated 14th May, 1955 and in exercise of the powers conferred by section 42 of the Rajasthan Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1954 (Rajasthan Act No. XXIV of 1954), the State Government is hereby pleased to delegate to the Collector, Ganganagar, the powers of the State Government under sub-section (4) of section 17 and section 37 of the aforesaid Act, subject to the condition that the Government may also, exercise the powers under the aforesaid provisions in such cases as the Government may deem suitable.

Revenue Colonisation Deptt. Notification No. F. 4 (2)-RCPD/61, dated 1-2-68.

केवल कार्यालय उपयोगार्थ

राजस्थान सरकार

मंत्रि-मण्डल सचिवालय

व्यवस्था एवं पद्धति (संकलन) अनुभाग

अप्रेल, 1969 में
शासन सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गए महत्वपूर्ण परिपत्रादि का मासिक संकलन

राजस्थान केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

1969

ग

6

LIST OF DEPARTMENT

(In respect of which important circulars etc. have been printed in this compilation of April, 69

विभागों की सूची

(उन विभागों की सूची जिनके महत्वपूर्ण परिपत्रों आदि को अप्रेल 69 के संकलन में मुद्रित किया गया है ।

नियुक्ति विभाग
APPOINTMENTS DEPARTMENT

INDEX

APPOINTMENTS DEPARTMENT

(9)

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with rule 11 of the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958 the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendments in schedules A. BII and III appended to the said rules, namely :—

AMENDMENTS

I. In schedule 'A' of the said rules, under the heading "(2) List of Heads of Departments (other than Class I)" after entry 49 the following new entry shall be added, namely:—

50-Chief Accounts Officer

II. In schedule 'B' of the said rules for the entry No. 48 , the following entry shall be substituted, namely:—

48.Chief Accounts Officer's Organisation.	Headquarters Office	Accounts Officer	Chief Accounts Officer.	Accounts Officer	Chief Accounts Officer
1	2	3	4	5	6

III. (a) In schedule II relating to subordinate services, appended to the said rules, the entry against item No. 1- "Junior Accounts Service" shall be deleted, and

(b) the following entry alongwith a note thereto under a new caption shall be added, namely:—

"Finance Department A&I"

1. Members of the Rajasthan Subordinate Accounts Service.

Note:—The powers of imposition of minor penalties in respect of Accountants attached to the departments/office shall also vest with the Heads of Departments/Offices.

IV(a) In schedule III of the said rules, the following entries appearing at Serial No. 1 shall be deleted, namely:—

"Accountants including Senior Accountants, Sub-Accountants, Deputy Accountants, Junior Accountants, Assistant Accountants. Stores Accountants and Assistant Stores Accountants."

[*Appointments (A-III) Deptt. Notification No.F.*3(5) *Apptts.* (*A-III*)/66, *dated* 10-4-69.]

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with rule 11 of the Rajasthan Civil Services (Classification. Control and Appeal) Rules, 1958, the Governor of Rajasthan hereby make the following amendments in Schedule B appended to the said rules, namely:—

AMENDMENT

In Schedule B to the said rules, in column 6 against S. No. 42, for the existing entry Joint Development Commissioner (Panchayats) the following entry shall be substituted and be deemed to have been substituted with effect from 31st July, 1968, namely:—

"Additional Development Commissioner"

[*Appointments (A-III) Deptt. Notification No. F.3(7) Appts. (A-III)/68, dated* 30-4-69]

---

(11)

विषय:—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के प्रत्याशियों के लिये राज्य सेवा में आरक्षण के सम्बन्ध में सम्पर्क अधिकारियों का मनोनयन।

अनुसूचित जाति। जन जाति के व्यक्तियों को दी गई सुविधाएं व राज्य सेवा के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण के आदेशों की शीघ्र क्रियान्विति करने व इस संबंध में सांख्यिक सूचना समय समय पर राज्य सरकार को भिजवाने की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष को इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी घोषित किया जावे। विभागाध्यक्ष अपनी सुविधा के लिए अपने अधीन वरिष्ठ अधिकारी को इस कार्य के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में निम्नलिखित कार्य सौंप सकते हैं:—

(1) विभाग के अधीनस्थ नियुक्तिक अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा घोषित रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति। जन जाति के व्यक्तियों के आरक्षण तथा अन्य सुविधा संबंधी आदेशों का परिपालन।

(2) विभाग के अधीन सेवाओं कार्यालयों एवं संस्थानों में अनुसूचित जाति। जन जाति के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व संबंधी वार्षिक अभ्यावेदन तथा आंकड़ों का संकलन एवं प्रेषण।

(3) मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के बीच उक्त मामलों में सम्पर्क अधिकारी का कार्य।

(4) इस संबंध में राज्य सरकार व विधान सभा द्वारा मांगी गई सूचना व सांख्यिक आंकड़े एकत्रित कर अविलम्ब प्रस्तुत करने का कार्य।

आपके विभाग में उक्त सम्पर्क अधिकारी का कार्य करने वाले अधिकारी का नाम पद व निवासस्थान की सूचना इस विभाग को तुरन्त भिजवाने का अनुग्रह करें।

[नियुक्ति. (क–5) विभाग परिपत्र संख्या प 6 (25)नियुक्ति (क–4)।62, दिनांक 3।21 अप्रेल, 69]

CABINET SECRETARIATE

Inc'uding (O & M) Section

INDEX

(40)

विषयः—कर्मचारियों द्वारा पत्र प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दिये जाने वाले हस्ताक्षर।

इस अनुभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 4-3 68 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि:—

(1) पत्र प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दिये जाने वाले हस्ताक्षर सदा सुपाठ्य तथा पूरे रूप में (लजिबल एण्ड फुल सिगनेचर्स) दिये जाने चाहिये।

(2) यदि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर सुपाठ्य न हों तो उसे अपने हस्ताक्षरों के नीचे अपना नाम सुपाठ्य अक्षरों में कोष्ठक में अनिवार्य रूप से लिखना होगा।

(3) इस आदेश की अवहेलना करने वाले संबंधित व्यक्ति अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी होंगे।

2. ऐसा देखने में आया है कि इन आदेशों का पालन पूरी तरह नहीं किया जा रहा है और अब भी बहुत से सरकारी कार्यालयों में आने वाले पत्रों की प्राप्ति स्वरूप कर्मचारी हस्ताक्षर स्पष्ट तथा पूरे रूप में नहीं कर रहे हैं। अतः समस्त कर्मचारियों का ध्यान इस ओर पुनःआकर्षित किया जाता है। यदि अब भी इस आदेश की अवहेलना की गई तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

[मंत्रि मन्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग परि.पत्र संख्या 1 (4) व्य. एवं प. 167, दिनांक 30-4 69]

---

(41)

विषय : लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग के लिये नवीकर पाठ्यक्रम।

इस सचिवालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 14-11-68 द्वारा यह निश्चय किया गया है कि एक सम्पूर्ण दिवस की उपस्थिति के लिये प्रति अभ्यार्थी को परिवहन एवं जलपान व्यय के लिये "क्षति पूर्ति भत्ता" के रूप में दो रुपये दिये जायेंगे।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि क्षतिपूर्ति भत्ते का भुगतान अभ्यर्थी को उसके विभाग से किया जायेगा।

[मंत्रि मण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग परि. प. सं. 1 (21) व्य. एवं प. 168, दिनांक 8-4-69]

---

(42)

विषय:—सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति वृत्ति (पेन्शन) के मामलों का शीघ्र निपटारा।

मुख्य सचिव महोदय ने इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19-10-67 द्वारा समस्त शासन सचिवों तथा अन्य अधिकारियों का ध्यान सेवा निवृत्ति वृत्ति (पेन्शन) के विचाराधीन मामलों की ओर आकर्षित कर यह अनुरोध किया था कि ऐसे मामलों का पूरा विवरण उस परिपत्र के संलग्न प्रपत्र मे हर तिमाही की समाप्ति के अगले माह की 10 तारीख तक व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग को निश्चित रूप से भेजने की व्यवस्था करें। इसके अतिरिक्त एक साल से अधिक समय के अनिर्णित सेवा निवृत्ति वृत्ति के मामलों के बारे में भी एक पूर्ण विवरणात्मक नोट भेजने के लिए भी निदेश दिये गये थे। उपयुक्त सामयिक सूचना प्राप्त करने का उद्देश्य इन मामलों में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को दूर करना तथा इनकी सामयिक प्रगति से अपने आपको अवगत रखना था परन्तु मुख्य सचिव महोदय द्वारा समस्त शासन सचिवों से किये गये इस अनुरोध के उपरान्त भी उनके अधीनस्थ विभागों से ये विवरण या तो आ ही नहीं रहे हैं या विलम्ब से आ रहे हैं। अतः निवेदन है कि भविष्य में आपके अन्तर्गत विभागो से हर त्रैमासिक अवधि की सूचना उससे अगले माह की 10 तारीख तक इस सचिवालय को निश्चित रूप से भिजवाने का कष्ट करें। दिसम्बर, 1968 की अवधि का जो विवरण पत्र 10-1-1969 तक प्राप्त हो जाना चाहिए था, वह अब अविलम्ब भेजा जावे।

(मंत्रीमंडल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग परिपत्र सं. प. 1 (24) व्य. एव प.167, दिनांक 25-4-69)

---

(43)

Sub.—Distribution of work in the Finance Department.

In partial modification of this Department Order No.F.2(6) O&M/64 dated 28-7-64 and in supersession of this Department orders of even number dated 14-6-67 and 15-4-68, it is hereby ordered that with effect from 1st May, 1969, the work in the Finance Department shall be distributed as follows :—

Financial Commissioner and Secretary to Government.

He shall function as Secretary to Government in all matters not dealt with by Financial Commissioner (Revenue) unit abolition of the said post, or by Special Secretary (Finance) with effect from the date the post is revived and filled in. He shall also function as Cell Officer for Plan Finance, and changes (if any) in New Pay Scales, D.A. and Economy Measures.

Officers under Financial Commissioner.

Deputy Secretary, Expenditure I
Deputy Secretary, Expenditure II
Deputy Secretary, Expenditure III
Deputy Secretary, Expenditure-Rules
Budget Officer
Deputy Secretary, Investment & Commercial Accounts

Financial Commissioner (Revenue) or Special Secretary Finance.

He shall function as Cell Officer for Taxation Policy, Town Planning Schemes and Treasury Rules and Manuals.

Officers under Financial Commissioner (Revenue) or Special Secretary Finance.

Deputy Secretary, Commercial Taxes and Accounts
Deputy Secretary, Excise, Recovery, R.A./C.S. and R.Sub. A/Cs.
Director Small Savings & Lotteries, and Ex-officio Deputy Secretary to Government.

2. In this Department Order No. F.2(6) O&M/64, dated 28-7-64, the following amendments shall be made :—

(*a*) The words "and Accounts Officer (Temporary)" appearing below "2 Deputy Secretary (Excise and Misc.)" shall be deleted, and the following subjects shall be deleted :—

(*ix*) Defunct Banks of erstwhile States;

(*x*) All administrative matters relating to Chief Accounts Officer Rajasthan and Chief Accounts Officer, Chambal;

(*xi*) Treasuries; and

(*xii*) Old cases relating to the Federal financial integration.

(*b*) The following subjects shall be added against Deputy Secretary (Taxation), which post shall be re-designated as Deputy Secretary (Taxation and Accounts) :—

(*xi*) Defunct Banks of erstwhile States,

(*xii*) All administrative matters relating to Chief Accounts Officer, Rajasthan and Chief Accounts Officer, Chambal,

(*xiii*) Treasuries,

(*xiv*) Old cases relating to the Federal financial integration,

(*xv*) All administrative matters (including non-gazetted establishments) relating to :—
  (*a*) Examiner, Local Fund Audit Department,
  (*b*) State Insurance Department.

(*xvi*) General Accounting procedure, General Financial and Accounts Rules, Rajasthan State Insurance Rules,

(*xvii*) Accounting portion of Departmental Manuals.

(*c*) The words "Senior Accounts Officer (Investment & Audit)" shall be substituted by the words "Deputy Secretary (Investment

and Commercial Accounts)" and the following subjects shall be deleted :—

(v) All administrative matters (including non-gazetted establishments) relating to :—

(a) Examiner, Local Fund Audit Department,
(b) State Insurance Department.

(vi) General Accounting Procedure, General Financial and Accounts Rules, Rajasthan State Insurance Rule,

(vii) Accounting portion of Departmental Manuals.

The following subject shall be added :—

(v) Performance Budgeting.

Cabinet Sectt. (O & M Section) Order No. F.2(16) *O & M/67, dated* 30-4-69]

विषय—समितियों का गठन (44)

इस सचिवालय के व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग द्वारा विभिन्न समितियों के गठन सम्बन्धी आदेश समय 2 पर जारी किये जाते हैं किन्तु कुशलता पूर्वक और समय पर ऐसा करने में कुछ बाधायें अनुभव की जा रही हैं जिनके कारण समितियों के गठन सम्बन्धी आदेश प्रसारित करने में कभी कभी पर्याप्त विलम्ब हो जाता है। इस विलम्ब को दूर करने की दृष्टि से प्रशासनिक विभागों से अनुरोध है कि किसी भी समिति के गठन सम्बन्धी आदेश प्रसारित कराने हेतु व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग को पत्रावली भेजते समय उनके द्वारा निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जावे:–

(क) समिति के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव, आदेश जारी कराने हेतु, व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग को भेजने के पूर्व संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा सम्बन्धित मंत्रीगणों आदि की अनुमति और यदि समिति में कोई गैर सरकारी (नोनआफिसियल) व्यक्ति सम्मिलित किया जाने को हो तो उसकी सहमति भी प्राप्त करली जावे।

(ख) सम्बन्धित पत्रावली भेजते समय सम्बन्ध नोट के उन अनुच्छेदों की जो कि समिति के गठन सम्बन्धि मूल प्रस्ताव से तथा उसकी स्वीकृति से संबंधित हो, नोट शीट पर, एक प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जावे।

(ग) समिति के गठन हेतु प्रसारित किये जाने वाले आदेश का प्रारूप अनिवार्य रूप से पत्रावली के साथ भेजा जावे जिसमें समिति के गठन सम्बन्धी उद्देश्यों का स्पष्ट उल्लेख हो और समिति के कार्यकाल की अवधि भी निर्दिष्ट की गई हो।

2. कभी 2 अस्थाई तौर पर गठित की गई समितियों की कार्यावधि को बढाने के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों से भेजे जाने वाले प्रस्ताव न तो समय पर भेजे हो जाते हैं और

न ही यथा समय सूचित किया जाता है कि समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है या नहीं इस से व्यवस्था एव पद्धति अनुभाग वांछित जानकारी से अ मि । रहता है और साथ ही समिति के गठन सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति समय पर न होने से काफी असुविधा उत्पन्न होती है। अतः व्यवस्था एव पद्धति अनुभाग को:-

(क) समिति के कार्य काल को बढाने सम्बन्धी प्रस्ताव यदि आवश्यक हों तो समिति के निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भिजवाये जावें ताकि निर्धारित समय पर वांछित आदेश जारी किये जा सकें।

(ख) समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सूचना प्रतिवेदन प्रस्तुत होते ही भेजी जावे।

(ग) प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही से भी अवगत कराया जावे।

3. प्रायः यह भी देखने में आया है कि महालेखाकार, राजस्थान द्वारा या किसी अन्य संस्थान द्वारा जब कभी किसी समिति से सम्बन्ध सूचना मांगी जाती है तो तत्सम्बन्धी मामला इस आधार पर व्यवस्था एव पद्धति अनुभाग को भेज दिया जाता है कि समिति के गठन सम्बन्धी आदेश यहां से प्रसारित किये गये हैं। पर यह उचित नहीं है। व्यवस्था एव पद्धति अनुभाग पर तो समिति के गठन सम्बन्धी आदेश प्रसारित करने का ही दायित्व है, मामलों से संबंधित कार्यवाही तो प्रशासनिक विभागों द्वारा ही करनी होती है। अतः भविष्य में एसे मामले व्यवस्था एव पद्धति अनुभाग को न भेजे जावे।

[मंत्रिमण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग परिपत्र सं. प. 5 (1) डीः व्य. एवं प. 62, दिनांक 10-4-69]

---

(45)

विषयः-राजस्थान राज्यान्तर्गत राजकीय तथा राज्य नियंत्रित विभागों एवं राजकीय उपक्रमों व स्वायत्त शासन संस्थाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के लिए अनुबन्धित कोटा के पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रगति की देख-रेख एवं नियंत्रण रखने हेतु समिति।

इस सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) के समसंख्यक आज्ञा दिनांक 17-2-69 के क्रम संख्या 5 व 6 को निम्न प्रकार पढ़ा जावे :-

5. विशिष्ट सचिव, नियुक्ति विभाग। सदस्य सचिव

6. निदेशक, समाज कल्याण विभाग। सदस्य

[मंत्रि मंडल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग संशोधन सं. प. 5 (6) व्य. एवं प.169 दिनांक 25-4-69]

---

(46)

विषयः—आदिम जाति शोध संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर की सलाहकार समिति ।

इस सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति) की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 18 अप्रेल, 68 के क्रम में राज्यपाल महोदय उक्त समिति में श्री परमानन्द शर्मा को सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

[मंत्रि-मंडल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा सं. प. 5 (14) व्य. एवं. प. 168 दिनांक 9-4-69]

(47

राज्यपाल, एतद्द्वारा राज्य में नये स्थापित उद्योगों के मामले तय करने हेतु निम्नांकित सदस्यों की एक स्थायी समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(1) वित्त आयुक्त (व्यय) — अध्यक्ष ।
(2) विशिष्ट सचिव, वित्त (राजस्व) — सदस्य ।
(3) अध्यक्ष, राज्य विद्यु् मण्डल, जयपुर — ,,
(4) सचिव, स्वायत्त शासन विभाग — ,,
(5) सचिव, राजस्व विभाग — ,,
(6) सचिव, जन स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग विभाग — ,,
(7) सचिव, उद्योग विभाग — संयोजक

आम तौर पर इस समिति की बैठकों में केवल

1. वित्त आयुक्त (व्यय)

2. विशिष्ट सचिव, (वित्त राजस्व)

3. सचिव, उद्योग तथा

4. उपरोक्त अधिकारियों में से संबंधित अधिकारीगण भाग लेंगे । आवश्यकता पर समिति विधि विभाग के एक प्रतिनिधि (जहां तक हो सके संयुक्त विधि परामर्शी) को भी आंमत्रित कर सकती है । समिति द्वारा निर्णय लेने के पश्चात् उसके अनुसार आदेश प्रसारित करने का उत्तरदायित्व संबंधित सचिव का होगा । यदि समिति द्वारा लिये गये किसी विशेष निर्णय से संबंधित विभाग के मंत्री सहमत न हों तो उस मामले को मंत्री परिषद् की उद्योग सम्बन्धी उप-समिति के विचारार्थ रखा जावेगा ।

[मंत्रि मण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा संख्या प. 5 (14) व्य. एवं प.169 दिनांक 19-4-69]

---

(48)

विषयः—नगरपालिका क्षेत्रों में चुंगी के बजाय सामान्य व्यापार कर (जनरल टर्न ओवर टैक्स) लागू करने तथा गृह-कर की वसूली की व्यवस्था के सम्बन्ध में समिति।

राज्यपाल इस सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग) के समसंख्यक आज्ञा दिनांक 25 फरवरी, 1969 द्वारा निर्मित उपरोक्त समिति को तुरन्त भंग करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

[मंत्रि-मण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा संख्या 5 (18) व्य. एवं प.166, दिनांक 10-4-69]

---

(49)

राज्यपाल एतद्द्वारा इस सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति) की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 27-11-67 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विभागीय संस्कृत परीक्षाओं के लिये निर्मित स्थाई समिति में आंशिक परिवर्तन करते हुए आदेश की क्रम संख्या 5 के समक्ष अंकित "श्री चैनसुखदास प्रिंसिपल, दिगम्बर जैन संस्कृत कालेज, जयपुर" के स्थान पर "प्रिंसिपल महाराजा संस्कृत कालेज जयपुर" को समिति का पदेन सदस्य मनोनीत किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

[मंत्रि-मण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा सं. प. 5 (29) व्य. एवं प.167, दिनांक 17-4-69]

---

(50)

विषयः—मोटर परिवहन के नियम में सिद्धान्त एवं व्यवहार संहिता के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य परिवहन सलाहकार समिति।

उपर्युक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 8 पर अंकित "डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट पश्चिमी रेल्वे, जयपुर" के स्थान पर "मार्केटिंग एण्ड सेल्स सुपरिन्टेन्डेन्ट वेस्टर्न रेल्वे, बम्बई" पढ़ा जावे।

[मंत्रि-मंडल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग शुद्धि पत्र संख्या प. 5 (45) व्य. एवं प.162, दिनांक 1-4-69]

---

(51)

प्रायः ऐसा देखा गया है कि सचिवालय के विभागों/अनुभागों/प्रकोष्ठों से विधान सभा के प्रश्नों के उत्तर और उनकी संलग्निकाओं की जो प्रतिलिपियां मंत्री महोदय को भेजी जाती है, वे फीकी व अस्पष्ट टंकित होने के कारण सुपाठ्य नहीं होती। इसका परिणाम यह होता है कि संबंधित मंत्री महोदय को सदन में उत्तर देने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः अनुरोध है कि भविष्य में इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जावे कि जो भी ऐसी प्रतिलिपियां संबंधित मंत्री महोदय को भेजी जावें वे पूर्णरूपेण स्पष्ट, स्वच्छ एवं सुपाठ्य हों जिससे उनको पढने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

[मंत्रि-मंडल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग परिपत्र संख्या प. 10 (36) व्य. एवं प. 169 दिनांक 9.4-69]

---

(52)

वर्तमान में, भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य सरकारों के कई प्रशिक्षण केन्द्र सेवा-रत अधिकारियों / कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देते हैं-जैसे वर्क स्टडी कोर्स, टैकनीक्स आफ एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूवमेन्ट, मिडिल मनेजमेन्ट, सुपरवाइजरी डेवलपमेन्ट फाउन्डेशन कोर्स व अन्य नवीकर पाठ्यक्रम आदि। राजस्थान विश्व विद्यालय व अन्य स्वायत्त शिक्षण केन्द्र भी सरकारी कमचारियों को प्रशिक्षण देते है।

2. सेवा-रत अधिकारियों। कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर सरकार अधिक महत्व देती है और समय समय पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में कई व्यक्तियों को मनोनीत करती है।

3. प्राय: ऐसा देखा गया है कि जब किसी अधिकारी / कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिये चयन किया जाता है तो संबंधित विभागीय अधिकारी उनको कार्य मुक्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं और किसी न किसी कारणवश प्रशिक्षण के लिये मुक्त नहीं करते। इससे एक तरफ तो हम अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के अवसर खोते हैं तथा दूसरी और विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र, प्रशिक्षणार्थियों के अभाव में अपनी क्षमता का पूरा पूरा उपयोग नहीं कर पाते। अतः शासन सचिवों की बैठक में विचार कर, यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को प्रशिक्षण विशेष के लिये चयन किया जावे तो उसके संबंधित उच्च अधिकारी को उसे प्रशिक्षण के लिये कार्य मुक्त करना ही होगा। जब तक कि वह उसके बजाय किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को जो कि आवश्यक अर्हता (Qualifications) प्राप्त हो तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य हो, मनोनीत नहीं कर पाते।

[मंत्रिमंडल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग परिपत्र संख्या प. 12 (3) व्य. एण्ड. प. 166 भाग 1, दि. 28-4-69]

---

(53)

Subject:—Economy measures in 1969-70.

All authorities empowered to make appointments to posts under Government, including Work-charged posts, and all authorities empowered to purchase vehicles are hereby ordered to observe the following instructions :—

2. *Ban on direct recruitment to fill up vacant post.*—(i) No 'Non-Plan post falling vacant in 1969-70 by retirement, resignation, termination of service, transfer or promotion of any employee, in regular

establishment or in Work-charged establishment, shall be filled in by direct recruitment. The words 'Direct Recruitment' will also apply to appointment of a person already in service in another State Government Department or cadre. Where there are Service Rules or Orders allowing posts to be filled by promotion, vacancies may be filled by promotion but there should be no consequential direct recruitment. The Treasury Officers shall not pass any pay bills of such any new employees.

(*ii*) In the case of work-charged employees the Words "Direct Recruitment" will apply to appointment of a person in one establishment by transfer from another establishment which is continuing to function. If however, one establishment is wound up, then the work charged employee of that establishment may be appointed to another establishment.

(*iii*) This ban will not, however, apply to filling up of new regular posts sanctioned under "Plan" against provision in 1969-70 Budget or to Work-charged posts necessary for plan schemes.

(*iv*) All Heads of Departments and offices should manage their affairs with the reduced strength by reallocation of duties or redistribution of jurisdiction.

(*v*) Any proposal for filling up of vacant posts of non-Gazetted ranks in relaxation of this ban will require specific approval of the Finance Minister, and any proposal for filling up of similar vacancies of gazetted rank will require the specific approval of the Finance Minister and the Chief Minister. Hence any sanction issued in relaxation of this ban must contain a reference that this has the approval of the Finance Minister and also of the Chief Minister where necessary.

3. *Ban on purchase of new vehicle.*—No new vehicle shall be purchased without the specific approval of the Finance Minister in individual cases. This will apply to vehicles purchased against the Budget provision for both Plan and Non-Plan, and whether as an additional vehicle or in replacement of an old vehicle. In the case of all branches of the P.W.D. including Irrigation Rajasthan Canal, and Chambal Project Departments, there is no separate Budget provision for purchase of vehicles and vehicles are purchased against provision for works expenditure. This ban will apply to the purchase of such vehicles by all branches of the P.W.D. In all cases where specific approval of the Finance Minister is sought, detailed information should be supplied regarding the following matters:—

(*a*) If the proposal is to purchase a new vehicle for a purpose for which no vehicle was already provided, the exact need should be mentioned and it should be explained how work was carried on previously without vehicle.

(*b*) If the proposal is to replace an old vehicle, details about the old vehicle should be furnished and the old vehicle must be surrendered to he States Motor Garage within one month from the date of issuing sanction.

4. *Grant of Leave Preparatory to Retirement.*—All Appointing Authorities are hereby directed not to refuse leave preparatory to retirement but to sanction it as soon as it is applied for. There should be no delay on account of obtaining leave title etc. and if the employee concerned claims that a certain Leave Preparatory to Retirement is due, he should be relieved pending receipt of title and issue of formal order.

5. The instructions at paragraphs 2, 3 and 4 are to be followed during 1969-70 and they shall be deemed to be in supersession of the powers of direct recruitment, purchase of vehicles and refusal of leave preparatory to retirement, which now vest in various authorities under the C.C.A. Rules, G.F.&A.R. and other Rules and orders on the subject.

[*Cabinet Sectt. (O. & M. Section) Order No.* F. 27 (1) *Cab./*69, *dated* 5-4-1969.].

---

(54)

Subject:—Economy measures in 1969-70.

With reference to the order, of even number dt. 5-4-69, a doubt has arisen whether this ban will cover the following categories also :—

(1) The retirement etc. has taken place before 31st March, 1969, but for some reason or other the posts have not been filled in.

(2) New posts which have been sanctioned before 31st March, 1969, and have not been filled in so far, as also posts which may be newly sanctioned during 1969-70.

It is clarified that while the ban will apply to post of category (1) above, it will not apply to posts of category (2).

It is further clarified that the ban shall not apply to the filling up of the posts by absorption of surplus employees & Swarankars done under GAD (C) order No. F. 1 (33) GA/C/66 dated 23-7-66 and G.A.D. (A) order No. F. 15 (2) GA/A/64 dated 11-1-68. The Appointing Authorities shall also obtain N.A.C. from the GAD(C) as hithertofore for filling any posts otherwise than by allotment of a surplus employee.

[*Cabinet Sectt. (O.&M. Section) No.* F. 27 (1) *Cab*/69, *dated* 23-4-69].

शिक्षा विभाग

EDUCATION DEPARTMENT

INDEX

S.No.	Subject.	No. & Date.	Page No.
6.	Amendment in the Rajasthan Oriental Research Institute Service Rules, 1967.	No. F. 1(9)Apptts. (A-II)/62, dated 6-4-69.	6
7.	Distribution of work between the Director of Education & Director, Primary Education.	No.F. 2(2) Edu /C.II/ 69, dated 26-4-69.	6—7

(6)

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules, to amend the Rajasthan Oriental Research Institute Service Rules, 1967 namely:—

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These rules may be called the Rajasthan Oriental Research Institute Service (Amendment) Rules, 1969.

(*ii*) They shall and shall be deemed to have come into force with effect from the 24th January, 1967.

2. In the Rajasthan Oriental Research Institute Service Rules, 1967,—

(*i*) for the figures "1966" appearing in the caption of the Rules before the expression "PART-I" and in rule 1(i), the figure "1967" shall be substituted; and

(*ii*) in rule 30 the words "from the Rajasthan Sanskrit Educational Subordinate Service" shall be deleted.

[*Edu. (C ll. IV) Dept. Noti. No.* F. *1* (*9*) *Apptt.* (*A-II*)/*62, dated 6th April, 1969*]

(7)

Consequent upon the redesignation of the post of Additional Director, Primary and Secondary Education as Director Primary and Secondary Education (vide this department order No. F. 2 (2) Edu /C. II/69, dated 7-3-69) the distribution of work between the Director of Education and the Director, Primary and Secondary Education will be as indicated in the annexure appended hereto.

This department order number F. 6 (e) (81)Edu./C. II/65, dated 18-9-65 will stand amended to this extent.

[*Edu. (Cell. II) Dept. Order No.* F. *2* (*2*) *Edu./C.II/69, dated 26th April, 1969*]

ANNEXURE

Director of Education. 1	*Director of Primary and Secondary Education.* 2
1. All matters relating to University Education—Degree and Post-graduate Colleges.	1. All matters relating to:— (*a*) Primary and Secondary Education.

1	2
2. Matters relating to:— (a) Curricula and text books. (b) Nationalisation of text books. (c) Approval of books for Libraries.	(b) Social Education. (c) Physical Education. (d) Vocational Guidance Bureau. (e) Departmental Examinations. (f) Rajasthan School of Arts. (g) Teachers Training Colleges.
3. All matters relating to Educational policy regarding the above matters in consultation with the Government.	2. Matters not otherwise mentioned in this annexure. 3. All matters relating to Educational policy regarding the above matters, in consultation with the Government.

वित्त (व्यय) विभाग

FINANCE DEPARTMENT (*Exp.*)

INDEX

(50)

Subject:—Treatment of portion of dearness allowance as pay.

The Governor is pleased to direct that in modification of existing rules and orders, the amount of dearness allowance indicated in para 2 below shall be treated as pay for the purpose and to the extent specified hereinafter, in respect of Government servants who draw pay in the Revised Pay Scales/Amended Revised Pay Scales under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961 or in New Pay Scales under the Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules, 1969.

2. While there will be no change in the scales of pay attached to the various posts and the basis on which the Dearness Allowance is calculated, out of the Dearness Allowance admissible, the following amounts shall be treated as "Dearness Pay" in relation to the pay in the ranges specified below :—

Pay range.	Amount of Dearness Pay.
	Rs.
Below Rs. 110/-	47/-
Rs. 110/- and above but below Rs. 150/-	70/-
Rs. 150/- and above but below Rs. 210/-	90/-
Rs. 210/- and above but below Rs. 400/-	110/-
Rs. 400/- and above but upto Rs. 499/-	120/-
Above Rs. 499/-	Amount by which pay falls short of Rs. 619/-.

PENSIONS AND GRATUITIES.

3. The dearness pay shall count as "emoluments" for pension and gratuity. For this purpose the emoluments as reckoned under rule 250 and 250A of the Rajasthan Service Rules shall be increased by the Dearness Pay appropriate to the pay equal to such emoluments, and the ultimate average emoluments under Rule 251 *ibid* shall be determined on the above basis.

4. Persons who are eligible for the benefits under para 3 above will not be entitled to any Temporary Increase in pension.

JODHPUR CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND

5. For the purposes of calculating the amount of subscription by Government servants and Government bonus to the fund, the Dear-

ness Pay appropriate to the pay on which these contributions are based shall be treated as part of such pay. For this purpose these orders will have effect from 1st March 1969, provided, however, that where the Government servant concerned desires to pay the arrears of subscription from 1st December, 1968, the concession will have effect from that date. For the purpose of calculating the amount of special contribution admissible under the Fund rules the dearness pay appropriate to the pay on which these contributions are based shall also be treated as part of such pay in respect of persons retiring on or after 1st December, 1968.

COMPENSATORY ALLOWANCES (INCLUDING HOUSE RENT ALLOWANCE) ETC.

6. The dearness pay will be treated as pay for the following purposes:-

(*a*) Compensatory (City) allowance admissible under Finance Department Order No. F. 1 (9) FD (Exp.-Rules)/64-II dated 23-9-1964.

(*b*) House Rent Allowance admissible under House Rent Allowance Rules contained in Appendix XVII of the Rajasthan Service Rules, Volume II.

RECOVERY OF RENT

7. The Dearness Pay will also be treated as part of 'emoluments' as defined in Rule 35 of the Rajasthan Civil Services (Determination & Recovery of Rent of Residential Accommodation) Rules, 1958 for the purpose of entitlement to Government accommodation and recovery of rent thereof. For this purpose, these orders will take effect from 1-3-1969.

LEAVE SALARY

8. Leave salary will be calculated as at present (excluding the dearness pay) and the rates of dearness allowance should then be determined in the usual manner on the amount so arrived at, a portion of it being treated as dearness pay in accordance with para 2 above.

Provided that during leave preparatory to retirement (in or out of India) in excess of the first four months dearness allowance of an amount equal to the dearness pay appropriate to the leave salary if the leave is on full pay and half of such amount, if otherwise, may be granted.

ADMISSIBILITY OF DEARNESS ALLOWANCE DURING DEPUTATION ABROAD AND TRAINING ABROAD.

9. During the first six months of their stay on deputation in any one country the Government servant on deputation abroad/training abroad will be granted dearness allowance at the rate at which they would have drawn it, had they not proceeded on deputation and thereafter, at the rate equal to the dearness pay appropriate to the pay during deputation.

TRAVELLING ALLOWANCE.

10. The dearness pay will be treated as pay for the travelling allowance (including mileage and daily allowance). This will, however, not count

as 'pay' for entitlement to rail accommodation. This will be applicable for journeys commencing on or after 1-3-1969.

FREE EDUCATION OF CHILLDREN AND RE-IMBURSEMENT OF TUTION FEES.

11. The dearness pay will also count as pay for determing the limits of pay for admissibility of free education of children and re-imbursement of tution fees. For this purpose these orders shall take effect from 1-3-1969.

ADVANCES.

12. Dearness Pay will also be treated as pay for the purposes of determining the quantum as well as the limits of admissibility of advances e.g. House Building Advance, Conveyance Advance, under the General Financial & Account Rules. For this purpose these orders shall take effect from 1-3-1969.

DATE OF EFFECT.

13. Except as specifically provided otherwise, these orders will take effect from the 1st December, 1968.

LIMITATIONS.

14. Except as specified in these orders the dearness pay will not be treated as pay for any other purposes. For example the dearness pay will not be taken into account for fixation of pay or drawal of increments or for fixation of deputation allowance, nor will it be taken into account for the drawal of dearness allowance. It will not also be shown as a separate element either in the pay bills or the service records.

15. These orders do not apply to—

(*i*) Members of the I.A.S. and I.P.S.

(*ii*) Persons appointed on contract.

(*iii*) Persons who are granted consolidated rates of pay and are not in receipt of dearness allowance.

(*iv*) Persons who are part-time employees and paid from contingencies.

(*v*) Persons on deputation from other Government.

16. Finance Department Orders No. F. 1 (73) FD-A/Rules/62 dated, 28-3-1963 and No. F. 4 (4) FD (Exp.-Rules)/63 dated 1-8-1963 are withdrawn.

17. Separate orders will be issued in respect of—

(*i*) Government servants drawing pay in existing scales of pay as defined in Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961 (as amended from time to time).

(*ii*) Employees of ex-Ajmer State who have opted for old scales of pay and are in receipt of dearness pay in terms of Rule 14 of the Rajasthan Services (Protection of Service Conditions) Rules 1957.

(*iii*) Government servants entitled to the concession of free board & lodging as a condition of service.

[*Finance Department (Rules) order No. F.* 1 (7) *F.D./Rules*/69 *dated* 7-4-69.]

(51)

Subject.—Removal, under Rule 32 of Rajasthan Service Rules of anomalies arising on account of fixation of pay of Government servants.

Consequent upon introduction of Rule 26-A of the Rajasthan Service Rules, Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961 and New Pay Scale Rules 1969 occasions have arisen where Government servant's pay was fixed, at a lower stage than the pay of a Government servant junior to him, by application of any of the rules mentioned above. In order to remove anomalies arising as a result of fixation of pay of senior/junior Government servants it has been decided that the pay of the senior Government servant may be stepped upto a figure equal to the pay as fixed for the junior Government servant. The stepping up should be done by the authority competent to make substantive appointment on the post held by the senior officer with effect from the date the junior officia started getting more pay subject to the following conditions :—

(*i*) The anomaly should be directly as a result of introduction of the aforesaid rules and stepping up of pay should be done only in cases where the appointment/promotion of the junior officer is regular and in accordance with provisions of relevant service rules issued under proviso to article 309 of the Constitution of India or on *ad-hoc* basis.

(*ii*) The senior and junior Government servants should belong to the same cadre/class of posts, and serving in the same department/ service and drawing pay in the same scale before their respective promotions.

(*iii*) Both the Government servants should be under the Administrative Control of one and the same Head of Department/Administrative Department.

(*iv*) The benefit under this decision will be allowed only when it is certified that there is no dispute about the *interse* seniority of senior/junior Government servants and the seniority is not provisional.

(*v*) Where the pay of the senior Government servant is stepped

up under these orders on account of junior Government servant *being promoted on ad-hoc* basis, it may be done with this condition that if the junior Government servant's *ad-hoc* promotion is not converted into a regular promotion according to rules and he is reverted, then from the date of reversion of the junior Government servant the pay of the senior officer would be re-fixed at the stage at which he would have drawn had his pay not been stepped up.

2. The provisions contained in this decision shall not be invoked to step up pay of the senior Government servant in the following cases—

(*a*) Where the junior Government servant is holding the higher post during leave vacancy or a short term vacancy caused due to the holder of the higher post proceeding for training for a period not exceeding 120 days or in any other situation where the higher post is held for a period of 120 days only.

(*b*) Where Junior Government servant already draws higher rate of pay than the senior by virtue of grant of advance increment or grant of higher initial pay for possessing higher qualifications or passing prescribed examinations or for any other reason not attributable to fixation of pay under rule 26-A of Rajasthan Service Rules or under Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, or New Pay Scale Rules, 1969.

(c) Where the junior Government servant holds a post in a different cadre and is appointed to another cadre/class of posts other than the cadre/class of posts to which senior Government servant is already appointed. For example if "A" (senior) L. D. C. was promoted to the post of U. D. C. and subsequently apointed as Accountant on or before the date on which the "B" (junior) was promoted as U. D. C., then there will be no comparison between the pay of the senior as Accountant and junior as U. D. C.

(*d*) Where the junior Government servant is allowed one advance increment in view of his prospective retirement within 10 years under rule 12 of the Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules, 1969.

3. The orders re-fixing the pay of the senior officer in accordance with this decision shall be issued under Rule 32 of the Rajasthan Service Rules. The next increment of the senior Government servant will be drawn on completion of the full requisite qualifying service counting under Rule 31 *ibid* with effect from the date of re-fixation of pay.

[*Finance Department (Rules) Order No. F.1 (8) F.D. (Exp. Rules)/67, dated 28-1-69*]

(52)

Sub:—Recovery of Government dues from death-cum-retirement gratuity.

As an exception to Finance Department Memo No. F1(9)F D (Rules)/68 dated 1-5-1968 it has been decided that any sum due from a Government servant on deputation to Rajasthan State Electricity Board, may be recovered out of death-cum-retirement gratuity payable to the Government servant concerned.

[*Finance Department (Rules) Memo No. F.*1 (9)*FD* (*Rules*)/68, *dated* 18-3-69.]

---

(53)

Sub:—Rajasthan Service Rules—Regularisation of underage appointments.

In accordance with provisions of Rule 8 of Rajasthan Service Rules, the minimum and maximum age for entry into Government service is 16 and 25 years. Cases have been brought to the notice of the Government for regularisation of underage appointments of Government servants which were made by Governments of Covenanting States/Pre-reorganisation States of Rajasthan.

The matter has been considered and the Governor has been pleased to order that cases of all underage appointments made by Government of Covenanting States/Pre-re-organisation States of Rajasthan, may be deemed, under this order, to bear the sanction of Government.

[*Finance Department (Rules) Order No. F* 1(15)*FD* (*Rules* /69, *dated* 17-4-69.]

---

(54)

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Service Rules, namely:—

1. These rules may be called the Rajasthan Service (Amendment) Rules, 1969.

2. In the Rajasthan Service Rules, to Rule 169, the following Explanation shall be added, namely:—

"*Explanation:*—In this rule, the expression "serious crime" *includes a crime involving an offence under* the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) and the expression "grave misconduct" includes the communication or disclosure of any secret

official code or pass-word or any sketch, plan, model. article. note, document or information. such as is mentioned in Section 5 of the said Act (which was obtained while holding office under the Government) so as to prejudicially affect the interests of the general public or the security of the State."

[*Finance Department (Rules) Noti. No. F* 1 (16) *FD (Rules)*/69, *dated* 19-4 1969]

---

(55)

Sub:—Transfer of services of Government servants directly recruited by Autonomous Bodies/Public Sector Corporations—regarding grant of concessions.

The undersigned is directed to refer to Finance Department order No. F. 1 (11) FD (Exp-Rules)/66, dated 23-7-1968 laying down the terms for transfer of the services of Government servants to Autonomous Bodies/ Public Sector Corporation. A question has been raised as to what treatment would be accorded to Government servants who, on their own accord. applied for direct recruitment and have already been appointed, went initially on deputation by their own choice and where subsequently given regular appointment or may be apointed in future by direct recruitment or transfer of services, in Public Sector Undertakings/Autonomous bodies. The matter has been considered and it is clarified that the provisions of the aforesaid order do not apply to such Government servants.

2. However, with a view to cover all such cases of transfers or appointments by direct recruitment in the past and also cases which may arise hereafter, the Governor has been pleased to order that in the case of permanent or temporary Government servants whose appointments under Government were made in accordance with provisions of relevant Service Rules regarding recruitment, promotion etc. promulgated under proviso to Article 309 of the Constitution of India, or on the recommendations of the Rajasthan Public Service Commission or Departmental Selection Committee and who have completed not less than 5 years continuous service under Government at the time of transfer of their services to Autonomous Bodies/Public Sector Corporations, the transfer of their services may be trated in public interest and retirement benefits, subject to provisions contained in paragraphs 3 and 4 below. may be allowed to such Government servants.

3. The term "transfer in public interest" referred to in paragraph 1 above, shall for the purpose of these orders. mean :—

(*a*) transfer to a Public Sector undertakings or autonomouns Body. situated in Rajasthan and in which Rajasthan Government money is invested either in shares or loans.

(b) transfer to a Public Sector Undertaking or Autonomous Body situated in Rajasthan in which Government money may not be invested, but the existence of such an undertaking/body may be beneficial for the economic development of Rajasthan. This will also apply to autonomous bodies or public Sector Corporation under the control of the Government of India, but situated in Rajasthan,

(c) transfer to the Universities situated in Rajasthan or the Malaviya Regional Engineering College, Jaipur or any other autonomous educational institution serving the cause of education in the State of Rajasthan.

4. (i) *Retirement benefits.—*

(a) Where the Government servant is under pension scheme, in lieu of pensionary benefits, an amount equal to what the Government would have contributed had the officer been on Jodhpur Contributory Provident Fund Scheme, together with simple interest at the rates applicable from time to time to employees governed by Jodhpur Contributory Provident Fund Rules, in respect of his pensionary service under Government, may be credited to his Provident Fund Account under the body, at the time the Officer attains the age of superannuation as existing at the time of his transfer to the Public Sector Undertakings or Autonomous Body.

(b) In the case of a Government servant who is on Jodhpur Contributory Provident Fund Scheme, the amount standing to his credit along with Government contribution plus interest thereon, shall be payable to him on his attaining the age of superannuation as existing at the time of his transfer to the Public Sector Undertakings or Autonomous Body.

(c) The amount payable under (a) and (b) above, will also earn simple interest @ 2% per annum from the date of transfer of his service till such time it becomes payable.

(ii) *Leave.—*

The amount of privilege leave standing at the credit of the Government servant on the date of transfer of his services may be availed of by him while under the service of the Autonomous Body/Public Sector Corporation. When leave of similar nature is applied for and is admissible under the rules of the new employer, no amount of leave salary from the Government shall be paid. However, if leave applied for on any particular occasion is in excess of the leave due under the new employer and such excess leave is sanctioned against the amount of leave due at the time of transfer from Government service, the Government shall reimburse to the Autonomous Body/Corporation the amount of leave salary in respect of the excess leave so availed of, according to the Rajasthan Service Rules, as existing on the date of his transfer to the Autonomous Body/Public Sector Corporation.

5. These concessions may not be claimed as a matter of right, but may be sanctioned by the Government in individual cases where the same are merited. Individual cases will be dealt with by the Administrative Department concerned, in consultation with the Finance Department.

6. The decisions contained in preceding paragraphs will apply only where the service of a Government servant is transferred permanently to Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings and it will not apply to cases of transfer to a Private Institution or Private Sector Corporation.

[*Finance Department (Rules) Memo No. F.*1 (48) *FD (Rules)*,68, *dated* 10-4-1969.]

(56)

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules, further to amend the Rajasthan Service Rules, namely :—

1. These rules may be called the Rajasthan Service (Amendment) Rules, 1969.

2. In the Rajasthabn Service Rules—

(*i*) "Note below Rule 89 shall be omitted. In audit instruction (6) appearing below rule 250, the words," or refused leave,

(*ii*) In audit instruction (.) appearing below rule 250, the words, ' or refused leave under Rule 89 of Rajasthan Service Rules" shall be omitted.

[*Finance Department (Rules) Noti. No. F.* 1 (48) *FD (Exp.Rules)*/67 *dated* 1-4-1969.]

(57)

In Fiananee Department Notification No F. 1(48)FD (Exp-Rules) 67, dated 1-4-1969. the words viz., "In audit instruction (6) appearing below rule 250 the *words or refused leave*" appearing in paragraph 2(i) shall be deleted.

[*Finance Department (Rules) Corri. No. F.* 1 (48) *FD (Exp-Rules*)/67, *dated* 16-4-1969.]

(8)

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan is pleased to make the following amendments in the Rajasthan Medical Officers Fee Rules,

1964 (issued under Finance Department Notification No F. 1 (14) FD/A/Rules/61-II, dated 23-10-1964, namely :—

In the said rules—the existing 'Note appearing in the Schedule to these rules shall be substituted by the following —

"*Note* 1. This Schedule shall apply to a patient treated in an out-door department or who is receiving treatment in an in-door ward of a Government hospital, provided the patient is an income-tax payer or is wholly dependent on an income tax payer. A person who is admitted as a patient in a private ward of a Government hospital shall be required to pay fee in respect of any work done for which fee is prescribed in the Schedule. Rajasthan Government servants shall not be required to pay fees prescribed in the Schedule but the fees shall be charged from the Central Government employees who are entitled to reimbursement of such fees under the medical attendance rules by which they are governed.

Note 2. All medical officers in Government hospitals will be provided with a rubber stamp containing the following declaration in Hindi, which will be affixed at an appropirate place on the prescription and which will be signed by the patient himself or in case of a minor patient by the guardian of the patient. In case of an illiterate patient, his/her thumb impression will be obtained on the declaration, in the presence of the medical officer.

मैं आयकर नहीं देता हूं/मैं आयकर देने वाले व्यक्ति पर आश्रित नहीं हूं ।

[*Finance Department (Rules) Noti. No. F.* 1 (77) *FD (Exp-Rules)*/65, *dated* 22-4-1969.]

---

(59)

Sub:—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Amendment thereto—Animal Husbandry Service—Radiologist—Special Pay-Schedule II - Part 4.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely:—

(1) In Schedule II-Part 4—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961-the following entries allowing special pay of Rs. 50/- with the posts of Radiologist X-Ray Unit with effect from 1-9-1961 under Animal Husbandry Department inserted *vide* sub-para 3(D) (ii) of Finance Department Notification No. F. 1 (51) FD (R)/IV/61, dated 29-1-1963 shall be substituted by the

following and deemed to have been substituted with effect from 20-6-1968.

"Radiologist X-Ray Unit 50/- (27)"

[*Finance Department* (*Rules*) *Noti. No. F.2* (*b*) (16) *FD* (*E-R*)/69, *dated* 30-4-1969.]

---

(60)

Sub:—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961-Education Department—Radio Mechanic.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely :—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1969.

2. They shall be deemed to have come into force with effect from 1-9-1961.

3. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961-Schedule I—Section D—Education Department, the following entries shall be inserted:—

	Revised Pay from 1-9-61 to 31-3-66.	Amended Revised Pay.
Radio Mechanic 50-3-95-100	75-3-90-4-110-5-130-EB-5-160. (6)	75-3-90-4-110-120-5-145-SB&EB-155 5-175 (6)

[*Finance Department* (*Rules*) *Noti. No. F.2*(*b*) (18) *FD* (*Rules*)/69, *Dated* 18-4-1969.]

---

(61)

Sub:—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule III and Table for Scale No. 6 appended with Finance Deartment Notification No. F.2(b) (34) FD (E-R)/65, dated 12-1-1968.

In this Department Notification No. F.2(b)(20) FD (Rules)/68, dated 7-1-1969, the following correction may be made:—

(1) The word "in" appearing before "Note 1" against item F.2(b) (13) FD (E-R)/66 dated 14-2-1966 may be read as "as."

(2) The figure "121" appearing in line 4 against item F.2(b) (34)/FD (E-R)/65 dated 12-1-1968 may be read as "and 121".

[*Finance Department* (*Rules*) *Corrigendum No. F.2* (*b*) (20) *FD* (*Rules*)/68, *Dated* 28-3-1969.]

(62)

Subject:—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Mines & Geology Service—Special Officer Projects.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely :—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1969.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1-4-1966.

(3) In the Rajasthan, Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule I—Section B (State Services)—Rajasthan Mines and Geological Service. the existing entry for the post of Special Officer Projects inserted *vide* Finance Department Notification No. ID. 60/62/F. 3 (7) FD/E. II/Gen./62, dated 4-6-1962. shall be substituted by the following :—

	Rationalised Pay Scale.	Revised Pay Scale from 1-9-1961.	Amended Revised Pay Scale.
Special Officer Project	900-50-1400	950-50-1400(31)	1300-60-1600(32A)

[*Finance Department (Rules) Noti. No. F. 2 (b) (20) FD (Rules) /69, dated* 25-4-69.]

---

(63)

Subject:—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Progress Assistant & Computor (Statistics).

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor hereby makes the Rules to amend further, the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, n...

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1969.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1-6-1966.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Schedule III—Scale No. 12:—

The entry for the post of 'Computors in Non-Engineering Department" inserted *vid-* para 3 (B) (1) of Finance Department Notification No. F. 2 (b) (35) FD (E-R)/66, dated 2-6-1966 shall be substituted by the following and deemed to have been substituted with effect from 1-6-1966—

(*i*) Progress Assistant or Computor in Non-Engineering Departments.	Graduate in Economics/Mathematics/Commerce/Science/Statistics, Agriculture or Computor's Certificate Part I (A.B.C.) of Indian Statistical Institute or Diploma in Rural Services awarded by the National Council of Rural Higher Education with any of the subjects specified above.

(*ii*) The words "or Progress Assistant" shall be inserted between the words "Computor" and "after regular appointment" appearing in line 2 under "qualification for promotion" in Schedule III for Scale No. 14 *vi 'e* para 3 (b) (ii) of Finance Department Notification No. F. 2 (b) (:5) FD (E-R)/66-II, dated 19-12-1968.

[*Finance Department (Rules) Notification No. F. 2 (b) (35) FD (E-R)/66, dated* 28-4-69.]

(64)

Subject:—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Medical Department–Drug Inspector & Senior Drug Inspector.

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely :—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1968.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1-4-1968 or from the date the posts are filled whichever is later.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—

Schedule I—Section B—other State Service Officers in various Departments-Medical & Health Department following new entries shall be inserted :—

			Qualifications
(i) Senior Drug Inspector. ..	360-25-560-30-590-EB-30-860-900 with minimum pay of Rs. 385/-.	(27)	The qualifications for the post will be as prescribed in Rule 49 (a) or (aa) of Indian Drugs & Cosmatics Act as in force on 1-4-1968 with 3 years experience in manufacture and testing of substance specified in Schedule C to the Rajasthan Drug Rules.

(ii) The existing entry for the post of "Drug Inspector" inserted under the head Medical Department *vide* Finance Department Notification No. ID 92/62/F. 3 (25) FD/EII-Gen./62, dated 8-6-1962 shall be substituted by the following :—

	From 1-9-61	From 1-4-68		
Drug Inspector.	225-15-270-20-390-25-640. (23)	285-25-560-EB-30-800.	(26)	The qualification for the post will be as specified in Rule 49 (a) of the Indian Drug & Cosmatics Act, as in force on 1-4-1968.

[*Finance Department (Rules) Notification No. F.* 2 (*b*)(57) *FD* (*Rules*)/68, *dated* 25-4-69.]

(65)

Subject:—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961–Bifercation of Medical & Collegiate Services–Special Pay to them.

In this Department Notification No. F.2(b)(67) FD(E-R)/66, dated 9-8-1968, the words 2 "Public Health Centres" wherever they occur in para 3 of the notification may be read as "Primary Health Centres".

[*Finance Department (Rules) Corri. No. F.* 2(*b*) (67) *FD*(*R*)/66, *dated* 10-4-69.]

(66)

Subject:—Instruction regarding issue of financial sanction.

Finance Department *vide* circular Memo No. F.9(22)FD(R)Gen/63, dated 7-12-65 (copy enclosed), had clarified the position regarding sending of drafts to Finance Department for vetting. The intention of the circular was to ensure that delay occurring due to the drafts having to be vetted by the Finance Department may be eliminated. Of late, the departments seem to have lost sight of this circular and in most cases even ordinary drafts are sent to Finance Department for vetting.

This circular is again brought to the notice of the Departments and it is impressed on them that routine drafts should not be sent to Finance Department for vetting unless specifically desired on the file.

[*Finance (Exp I) Department. No. F.* 3(I)/*FD/Exp.-I/*69, *dated* 5-4-69.]

(67)

In pursuance of Rule 21 of Rajasthan Service Rules, the Governor of Rajasthan hereby directs the following amendments in the General Provident Fund (Rajasthan Services) Rules 1954, namely :—

In the said rules :—

1. In rule 10, for the existing clause 3 (1) (A), and 3(1)(B), the following clause shall be substituted, namely :—

"3(1) (A)"—The amount of the subscription in case of subscriber governed by rule 4(2) shall not be less than :—

(*i*) The monthly premium as specified in the table of rates of premium under rule 13(1) of the Rajasthan Government Servants Insurance Rules, 1953, reproduced below, where the first assurance can not be granted on account of overage or on medical grounds :-

Pay Group.	*Rate of Subscription.*
45-70	4
71-90	6
91-140	8
141-200	12
201-300	18
301-450	27
451-650	40
651-900	55
901-1250	78
1251-1600	100
1601-2000	125
2001 and above.	155

(*ii*) The amount equal to the difference between the premium as per the table of rates specified in sub-rule 13 (1) of the Rajasthan Government Servants' Insurance Rules, 1953 and the premium already being paid towards Compulsory Insurance Scheme in case where after the issue of the policy the further assurance cannot be granted on account of overage or on medical grounds.

2. "3(1)(B)"—The amount of subscription, under sub-rule 3(1,(A) shall be subject to the following conditions :—

(*a*) It shall be expressed in whole rupees.

(*b*) It may be any sum, so expressed not less than the amount arrived under rule 3 (1) (A) and shall not be more than his total emoluments.

[*Finance Deptt. (Rules) Noti. No. F.* 4 (4) *FD (Rules)*/68, *dated* 18-3-69.]

(63)

Subject:—Issue of sanctions under Plan Schemes for 1969-70.

Attention of the Departments is invited to Finanace Department's Circular No. F. 7 (23) FD/Exp.-I/68, dated the 26th April, 1968 (copy enclosed for ready reference) whereunder instructions were issued for issue of sanctions in respect of Plan Schemes during 1968-69. Similar procedure is to be followed for issue of sanctions for 1969-70 based on the notes recorded as a result of discussions in the Budget Finalisation Committee meetings.

The Heads of Departments/Administrative Departments are, therefore, requested to please check up the details agreed to in the Budget Finalisation Committee meetings with those appearing in the printed Budget 1969-70 Volume II and initiate action for issue of sanctions immediately after the Budget has been voted by the Assembly. While issuing sanctions care should be taken to ensure that these are complete in all respects and particularly indicate the following :—

1. The new scale of pay in which posts are being created.

(2) The service to which these shall belong. That is to say, the name of the service be shown against the concerning posts.

(3) The duration for/from which these are to be effective. Except otherwise indicated in the B.F.C. notes, all posts may be sanctioned up to 28-2-1974. However, the date from which posts are created may be checked up carefully, as provision for new posts has not been nade for twelve months during 1969-70. It will be the responsibility of the Administrative Department to see that posts are created only for the period for which the provision in the Budget will suffice.

(4) In case any fresh qualifications have been agreed to in the Budget Finalisation Committee notes, then the Administrative Department should move Finance (Rules) Department for issue of necessary orders. The sanctions being issued by the Department should only say that pay scales and qualifications are being prescribed separately in consultatoin with Finance (Rules) Department in respect of these posts.

(5) Correct chargeable head to which the expenditure is to be charged

Only drafts of important nature should be sent to Finance(Exp-I) Department for vetting.

[*Finance (Exp-I) Deptt. Circular No. F.*7(27)*FD*/*Exp*-1/69, *dated* 7-4-69]

Copy of Circular No.F. 7(23)FD/Exp-I/68, dated the 26th April, 1968 from Shri Satish Kumar, Dy.Secretary to Govt., Finance (Exp-I) Department to All Secretaries to Govt., All Heads of Departments (dealt with by F.D.(Exp-I)) etc

As you are aware, the Plan Budget of 1968-69 was finalised during B.F.C. meetings and the items agreed to have also appeared in the annual Budget of the year 1968-69. In respect of all such cases which have been to agreed in BFC meeting and which have appeared in printed Budget 1968-69, you are kindly requested to issue sanctions of the schemes, creation of posts, incurring expenditure on non-recurring items, capital works, loans subsidies etc immediately so that the implementation of the plan may not suffer as a result of delay in issue of sanctions

Most of the sanctions would be of very ordinary nature and there will be no necessity of these being got vetted by Finance Department. The Administrative Departments can itself issue the sanctions directly without getting the draft vetted in respect of such sanctions. Only important sanctions need be referred to Finance Department for vetting.

Some of the items had been placed under lump sum during the BFC meetings for various reasons, chief amongst which was that the Administrative Departments had not supplied the details of the schemes Also amounts saved as a result of the items not being agreed to by Finance Department were put under lump sum. In the interest of Plan implementation, you are kindly requested to move Finance Department immediately for sanctioning break up of these amounts and issuing sanctions thereafter, without delay.

It may be once again brought to your notice that no sanction for a post for which the qualifications do not stand approved by Finance Department can issue. In case such posts have been agreed to during the B.F.C. meetings for which qualifications have not been finalised so far, the Administrative Departments should move Finance Department without delay for finalising the qualifications.

---

(69)

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (New Pay) Scales Rules, 1969 namely.—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Amendment Rules, 1969

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1-9-1968 except otherwise provided.

(3) In Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules, 1969, the following amendments shall be made :—

(a) The exisiting rule 10 (1) and 12 (2) shall be substituted by the following :—

10(1)—' The initial pay of a Government servant who elects or is deemed to have elected under rule 9 to draw pay in the New Pay Scales with effect from 1-9-1968 or from a subsequent date in accordance with sub-rule (1) of Rule 8 shall be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or on which he would have held a lien if it had not been suspended, and in respect of officiating pay in the following manner".

12(2)— 'A Government servant who is drawing pay below Rs. 1500/- in the existing pay scale and is due to retire within 10 years from 1-1-1969 shall be granted one advance increment provided he elects to draw pay in the existing scale, until he vacates the post or ceases to draw pay in that time scale of pay, under rule 8 of these rules. The date of increment shall remain unchanged."

Note:—A Government servant who elects to continue to draw pay in the existing pay scales until the date of his next increment or the date of his subsequent ncrement s, shall get benifit of advance increment under provisions of sub-rule (1) of this rule after fixation of his initial pay in the New pay Scales.

(b) In Schedule I—Section F—Government Secretariat—the following new entries shall be inserted at serial number 1 and 2 and existing serial number 1 to 10 shall be re-numbered as serial numbers 3 to 12 respectively :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Head Translator	285-540	275-20-375-25-650	(17)	—
2.	Head Legal Assistant.	285-540	275-20-375-25-650	(17)	—

(c) In Schedule I—Section F—Archaeology and Museum Department tee following new entry shall be inserted as Seiral No. 16—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Modeller	—	180-10-220-15-385-20-425.	(13)	For Diploma holders from I.T. I. School of Arts or equivalent qualifications recognised by the Government.

(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
			130-8-170-10-210-15-300	(9)	For others.

Instructions appearing at item (c) shall be deemed to have come into force with effect from 22-9-1968.

[*Finance Department (Rules) Noti. No. F.*9(2) *FD (E-R)*/69, *da'ed* 19-4-69.]

(70)

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules to a mend further the Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules, 1969,namely:—

(1) These rules may be called Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Amendment Rules, 1969.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1-9-1968 except as otherwise provided hereinafter.

(3) In Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules, 1969, the following entries shall be inserted:—

(*a*) In Schedule I—Section C—Sheep and Wool Department, the existing entries 375-850" and "(19)" appearing under column No. 4 and 5 respectively against Serial No. 9- Principal, Sheep and Wool Training School, shall be substituted by "500-1000" and "(20)" respectively.

(*b*) In Schedule II—Rajasthan Administrative Service-the following new entry shall be inserted at Serial No 2 and existing serial numbers 2 and 3 shall be renumbered as 3 and 4, respectively:—

1	2
2. Deputy Secretary to Chief Minister drawing pay in Senior Scale.	150/-

(*c*) In Schedule I—Section C—Ground Water Board, the existing entries "1650-2000" and "(31)" appearing under column No. 4 and 5 respectively against serial No. 1- Chief Ground Water Engineer shall be substituted by "1800-2250" and "(32)" respectively.

The item (C) shall be deemed to have come in force from 1-3-1969.

(*d*) In Schedule I - Section C—Industries Department the existing entries appearing under column 4 and 5 against serial number 4(i) and 4(ii) shall be substituted by the follwoing :—

		1	2
4(i)	Project Officer	Rajasthan Industries Service.	Pay in scale equivalent to Assistant Director, Industries will be admissible to persons directly recruited through the Rajasthan Public Service Commission prior to promulgation of Rajasthan Industries Service Rules.
4(ii)	Planning-cum-Survey Officer.	Rajasthan Statistical Service.	

(*Finance Deptt.* (*Rules*) *Noti. No. F* 9.(*15*) *FD* (*E-R*)/*69 dated 28-4-69*

(71)

Sub.—Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules, 1969-Clarification with regard to Personal Pay.

A doubt has been expressed that at what stages pay of Government Servants would be fixed in Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules 1969 who were in receipt of Personal Pay on 1-9-1968 with the pay in the 'existing scales'.

The matter has been examined. The fixation tables given in Schedule III of Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules 1969 indicate the pay in the existing pay scales and the corresponding stages in the New Pay Scales at which the pay is to be fixed, Personal 'Pay' drawn with the existing pay scale on 1-9-1968, shall be included in pay under provisions of Rule 5(3) of the Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules, 1969. Therefore, it is clarified that where pay is fixed in the New Pay Scale, Personal Pay shall first be added to the pay in the existing pay scale and thereafter the pay shall be fixed in the New Pay Scale at the appropriate stage according to provisions of Rule 10(1) (II) and 10(1) (III) ibid.

[*Finance Department* (Rules) *Circular No*. F. 9 (37) *FD* (*Rules*)/69, *dated* 28-4-1969.]

(72)

Sub:—Fixation of pay of Government servants in the Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules, 1969—Pre-checking of Pay Fixation Statements.

In continuation to Finance Department (Memorandum No. F9(47) FD (E-R)/68 dated 28-1-1969, The Governor has been pleased to declare the Treasury Officers as "Prechecking authority" of the pay fixation statements of the non-gazetted revenue staff under the control of the Collectors.

[*Finance Department* (*Rules*) *Order No. F*.9 (47) *FD* (*Rules*)/68, *dated* 28-4-1969.]

—-—

(73)

Sub:—Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules, 1969—Schedule I—Section B—State Services—Rajasthan Mining and Geological Service—Special Officer (Projects).

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules, to amend further the Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules, 1969, namely:—

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Amendment Rules, 1969.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1-9-1968.

(3) In Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules, 1969—Schedule I—Section B—State Services-Rajasthan Mines & Geological Service—the figure "1300-1600" shall be inserted in column No. 3 against the post 'Special Officer (Projects)" appearing at S. No. 3 (page 56).

[*Finance Department (Rules) Noti. No. F.9 (52) FD (Rules)/68, dated* 24-4- 9.]

---

(74)

Subject:—Waiving of petty and isolated claims between State Governments.

I am directed to refer to the Government of Maharashtra, Finance Department letter No. FNR 1069/(2439-68)/VII, dated the 26th March, 1969 and to convey concurrence of this State Government to the continuance of the reciprocal arrangement contemplated in Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) letter No. F.22(15)E-II (A)/65 dated the 30th August, 1965 for a further period of three years with effect from the 1st April, 1969.

[*Finance Deptt. Ways and Means Section No. F.16(21)E.W.M/61, dated* 18-4-69.]

Copy of letter No. FNR/(2439-68)/VII. dt. 26th March, 1969 from the Under Secy, to Govt. of Maharashtra, Finance, Daptt., Sachivalaya Bombay 32 BR.

Subject:—Waiving of petty and isolated claims between the Union Government and State Governments.

Sir,

I am directed to refer to your letter No.F16(21)FWM/61 dated the 25th May, 1966 on the subject mentioned above, and to state that the reciprocal

arrangement as contemplated in Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) letter No.F.22(15)E II (A)/65, dated the 30th August, 1965 expires on 31st March 1969 and to say that the Government of Maharashtra is agreeable to continue the arrangement with the Government of Rajasthan, for a further period of three years with effect from 1st April 1969, if the latter Government has no objection.

Yours faithfully,

Sd-
Under Secretary to Government,
Maharashtra, Finance Department.

वित्त (राजस्व) विभाग

FINANCE (REVENUE) DEPARTMEN

INDEX

(40)

Subject:—Amendment in the General Financial & Account Rules Vol. I. Insertion of Government of Rajasthan Instruction below Rule 46 of the said Rules.

The Governor has been pleased to order that the following be added as Government of Rajasthan Instructions below Rule 46 of the General Financial & Account Rules Vol. I. viz,:—

"Government of Rajasthan's Instructions"

"Orders and letters conveying sanctions should be drafted in clear and unambiguous terms, giving brief but clear details, so as to avoid confusion at a later stage. Special care should be taken that the language used in the draft is concise and incapable of misconstruction, lengthy sentences, abruptness, redundancy, circumlocution, superlatives and repetitions whether of words, expressions or ideas should be avoided. Communications of some length or complexity should generally be concluded with a summery. All legal and statutory documents, drafting of Notifications etc., relating to financial matters should be brought home to the officers responsible thereefr".

[*Finance (Accounts & Investment) Deptt. Order No.* F. 13 (56) *FD/A & I/GFA*R/68, *dated* 18-4-69.]

सामान्य प्रशासन विभाग
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

INDEX

(5)

Subject:—Powers and functions of the Commissioner for Border Districts in Rajasthan.

In continuation of the General Administration Department order of even number dated the 10th June, 1965, the Governor is pleased to further order that the Border Commissioner shall supervise relief programme in the districts of Bikaner, Jaisalmer, Barmer, Jodhpur and Jalore. He shall specially ensure that the necessary arrangements are made to preserve the health of the affected population.

[*General Administration (A) Deptt. Order No.* F. 1 (21) *GA/A/Gr. II/*64, *dated* 14-4-69.]

---

(6)

इस विभाग के सम संख्यक आदेश दिनांक 14-3-68 की ओर राज्य सरकार के अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों, कार्यालय अध्यक्षों व न्यायालयों (राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों को छोड़ कर) के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह आदेश दिए गए थे कि मध्यान्ह अल्पाहार का समय 1.30 बजे से 2.00 बजे तक रहेगा। राज्य सरकार के पास ऐसी शिकायतें पहुंची हैं कि इस समय की पालना नहीं की जा रही है और अल्पाहार अथवा भोजन के लिए आधे घंटे से अधिक समय लिया जाता है, अतः यह आदेश दिया जाता है कि मध्यान्ह अल्पाहार भोजन का समय जो कि 1.30 बजे से 2.00 बजे तक का है उसे दृढ़ता से पालन किया जाए और कार्यालय के समय जो कि प्रातः 10 बजे से शाम के 5 बजे तक है कोई अधिकारी एवं कर्मचारी गण घर पर भोजन के लिए न जाएं। इस आज्ञा के उल्लंघन पर सरकार द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 14 अप्रेल, 1969 से लागू किए जावें।

[सामान्य प्रशासन (क) विभाग आज्ञा संख्या प. 1(51) सामप्रक/64, दिनांक 5-4-69]

---

(7)

Subject:—Allotment of Government residential accommodation.

The Governor has been pleased to make the following addition in the Rajasthan Civil Services (Residential Accommodation) Rules :—

In sub-rule 10 (i) Secretary to Chief Minister may be added between the words "The Secretaries to Government of Rajasthan and Heads of Departments Class I and" "Commissioners" occuring in line 1 of this Rule.

[*General Administration (A) Deptt. Order No.* F. 4 (20) *GA/A/*69, *dated* 23-4-69.]

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग
MEDICAL & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

INDEX

(3)

विषयः—राजस्थान जल प्रदाय नियम, 1967

राजस्थान सरकार. राजस्थान जल प्रदाय नियम, 1967 जो कि इस विभाग की अधि-सूचना संख्या एफ. 4 (97) चि.। स्वा। 67 दिनांक 1-7-67 द्वारा जारी किये में निम्न संशोधन करती है अर्थात्:—

"नियम 16 में उप-नियम (2) के पश्चात निम्नांकित नया उप नियम

(3) जोड़ दिया जायः—

(3) यदि विभाग के पास स्टाक में कोई मीटर तुरन्त उपलब्ध न हो तथा उपभोक्ता मीटर युक्त कनेक्शन लेने का इच्छुक हो, तो उपभोक्ता द्वारा प्रदान किया मान्यता प्राप्त फर्म का बना नया मीटर स्वीकृति किया जाकर उसे मीटर युक्त कनेक्शन दिया जा सकता है। यह सहुलियत उन उपभोक्ताओं को भी मिल सकेगी जिनके इस समय फ्लेट रेट कनेक्शन हैं अथवा स्वयं के मीटर हैं। उप नियम (2) की समस्त शर्तें ऐसे उपभोक्ताओं पर भी लागू होगी और उनसे मीटर का निर्धारित मासिक किराया भी वसूल किया जायेगा"

[चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग विज्ञप्ति संख्या प. 1 (2) जन. स्वा. 168, दिनांक 10-4-69]

राजस्व विभाग
REVENUE DEPARTMENT

INDEX

(4)

Subject:—*Village Service Grants.*

I am directed to state that in accordance with the provisions of section 193 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, the Collectors of the respective districts are required to declare that the services rendered by the village servant are no longer required and the concerned village servant shall become a Khatedar tenant of his village service grant and shall be liable to pay rent accordingly. It has been brought to the notice of the State Government that the custom of utilising the services of village servant has still not ceased altogether in scme parts of the State. The State Government is keen to abolish this system of village service grants in the State at an early date. Orders regarding abolition of the system in the colony areas of Ganganagar District were issued vide No. F. 2 (682) Rev./B/62. dated 5-6-65 but no separate orders had been issued regarding non-colony areas. Action regarding the abolition of village service grants which come under section 193 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 has now to be taken by the concerned Collectors for non colony areas immediately.

[*Revenue (B) Deptt. No.* F. 2 (682) *Rev./B/*62, *dated* 29/30-4-69.]

केवल कार्यालय उपयोगार्थ

राजस्थान सरकार

मंत्रि-मण्डल सचिवालय

व्यवस्था एवं पद्धति (संकलन) अनुभाग

मार्च, 1969 में शासन सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गए महत्वपूर्ण परिपत्रादि का मासिक संकलन

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

1969

LIST OF DEPARTMENTS

(In respect of which important circulars etc. have been printed in this compilation).

विभागों की सूची

(उन विभागों की सूची जिनके महत्वपूर्ण परिपत्रों आदि को मार्च, 69 के संकलन में मुद्रित किया गया है) ।

नियुक्ति विभाग

सूची

(6)

In this Departm nt Notification of even number dated the 15th July, 1966 published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV-C, dated the 16th July, 1966, at serial number 2(a) regarding amendments in the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Staff Rules, 1957, for the figure "21" wherever occurring read the figure and letter "21A".

[Appointments (A-II) Department Corrigendum No. F. 1 (2) Apptts. (D)/60, dated 25-3-69.]

---

(7)

इस विभागीय आज्ञा सं. 5 (2) नियुक्ति (क-1)/68, दिनांक 23 अगस्त, 1968 के प्रथम पैराग्राफ की द्वितीय लाइन में अंकित शब्द "दिनांक 15 जुलाई, 1968" के बदले "दिनांक 19 जुलाई, 1968" ठीक कर पढ़ा जाय।

[नियुक्ति (क-1) विभाग शुद्धि-पत्र सं. प. 1 (7) नियुक्ति (ग)/51, दिनांक 25-3-69]

---

(8)

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with rule 11 of the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendment in the Schedule I appended to the said rules, namely:—

AMENDMENT

In the Schedule I to the said rules, under the heading 'State Services', in the note below 'Commercial Taxes Department', between the expressions "Assistant Commercial Taxes Officer (P.F.)" and "shall vest", the expression "and Non-R.A.S. Commercial Taxes Officers (S.No.4)" shall be inserted.

[Appointments (A-III) Department Notification No. F. 3(3) Apptts. (A-III)/67, dt. 26-3-69.]

मन्त्रि-मण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति अनु. सहित)

सूची

(31)

A provision has been made in the New Pay Scale Rules, 1969 that fresh recruits on the posts of L.D.Cs. shall not be allowed increments beyond the minimum pay of New Pay Scales unless they pass typing test as prescribed under the Rules.

In order to avoid complications in future, it is enjoined upon all Appointing Authorities that no candidate should be appointed as L.D.C. on *ad hoc* basis or otherwise, unless the candidate has taken the typing test and has passed the same with the prescribed Speed. With a view to ensure the compliance of these instructions, the Treasuries will see that the pay of the persons newly recruited as L.D.C. is not passed unless the order of appointment contains a certificate from the Drawing Authority to the effect that the person concerned has passed the typing test as prescribed under the Rules.

Cabinet Secretariat (O.&M. Sec.) Circular No. F.1(5)O. & M./69, dt. 24-3-69.]

---

(32)

विषय :—सलादीपुरा (सीकर), उदयपुर तथा ब्यावर-पाली क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु पानी की उपलब्धी की संभावनाओं पर विचार हेतु समिति का गठन ।

1. राज्यपाल, एतद्द्वारा,

(1) सीकर जिले में सलादीपुर के निकट फर्टिलाइजर कम्प्लेक्स स्थापित करने,

(2) उदयपुर क्षेत्र में रोक फोस्फेट के उपयोगार्थ एक प्लान्ट स्थापित करने और जिंक स्मेल्टर की नई यूनिटें कायम करने, तथा

(3) ब्यावर में सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित करने,

के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने की संभावनाओं/साधनों पर विचार करने हेतु निम्नांकित सदस्यों की एक समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(1) मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर ।

(2) मुख्य अभियंता, पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग, जयपुर ।

(3) चीफ ग्राउन्ड वाटर इंजीनियर, राजस्थान अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड, जोधपुर ।

2. समिति निम्नलिखित बातों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करेगी :—

(क) सलादीपुरा (सीकर) के निकट लगभग 15 लाख गैलन जल प्रति दिन उपलब्ध कराने के साधन जिनमें (1) रानोली नदी, (2) कांटली नदी, तथा (3) सावी नदी से पानी उपलब्ध कराने के साधन भी सम्मिलित हैं।

इस सम्बन्ध में समिति जिओलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के जयपुर स्थित प्रतिनिधि को भी, जिसे सलादीपुरा के निकट जल के अन्वेषण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कोआप्ट कर सकेगी।

(ख) उदयपुर क्षेत्र में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की विभिन्न संभावनाओं को अन्वेषण यथा :–

(1) टीडी बांध की, जिस पर कि कार्य पहले से ही चालू है, जल क्षमता बढ़ाई जाने के संबंध में भी विचार।

(2) उदयपुर शहर की झीलों में पानी वृद्धि के प्रश्न पर भी, जो प्राथमिकता देने योग्य है, विचार।

(3) उदयपुर डिवीजन के दक्षिणी भाग में उपलब्ध पानी को मोड़ कर उसे राजस्थान के शेष भागों में सुलभ कराने की योजनाओं पर विचार।

(ग) ब्यावर—पाली क्षेत्र में प्रस्तावित सीमेन्ट फैक्ट्री के लिये पानी की उपलब्धी :

समिति की सुविधार्थ राज्य का खनिज विभाग उसे यह बतायगा कि ब्यावर पाली के किन क्षेत्रों में चूने के पत्थर (लाइम स्टोन) के अच्छे भंडार पाये गये हैं। खनिज विभाग, जिओलोजिकल सर्वे आफ इंडिया से सम्पर्क कर भूगर्भ जल प्राप्त होने की संभावनाओं पर तथा जयपुर उद्योग लिमिटेड से जो कि ब्यावर में सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित करना चाहता है सम्पर्क कर उनके द्वारा नारायण सागर से जल प्राप्त करने की संभावनाओं पर जानकारी लेकर समिति को उपलब्ध करावेगा। इस सारी जानकारी के आधार पर भी विचार कर समिति सुझाव देगी कि उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिये क्या उपाय काम में लाए जावें। सुझाव देते समय समिति नारायण सागर के पानी की उपलब्धी की संभावना को भी दृष्टि में रखेगी।

3. समिति की प्रथम बैठक का संयोजन सचिव, सिंचाई विभाग करेंगे जिसमें राज्य के उद्योग सचिव भी उपस्थित होंगे और वे समिति के विचारणीय विषयों पर पूरा पूरा प्रकाश डालेंगे।

4. समिति, सलादीपुरा क्षेत्र में पानी की उपलब्धी से संबंधित अपनी प्रतिवेदन दो माह की अवधि में सरकार को सचिव, सिंचाई विभाग को प्रस्तुत करेगी और शेष विषयों पर इसके अगले दो माह की अवधि में।

[मंत्रि-मंडल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा सं. प. 5 (10) व्य. एवं प.169, दिनांक 6-3-69]

(33)

विषय :—केशवरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लिमिटेड समिति का गठन ।

केशवरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लिमिटेड जिला बून्दी की संस्थापना में हुई प्रगति की नियमित समीक्षा करने हेतु राज्यपाल महोदय, एतद्द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों की एक स्थायी समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1.	विशिष्ट सचिव (सहकारिता) ।	अध्यक्ष
2.	पंजीयक, सहकारी समितियां ।	सदस्य
3.	मुख्य अभियन्ता, सिंचाई या उनके द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति जो अधीक्षण अभियन्ता के पद से कम का न हो ।	,,
4.	कृषि निदेशक (या उनके द्वारा मनोनीत संयुक्त या उप कृषि निदेशक) ।	,,
5.	अध्यक्ष, सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, बून्दी ।	,,
6.	मैनेजिंग डाइरेक्टर, केशवरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स, लि.	सदस्य सचिव ।

2. समिति की एक पक्ष में एक बार बैठक यह सुनिश्चित करने के लिये होगी कि कार्य की प्रगति अनसूची के अनुसार हो रही हैं । समिति द्वारा नियमित प्रगति समीक्षा, विशेषतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर की जावेगी :—

(क) संस्थापना और फैक्ट्री के सामयिक कार्य से संबद्ध सभी पहलू जिसमें कार्य के कार्यक्रम, मशीनों का प्रतिष्ठापन और कर्मचारियों की व्यवस्याएं सम्मिलित हैं ।

(ख) फैक्ट्री की संस्थापना और उसके चलाने हेतु पर्याप्त एवं सामयिक वित्तीय व्यवस्था ।

(ग) वांछित सीमा तक गन्ना क्षेत्रों का विकास और आवश्यक आदान की सामयिक सप्लाई ।

(घ) अन्य सम्बद्ध मामले ।

(मंत्रि मंडल–सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा सं. प. 5(11) व्य. एवं प.169, दिनांक 13-3-69)

---

(34)

7 मार्च, 1967 को जयपुर में होने वाले पुलिस फायरिंग से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को एवं घायल व्यक्तियों को एक्स-ग्रेशिया अनुदान के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये राज्यपाल एतद्द्वारा, हिज हाईनेस महाराजा साहिब, जयपुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का आदेश देते हैं । इस समिति के अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे:—

1. श्री के. क. शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश ।

2. श्री गंगासहाय पुरोहित, भूतपूर्व वित्त आयुक्त ।

3. मुख्य सचिव, राजस्थान ।

4. वित्त आयुक्त (व्यय) सदस्य सचिव

यह समिति अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करेगी ।

[मन्त्रि मण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा सं. प. 5 (12) व्य. एवं प.169, दिनांक 20-3-69]

---

(35)

राज्यपाल, एतद्द्वारा 7 मार्च सन् 1967 को जयपुर नगर में हुये पुलिस फायरिंग के सम्बन्ध में बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति के गठन का अनुमोदन करते हैं :—

1. मुख्य सचिव ।

2. महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) ।

3. विधि सचिव ।

यह समिति अपने सुझाव सरकार को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करेगी ।

[मन्त्रि-मण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा सं. प. 5 (13) व्य. एवं प., /69, दिनांक 21-3-69]

---

(36)

विषयः-नियमों/परिनियमों आदि की 15-15 प्रतियां अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के परिनिरीक्षणार्थ भेजन के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषय में सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर द्वारा मुख्य सचिव को सम्बोधित उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 2488, दिनांक 10-2-69 की एक प्रति संलग्न है, इस सम्बन्ध में समस्त शासन सचिवों का ध्यान तत्कालीन मुख्य सचिव श्री के. पी. यू. मेनन के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 20 जून, 1968 तथा वर्तमान मुख्य सचिव श्री आर. डी. माथुर के अर्द्धशासकीय समसंख्यक पत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 1968 की ओर आकर्षित किया जाता है—जिसमें ये स्पष्ट आदेश दिए गये थे कि नियमों/परिनियमों आदि के बनते ही उनकी 15-15 प्रतियां विधान सभा सचिवालय को राजस्थान विधान सम्बन्धी समिति के परिनिरीक्षण हेतु भेजी जावें । परन्तु खेद है कि विभागों द्वारा इस ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया है और नियमों की वांछित प्रतियां समय पर न पहुंचने के कारण विधान सभा सचिवालय को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा है और इस बारे में पुनः उन्होंने मुख्य सचिव का ध्यान आकर्षित किया है ।

2. अतः पुनः अनुरोध है कि अब तक निर्मित सभी नियमों/परिनियमों आदि की 15-15 प्रतियां जो अब तक विधान सभा सचिवालय को नहीं भिजवाई गई हों, तुरन्त भिजवाने का प्रबन्ध

किया जावे तथा भविष्य में भी बनने वाले समस्त नियमों/परिनियमों की 15-15 प्रतियां समय पर विधान सभा सचिवालय को भिजवाने की व्यवस्था की जाये। सचिव, राजस्थान विधान सभा के संलग्न पत्र में चाहे अनुसार, नियमादि जब सदन की मेज पर रखन हेतु विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किये जावें तो उनकी 15-15 अतिरिक्त प्रतियां भी सम्बन्धित शासन सचिवों द्वारा अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के प्रयोजनार्थ प्रेषित कर दी जाया करें।

[मन्त्रि-मण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति) अनुभाग आज्ञा सं. प 10 (24) व्य. एवं प. 68 दि. 20 3-69]

प्रतिलिपि संख्या 2488, दिनांक 0- -1 . सचिव, राजस्थान विधान सभा की ओर से मुख्य शासन सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर को।

विषय :—नियमों, परिनियमों आदि की 15-15 प्रतियों को अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के परिनिरीक्षणार्थ भेजने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के परिनिरीक्षण हेतु नियमों/परिनियमों आदि की 15-15 प्रतियां भेजने के संबध में इस सचिवालय द्वारा कई दफा लिखा जा चुका है तथा राज्य सरकार ने भी समस्त शासन सचिवों को निदेश दिये हैं कि नियमों आदि की प्रतियां नियम निर्माण होते ही भेज दी जाय, लेकिन फिर भी वांछित प्रतियां राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा समय पर प्रेषित नहीं की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन है कि नियमादि जब सदन पटल पर रखने हेतु इस सचिवालय को प्रेषित किये जायं उस समय उनकी 15-15 अतिरिक्त प्रतियां भी संबंधित शासन सचिवों द्वारा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रयोजनार्थ प्रेषित कर दी जाया करें।

कृपया इस संबंध में आप द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की सूचना अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सूचनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवन्निष्ठ
बी. के. डी. बैजल,
सचिव।

---

(37)

विषय:—राजस्थान में तथा राजस्थान से बाहर स्थित देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों तथा उनसे संबंधित जायदाद को रखने या बेचने के संबंध में निर्णय हेतु परामर्शदात्री समिति का गठन।

उपर्युक्त विषय में इस सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति) अनुभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 6-11-64 के क्रम में राज्यपाल महोदय, एतद्द्वारा, (1) उक्त समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री प्रताप मल सिंह भण्डारी, विकास आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन विभाग के स्थान पर विशिष्ट सचिव, नियुक्ति (क) विभाग को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किये जाने

की तथा (2) उक्त समिति को एक स्थायी समिति का रूप दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

[मंत्रि-मंडल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग आज्ञा सं. प. 5(55) व्यय. एवं प.164, दिनांक 20-3-69]

(38)

राजस्थान के राज्यपाल ने मुख्य मंत्री के परामर्श से शासन कार्य नियमावली के नियम 5 (1) के अनुसार समसंख्यक आदेश दिनांक 22-6-68 के आंशिक संशोधन में मंत्रियों के विभागों में निम्नांकित परिवर्तन के आदेश दिये हैं :—

खादी एवं ग्रामोद्योग	श्री अमृतलाल यादव से श्री हरिदेव जोशी को
यातायात	श्री अमृतलाल यादव से श्री रामप्रसाद लढ्ढा को

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशाली है ।

[मंत्रि-मंडल सचिवालय विज्ञप्ति सं. प. 8(5) फवि।67, दि. 20-3-69]

(39)

इस सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति) अनुभाग के परिपत्र संख्या प. 15(24) व्य. एवं प.165, दिनांक 19 फरवरी, 69 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

1. आइटम 1 की आठवीं पंक्ति के शब्द "विकास अधिकारी" के स्थान पर शब्द "जिला विकास अधिकारी" एवं

2. आइटम 2 की प्रथम पंक्ति में "संख्या 8 से अधिक" के स्थान पर "संख्या 8 या 8 से अधिक" पढ़ा जावे ।

[मंत्रि-मंडल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति) अनुभाग शुद्धि-पत्र सं. प. 15 (24) व्य. एवं प.165, दिनांक 20-3-69]

शिक्षा विभाग

सूची

(3)

The Governor has been pleased to order that the following new para may be added to Rule 3(16) of the Rules for Payment of Grant-in-aid to Non-Government Educational, Cultural and Physical Education Institutions in Rajasthan 1963, published in Rajasthan Gazette *vide* No. F.2 24) Edu, Cel./VI/62, dated 19-1-1963.

"The age of superannuation of employees holding posts equal to Class III and Class IV employees of Government shall not exceed 58 and 60 years respectively."

This order shall be applicable from 1st July, 1969.

This issues with the concurrence of Finance Department Exp.I) *vide* their I.D.No.1046, dated 20-3-1969.

[Education (Cell.VI) Department No.F.1(164) Edu/Cell/VI/68, dated 21st March, 1969.]

---

(4)

In partial modification of Government Orders No.F.17 A(2) Edu/II/54, dated 11th August, 1954, F.4(11) Edu/Cel /VI/62 Pt. II, dated 11th October, 1963 and F. 15(22) Edu./59, dated 18-9-59, 26-9-60 and 21-8-67 regarding the Schemes and Rules for the award of financial assistance to students, and other Rules on the subject, the Governor has been pleased to order that the following Schemes may be operated as under with effect from 1-7-1969:

(1) *Merit Scholarship.*—300 Scholarships (200 for Science, Technical and Professional Courses, 75 for Arts and 25 for Commerce Courses) shall be awarded every year on the same conditions of eligibility as in the case of National Scholarship. These Scholarships would be available to all those in the Merit list who have not been able to receive National Scholarship.

(2) *Need-cum-Merit Scholarship.*—200 Scholarships (125 in Science, Technical and Professional Courses and 75 in Arts/Commerce Courses) at the undergraduate level shall be awarded evey year to students whose Parents/Guardians have an annual income of Rs. 2500.00 or less (excluding allowances). All students obtaining 55% or more marks at the High/Higher Secondary Examinations would be eligible for this Scholarship.

Loans.—No study Loans shall be given to the students studying in Rajasthan, elsewhere in India and abroad.

Extreme Poverty Scholarship.—No extreme Poverty Scholarship shall be awarded in Colleges.

Action to modify the relevant provisions of the Rules is being taken separately by the Department.

This issues with the concurrence of the Finance Department (Exp.I) *vide* their I.D. No. 607, dated 18-2-69.

[Education (Cell VI) Department Order No. F.2(53) Edu/Cell/VI/68, dated 7th March, 1969.]

---

(5)

The Governor has been pleased to order that the facility of free education be also extended to the wards of the employees of Panchayat Samitis and Zila Parishads both Gazetted and Non-gazetted who are in receipt of pay below Rs. 400.00 (Rupees four hundred) per month in all Government Educational Institutions in Rajasthan Technical or otherwise, as admissible under the Government Orders No.F.1.(127) Edu/Cell/VI/56, dated -7-56 as modified *vide* Orders No. F. 1(17) Edu./Cell/56, dated 9-4-62 and F.3(9) Edu./Cell/VI/64, dated 26-10-1964.

This Order will take effect from 1-7-1969.

[Education (Cell VI) Department Order No.F. 3(2) Edu./Cell/VI/65, dated 20-3-69.]

वित्त (व्यय) विभाग

(43)

Sub:—Procedure regarding appointment-Delegation of powers to the Secretaries of Administrative Departments to make Provisional Payment of Salary.

The undersigned is directed to refer to this Department Memo No. F '(39)FD(Exp-Rules)/65. dated 11th September, 1968 and to say that the Government have decided further to authorise Secretaries to Government in the Administrative Departments to sanction Provisional Payment of Salary upto 31-8-1969 in respect of Gazetted and Non-gazetted Officers in which cases concurrence of the Rajasthan Public Service Commission to their appointment has not been obtained or promotions have not been finalised by the Departmental Promotion Committee constituted under respective Service Rules.

[Finance Department Memo No. F1 (39) FD(Exp-Rules/65,dt. 12-3-69.]

(44)

Sub:—Rajasthan Service (Concession on Project) Rules, 1962—Applicable to the staff of U.N.S.F. Agriculture Department and Colonisation Department.

In pursuance of Rule 42 of Rajasthan Service Rules, the Government are pleased to order that the provisions of the Rajasthan Service (Concession on Project) Rules, 1962 shall also be applicable to the staff of the following departments with effect from 1-9-1968.

1. Agriculture Department staff sanctioned for U.N. Special Fund Soil Survey and Water Management Research and Demonstration in the Rajasthan Canal area.

2. Colonisation Department staff sanctioned for the Rajasthan Canal areas.

[Finance Department (Rules) Order No. F.2(b)(12)FD(E-R)/69,dated 12-3-69.]

(45)

Sub;—Advance increments to persons drawing pay in old scale. Opportunity to exercise option to persons drawing pay in old scales.

Doubt has been expressed as to whether the benefit of advance increments admissible to officers/officials of Medical/Education Department possessing or acquiring higher qualifications may be allowed to officers and officials of these Departments drawing pay in scales other than

Revised Pay Scales, 1961 or Amended Pay Scales, 1966 or not. The matter has been examined. The provision of allowing advance increment or higher initial pay has been made in the Revised Pay Scales 1961 and the Amended Revised Pay Scales, 1966 in respect of officers/officials of the Medical Department (both General and Collegiate Branches) and Education Department and as such Government servants of the aforesaid Departments drawing pay in scales other than Revised Pay Scales/Amended Revised Pay Scales are not eligible to draw advance increments for possessing or acquiring qualifications in the same manner in which advance increments are admissible to those Government servants who had opted Revised Pay Scales, 1961 or Amended Revised Pay Scales, 1966, This causes hardship to such Governments servants.

The Governor has been pleased to order that Government servants of Medical and Education Department drawing pay in scales other than Revised Pay Scales 1961 and Amended Revised Pay Scales, 1966 may be allowed an opportunity to give fresh option to opt the Revised Pay Scales, 1961 or Amended Revised Pay Scales, 1966 within a period of three months from the date of issue of these orders.

[Finance Department (Rules) Order No. F.2(b) (13)FD(Rules)/69 dated 12-3-69.]

(46)

Sub:—Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961—Medical Department—Senior Foreman.

In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, namely:—

1. These Rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1969.

2. They shall be deemed to have come into force with effect from 1-11-1966.

3. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961 Schedule I—Section D—Medical Department—the entries inserted for the post of "Senior Foreman" *vide* para 3 of Finance Department Notification No. F2(b) (18)FD(Exp-Rules)/68, dated 25-6-1968 shall be deleted and the following new entries shall be inserted:—

Senior Foreman	285-20-385-25-510-540.	(22)	Diploma in Automobile Engineering.

[Finance Department (Rules)/68 Notification No. F.2(b)(18)FD(E-R)/68, dated 12-3-69.]

(47)

विषय :—राजस्थान सिविल (पुनरीक्षित वेतन श्रृंखला) नियम, 1961—वेतन श्रृंखला 9 व 10-स्पष्टीकरण ।

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.2 (बी) (21) एफ. डी. (ई.आर.)।67,1 व 11, दिनांक 2-3-67 के प्रावधानों के अनुसार कनिष्ठ लिपिक को वेतन श्रृंखला संख्या 9 व 10 में क्रमश : 98/- व 102/- रु. का उच्च वेतन मुद्रण गति अंग्रेजी व हिन्दी में क्रमश : 40 व 30 शब्द प्रति मिनिट की निर्धारित गति योग्यता प्राप्त करने पर दिया जाता है, इस संबंध में शंका की गई है कि जो कनिष्ट लिपिक उपरोक्त योग्यता सर्विस में आने के बाद प्राप्त करते हैं, उनकी अग्रिम वेतन वृद्धि की तिथि सामान्य रहेगी या उच्च वेतन प्राप्त करने की तिथि ।

इस विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों के मामलों में वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि उनके उच्च वेतन प्राप्त करने से राजस्थान सेवा नियम के नियम 31 के अन्तर्गत पूरे एक साल की अवधि समाप्त होने पर होगी ।

[वित्त विभाग (नियम) परिपत्र स. एफ. 2 (बी) (21) वित्त (व्यय-नियम)/67, दिनांक 7-3-69।]

(48)

वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 10 (13) वित्त (ए) । 61, दिनांक 31-8-61 के अनुसार जो लेखालिपिक बाहर से प्रशिक्षण के लिए "अधिकारी प्रशिक्षणालय" में आते थे उन्हें 40) रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाता था ।

सभी कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण हेतु आवें, उन्हें प्रतिपूर्ति भत्ता देने के संबन्ध में विस्तृत आदेश, राजस्थान यात्रा भत्ता नियम के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 7 (डी) (25) वित्त विभाग (ए) नियम।60, दिनांक 19-9-62 द्वारा प्रसारित किये जा चुके है । अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 18-9-62 के पश्चात् जो लेखालिपिक बाहर से प्रशिक्षण के लिये "अधिकारी प्रशिक्षणालय" में आवेंगें उन्हें प्रतिपूर्ति भत्ता वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 7(डी) (25) वित्त विभाग (ए) नियम।60, दिनांक 19-9-62 के अनुसार ही मिलेगा ।

[वित्त विभाग (नियम) परिपत्र सं. प. 3 (13) वित्त (नियम)/68, दिनांक 6-3-69]

(49)

Sub:—New Pay Scales, 1969—Inclusion of left out or newly created posts in the Schedule I.

The Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules, 1969 have been promulgated *vide* Finance Department Notification No. F. 9(47)FD(Rules)/68, dated 28-1-1969, published in the Rajasthan Rajpatra, Extraordinary, Part IV (C), dated 28-1-1969. In Sections B, C, D, E and F of Schedule I appended to these rules, New Pay Scales in respect of various services and departmental posts have been indicated.

Despite care and every possible efforts to include the existing posts in the Departments it may be that some posts have been left out. Besides there may be certain printing errors and omissions in the new pay scales rules notified in the Gazette.

The incumbents of the left out posts will not get the benefit of fixation of pay as long as the omitted posts are not incorporated in the respective sections of the Schedule I. It is, therefore, enjoined on all Heads of Departments/Offices that they may kindly go through Schedule I carefully and bring to the notice of the Finance Department factual errors, incorrect nomenclature of posts, and particulars of posts not included in Schedules as early as possible. The information should be furnished separately in the enclosed *proforma* in respect of (1) posts sanctioned and created since 1-9-1968 but not included in the new pay scales (2) posts existing on 31-8-1968 but left out or omitted in the New Pay Scales.

It is particularly requested that complete and up-to-date information in respect of posts for inclusion in the New Pay Scales may be sent to Finance Department (Rules) by the end of March, 1969.

[Finance Department (Rules)/68 Circular No. F. 9(47)F.D. Exp. Rules/68, dated 6-3-1969.]

Particulars of New Posts created on or after 1-9-1968 but not included in the Schedule I appended to New Pay Scale Rules, 1969

S. No.	Name of the post	Existing pay scale in Revised Pay Scales 1961/Amended Pay Scales, 1966.	Temporary or permanent (if temporary period for which created)
1	2	3	4

Reference of Government Order creating post (True copy of order be attached.	Whether encadred in State Service/Subordinate Service/ Ministerial Service or not. If yes, indicate name of the service.	Qualifications prescribed by Government (attach a copy of Government Order/ Notification prescribing pay scale and Qualifications).
5	6	7

Proposals for change in qualification, if already made to Government or desired to be made now.	Method of recruitment including ratio as between direct recruitment and promotion.
8	9

Name of the lower post from which promotion to this post is made.	Nature of duties and responsibilities. (Briefly give details explaining lever of authority, jurisdiction etc.	Remarks
10	11	12

Particulars of posts existing on 31-8-1968 but not included in the Schedule I appended to New Pay Scale Rules, 1969.

S. No.	Name of the post	Existing pay scale in Revised Pay Scales 1961/Amended Pay Scales, 1966.	Temporary or permanent (if temporary period for which created.)
1	2	3	4

Reference of Government Order creating post. (True copy of order be attached.)	Whether encadred in State Service/Subordinate Service/Ministerial Service or not. If yes, indicate name of the service.	Qualifications prescribed by Government (attach a copy of Government Order/Notification prescribing pay scale and Qualifications).
5	6	7

Proposal for change in qualification, if already made to Government or desired to be made now.	Method of recruitment including ratio as between direct recruitment and promotion.
8	9

FINANCE DEPARTMENT (REVENUE)

FINANCE DEPARTMENT (REVENUE)

1	2	3	
32.	Amendment in the General Financial & Account Rules Vol. I—Procedure to be followed when a cheque is alleged to have been lost and a fresh cheque is required to be issued (Rule 129(i).	F.13(59)FD/A&I/GFAR/68, dated 5-3-69.	21—24
33.	Amendment in General Financial and Account Rules Vol. I.	F.13(88)FD/A&I/GFAR/68, dated 20-3-69.	24
34.	सा.वि.ले. नियमों के परिशिष्ट XX में दिये गये राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 के नियम 3 के अनुपालन के सम्बन्ध में।	एफ. 13 (104) वित्त (लेखे) / 68. दिनांक 5-3-69.	24
35.	Amendment in General Financial & Account Rules Vol. I.	F.15(22)FD/A&I/GFAR/63, dated 14-3-69.	25
36.	-do-	F.15(22)FD/A&I/GFAR/63, dated 14-3-69.	25
37.	Delegation of powers to Collectors for sanctioning and making payment without investigation in Audit of time barred personal claims of employees of Civil Supplies Department.	F.26(1)FD/A&I/GFAR/62, dated 14-2-69.	25
38.	Amendments to the Rajasthan Govt. Servants' Insurance Rules, 1953.	F.26(3)FD/A&I/62, dated 26-3-69.	25—26
39.	Amendment in G.F.&A.R. Vol. I—Appendix IV.	F.26(8)FD/A&I/GFAR/62, dated 11-2-69.	26—27

(22)

विषयः—महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में क्यू-लोन्स एण्ड एडवान्सेज, डेट एवं डिपोजिट मदों से संबन्धित ब्राड शीट एवं लेजर में भारी अन्तर के मिलान के सम्बन्ध में।

महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा पुनः इस विभाग के ध्यान में लाया गया है कि इस विषय पर इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 11-9-65 के जारी किये जाने के उपरान्त भी अभी तक, उनके कार्यालय में रक्खे जाने वाले ब्राड-शीट एवं लेजर में लम्बी अवधि से चले आरहे अन्तर के मिलान में कोई प्रगति नहीं हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेशों का विभागीय अधिकारियों द्वारा उचित पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति किसी प्रकार संतोषजनक नहीं कही जा सकती।

विभागों में नियोजित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार का यह दायित्व होगा कि वे उनके विभाग से सम्बन्धित आंकड़ों का मिलान यथाशीघ्र करावें।

विभागाध्यक्षों से पुनः अनुरोध है कि वे इस विषय की ओर अपना निजी ध्यान देवें और यदि इस कार्य को शीघ्र ही निपटाने में कोई कठिनाइयां आ रही हों तो सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उनका तुरन्त निराकरण करावाया जावे ताकि, लम्बी समयावधि से चले आ रहे अन्तर का तुरन्त निपटारा हो सके।

[वित्त (लेखा एवं विनियोजन) विभाग परिपत्र सं. प. 5 (1) वित्त (लेवि) / 59, दिनांक 26-2-1969]

---

(23)

Sub:—Amendment in Appendix XVI of General Financial and Account Rules, Vol. I.

The Governor has been pleased to order that following be added as note number 12 below rule 2 of Appendix XVI of the General Financial & Account Rules, Vol. I; viz.:—

Note:—The following types of purchases may be made from the Rajasthan Small Industries Corporation without inviting tenders or quotations:—

(*a*) The value of purchases not exceeding Rs. 1000/- in one transaction and Rs. 5000/- in a year in the case of the article noted at(*i*) to (*iii*) below:—

(*i*) Wooden furniture made by Rajasthan Small Industries Corporation other than common types of office chairs, racks, office tables and almirahs.

(*ii*) Brass Ware.

(*iii*) Hand printed or hand woven furnishing fabrics, table cloths and Bedding material.

(*b*) All articles required to be presented to the V.I. P,s.

[Finance (Accounts and Investment) Department Order No. F. 6(37) FD/A&I/GFAR/64, dated 26-2-69.]

---

(24)

Subject :—Amendment in the General Financial and Account Rules, Vol. I—Substitution of Rule 162 *ibid.*

The Governor has been pleased to order that the existing rule 162 of the General Financial & Account Rules, Vol. I be substituted by the following :—

Rule 162 :—(1) When a Government Servant presents his pay bill for the first time, or when the name of a Government Servant appears for the first time in an establishment, the bill shall be supported by a last pay certificate in form G.A.62, prescribed by the Comptroller and Auditor General (Appendix---I) or if he did not previously hold any post under the Government or is re-employed after resignation or forfeiture of past service, a certificate, by the authority to whom the medical certificate of fitness has been submitted in the case of a Gazetted Officer or the drawing and disbursing officer in the case of non-Gazetted Officer, to the effect that the medical certificate of fitness in the prescribed form, has been obtained in respect of the Government Servant, must accompany the bill in conformity with, and if so required by, any rule or order governing the conditions of the service to which he belongs.

(2) If a pensioner is re-employed, the fact shall be stated in the bill.

(3) Where the pay and allowances of the newly appointed Government Servant, who, under any rule or order has been exempted to produce the medical certificate of health, are drawn for the first-time a certificate to this effect shall be furnished in the first pay bill".

[*Finance (Accounts Investment) Deptt. Order No. F*6(40) *FD/A &I/ GFAR*/67, *dated* 24-2-69.]

---

(25)

SUBJECT:—Amendment in Rule 171 of General Financial and Account Rules Vol. I.

The Governor has been pleased to order that the exis ing note appearing below rule 171 of the General Financial & Account Rules Vol—I be deleted.

[*Finance (Accounts and Investment) Deptt. Order No. F.*6, (60) *FD/A &I/GFAR/*67 *dated* 18-2-69]

---

(26)

SUBJECT :—Amendment in Rajasthan Treasury Manual.

In exercise of the powers conferred by Article 283 (2) of the Constitution of India. the Governor has been pleased to order that the following amendments be made in Rule 20 of the "Rajasthan Treasury Rules" (as given in Part I of the Rajasthan Treasury Manual and Appendix I of the General Financial & Account Rules Vol. I) as substituted vide this department order of even number dated 4th Nov., 1968.

"Note No.1 appearing below the said rule be deleted and the Note No.2, there under, re-numbered as Note Nos. 1.".

[*Finance (Accounts & Investment) Deptt., Order No.F.*6 (60)*FD/A &I/ GFAR/* 67 *dated* 18-2-69.]

---

(27)

In pursuance of ru'e 21 of the Rajasthan Service Rules, 1951, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendment in the Rajasthan Government Servants' Insurance Rules, 1953 namely :—

AMENDMENT

In the Rajasthan Government Servants' Insurance Rules, 1953, in Sub-rule (3) of rule 45 between the words "c 'ases to be in service" and "the Policy" the words "or from the late of issue of the order of cessation of Service whichever is later "shall be inserted.

[*Finance (Accounts and Investment) Dep't. Notification No.F.*7(22) *FD/ A &I/*67 *dated* 26-3-69.]

---

(28)

SUBJECT :—Amendment in Appendix XXI to General Financial and Account Rules Vol. I

The Governor has been pleased to order that Rule 7(*a*)of Appendix XXI to the General Financial and Account Rules. Vol.I be substituted by the folloiwng viz :—

"7(*a*) *Stock verification sheet.*—The Inspecting Accounting should daily prepare in triplicate (by Carbon process) stock verification

sheets for all items of stores the verification of which has been completed that day in case where a certain percentage of items are required to be verified under these rules but in cases where cent percent items are verified he will prepare the verification sheet for those items only in which the excesses or shortages are noticed by him".

[*Finance (Accounts and Investment) Deptt. Order No. F.13(4) FD/A &I/* 69 *dated* 20-3-69]

---

(29)

SUBJECT :—Amendment in Rule 427 and Appendix IV of General Financial & Account Rules Vol I

The Governor has been pleased to order that following amendments be made in General Financial & Account Rules Vol I

I. The word "Commissioners" occuring in second line of rule 427 of the said rules be substituted by the words "Administrative Departments/Heads of Departments."

II. Item No.14 to Appendix IV of the said rules be substituted by the following :—

"*Item No.* 14:—	To accept security and to prescribe security bond to be executed by a sub-ordinate authority entrusted with the custody of Cash, Stores etc.	Full powers to the Departments o Government & Heads of Department subject to the condition prescribed in the rules.

[*Finance (Accounts and Investment) Deptt Order No. F.13(5) FD/ A &I/GFAR/*69 *dated* 14-3-69]

---

(30)

SUBJECT :—Amendment in Appendix IV of General Financial And Account Rules.

The Governor has been pleased to order that the following amendment be made in the General Financial and Account Rules Vol. I viz:—

(I) The following be added as item No. 13-C. in Appendix IV of the said Rules :—

13C. To sanction advances for payment of prize money to the Prize Winners of Rajasthan State Lotteries.	Director of Small Savings & State Lotteries.	Upto the amount fixed by the Government for a particular draw.

(II) Add the following as item No.34 in Annexure 'A' to Chapter XI of the said Ru'es :—

Director, Small Savings and State Lotteris.	For payment of Prize-money to the Prize-winners, upto the amount fixed by the Government for a particular draw. The amount shall not be drawn in cash but in the form of a Government cheque or Draft.

[Finance (Accounts & Investment) Deptt. Order No. F. 13(23)FD/A&I/GFAR/68 Dated 13-3-69.]

(31)

SUBJECT :—Sanctions of the House Building Advances to the Government Servants.

Rules 398 and 406 (4) of the General Financial & Account Rules provide that the advance for construction of a house, should ordinarily be drawn in instalments, the amount of each instalment being such as is likely to be required for expenditure in the next three months. However, when the amount is small and the Drawing Officer certifies that it is likely to be utilised within three months; it may be made payable in one instalment.

It has been brought to the notice of the Government by the Accountant General that the provisions of the above said rules are not being adhered to by the sanctioning authorities while sanctioning the House Building Advance to the Government Servants, in as much as even large amounts ranging from Rs. 20,000/- to Rs 40,000/- have been paid in one instalment, without assigning any reason, therefore or certifying that the amount is likely to be spent within three months.

It is, therefore, enjoined upon all the sanctioning authorites that the provisions of the above said Rules may please be strictly ahdered to, while sanctioning the House Building Advance and if the whole amount of the advance is sanctioned to be paid in one instalment the position should be explained in the body of the sanction itself.

[*Finance (Accounts & Investment) Deptt. Circular No. F.*13 (33) *FD/A &I*/68 *dated* 26-3-69.]

(32)

SUBJECT :—Amendment in the General Financial & Account Rules Vol.I Procedure to be followed when a cheque is alleged to have been lost and a fresh cheque is required to be issued (Rules 129(*i*))

The Governor has been pleased to order that the following be inserted as Government of Rajasthan Instruction below Rule 129(1) of the General Financial and Account Rules, Vol.I, viz :—

Government of Rajasthan Instructions

I. Rule 129, lays down the procedure that should be followed by a drawing officer in issuing a fresh cheque in lieu of a cheque alleged to have been lost. The Reserve Bank of India have represented that it is not the normal Banking practice to certify the non-payment of a cheque in such cases and that the Bank, should therefore, be relieved of this responsibility. This view of the Bank has been accepted by the Government of India. The following procedure, for issuing a fresh cheque in lieu of a cheque alleged to have been lost, should be followed in cases where the cheques issued by Government officers are payable at the Bank and have been lost before payment :—

(*i*) On receipt of a request for issue of a fresh cheque in lieu of a cheque alleged to have been lost, the drawing officer should send an intimation by Registered Post A.D. to the Bank, regarding the alleged loss of the cheque and advise to stop payment if the cheque alleged to have been lost is presented thereafter. A written confirmation about the Bank having recorded the 'Stop Order' should also be obtained from it. However, in case where the currency of the cheque alleged to have been lost has already expired, in terms of Rule 126 ibid, at the time when the request for recording the 'Stop-Order' by the Bank is made no acknowledgement of the 'stop order' by the Bank, other than a postal acknowledgement due, is necessary.

(*ii*) The Certificate prescribed in Sub-rule (1) of Rule 129 ibid should be called for from the Treasury Officer, who would give the Certificate after a search through the list of cheques paid as provided in sub-rule (2) thereof.

(*iii*) The party requesting for a fresh cheque in lieu of a lost one should execute an indemnity bond in the form given in Annexure 'B' to this Chapter. However in case of a Government department or a bank the execution of an indemnity bond is not necessary but fresh cheque should be issued in its favour only on receipt of a certificate stating that it has not received the cheque alleged to have been lost or having received it, it has been lost and that it will be returned to the drawer if found later.

(*iv*) On completion of the requirements stated in clause (*i*), (*ii*) and (*iii*) above, the drawing officer may issue a fresh cheque in lieu of the lost one, under intimation to the drawee officer.

II. The attached form may be inserted as 'Annexure B' to Chapter VII of the said rules.

[*Finance (Accounts & Investment) Deptt Order No.F.*13 (59) *FD/A &I/GFAR/*68 *dated* 5-3-69.]

Rule 129(i)

ANNEXURE 'B'

(INDEMNITY BOND TO BE EXECUTED BEFORE A FRESH CHEQUE IS ISSUED IN LIEU OF A CHEQUE THAT HAS BEEN LOST)

THIS DEED OF INDEMNITY made on the .... day of ....Between........................... son of ....Resident of ....or

(1) ....son of.................... .... resident of.................. ....

(2) ....son of............. .... resident of ....etc. carrying on business in copartnership under the name and style of....... .. ..at .... or...................... a company registered under the Indian Companies Act, 1913/Companies Act, 1956 having its registered office at.........................(hereinafter called 'the Indemnifier' which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his heir's, executors. administrators, legal representatives, successors and permitted assigns) of the ONE PART AND the Governor of Rajasthan (hereinafter called 'the Government' which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successors or assigns) of the OTHER PART.

Whereas on the.............day of.................cheque No...................dated.........................on......... (name of the bank) for Rs...........was drawn by.........in favour of the Indemnifier.

AND WHEREAS the Indemnifier has represented to the Government that the said cheque has been lost by him/during transmission by post to him.

AND WHEREAS at request of the Indemnifier the Government has agreed to issue a second cheque for Rs................being the amount of the said previous cheque No...................... ... . dated ....upon the Indemnifier giving such Indemnity as hereinafter contained.

NOW IT IS HEREBY AGREED BY and between the parties hereto as follows:—

(1) In consideration of the said premises and of the agreement on the part of the Government in issuing in favour of the Indemnifier a second cheque for Rs................being the amount of the previous cheque No..............dated ....the Indemnifier doth hereby agree and undertake to refund to the Government on demand and without demur the said sum of Rs............in the event of the said previous cheque No...............dated ....being presented to and paid by the bankers and to indemnify the Government and keep the Government harmless and indemnified from and againt all expenses which may be incurred by the Government in relation thereto or in connection therewith.

(2) The Government agrees to bear the stamp duty, if any, chargeable on these presents.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have set and subscribed their respective hands hereunto on the.................... day and year first above written.

Signed by the said Indemnifier in the presence of:—
(1) Indemnifier..................
(2) Address..................
Signed for and on behalf of the Governor of Rajasthan by Shri ......
(name and designation) in the presence of:—

(1) Name and designation
(2) of the officer................

(33)

SUBJECT:—Amendment in General Financial and Account Rules Vol—I

The Governor has been pleased to order that following be added as note No. 4 below rule 358 of General Financial and Account Rules Vol - I viz—

Note 4:—No amount will be credited towards the payment of principal as long as any sum is due on account of interest unpaid. While calculating the interest unpaid it should be seen that interest for any half year (or year) is not due "until the end of half year (or year) during which it accrues."

[*Finance (Accounts and Investment) Deptt Order No. F.*13 (88) *FD A & I/GFAR/*68 *dated* 20-3-69.]

(34)

विषय :—सा. वि. ले. नियमों के परिशिष्ठ XX में दिये गये राजस्थान, भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 के नियम 3 के अनुपालन के संबंध में।

राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 के नियम 3 के अनुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त की गई भूमि, के मुग्रावजे (एवार्ड) भुगतान के विवरण-पत्र भुगतान की तिथि को ही महालेखाकार को भेजे जाने चाहिये। परन्तु महालेखाकार, राजस्थान द्वारा मेरे यह ध्यान में लाया गया है कि उक्त नियम का पूर्णतया पालन नहीं किया जाता है। इस विषय पर राजस्व (ग) विभाग द्वारा भी आपको लिखा जा चुका है। परन्तु फिर भी स्थिति में संतोषजनक सुधार हुआ प्रतीत नहीं होता।

अतः मैं यह चाहूंगा कि आप इस विषय पर अपना निजी ध्यान दें तथा ऐसी व्यवस्था करें कि भविष्य में इस प्रकार के विवरण पत्र समय पर ही महालेखाकार को भिजवा दिये जावें।

[वित्त (एवं लेखा विनियोजन) विभाग परिपत्र सं. एफ. 13(104) वित्त (लेवि) 68 दिनांक 5-3-69]

(35)

SUBJECT :—Amendment in General Financial & Account Rules Vol.I.

The Governor has been pleased to order that the following be added as note below rule 22 of the General Financial & Account Rules Vol. I viz.—

Note :—Loss exceeding Rs. 5000/- in value, caused by breaches in canals on account of natural causes (flow of water) be reported to the Accountant General, Rajasthan, Jaipur. The term value for this purpose means the book value.

[*Finance (Accounts &Investment) Deptt. Order No. F.*15(22) *FD/A &I/ GFAR*/63 *dated* 14-3-69]

(36)

SUBJECT :—Amendment in General Financial & Account Rules Vol. I

The Governor has been pleased to order that the figure of Rs."200/-" appearing in first line of exception 2(*a*) under rule 20(2) of General Financial and Account Rules Vol. I be substituted by the figure of Rs. "500/-"

[*Finance (Accounts and Investment) Deptt. Order No. F.*15(22) *FD/ A &I/ GFAR*/63 *dated* 14-3-69.]

(37)

SUBJECT :—Delegation of Powers to Collectors for sanctioning and making payment without investigation in Audit of time barred personal Claims of Employees of Civil Supplies Department.

In continuation of this department order of even number dated 2nd August, 1965 on the above subject the Governor has been pleased to exte d the term mentioned in Finance Department Order No. F. 19 (1) FD/A/R/60 dated 31-5-61 upto 31-12-69.

[*Finance (Accounts &Investment) Deptt Order No. F.*26(1)*FD/A & I/ GFAR*/62 *dated* 14-2-69]

(38)

In pursuance of Rule 21 of the Rajasthan Service Rules 1951, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendment to the Rajasthan Government Servants' Insurance Rules, 1953, namely :—

AMENDMENT

In the Rajasthan Government Servants' Insurance Rules, 1953, for the existing Rule 7 the following shall be substituted, namely :—

"7. *Accounts*:—All receipts and disbursements of the Department shall be carried to a separate head of account, called the Insurance

Fund, and such account shall be credited every year with interest at the rate paid, from time to time, on the money borrowed by the Government.

[*Finance (Accounts &Investment) Deptt. Notification No. F.*26 (3)*FD/A &I*/62 *Dated* 26-3-69]

---

(39)

SUBJECT :—*Amendment in the General Financial and Account* Rules, Volume I—Appendix IV—Substitution of item No.3 thereof.

The Governor has been pleased to order that the following amendments be made in the General Financial and Account Rules Vol.I viz :—

I. Substitute the words "three years" for the existing words "one year" occurring in the fourth line of Rule 69 of the said Rules.

II. Substitute the following for the existing item No. 3 and the condi'ions thereunder (excepting the Annexure of Appendix IV of the said rules :—

Item No.3(a)		
To sanction investigation by Audit of personal claims of Government servants, except T.A. claims , of more than 3 years but not more than 6 years old.	Administrative Deptt. and Head of Deptt.	Full powers
Item No.3(b)		
To redelegate the powers at item No.3 (a) to subordinate authority which appoints the Government s rvant preferring the claim	-do-	Full powers
Item No.3(c)		
To sanction payment in satisfaction of old claims of Government servants, other than T.A. claims, which are more than 6 years old & T.A. claims which are more than 3 years old.	Administrative Deptt./ Head of Department Class I.	-do-
Item No.3 (d)		
To sanction investigation into audit of old contingent claims.	Administrative Deptt. and Heads of Dept.	Full powers provided the claim is not more than 3 years old.

The heads of Departments shall exercise the powers subject to the following conditions :—

(i) In respect of the powers delegated necessary requirements and certificates as mentioned in Annexure 'A' to this Appendix shall be satisfied by the sanctioning authority.

(ii) In addition to satisfying the condition No. (1) above, the claims for which powers have been delegated in item No.3 (c) the claims shall be pre-checked and audited by the Accounts Officer of the department and in case of the claims of Government Servants of District Collectorate by District Officer, Revenue Accountant or by an Accountant encadered in Subordinate Accounts Service and shall be sanctioned provided the claim is found in order or passed for payment as a result of such pre-check and audit. This will not apply in departments where the Chief Accounts Officer is the Head of Department Class I.

[*Finance (Accounts and Investment) Deptt. order No. F.*26(8) *FD/ A &I/ GFAR*/62, *dated* 11-2-69.]

सामान्य प्रशासन विभाग

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

सूची

(4)

In exercise of the powers conferred by the Article 166 of the Constitution of India, the Governor has been pleased to order that all matters relating to "State Motor Garage" at present being dealt with in Home Department will henceforth be dealt with in General Administration Department.

[*General Administration Department Order No.F.*1(1) *GA/A/*69, *dated* 6-3-69.]

गृह विभाग
HOME DEPARTMENT

सूची

HOME DEPARTMENT

(4)

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3-8-68, जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिये उपयोगकर्ता सलाहकार समितियों की स्थापना की गई है, के हर तीनों खंडों के मद संख्या (2) पर "राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा मनोनीत सदस्य-1" के स्थान पर "राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का प्रतिनिधि" पढ़ा जाये।

[गृह ख-1 विभाग संशोधन सं. प. 2(4) (85) गृह (ख-1) 67 दिनांक 22-3-69.]

राजस्व विभाग
Revenue Department

सूची

REVENUE DEPARTMENT

(3)

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to further amend the Rajasthan Forest Subordinate Service Rules, 1963, namely .—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Rajasthan Forest Subordinate Service (Amendment) Rules, 1969.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st September, 1968.

2. *Amendment of Rule* 10.—In rule 10 of the Rajasthan Forest Subordinate Service Rules, 1963, for words 'on the date the course of training starts', the words 'on the date the course of training for the year he is selected starts' shall be substituted.

[*Revenue Department Notification No. F.* 11(76)*Rev/A/*67, *dated* 10-3-69.]